

**“भारतीय राजनीति की १९६७-१९८६ तक की प्रवृत्तियाँ
एक अध्ययन विकसित हो रही भारतीय राजनीतिक
संस्कृति के सन्दर्भ में”**

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डॉक्टर ऑफ फ़िलासफी उपाधि के लिए प्रस्तुत
शोध प्रबन्ध

शोधकर्ता
संतोष कुमार चतुर्वेदी
एम०ए० (रा०वि०)

निर्देशक
श्रीमती सुनीता अग्रवाल
रीडर



राजनीति विज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

१९९५

प्राक्कथन

वर्तमान समय में भारतीय जन-मानस में भारतीय राजनीति के गिरते चरित्र के कारण पैदा हो रही उदासी सम्पूर्ण भारतीय राजनीतिक संस्कृति के लिए समस्या का विषय होती जा रही है। वर्तमान समय में किसी भी देश को सामान्य संस्कृति वहाँ की राजनीतिक संस्कृति से बहुत हद तक दिशा प्राप्त करती रही है। इसी से समाज के उमर राजनीति के असर को समझा जा सकता है। इसका मुख्य कारण राजनीति के जरिये सत्ता प्राप्ति एवं सत्ता से देश को राजनीतिक संस्कृति का निरूपण होना है। अतः राजनीति की स्थिति वह मापदण्ड है जिससे देश अथवा काल का वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

भारतीय राजनीति में 1967 से लेकर वर्तमान तक अनेको परिवर्तन दिखाई देते हैं। वैसे 1967 का वर्ष भारतीय राजनीति में मोल का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि इस वर्ष से हो तथाकथित कमिंस व्यवस्था का एकाधिकार टूटने लगा एवं राष्ट्रिय नेतृत्व धीरे-धीरे समाप्त सा होता दिखाई देने लगा। इसके बाद के वर्षों में भारतीय राजनीति में जिन प्रवृत्तियों का समावेश हुआ उनमें क्षेत्र विशेष आधारित राजनीति, सत्ता प्राप्ति के लिए दल-बदल, वोट के लिए जाति एवं धर्म जैसे विषयों को विशेष बल देना, राजनीति का पैसे एवं हिंसा के बल पर अपराधिकरण का स्वरूप ले लेना इत्यादि विशेष रूप से दिखाई देते हैं। इन प्रवृत्तियों के कारण भारत की एकता एवं अखंडता प्रभावित हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय साम्प्रदायिक राजनीति के कारण ही देश का बँटवारा हुआ। देश की जनता आज भी उस सदमे की पूर्ण रूप से नहीं भूल पाई है, एवं उससे कोई सबक नहीं ले पाई है। इसके बाद राजनीतिक दल चुनावों में साम्प्रदायिक एवं जातिवादी मत का कार्ड इस्तेमाल करने से नहीं चुकते जिनका

प्रत्यक्ष प्रमाण आजकल के चुनावों में दिखाई देते हैं एवं वर्तमान भारतीय राजनीति में इन्होंने प्रवृत्तियों का बोल-बाला है। इन प्रवृत्तियों ने ही राजनीतिक उद्देश्यों को संकुचित कर दिया है एवं सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणाली को दोष पूर्ण कर दिया है। इसी के कारण सम्पूर्ण राजनीतिक संस्कृति का परिवर्तन होता जा रहा है। इस परिवर्तन के कारण ही भारतीय सामान्य जनमानस का राजनीति से विश्वास दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है अतः भारतीय राजनीति को समकालीन प्रवृत्तियों के कारण विकसित हो रहे राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन सामान्य जनता एवं राजनीतिक दलों एवं उनके नेताओं के लिए रुचि एवं जिज्ञासा का विषय है।

इस शोध प्रबंध में राजनीति शास्त्रियों के शोध अध्ययनों का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। समकालीन राजनीति को प्रवृत्तियों को जानने के लिए चुनाव आयोगों की रिपोर्टों का भी प्रयोग किया गया है। समकालीन भारतीय राजनीति को जानने के मुख्य स्रोत रहे हैं तत्कालीन समाचार पत्र, जनरल एवं शोध संस्थानों द्वारा प्रकाशित आर्टिकल्स। शोध प्रबन्ध में इस सामग्री का यथेष्ट प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पत्रिकाएँ, राजनीतिक विज्ञान के विद्वानों द्वारा लिखित पुस्तकें तथा राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र शोध प्रबंध के प्रमुख आधार रहे हैं।

अपने पूज्य अध्यापक श्री एच०एम० जैन, भूतपूर्व अध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग के प्रति कृतज्ञ हूँ जिनके सहयोग से इस शोध कार्य के प्रारंभ एवं पूर्ण करने में मुझे हर तरह की सहायता मिली। मैं श्रेया श्रोमती सुनीता अग्रवाल का अत्यन्त आभारी हूँ जिनके योग्य निर्देशन के अभाव में यह शोध प्रबंध पूर्ण नहीं हो सकता था। मैं अपने अध्यापकों डॉ० यू०के० तिवारी वर्तमान विभागाध्यक्ष एवं डॉ० के०के० मिश्र का भी आभारी हूँ जिनसे सहयोग से यह शोध प्रबंध पूर्ण हो सका।

संतोष कुमार चतुर्वेदी

दिनांक 29/3/95

सूची- पत्र

प्राक्कथन

पृष्ठ संख्या

§ 1 § अध्याय - 1

6 - 27

विषय- प्रवेश

§ 2 § अध्याय - 2

28 - 60

भारत में 1967-69 बीच राजनीतिक दलों
को स्थिति एवं दलीय राजनीति ।

§ 3 § अध्याय - 3

61 - 98

क्षेत्रवाद

§ 4 § अध्याय- 4

99 - 131

दल-बदल एवं संविद सरकारों को राजनीति

§ 5 § अध्याय - 5

132 - 165

जातिवाद एवं सम्प्रदायवाद

§ 6 § अध्याय- 6

166 - 179

राजनीति का अपराधोकरण

§ 7 § अध्याय - 7

180 - 198

नौकरोशाहो को भूमिका

§ 8 § अध्याय - 8

199 - 219

उपसंहार

§ 9 § परिशिष्ट

220 - 247

§ 10 § संदर्भ - सूची

248 - 258

अध्याय - ।

विषय - प्रवेश

अध्याय - 1

विषय - प्रवेश

राजनैतिक संस्कृति :

किसी भी युग को किसी संस्कृति के सहो मूल्यांकन के लिए उन सभी तत्कालीन सामाजिक तत्वों का अध्ययन जरूरी है जो मनुष्यों को समाज में परस्पर संयुक्त करते हैं। आर्नाल्ड ग्रेन के अनुसार संस्कृति, ज्ञान, व्यवहार एवं विश्वास के आदर्शकृत ढंगों को सामाजिक रूप से हस्तांतरित प्रणाली, इसको कलाकृतियों सहित, जिन्हें ज्ञान, व्यवहार, समय के परिवर्तन के अनुसार उत्पन्न एवं रक्षित है¹।

राजनैतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रेवियल आमण्ड ने किया। राजनैतिक संस्कृति को संकल्पना का अध्ययन राजनैतिक विकास के विषय के समाज वैज्ञानिक पहलुओं का परोक्षण करना है। जब से उल्म, वोर, आमंड ने इस शब्द को लोकप्रियता प्रदान की है, यह राजनैतिक व्यवस्थाओं के आकारोप अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण कसौटी बन गया है। इसने समाजशास्त्रियों को इस बात का आग्रह करने के लिए प्रभावित किया है कि एक राजनैतिक व्यवस्था दूसरी राजनैतिक व्यवस्था से न केवल संरचना की दृष्टि से बल्कि राजनैतिक संस्कृति की दृष्टि से भी भिन्न है जिसमें ये स्थिति होती है।

किसी राजनैतिक संस्कृति में उस समाज की अभिवृत्तियाँ, विश्वास, भावनार्य और मूल्य शामिल होते हैं जिनका राजनैतिक व्यवस्था और राजनैतिक मुद्दों से सम्बन्ध होता है।² इसको परिभाषा किसी राजनैतिक व्यवस्था के सदस्यों के राजनैतिक प्रति व्यक्ति की अभिवृत्तियों और अभिविन्यासों के

1- क्लयर इन सोशल ट्रांसमोटेड सिस्टम ऑफ अडियालाइज्ड वेज इन नाजेज, प्रैक्टोस एंड बिलोफ, एलांग विथ द आर्टिफैक्ट्स टैट नालेज एंड प्रैक्टोस प्रोड्यूस एंड मेन्टेन ऐज दे धेंज इन टाइम - आर्नाल्ड ग्रेन।

2- ए. आर. बॉल : मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट पेज 56

प्रतिमानों के रूप में को जाती है ।¹

किसी समाज के सदस्यों में भावात्मक प्रेरणाओं, बौद्धिक क्षमताओं और नैतिक परिप्रेक्ष्यों के रूप में समान मानव प्रकृति होती है, यह मानव प्रकृति किन्हीं मूल्यों, विश्वासों और भावात्मक अभिवृत्तियों के रूप में अन्धेने आपको अभिव्यक्त करती है जो क्मोवेश संशोधनों के साथ एक पौढ़ो से अगले पौढ़ो तक सम्प्रेषित की जाती है और इस प्रकार किसी समाज को समान संस्कृति की रचना करती है । समाज की सामान्य संस्कृति का सम्बन्ध इस बात से होता है कि सरकार किस प्रकार चलाई जानी चाहिए और इसे क्या करने की कोशिश करना चाहिए । संस्कृति के इस क्षेत्र को हम राजनैतिक संस्कृति कह सकते हैं ।² यह उन अभिवृत्तियों, विश्वासों और सम्बेदों का समुच्चय है, जो किसी राजनैतिक प्रक्रिया को व्यवस्था और अर्थ प्रदान करते हैं और वे उन अतंनिर्हित परिकल्पनाओं व नियमों को व्यवस्था करते हैं जो राजनैतिक व्यवस्था में व्यवहार का संचालन करते हैं ।³

अतः राजनैतिक संस्कृति को राजनैतिक उद्देश्यों के प्रति नागरिकों के अभिविन्यास के सामूहिक वितरण के रूप में देखा जा सकता है ।⁴

लुसियन पाई ने तीसरी दुनिया के नए राज्यों से सम्बन्धित अपनी राजनैतिक विकास की संकल्पना के संदर्भ में राजनैतिक संस्कृति के अभिप्राय का अध्ययन किया है और इसके लिए उसने अध्ययन में तीन कारकों को शामिल किया है ।⁵

1- जो. ए. आर्मंड एंड जो. वोग पावेल कम्परेटिव पार्लिटिक्स ए डेबलपमेंटल एप्रोच पेज 50

2- बोएर एंड उलम : पैटर्न्स ऑफ गवर्नमेंट & न्यूयार्क रेंडम हाउस 1962 पेज- 32

3- लुसियन पाई - रेस्पेक्ट ऑफ पार्लिटिकल डेबलपमेंट पेज - 104

4- डेनिस क्वांथ - पार्लिटिकल कल्चर पेज- 11

5- लुसियन पाई : पार्लिटिक्स, पर्सनैलिटी एंड नेशन बिब्लिंग पेज - 122-23

- 1- राजनीति का विस्तार, राजनीति में साध्य एवं साधन किस प्रकार से सम्बन्धित है ।
- 2- राजनीतिक कार्य के मूल्यांकन के लिए मानक ।
- 3- राजनीतिक कार्य के लिए प्रमुख मूल्य ।

यह जाहिर है कि राजनीतिक संस्कृति को संकल्पना आत्मपरक क्षेत्र का हिस्सा है । आमंड एवं पावेल के अनुसार, इस प्रकार के व्यक्तिगत अभिविन्यास के तीन संघटक होते हैं -

- 1- संज्ञानो अभिविन्यास - जिससे अभिप्राय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में यथार्थ अथवा अन्यथा से है ।
- 2- भावात्मक अभिविन्यास- जिससे अभिप्राय लगाव, सहयोग अस्वीकृति आदि को राजनीतिक वस्तुओं के बारे में भावनाओं से है ।
- 3- मूल्यांकक अभिविन्यास - जिससे अभिप्राय राजनीतिक वस्तुओं के बारे में निर्णयों और राज्यों से है जिसके अंतर्गत सामान्यतः राजनीतिक विषयों और घटनाओं पर मूल्य मानकों को लागू किया जाता है ।¹

राजनीतिक संस्कृति के कइसे घटक हैं जिनका स्थान समाज विज्ञान के जगत में है । वे है मूल्य, विश्वास और सम्वेदनात्मक अभिवृत्तियाँ, जो लोग अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति रखते है ।² हम यह देख सकते हैं कि लोगो के आम झोर पर कुछ राजनीतिक मूल्य होते है, जैसे एक निश्चित अवधि के बाद निर्वाचन उपयुक्त और निष्पक्ष ढंग से होने चाहिए, जनता का विश्वास खोने पर मंत्रियों को अपने पदों से त्यागपत्र दे देना चाहिए । लोगो और देश के वास्तविक व्यवहार के बारे में राजनीतिक विश्वासो का घटक राजनीति मूल्यों से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है । विश्वासो के सार्थक कारण को इस तथ्य में खोजा जाना चाहिए जो विचार पहली नजर में राजनीति से सम्बन्ध प्रतीत

1- आमंड रंड पावेल आफ सोट पेज - 50

2- फिर वही,

नही होते है वे राजनौतिक संस्कृति को विश्वास व्यवस्था द्वारा इससे धनिकृठ रूप से प्रतीत हो सकते है ।¹ अंतिम हम सम्वेदनात्मक अभिवृत्तियों अर्थात् लोगो के सूर एवं मिजाज के घटक पर आते है सांविधानिक लोकतंत्र के लिए संघर्ष से भरे अतीत विरासत में प्राप्त अभिवृत्तियों को देखकर पता चलता है कि वक्ताओं को सम्य तरोके और नम्रता से हो व्यवहार करना चाहिए, चर्चा का सूर वातलाप पूर्ण होना चाहिए और व्यवहार भाषण को सारो शैली हो न केवल संसद को प्रक्रिया नियमो के अनुरूप हो बल्कि परंपराओं के जटिल और बहुत हद तक अत्यक्त समुच्चय के अनुसार भी होनी चाहिए ।²

राजनौतिक संस्कृति का निर्माण इन विभिन्न प्रकार के अभिविन्यासो के संयोग से होता है उपर्युक्त आधार पर प्रत्येक व्यक्ति एवं समूह को राजनौतिक संस्कृति को निश्चित रूप से समझा जा सकता है । अतः यदि किसी व्यक्ति के या समूह या किसी देश को राजनौतिक संस्कृति के संबंध में जानना है तो हमें यह देखना होगा कि उस व्यक्ति या समूह को अपने राष्ट्र, उसकी राजनौतिक व्यवस्था, इतिहास, राजनौतिक संरचना सांविधानिक विशेषताओं, पद धारको, विशेष नीतियों के कार्यान्वयन, राजनौतिक तंत्र में स्वयं के कार्यभाग, अपने अधिकारो और कर्तव्यों का ज्ञान आदि के सम्बन्ध में कितनी जानकारी है तथा उनके संबंध में उनको क्या भावना तथा निर्णय या मत है १ इसीलिए बर्बा ने लिखा हैकि राजनौतिक तंत्र के प्रति सामान्य रूप से तथा इसको अदा या प्रदा प्रक्रिया के पक्षो और एक राजनौतिक कर्ता के रूप में स्वयं के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मूल्यांकित अभिविन्यासो को आवृत्ति से राजनौतिक संस्कृति को संरचना होती है ।³

1- वोर एंड उलम आफ सोट पेज - 4।

2- पिरर वही,

3- जो. ए. आमंड एंड एस. बर्बा दि सिविक कन्वर प्रिस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1963 ।

भारत में राजनीतिक संस्कृति -

भारत को राजनीतिक संस्कृति के बारे में जानने के लिए पहले भारतीय राजनीति की प्रवृत्तियों को जानना होगा। भारत को राजनीतिक संस्कृति के बारे में कुछ पश्चिमी लेखकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं जिन पर काफी विवाद रहा है। ऐसे विचारकों में माडरन वोनर एवं मारिस जोंस का नाम उल्लेखनीय है - माडरन वोनर के अनुसार भारत भारत में दो राजनीतिक संस्कृतियाँ पाई जाती हैं।¹

विशिष्ट वर्गीय राजनीतिक संस्कृति उन व्यक्तियों को राजनीतिक संस्कृति है, जो राष्ट्रीय राजनीति में क्रियाशील है यह राजनीतिक संस्कृति मुख्यतः दिल्ली में पाई जाती है। वोनर का कहना है कि भारत को राष्ट्रीय राजनीति पर विशिष्ट वर्ग का आधिपत्य दिखाई देता है। इस विशिष्ट वर्ग में संसद के सदस्य, नियोजन आयोग के सदस्य, राष्ट्रीय स्तर के नेता और वरिष्ठ पदाधिकारी आदि सम्मिलित हैं। इस विशिष्ट वर्ग से विकसित होने वाली संस्कृति को वोनर ने विशिष्ट वर्गीय राजनीतिक संस्कृति की संज्ञा दी है। उसके अनुसार इस विशिष्ट वर्ग में ऐसे लोग हैं जो उच्च शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं और जिनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय है जो अधिक पश्चिमाभिमुख हैं और धर्म निरपेक्षता के आदर्शों के पोषक हैं। संक्षेप में ये लोग आधुनिकोक्त हैं।² वोनर ने विशिष्ट अथवा अभिजनात्मक राजनीतिक संस्कृति का नाम दिया है भारत में स्वतंत्रता से पहले तक इसी प्रकार की राजनीतिक संस्कृति थी।²

भारत में 1947 के बाद एक और राजनीतिक संस्कृति का उदय हुआ। यह संस्कृति स्थानीय से विकसित होकर जिला स्तर की राजनीति और

1- माडरन वोनर के लेख - दू पोलिटिकल कल्चर एंड पोलिटिकल डेवलपमेंट, प्रिन्स्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, 19

2- फिर वहाँ,

जिला से राज्य स्तर तक को राजनीति में प्रवेश कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में उभरने वाली इस राजनीतिक संस्कृति को वीनर जन राजनीतिक संस्कृति को संज्ञा देता है। इसके अनुसार स्वतंत्रता के पश्चात जन साधारण को सक्रिय राजनीति में भाग लेने का समान अवसर प्राप्त हुआ और वयस्त मतधिकार दिए जाने के परिणाम स्वस्थ, सर्व साधारण विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में दाखिल होने लगे। इन व्यक्तियों के राजनीतिक विश्वास, उनको राजनीतिक धाराणाये, उनका राजनीतिक ज्ञान, राज्य तथा सरकार के प्रति उनका दृष्टिकोण उन लोगों से भिन्न है, जो राष्ट्रीय स्तर को राजनीति में है। इस दूसरे प्रकार को राजनीतिक संस्कृति के उदय के वीनर के तीन कारण बताए हैं।¹

- 1- सरकार के कार्यों का अधिक विस्तार।
- 2- सत्ता का विकेन्द्रोकरण।
- 3- सत्ता का जनतांत्रिकरण।

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राज्य के कार्य क्षेत्र का अधिक विस्तार हुआ। आंतरिक शांति को स्थापना और बाह्य आक्रमण से रक्षा के कार्यों से लेकर छोटी से छोटी सेवाओं के संपादन का उत्तरदायित्व राज्य पर डाला गया। जिसके कारण व्यक्ति राज्य के करीब आता गया और उसे राज्य तथा सरकार को समझने का समुचित अवसर प्राप्त हुआ।²

राजनीति में जन साधारण द्वारा सक्रिय भाग लिए जाने का दूसरा कारण सत्ता का विकेन्द्रोकरण है। भारतीय संविधान ने एक संघात्मक शासन प्रणाली को स्थापना की जिसके अनुसार केन्द्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन संविधान द्वारा किया गया। राज्य सरकारों के अतिरिक्त शक्ति का अतिरिक्त विकेन्द्रोकरण ग्रामीण स्तर तक हुआ और ग्राम

-
- 1- फिर वहीं,
 - 2- फिर वहीं,

पंचायत, क्षेत्र समिति जिला परिषद, नगर पालिका आदि प्रशासकीय संस्थाओं को स्थापना की गई। प्रत्येक प्रशासकीय इकाई को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। इन नई प्रशासकीय संस्थाओं को स्थापना ने जन साधारण को अपने ओर आकर्षित किया और जन साधारण को सत्ता की राजनीति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया।¹

जन साधारण को राजनीति में भाग लेने का अधिक अवसर न मिलता यदि सत्ता का जनतंत्रोत्थरण न किया गया होता। संविधान लागू होने के बाद सत्ता की जो विकेंद्रीकरण किया गया और फलस्वरूप जिन राजनीतिक संस्थाओं का उदय हुआ उनके संगठन का आधार जनतंत्रात्मक था।²

प्रशासन को निम्न इकाई ग्राम पंचायत है। पंचायतों से लेकर क्षेत्र समितियों, जिला परिषदों, नगर पालिकाओं आदि स्थानीय निकायों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है। संविधान ने राजनीतिक समानता के सिद्धान्त को मानते हुए व्यस्त मत अधिकार के सिद्धान्त को मान्यता प्रदान की है जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक नागरिक को उसकी जाति, धर्म, शिक्षा, योग्यता आदि के आधार पर कोई भेदभाव किए, बिना विभिन्न प्रशासकीय तथा राजनीतिक संस्थाओं की सदस्यता के लिए खड़े होने तथा मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसका परिणाम है कि आज ग्राम पंचायतों से लेकर राज्य विधान सभाओं तक नए लोग राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। इन नए लोगों के राजनीति में प्रवेश करने से एक नई राजनीतिक संस्कृति का उदय हुआ जिसे वीनर ने जन राजनीतिक संस्कृति का नाम दिया है। राजनीति में प्रवेश करने वाले ये नये व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों से राजनीति में प्रवेश करते ऊपर की ओर बढ़ते हुए राज्य विधान सभाओं में पहुँच रहे हैं कम शिक्षित हैं और उन पर परम्परावादी मान्यताओं की छाप अधिक है तथा वे राष्ट्रीय समस्याओं से पूर्ण रूप से परिचित नहीं हैं। इसलिए वे राष्ट्रीय हितों का

बलिदान करके स्थानीय हितों को अधिक बढ़ावा देने में संकोच नहीं करते ।
उन पर धर्म एवं जातिवाद का प्रभाव अधिक दिखाई देता है ।

सर्वसाधारण को राजनीतिक संस्कृति निरन्तर फैलने वाली संस्कृति है, अर्थात् यह संस्कृति स्थानीय राजनीति से लेकर जिलों को राजनीतिक संस्थाओं से होतो हुई प्रदेश के विधान मंडलों तक पहुँच रही है । जब कि विशिष्ट वर्ग को संस्कृति दिल्ली तक ही सीमित है । वीनर के अनुसार जनसाधारण को संस्कृति में परम्परावाद को छाप पूर्ण रूप से दिखाई देती है ।¹ प्राचीन समाज में विभिन्न वर्गों अथवा दो व्यक्तियों के बीच होने वाले झगड़ों का निपटारा समझौते द्वारा किया जाता था । विवादों से निपटने का यह परम्परावादों तरिका आप भी जनसाधारण को राजनीतिक संस्कृति को एक प्रमुख विशेषता है । सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच श्रमिकों और पूँजीपतियों के बीच दल के विभिन्न गुटों के बीच, उठने वाले झगड़ों का निपटारा आज भी मध्यस्थता के द्वारा किया जाता है ।²

ब्रिटिश काल में सरकारी कर्मचारियों और जनसाधारण के बीच कोई प्रत्यक्ष सम्पर्क न था और उनके सम्बन्ध शासक एवं शासित के समान था । लोक पदाधिकारी अपने को जनसाधारण का शासक मानते थे और जनसाधारण उन्हें अपने मालिक के समान मानते थे । इन लोक पदाधिकारियों का जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व न था । स्वतंत्रता के पश्चात् सैद्धान्तिक रूप से यह सम्बन्ध नागरिक एवं जन सेवक के संबंधों में परिवर्तित हो गए । जिसके अनुसार लोक पदाधिकारियों को अपने को जनता का सेवक समझना चाहिए लेकिन वे आज भी ब्रिटिश कालों परंपरा के अनुसार अपने को जनता का शासक समझते हैं और उनके जनता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का अभाव है। स्थानीय शासन के पदाधिकारी अपने उच्च अधिकारियों की सेवा करने पर ज्यादा धन

1- फिर वहीं,

2- फिर वहीं,

देते हैं और जनता को सेवा में पर कोई ध्यान नहीं देते प्रशासन में रिश्वत खोरो और भ्रष्टाचार को अधिक प्रोत्साहन मिलता है ।¹

वोनर के अनुसार सरकार के कार्य क्षेत्र के विस्तार तथा राजनीतिक सत्ता के विकेन्द्रोकरण एवं जनतांत्रिकरण ने राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर को राजनीति में सर्व साधारण को भाग लेने का पूर्ण अवसर प्रदान किया और जो लोग इससे पहले राजनीति से बिल्कुल अलग थे वे धीरे-धीरे राजनीति के विभिन्न स्तरों में प्रवेश पा रहे हैं जिससे एक नई राजनीतिक संस्कृति विकसित हो रही है । वोनर के अनुसार सर्वसाधारण को यह राजनीतिक संस्कृति विकसित हो रही है । वोनर के अनुसार सर्वसाधारण को यह राजनीतिक संस्कृति न पूर्णतया परम्परावादो है और न ही पूर्ण आधुनिक , बल्कि यह परम्परावाद तथा आधुनिकता का मिश्रण है जिसमें संकीर्णता एवं स्थानोपता को प्रधानता है ।²

ऐसा कहा जाता है कि भारतीय राजनीति पर एक भी सत्यतापूर्ण पुस्तक नहीं लिखी गई है । मारिस जोंस का कहना है कि इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय राजनीति पर पुस्तकें लिखने वाले ने झूठ का सहारा लिया है बल्कि इसका कारण यह है कि भारत की राजनीतिक के पथार्थ रूप तक पहुँचना कठिन है । प्रत्येक राज्य के राजनीतिक जीवन का अंतर्निहित स्वस्व होता है और उससे सम्बन्धित पुस्तक में उस वास्तविक स्थिति का उल्लेख किया जाना चाहिए । लेकिन भारतीय राजनीति के संबंध में कठिनाई यह है कि यहाँ की राजनीति का सैद्धान्तिक और व्यवहारिक स्वस्व इतना भिन्न है कि उसे समझने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । जोंस का कहना है कि भारत की राजनीतिक जीवन का गूढ़ अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ कोई भी चीज जिस रूप में दिखाई देती है वास्तव में वह

1- फिर वहाँ,

2- फिर वहाँ,

वैसा हो नहीं है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय राजनीतिक शैली के दिखावे और उसकी वास्तविकता में मौलिक अंतर है। इसलिए राजनीति के केवल वाह्य स्वरूप को देखकर जिन निष्कर्षों अथवा सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जाता है वे राजनीति की वास्तविकताओं को प्रस्तुत नहीं करते। मारिस जोस का यह दावा है कि भारत को विभिन्न राजनीतिक संस्थाएँ जिन आदर्शों को प्रस्तुत करती हैं और यहाँ के राजनीतिक नेता जिन सिद्धान्तों का उपदेश देते हैं व्यवहार में वे स्वयं ही उन्हें तिरस्कृत करते हैं। उनका यह भी कहना है कि भारतीय राजनीति का स्वरूप इतना उलझा हुआ है कि उसे उसके वाह्य स्वरूप के आधार पर नहीं समझा जा सकता।¹

भारत के राजनीतिक जीवन में संलग्न व्यक्तियों की राजनीतिक अवधारणा, विभिन्न समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण, उनके द्वारा अपनाए जाने वाले मूल्य और उनका राजनीतिक आचरण एक समान नहीं दिखाई देता। उनमें इतनी मौलिक विभिन्नताएँ दिखाई देती हैं जिन्हें श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। इन विभिन्नताओं की दृष्टि में रखते हुए मारिस जोस ने भारत के राजनीतिक जीवन को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है जिनको उन्होंने भारतीय राजनीति को तीन मुहावरे कहा।² मारिस जोस का कहना है कि भारतीय राजनीति की प्रकृति को इन मुहावरों के जरिये समझा जा सकता है। उनके अनुसार तीन भाषायें जिनके अनुसार भारतीय राजनीतिक जीवन का संचालन होता है उन्हें आधुनिक परम्परावादों और संतवादों भाषा का नाम दिया जा सकता है। ऐसा लगता है कि मारिस जोस ने राजनीति के इन विभिन्न रूपों के लिए इंडियन शब्द का प्रयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि जिस प्रकार प्रत्येक भाषा में अलग-अलग मुहावरे होते हैं जिनका अर्थ साधारण वाक्यों की तरह स्पष्ट नहीं होता बल्कि वास्तविक अर्थ उनमें छिपा हुआ होता है जिन्हें गूढ़

1- मारिस जोस की पुस्तक दि गवर्निमेंट ऐट पार्लिटिक्स ऑफ इंडिया के अध्याय पार्लिटिक्स एंड सोसाइटीज पृष्ठ 52 से।

विचार के बाद हो समझा जा सकता है। उसी प्रकार भारतीय राजनीति के ये विभिन्न रूप आसानों से नहीं समझे जा सकते क्योंकि इनका अंतर्निहित स्वरूप इनके वाह्य स्वरूप से भिन्न है।¹

मारिस जॉस के द्वारा प्रतिपादित भारतीय राजनीति के इन तीन मुहावरों का साधारण अर्थ यह है कि भारत के राजनीतिक जीवन में तीन प्रकार के विचार वाले लोग पाए जाते हैं। कुछ वे लोग हैं जिनका दृष्टिकोण विस्तृत है और जो राष्ट्रीय हितों को महत्व देते हैं। इन्हें आधुनिक वर्ग में शामिल किया जाता है। दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो परंपरावादों विचार धाराओं के पोषक हैं जातीय भेदभाव पर विश्वास करते हैं स्थानीय हितों को महत्व देते हैं और राष्ट्रीय समस्याओं और हितों को गौढ़ स्थान देते हैं।²

इन्हे परम्परावादों श्रेणी में रखा जा सकता है। इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच राजनीतिक का तीसरा वर्ग उन लोगों से निर्मित होता है जो आत्म बलिदान और जनहित के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करते हैं इसे संतवादों राजनीति को संज्ञा मारिस जॉस ने दी है।³

स्वतंत्रता से पूर्व विदेशी शासन ने समाज और राजनीति को एक दूसरे से काफी दूर रखा था। स्वतंत्रता के पश्चात् और सार्वभौमिक मताधिकार के दिए जाने के फलस्वरूप समाज और राजनीति एक दूसरे के समीप आए अर्थात् राजनैतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर जनसाधारण को समान रूप से प्राप्त हुआ इसका अर्थ यह नहीं कि परंपरावादों भारत अराजनी था अंतर केवल यह है कि स्वतंत्रता से पूर्व की भारतीय राजनीति का स्वरूप स्वतंत्रता के बाद विकसित होने वाली राजनीति के स्वरूप से बिल्कुल भिन्न था।

1- फिर वहाँ,

2- फिर वहाँ,

3- फिर वहाँ, पृ० 54

राजनोति के इस क्षेत्र में सिद्धान्तों और हितों को लेकर अनेक प्रकार के पारस्परिक विरोध पाए जाते हैं ।¹

राजनोतिक संस्कृति, सामान्य संस्कृति का अटूट अंग होता है । जिस प्रकार किसी देश को सामान्य संस्कृति परिवर्तित होती रहती है उसी प्रकार राजनोतिक संस्कृति में भी परिवर्तन होता रहता है । इसी लिए प्रत्येक देश को राजनोतिक संस्कृति प्रत्येक काल में भिन्न होती है और स्वयं एक ही देश में अनेक उप राजनोतिक संस्कृतियाँ पाई जाती हैं । किसी भी देश को राजनोतिक संस्कृति स्थिर नहीं रहती वह परिवर्तित होती रहती है भले ही परिवर्तन की गति में अंतर हो । इस बात पर सभी विचारक एकमत हैं कि सभी देशों को राजनोतिक संस्कृति में शासक एवं शासित को राजनोतिक संस्कृति में अंतर पाया जाता है ।²

भारत में स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के पुर्नगठन की माँग को गृह विभाग स्वस्थ 1956 में भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुर्नगठन किया गया । राज्यों के पुर्नगठन के बाद भी नए राज्यों के निर्माण की माँग उठती रही और कुछ नए राज्यों का निर्माण किया गया । परिवहन एवं संचार के साधनों के विकसित होने के कारण देश के विभिन्न भागों में विकसित होने के कारण देश के विभिन्न भागों में रहने वाले जातियाँ एक दूसरे के सम्पर्क में आई और वे एकता में बंध गई । इससे जातीय भेदभाव बढ़ा और जातीय निष्ठा को प्रोत्साहन मिला । राजनोतिक दलों ने इस परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया और विभिन्न विधायकों में दल के उम्मीदवारों के चयन से लेकर मतदाताओं के समर्थन को प्राप्त करने तक के लिए धर्म तथा जाति को एक साधन के रूप में प्रयोग किया । स्थानीय तथा प्रादेशिक राजनोति में

1-फिर वही, पृ० 55

2- फिर वही,

सक्रिय रूप से कार्य करने वाले अधिकांश व्यक्तियों के सामने सम्पूर्ण देश के हितों की अपेक्षा अपने प्रदेश जिले तथा ग्राम आदि के हित से अधिक महत्व रखते हैं ।¹

इस प्रकार की राजनीति के कारण भारत में जिस राजनीतिक संस्कृति का विकास हो रहा था, उसका पूर्ण असर 1967 के चुनाव के नतीजे से दिखाई देने लगा ।

भारतीय राजनीति एवं वर्ष 1967 :-

भारतीय राजनीति में 1967 का वर्ष काफी महत्वपूर्ण वर्ष था, क्योंकि इस वर्ष भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् स्थापित एक दलीय राजनीतिक संस्कृति का असर कम होता दिखाई पड़ने लगा । राज्यों में अनेक क्षेत्रीय दल स्थानीय हितों को प्रमुखा देते हुए राजनीतिक मंच पर उभर कर आए । जिसके कारण 5 राज्यों में विपक्षी दलों ने चुनाव के बाद सरकार बना ली तथा इसके पश्चात् तीन राज्यों में कांग्रेस में आपसी फूट के कारण कांग्रेस की सरकारें गिर गई । कांग्रेस दल की इस फूट के संदर्भ में फरवरी 1967 का आम चुनाव हुआ । चुनाव के बाद भी कांग्रेस की फूट जारी रही चुनाव के बाद दल-बदल प्रक्रिया शुरू हुई जिसके कारण तीन राज्यों में कांग्रेस सरकार का पतन हुआ² । इस दल बदल में दो बातों का मुख्य हाथ रहा । चुनाव के पहले टिकट का बटवारा और चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का गठन । ये कोई नए कारण नहीं थे । नई बात सिर्फ यह थी कि 1967 में और बाद में जितनी आसानी से लोग

1- रजनी कोठारी - भारत में राजनीति पृ० 123

2- चुनाव में कांग्रेस की हार, मद्रास, गुजरात, अकेले द्र. मु. क. को जीत हुई । बंगाल, बिहार, उड़ीसा में विरोधी दलों के साथ मोर्चे को जीत हुई इन मोर्चों में कम्युनिस्ट मार्क्सवादियों से लेकर जनसंघ तक थे । चुनाव के बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में दल-बदल के कारण कांग्रेस सरकार का पतन हुआ । - रजनी कोठारी - भारत में राजनीति

कांग्रेस छोड़ देते थे, उतनी पहले कभी नहीं देखी गई थी कांग्रेस में उनको बांध कर रखने की शक्ति बहुत कम हो गई थी । अब तक चुनाव का टिकट या मंत्रिमंडल में स्थान न मिलने पर भी असंतुष्ट गुट कांग्रेस के अंदर हो बने रहते थे अब वे कांग्रेस से अलग होने लगे ।¹ अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ कि लोग अस्थायी तौर पर कांग्रेस से अलग हुए हैं या स्थायी तौर पर, दोनों ही प्रवृत्तियाँ दिख पड़ती हैं । फूट की प्रवृत्ति कांग्रेस में ही नहीं, अन्य दलों में भी है । कुछ राज्यों में कांग्रेस से असंतुष्ट गुट ने प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेस बना लिया है । 1964 में केरल कांग्रेस को स्थापना हुई, 1966 में बंगाल में बंगला कांग्रेस बनी । 1967 में चुनाव से पूर्व उत्तर के कई राज्यों में जन कांग्रेस बनी । बिहार और उत्तर प्रदेश में असंतुष्ट कांग्रेसियों ने भारतीय क्रांति दल बनाया और बिहार में असंतुष्ट कांग्रेस जनों के एक दल ने विनोदानंद झा के नेतृत्व में जनक्रांतिक कांग्रेस बनाई ।²

इन कांग्रेसी दलों के निम्नलिखित के बावजूद भी संस्कृति कांग्रेस को हो बनी रहो है क्योंकि इनके प्रमुख नेता पूर्व कांग्रेसी हो थे । गैर कांग्रेसी संयुक्त सरकारों के गिरने के बाद अनेक भूतपूर्व कांग्रेसी कांग्रेस में या कांग्रेस से संबंधित दलों में लौट आए । पश्चिम बंगाल बिहार में ऐसा हो हुआ । मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस छोड़ने वालों का पूरा गुट कांग्रेस में लौट आया और कांग्रेस को सरकार बनाने में उसने सहायता दी । कांग्रेस छोड़ने वाले जो लोग मुख्यमंत्री बने उनमें से अनेक का केन्द्र सरकार और कांग्रेस से बहुत अच्छा स-बन्ध रहा । दूसरी ओर कांग्रेस हाईकमान विद्रोहियों को वापस लेने को बहुत इच्छुक न थी,

1- कांग्रेस दल में चुनाव टिकट बटने में जो खींच तान होता है, वह कभी-कभी चुनाव से भी ज्यादा महत्व को होता है । इसमें चुनाव से भी ज्यादा जनसाधारण में प्रसार का मौका मिलता है । - रामाश्वराय सेलेक्शन ऑफ कांग्रेस कैडेट्स - इकनामिक एंड पार्लिकल वोकलो फरवरी 11 एवं 18, 1967 ।

2- राजनी कोठरी - भारत में राजनीति पृ० 127

क्योंकि उसमें नया गठजोड़ उलटने का डर था, जहाँ झगड़ा ज्यादा था वहाँ विद्रोहियों को वापस लाने के प्रयत्न विफल हुए ।¹

इसी प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी भी दो दो और कहीं तीन तीन है । समाजवादो पार्टी भी टूटकर संतोषा और प्रसोषा में बंट गई । और संतोषा में भी कई गुट हो गए हैं जो एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं । जनसंघ में उग्र एवं नरम दो गुट हो गए । स्वतंत्र पार्टी में लगातार झगड़े होते रहे और अनेक लोग दल भी छोड़ गए । पिछड़े वर्गों, हरिजनो और आदिवासियों में अनेक धड़ थे । इसके अलावा 1967 के बाद गैर कांग्रेसी दलों में भी गठजोड़ होते रहे । अनेक बार ये गठजोड़ बिल्कुल विरोधी और विपरीत दलों में भी हुए हैं । ये गठजोड़ भानुमती के कुन्बे जैसे हैं । पलस्वरूप ये गैर-कांग्रेसी संयुक्त सरकारें ज्यादा दिन न चली । दिसम्बर 1967 से फरवरी 1968 के बीच हरियाणा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार इन पांच राज्यों में संयुक्त सरकारें गिर गईं । बिहार में दो बार ऐसा हुआ । संयुक्त सरकार के टूटने पर बिहार एवं बंगाल में कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोरचे के अत्यसंख्यक दलों ने सरकार बनाई, किन्तु वह चल न सकी । पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस खुद मिली जुली सरकार में शामिल हुई मगर टिक न सकी । मध्य प्रदेश में मार्च 1966 में संयुक्त दल को सरकार में कांग्रेस विद्रोहियों का गेट निकलकर फिर कांग्रेस में आया, और संयुक्त सरकार गिर गई ।

स्वतंत्रता के बाद शक्ति ग्रहण करने के लिए कांग्रेस सभी तरह के लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती रही । सन् 1967 से 1969 के बीच गैर कांग्रेसी दलों को भी यही नीति थी । हिन्दु समाज को भौतिक कांग्रेस भी भिन्न और विरोधी विचार और रीति रिवाज वाले समूहों को

1- फिर वहाँ,

2- राजनी कोठारो -भारत में राजनीति - पेज 128

एक साथ लाने को कोशिश करती थी और विचारों की एकस्यता के बजाए विचार वैभिन्य को सहन करती थी । कांग्रेस शुरू से समूचे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने को कोशिश करती आई है और भारतीय राष्ट्र के अधिकांश तत्व उसमें भी पाए जाते थे । विरोधी दलों ने देखा कि संयुक्त मोर्चा बना करके वे कांग्रेस को हरा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस को कभी भी देश के 45 प्रतिशत से अधिक वोट नहीं मिले ।¹ इस नीति के मुख्य प्रतिपादक थे डॉ० राम मनोहर लोहिया । लोहिया जन्म जात विद्रोही थे और उनका व्यक्तित्व चमत्कारी था । उन्होंने शीघ्र ही समझ लिया कि थोड़े विद्रोह से कुछ होना जाना नहीं, इसलिए उन्होंने सत्ता पर एकाधिकार समाप्त करने के लिए विरोधी दलों को एक साथ लाने को कोशिश की । कांग्रेस के विरोधी किसी तत्व से हाथ मिलाने को तैयार रहते थे । कांग्रेस को उखाड़ने के उनके तात्कालिक लक्ष्य से उन्हें सफलता मिली किन्तु इसका कोई स्थायी नतीजा नहीं मिला ।²

यह देखने के लिए कि 1967 के चुनाव में पार्टियों की स्थितियों में कितना परिवर्तन आया, हमें उसी पार्टी की बात से आरम्भ करना होगा, जिसकी स्थिति में सबसे कम परिवर्तन हुआ । 1967 के चुनाव के कुछ नए विशेष लक्षण थे जिसका अल्पकालिक असर जरूर पड़ा । ऐसे तत्वों में कांग्रेस ही सबसे प्रमुख पार्टी है, जहाँ तक इस बात का सवाल है कि कुल वोटों में उसे कितने प्रतिशत वोट मिले । कांग्रेस को लोकसभा के चुनावों में 1952 और 1962 में 45 प्रतिशत वोट मिले थे, जब कि इस चुनाव में § 1967 में § उसे सिर्फ 4 प्रतिशत कम अर्थात् 40.7 प्रतिशत वोट मिले । इस पार्टी को राज्य विधान मंडलों के चुनाव में जहाँ 1952, 1957, 1962 में क्रमशः 42.2, 44.9 और 43.6 प्रतिशत वोट मिले थे, 1967 में सिर्फ 40.0 प्रतिशत वोट मिले । यद्यपि यह परिवर्तन कोई चौंका देने वाला परिवर्तन नहीं था, किन्तु कांग्रेस के लिए

1- राजनी कोठारों- भारत में राजनीति - पृ० 128

2- फिर वही, पृ० 129

चुनौती देने वाली जो प्रमुख पार्टियां थीं उनको स्थितियों में बड़े परिवर्तन हुए ।¹ 1967 तक कम्युनिस्ट दो हिस्सों- सो.पो. आई और सो.पो. आई एम॥ में बँट गए थे । ये दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल पृथक थे और उनके बीच लगातार बैर बढ़ रहा था । हालाँकि भारत चीन युद्ध के मसले को लेकर कम्युनिस्टों का दृष्टिकोण दो हिस्सों में बँट गया था, परन्तु विभाजन के बाद सो.पो. आई को मास्को समर्थक और सो.पो. आई. एम को पeking समर्थक कहा जाने लगा था । लेकिन सारी बात को जड़ यह नहीं थी । उनके बीच मतभेद का जो भारत में कम्युनिस्ट सिद्धान्तों को लागू करने के संबंध में उनके अंदरूनी परस्पर विरोधी विचारों के कारण पैदा हुए थे - मुख्य आधार कमिंस और भारतीय राष्ट्रवाद के संबंध में उनके अलग-अलग दृष्टिकोण थे ।² सो. पो. आई प्रगतिशील कमिसियो के साथ सहयोग की बात सोच सकती थी लेकिन सो.पो. आई. एम. सो. पो. आई. को नजर में कमिंस के लोग जनता के शत्रु वर्ग शत्रु थे । सो.पो.आई एम के विभाजन के बाद जो पार्टियाँ बनीं थी वे करोड़-करोड़ समान शक्तिशाली थीं उनके बीच यही एक महत्वपूर्ण अंतर था कि सो.पो. आई को शक्ति देना के सभी हिस्सों में बिखरी थी जबकि सो.पो. आई एम॥ पश्चिम बंगाल और केरल के प्रमुख कम्युनिस्ट क्षेत्रों में खासतौर से असरदार थी । जहाँ तक 1967 के चुनाव का संबंध है, दोनों पार्टियों के बीच जमकर संघर्ष हुआ - शायद इसलिए कि दोनों पार्टियों के बीच कम्युनिस्ट वोटों के लिए होड़ थी और इसी बात से कुछ हद तक इस प्रश्न का जवाब मिल जाता है कि कुल वोटों में कम्युनिस्टों को मिले वोट सो.पो.आई के बीच समान रूप से विभाजित। 1962 में इस पार्टी को मिले वोटों से कम थे । सोशलिस्ट पार्टियों पो.एस.पो. और एस.एस. पो को मिलाकर कोई विशेष सफलता नहीं मिली ।³

1- गोपाल कृष्ण, वन पार्टी डामिनेंस- डेबलपमेंट्स, पार्टी सिस्टम एंड एलेक्शन स्टडीज- अकेजनाल पेपर्स । सेंटर फार स्टडी आफ डेवलपिंग सोसाइटी सो नई दिल्ली 1967

2- पार्टी सिस्टम - कोठारी रजनी पेज - 210

3-फिरवही, पेज-211

कम्युनिस्टों को भीति सोशलिस्टों को भी लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों में 1962 में प्राप्त वोटों से भी कम मिले । ऐसी भी बात नहीं कि कांग्रेस की स्थिति खराब होने का फायदा अगर वामपंथी पार्टियों को नहीं मिला, तो दक्षिणपंथी पार्टियों को मिला हो । स्वतंत्र पार्टी भी, जो 1962 में प्रमुख दक्षिण पंथी पार्टी थी, 1967 में थोड़े ही अधिक वोट पाने में सफल हो गयी । और यह स्थिति तब थी, जब उड़ीसा की सफल गणतंत्र परिषद की स्वतंत्र पार्टी ने अपने में शामिल कर लिया था ।¹

इस प्रकार 1967 के चुनावों में परिवर्तन परिलक्षित करने वाले या परिवर्तन पैदा करने वाली बात क्या थी ? इस चुनाव में हर पार्टी को मिले वोटों का प्रतिपादित बताने वाली कालमी से सम्बन्धित कुछ बातें नोट करने लायक हैं । एक बात यह है कि सारे देश में सिर्फ एक ही पार्टी थी, जिसने शुरू के तीन चुनावों में लगातार प्रगति करने के बाद 1967 के चुनाव में भारी तरहकी को थी । वह पार्टी थी जनसंघ । काफ़ी कोशिशों के बाद उत्तर भारत के हिन्दो भाषी क्षेत्र के बाहर वह काफ़ी असरदार नहीं बन पायी थी, लेकिन पाँच सम्बन्धित राज्यों में इसने पुराने समर्थन को दृढ़ बनाकर और कुछ नए वर्गों को वोट प्राप्त करके अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत बना ली ।² इसके अलावा इस पार्टी में चुनाव में उत्पटांग एवं बड़ो मात्रा में धन खर्च करके यह सफलता नहीं प्राप्त की थी, बल्कि उम्मीदवारों की संख्या में सामान्य और सावधानोपूर्वक सुनियोजित ढंग से वृद्धि करके प्राप्त की थी, दूसरी बात यह है कि यद्यपि सोशलिस्टों को कुल मिलाकर पहले से अधिक वोट नहीं मिले थे, किन्तु एस. एस. पी. की निश्चित ही पहले से अधिक वोट मिले थे ।³ एस. एस. पी. वामपंथियों में एक प्रमुख गैर कम्युनिस्ट

- 1- पार्टी पालिटिक्स इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ़ ए मल्टी पार्टी सिस्टम पृष्ठ 107
- 2- फिर वही,
- 3- फिर वही,

पार्टी बन गई और खासतौर से उन्ही हिन्दो भाषी क्षेत्रों में अत्यधिक गरीब लोग बड़ी मेहनत के साथ अपनाने और अपनी उग्र क्रांतिकारी वाणी के बल पर इसने भी कम्युनिस्टों को तुलना में जनसंघ के साथ अपनी स्थिति सुधार ली। लेकिन इसके साथ इस चुनाव नतीजों से कुछ और महत्वपूर्ण बातें सामने आईं, पहली बात यह कि एक राज्य में सीमित कुछ विशेष पार्टियों को सफलता मिली, जैसा कि पहले बताया जा चुका है उड़ीसा में स्वतंत्र पार्टी वस्तुतः नए रूप में उस राज्य की गणतंत्र परिषद पार्टी थी। इसके अलावा नये व पहले की अपेक्षा छोटे पंजाब राज्य में अकाली दल को पुनः प्रमुख स्थान प्राप्त हो गया, कुल हिस्सों में इस पार्टी का हिस्सा दो गुना हो गया, और इन सबसे बड़ी बात यह थी कि तमिलनाडु में डॉ. एम. के. को अचानक भारी सफलता मिली। कुल वोटों में 40% वोट मिले। दूसरी बात अन्य पार्टियों और निर्दलीय दोनों से सम्बन्धित आंकड़ों से साफ नजर नहीं आती और वह है कांग्रेस से दल-बदल¹। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले कुछ लोगों ने वर्तमान पार्टी को होड़ में लगभग औपचारिक संगठन बना लिए। अलग होने वालों ने जो संगठन बनाए थे अब एक-एक राज्य में हो "मजबूत थे और राज्य स्तर की अंदरूनी फूट के कारण हो इनका जन्म हुआ था। इसलिए इन संगठनों ने पार्टियों के क्षेत्रीकरण की प्रवृत्ति को मुखारिप किया और मजबूत बनाया—अकाली दल और डॉ. एम. के. पहले से ही क्षेत्रीय पार्टियों के उजागर रूप में विद्यमान थे। इसका प्रमाण इस बात से भी मिल जाता है कि 1969 में इन पार्टियों से इन पार्टियों को एक अखिल भारतीय संगठन के भीतर लाने की कोशिश में मुश्किलें आईं। विद्रोह करके दल छोड़ने वालों के संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण संगठन ये थे—केरल कांग्रेस & 1964 में बन गई थी & इसमें अधिकांशतः ईसाई समुदाय के वे लोग थे जो कांग्रेस से पृथक हो गए थे।

जम्मू काश्मीर में नेशनल काँग्रेस, ४ जब इस संगठन के अधिकांशतः लोग कांग्रेस में शामिल हो गए तो बखशी ने अपने समर्थकों को बनाने के लिए यह पुराना सम्मानित नाम हड़प लिया, बंगला कांग्रेस इस संगठन का जन्म कांग्रेस नेता अतुल्य घोष के प्राधान्य के खिलाफ पार्टियों में पड़ो क्षेत्रीय आंशिक फूट के कारण ४ और उत्तर प्रदेश में भारतीय क्रांति दल । इसके अलावा काफी संख्या में छोटे-छोटे समूहों और अलग-अलग व्यक्तियों ने पार्टियों बदल ली । इसी वजह से निर्दलीय लोगों की संख्या पुनः बहुत बढ़ गई, जबकि कुछ पहले उनकी संख्या कम होती जा रही थी । 1967 में बहुत से और शायद अधिकांश निर्दलीय ऐसे व्यक्ति थे, जो कांग्रेस काटिकट पाने में सफल नहीं हो पाए थे ।¹

इस फूट और दल-बदल के महत्त्व को देखते हुए यह कहना उचित हो है कि 1967 में कांग्रेस को जो धक्का पहुँचा, उसके लिए कांग्रेसी ही जिम्मेदार थे । लेकिन इस चुनाव को दूसरी विशेषता का पता तब चलता है जब सिर्फ इस बात को ही ध्यान में न रखा जाए कि हर पार्टी को कुल वोटों में से कितने-कितने वोट मिले- बल्कि इसके साथ यह भी देखा जाय कि हर पार्टी को जो वोट मिले, उनके बल पर उन्हें कितनी-कितनी सीटें मिली ।²

इस तरह से विचार करने पर पता लग जाएगा कि कांग्रेस को छोड़कर लगभग हर पार्टी या समूह को कितने-कितने वोट मिले थे उनको देखते हुए उनकी मिलोसीटों का अनुमात अधिक था ।

कांग्रेस का अनुभव इसके बिल्कुल विपरीत रहा, क्योंकि उसे 40 प्रतिशत वोटों के बल पर 60-70 प्रतिशत सीटें नहीं मिलती थीं। अतः वह केवल 50 प्रतिशत ४ बल्कि लोकसभा में कुछ ज्यादा और राज्य विधान सभाओं में कुछ कम ४ पर संतोष करने को आदी हो गई थी। इसके पीछे बात तो सीधी-सादी थी किन्तु उसके लिए बड़ी कोशिश की गई थी । 1967 के चुनाव में हालाँकि

1- फिर वही, पृ० 109

2- फिर वही, पृ० 112

उम्मीदवारों की संख्या कुल संख्या और प्रति सीट संख्या दोनों पहले से भी ज्यादा थी, लेकिन कई राज्यों में विरोधी पार्टियों के नेता चुनाव से पहले ही इस बात की कोशिश कर रहे थे कि वे सब मिलकर कांग्रेस के सामने जबरदस्त चुनौती खड़ी करें और उनको कोशिश सफल हुई। विरोधी पार्टियों के बीच जमकर सौदेबाजी हुई, क्योंकि उनके बीच यह बात तय नहीं हो पाई कि कौन-कौन सी पार्टियाँ कौन-कौन से चुनाव क्षेत्र, दूसरी पार्टियों के लिए छोड़ दें। फिर भी अन्त में केरल में एक मजबूत संयुक्त मोर्चा बन गया। बंगाल में कुछ हद तक परस्पर विरोधी दो मोर्चे सी.पो. आई. और सी.पो.आई. एम. के साथ आ गए। और आधा दर्जन अन्य राज्यों में तरह-तरह के चुनाव समझौते हो गए। सीधी टक्कर की इस स्थिति में कांग्रेस को मोटे तौर से कुछ वोटों में उतने ही वोट मिले जितने पहले मिले थे - सच तो यह है कि लगता है कि वोटों की दृष्टि से कांग्रेस को अपेक्षाकृत ज्यादा वोट मिले।¹ यदि किसी सीट के लिए उम्मीदवार कम हो- लेकिन उसे पहले जितनी सीटें नहीं मिल पाई इसका मतलब साफ है कि विरोधी पार्टियों ने जो चुनाव समझौते किए थे, वे सफल रहे और विरोधी पार्टियों के वोट उन्हीं के ही उम्मीदवारों की ही मिले, अर्थात् उदाहरण के लिए, यदि किसी चुनाव क्षेत्र में जनसंघ के पक्ष में स्वतंत्र पार्टी का उम्मीदवार बैठा गया तो स्वतंत्र पार्टी को वोट देने वालों ने सुनियोजित ढंग से जनसंघ के उम्मीदवारों को अपने वोट दिए। इसमें वोट देने वालों तथा विचारिलों ने जो अनुशासन दिखाया वह आशा से अधिक था।²

इस बात के कारण जान लेने के बाद कि कांग्रेस को इस चुनाव में क्यों कम सीटें मिलीं? अब सवाल उठता है जब विरोधी पार्टियों ने कांग्रेस को हराने की कोशिश की थी तो उन्हें सफलता नहीं मिली थी तो इस बार उन्हें इस काम में सफलता क्यों मिली? इसका कारण कुछ हद तक तो

1- फिर वही,

2- फिर वही,

निःसंदेह यह था कि 20 साल तक सरकार न बना सकने के कारण विरोधी पार्टियों में जो निराशा पैदा हो गई थी, इसके वजह से उनके बीच ऐद्वान्तिक वैमनस्य और व्यक्तिगत अविश्वास दब गया था और शायद यह बात भी थी कि विरोधी दल के नेताओं को आभास था कि जनता में पहले को अपेक्षा अधिक असंतोष एवं निराशा है जिसका फायदा उठाया जा सकता था ।¹ लेकिन कांग्रेस से बाहर की पार्टियों के बीच एकता पैदा करने में शायद अन्य कोई तत्व उतना सहायक नही था जितना यह तथ्य कि कांग्रेस स्वयं टूट रही थी और यह पहला मौका था जब कांग्रेस में कोई ऐसा महान नेता नही था जो पार्टी को संगठित कर पाता तथा अपने व्यक्तित्व से जनता को भी प्रभावित कर सकता । इस प्रकार कांग्रेस को धक्का लगने के दो कारण थे - आन्तरिक मतभेद एवं विरोधी दलों के समझौते ।²

इस प्रकार 1967 का वर्ष उत्तरोत्तर भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए मोल के पत्थर के समान है । क्योंकि 1967 के अध्ययन से यह पता चलता है कि किस प्रकार 1967 से तथाकथित कांग्रेस व्यवस्था ब्य टूटी । क्षेत्रीयता एवं जातिवादो तत्वों का भारतीय राजनीति कैसे उदय हुआ ! राजनीतिक संसदीय व्यवस्थाओं में पतन, दल-बदल, क्यों हुआ 9 जिनका बाद को भारतीय राजनीति पर असर दिखाई देने लगा, एवं इनका असर दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है, तथा इन प्रवृत्तियों के कारण एक नई राजनीतिक संस्कृति का उदय होता जा रहा है ।

1- फिर वही,

2- फिर वही,

अध्याय - 2

भारत में 1967 से 1989 के बीच राजनीतिक दलों की स्थिति एवं दलीय राजनीति ।

अध्याय - 2

भारत में 1967 से 1989 के बीच राजनीतिक दलों की स्थिति एवं दलीय राजनीति

दल व्यवस्था विस्तृत राजनीतिक व्यवस्था का ही एक भाग है। यह इसकी उप व्यवस्था है तथा इसकी कार्य प्रणाली एक संचालक शक्ति है। प्रत्येक देश में दल व्यवस्था केवल उसकी राजनीतिक परिस्थिति का परिणाम ही नहीं है, बल्कि उसके इतिहास, संस्कृति भूगोल और अर्थ व्यवस्था का ही प्रतिफल होता है।

राजनीतिक व्यवस्था के उदय तथा ऐतिहासिक विकास ने दलीय व्यवस्था के रूप को निश्चित किया है दलों की विचारधारा, उद्देश्य नीति तथा संगठन इस बात पर निर्भर रहे हैं कि कोई दल कब और कैसे अस्तित्व में आया तथा स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में दलीय पद्धति का किस प्रकार विकास हुआ है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ब्रिटिश संसदीय पद्धति के अनुरूप लोकतंत्रीय पद्धति को अपनाने की उत्सुकता ने भारत को राज्य तंत्र चलाने के लिए दलीय पद्धति का शीघ्र गठन करने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए सरल और तीव्र विधि यही थी कि राष्ट्रीय आन्दोलन को अग्रदूत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नए शासक दल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय।

भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का दल के रूप में तुरन्त परिवर्तन इससे पूर्व हुए आन्दोलनों में एक मात्र उदाहरण था जिसने अपने-आपको आधुनिक राजनीतिक उपकरण में परिवर्तन कर लिया। इससे भारत में लोकतंत्र के अविष्य, दलीय पद्धति के विकास तथा कांग्रेस दल के संगठन पर काफी प्रभाव पड़ा। इस प्रकार के राष्ट्रीय आन्दोलन परिवर्तन से नई कांग्रेस

§ जिसे अब राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाता है§ संसार में सबसे प्राचीन तथा बड़े दलों में से एक दल बन गई तथा गैर साम्यवादो दलों में सबसे बड़ा दल बन गई । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा आन्दोलन था जिसका साठ से अधिक वर्षों से धीरे-धीरे विकास हुआ था तथा विचार धारा एवं अन्य विचारों को विभिन्नताके बावजूद उसने अनेक व्यक्तियों का मिला जुला संगठन बनाया जिसका सबसे मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्रता की प्राप्ति । स्वतंत्रता के बाद मतैक्य का दावरा सिकुड़ना था और मतभेद उभरकर सामने आने थे । बहुत से गुटों ने विचारधारा, नीति तथा निजो संबंधों के बारे में मतभेदों को स्पष्ट करना शुरू कर दिया ।¹

भारतीय गणराज्य एक मुक्त समाज है। जो निरपेक्ष राजनीति को प्रोत्साहन देने वाला, जनसंचार माध्यमों का सम्मान करने वाला, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण और कानून के शासन के सिद्धान्तों का पालन करने वाला है।²

समकालीन भारतीय राजनीति का प्रमुख जोर और संघर्ष नीति, वास्तव में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की राजनीति, आधुनिकीकरण की राजनीति राष्ट्रीय एकता और विकास की राजनीति पर है । इस संदर्भ में भारत की दल व्यवस्था सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन की एक राजनीतिक युक्ति की भूमिका अदा करती है। यह जनता को केवल विधायिका में सीट जोतने और चुनावों राजनीति के लिए प्रेरित नहीं करती है । बल्कि इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य जैसे राष्ट्र निर्माण नागरिकों के जीवन स्तर को उभार उठाने और लोकतांत्रिक पहचान बनाने के लिए उत्साहो जनता और उसकी चेतना को उद्बलित करती है।

1- पार्टी सिस्टम - राजनीति कोठारी पृ० 7

2- फिर वही,

भारतीय दल व्यवस्था के तीन महत्वपूर्ण नियम रहे हैं ।

- 1- राष्ट्रहित के तीन पक्षों पर आम सहमति स्थापित करना राष्ट्रीय आन्दोलन को एक महत्वपूर्ण परम्परा के तीन महत्वपूर्ण पक्ष थे, राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक समन्वय, राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक विकास तथा राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अखंडता । स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले राष्ट्रीय आन्दोलन को गाड़ों के रूप में कांग्रेस को श्रेष्ठता ठीक प्रकार से जनमानस में व्याप्त थी । अतः कांग्रेस ने राष्ट्रीय आम सहमति के विकास के साथ अपने दल को सुरक्षित और लोकप्रिय बनाए रखा । इसको इस चार्चित्रिक विशेषता ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय दल व्यवस्था के रूप में इसे उभरने में बहुत अधिक मदद प्रदान की ।
- 2- राष्ट्रीय आन्दोलन को दूसरी परम्परा का आधार वैचारिक था, जिसमें क्रान्तिकारों वामपंथी लेकर रुढ़िवादों, पुनरुत्थानवादों और परंपरावादों दक्षिणपंथी शामिल थे । स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय आन्दोलन में वामपंथी, मध्यमार्गी और दक्षिणपंथी तीनों के सहअस्तित्व से इसे केवल व्यापक समर्थन का आधार और अखिल भारतीय वैधता हो नहीं मिली बल्कि इससे विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच सामंजस्य और उदारता की एक परम्परा को स्थापना भी हुई जो कि बहुत जरूरी था । यही कारण है जिससे कि भारतीय राज्य व्यवस्था कभी वैचारिक दृष्टि से ध्रुवित नहीं हुई । वास्तव में संगठित भारत आधुनिक राज्य व्यवस्था का एक उत्कृष्ट और क्लासिक उदाहरण है भारतीय राजनीतिक संस्कृति का यह पक्ष जिसको जड़ राष्ट्रीय आन्दोलन में है भारत के बहुदलीय व्यवस्था की स्थिति के विकास का एक ढांचा प्रदान करता है ।²

1- राजनी कोठारों- भारत में राजनीति पृ० 187

2- फिर वही, पृ० 187

3- देश के महाद्वीपीय विस्तार क्षेत्र में सुपरिभाषित और भिन्न सामाजिक सांस्कृतिक प्रदेश जिनको अपने निजो भाषा और बोलियाँ हैं, जाति एवं उपजाति के विशिष्ट मानदंड सामुदायिक और जनजातीय संगठन शामिल हैं। इस प्रकार को विभिन्नताओं ने समूहों और दलों के उदय होने के लिए परिस्थितियाँ एवं लक्ष्य प्रदान किये। भारत के क्षेत्र प्रादेशिक इकाई हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता की शर्तों और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को कार्य प्रणाली के अन्तर्गत क्षेत्र समुचित वैधानिक मांग रखने और आत्म विकास के लिए अपने स्वायत्त अधिकार के लिए आबद्ध थे। यह संक्षेप व्यवस्था का तार्किक सिद्धान्त है। इसलिए योजना के दो दशकों ने सम्यक विकास के आरंभिक काल के बाद दृढ़ता पूर्वक क्षेत्रीयता § प्रादेशिकता § को बढ़ती मांग स्वाभाविक रूप से आवश्यक थी। इसके परिणामस्वरूप अन्य चीजों के बीच क्षेत्रीय दलों की लोकप्रियता प्रकाश में आई।¹

इन तीन पक्षों के अनुवर्ती क्रम में भारतीय दल व्यवस्था दो प्रमुख विशेषताएँ प्रदर्शित करती है।

- 1- केन्द्र में बहुदलीय व्यवस्था के ढाँचे के अन्तर्गत एक प्रभावो दल।
- 2- कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दलों के संयोजन से राज्यों में संचालित एक बहुदलीय व्यवस्था। कुछ दूसरे राज्यों में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के संविद सरकार तथा अन्य राज्यों में अखिल भारतीय दलों की शाखाओं द्वारा संचालित दलीय व्यवस्था।²

भारतीय दलीय व्यवस्था अद्वितीय रही है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के चारों ओर घूमती रही है। इसलिए इसे प्रभावो एक दलीय व्यवस्था कहा जाता रहा है। यद्यपि भारत में अनेक दल भी रहे हैं किन्तु

1- फिर वही,

2- फिर वही, 188

भारतीय दल कांग्रेस निवचिक समर्थन में अनेक उतार-चढ़ाव के बावजूद बहुदलीय व्यवस्था के होते हुए भी एक प्रभावो एकल दल के रूप में रहो है ।¹

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पिछले चार दशकों में भारतीय दलीय व्यवस्था को कार्य प्रणाली में विकास के सात चरण स्पष्ट दिखाई देते हैं ।²

- 1- 1952-64 राष्ट्रीय आम सहमति का काल ।
- 2- 1964-69 बहुदलीय स्थिति के उदय से विकट संक्रमण का युग ।
- 3- 1969-75 अंतरदलीय संघर्ष में वृद्धि और नई आम सहमति का युग ।
- 4- 1975-77 आपातकालीन सत्ता युग ।
- 5- 1977-80 संविद राजनौतिक व्यवस्था, जनता पार्टी का युग ।
- 6- 1980-89 केन्द्र में कांग्रेस और विपक्ष तथा राज्यों में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच विकट संघर्ष का युग ।
- 7- 1989 से बहुदलीय स्थिति में बहुदलीय व्यवस्था का संक्रमण काल ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रथम दो दशकों §1947-67§ में संघीय स्तर तथा राज्यों को राजनौति में लगातार कांग्रेस दल प्रभावो रहा । लेकिन बढ़ते विकास तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न अंतर्विरोधों के ढेर तले दबे भारत को तो सामाजिक विभेदोकरण के प्रक्रिया में गुजरना हो था । आर्थिक विकास को सोमाओं तथा पुरस्कृत §भ्रष्ट§ लाभों से संकुचित आकार से भिन्न-भिन्न वर्गों तथा शासक वर्ग के अनेक भागों में परस्पर संघर्ष उभर कर सामने आ गए । भिन्न-भिन्न आर्थिक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले नए राजनौतिक दल 1950 और 1960 के मध्य में सामने आए । इसके साथ-साथ अनेक पुराने छोटे दलों ने विस्तारशोल तथा अधिक चेतन सामाजिक आधार द्वारा अपनी शक्ति में बढ़ोत्तरी कर ली । स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल जैसे राजनौतिक दलों ने जन्म लिया । जबकि सो.पो. आई, सोशालिस्ट पार्टी, जनसंघ, तथा

1- फिर वही, 189

2- खान रशीउद्दीन - भारत में लोकतंत्र पृष्ठ 96

डॉ. एम. के ने विस्तारशील आर्थिक आधार का लाभ उठाया । कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती दी गई तथा भारत के कुछ भागों में उसे तोड़ दिया गया । चौथे आम चुनावों में आठ राज्यों में कांग्रेस का शासन खत्म हो गया तथा केन्द्रीय संसद में भी इसे कम स्थान मिले ।¹

इससे यह बात स्पष्ट हुई कि कांग्रेस हमेशा प्रभुत्वशाली वर्ग नहीं रहा, और इसे अल्पमत वोट हो मिलते रहे हैं, इस बात ने लोगों में संकुचित आधार को सिद्ध कर दिया ।

इस प्रकार 1967 से केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर एक बहुदलीय स्थिति पैदा हो गई थी । सन् 1989 तक संघीय स्तर पर प्रभावों कांग्रेस दल के निरन्तर शासन के कारण औपचारिक बहुदलीय व्यवस्था का निर्माण नहीं हो पा रहा था ।²

§ 1977-79 में टाई वर्ष और इसके बाद 1989 को छोड़कर § ।

भौगोलिक विस्तार को दृष्टि से भारत में चार प्रकार के दल प्रभावों हैं । अखिल भारतीय दल, पराक्षेत्रीय दल और स्थानीय दल । विचारात्मक दृष्टिकोण से वाम, दक्षिण, मध्यमार्गी और नेता समर्थक दल होते हैं । वाम दल में कम्युनिस्ट दल और समाजवादो समूह आते हैं और दक्षिण दल में धार्मिक समुदायों और जाति के आधार पर बने पारंपरिक और पुरातनवादो दल शामिल हैं ।³

सन् 1957 के दूसरे लोकसभा के आम चुनाव से निर्वाचन आयोग ने अनेक दलों को निर्धारित मानदंड के आधार पर अखिल भारतीय दल के रूप में मान्यता दी है । किसी दल को अखिल भारतीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निर्धारित शर्त यह है कि उसने § दल § विगत आम चुनाव में कम से

1- फिर वही,

2- फिर वही, पृष्ठ ३७

3- फिर वही,

कम चार राज्यों में कुल मतदाता संस्था का 4 प्रतिशत वैध मत प्राप्त किया हो।¹ इस शर्त के आधार पर वर्ष 1957 से 89 तक अखिल भारतीय दलों की संस्था 4 से 8 के बीच रहो है। केवल सन् 1952 के प्रथम आम चुनाव के दौरान अखिल भारतीय दल का दावा करने वाले कुल दल 14 थे।

वर्षों से लोक सभा में दलों के संघटन से प्रकट होता है कि संसद में एक तरफ बहुदलीय स्थिति है तो दूसरी तरफ कांग्रेस दल की प्रभावो स्थिति। वर्ष 1952 से 1989 को चुनाव प्रवृत्ति से स्पष्ट है कि वर्ष 1977 और 1989 को छोड़कर हमेशा ही कांग्रेस दल सभी विपक्षी दलों की तुलना में अधिक सीट और अधिक मत प्राप्त करता रहा है।

भारत में अखिल भारतीय दल एवं उनकी भूमिका : § 1967 से 1989 के बीच §

1- कांग्रेस दल -

पिछले सौ वर्षों से कांग्रेस भारतीय जनता का एक प्रमुख तथा महान राजनैतिक संगठन रहा है। इसके विशाल आकार, प्रसिद्धि तथा प्रभाविता का निधारण इसको उपलब्धि एवं कमजोरियाँ, इसकी मजबूती एवं ढोलापन, इसके साहसपूर्ण कदम तथा त्रासदो इत्यादि सभी ने मिलकर, इसे निर्धारित किया है। 1885 में स्थापित कांग्रेस ने 1920 के बाद से लगभग तीस वर्ष तक राष्ट्रीय आन्दोलन का सक्रिय रूप से संचालन किया है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता का श्रेय कांग्रेस को मिला है।²

स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में इसने लोकतंत्रोप मूल्यों की श्रेष्ठता, नैतिकता तथा व्यवहारिकता प्रदान की है, तदुपरांत भारत के जन जीवन को उत्तम बनाए रखने की आस्था बनाए रखी है तथा अब भी अधिकतर लोगों की

1- फिर वहो,

2- कृष्ण गोपाल, वन पार्टी डामिनेंस-डेबलपमेंट्स, पार्टी सिस्टम एंड एलेक्शन स्टडीज - अकेजनाल पेपर - सेंटर फार स्टडी आफ डबलपिंग सोसाइटी
§ नई दिल्ली 1967 § ।

यह धारणा है कि कांग्रेस एक प्रगतिशील तथा समाजवादी प्रकार का विशालकाय राजनैतिक दल है ।¹

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश भी राजनैतिक परिस्थितियों में पूर्ण परिवर्तन हुआ । इस समय कांग्रेस जनो के समक्ष एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न था कि क्या कांग्रेस को भंग कर दिया जाए ? महात्मा गाँधी का विचार था कि "कांग्रेस को भंग करके इसे एक सर्वसिद्ध संघ का रूप दे दिया जाए । नवंबर 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को सभा में बोलाते हुए उन्होंने कहा था " मुझे पूरा विश्वास है कि कोई अधूरा उपचार कांग्रेस को नहीं बचा सकता । इससे तो वेदना और बढ़ेगी । इससे पूर्व कि कांग्रेस में बुराई शुरू हो, इससे पहले इसे भंग कर देना चाहिए । " 1964 तक नेहरू कांग्रेस का नेतृत्व करते रहे इसके पश्चात् अपनी असामायिक मृत्यु तक डेढ़ वर्षों के अत्य काल तक शास्त्री ने इसका नेतृत्व किया ।²

सन् 1965 से अक्टूबर 1964 तक श्रीमती इंदिरा गाँधी कांग्रेस दल की नेता रही । अनेक राजनैतिक घटनाओं तथा दल विभाजनों के बावजूद उनका दल पर पूरा आधिपत्य बना रहा । 1967 के चुनावों में कांग्रेस को जो धक्का लगा, उसके कारण 1969 में उनके नेतृत्व को एक गंभीर चुनौती मिली, जो उनके सहयोगियों द्वारा थी, लेकिन उसमें उनको विजय हुई ।³

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही कांग्रेस देश की एक सबसे बड़ी व्यापक राजनैतिक शक्ति रही, कांग्रेस एक अखिल भारतीय दल और एक क्षेत्रीय सहित स्थानीय दल दोनों ही नहीं है । राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर इसकी भूमिका भिन्न रही है । यह एक समष्टि राजनैतिक व्यवस्था है जिसमें समष्टि उप व्यवस्था, गुंठ , मंच समूह, लॉबी , गोष्ठी भी साथ-साथ

- 1- फिर वही,
- 2- फिर वही,
- 3- फिर वही,

रहे हैं इसके परिणाम स्वल्प कांग्रेस का स्वल्प सम्मिलित रूप से बहुजातीय , बहु सामुदायिक और बहुवर्गीय रहा है इस व्यापक अधिरचना में राजनैतिक व्यवस्था के जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं वे विविध राजनैतिक प्राणियों को प्रकट करते हैं, जो प्रभावों राजनैतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए इस राजनैतिक व्यवस्था के तत्वाधान में मान्यता चाहते हैं ।¹

वस्तुतः कांग्रेस का भारतीय चरित्र उसको सबसे बड़ी पहचान है । ये अपने में विभिन्न पारस्परिक विरोधी प्रवृत्तियों को जिनमें विचारात्मक, जातीय क्षेत्रीय तथा हित समूह शामिल किए हुए हैं, जो राजनैतिक महत्वाकांक्षा सत्ता तथा प्रभाव प्राप्त करने के लिए निरन्तर जोरित रहने को सामान्य इच्छा से संगठित है तथा देश के सबसे विशाल राजनैतिक दल हैं । राजनीति में इसके लचीले स्वभाव का लाभ उठाते हुए, विभिन्न समूह वर्ग अपने स्वार्थ और राजनैतिक लाभ के लिए इसको नीतियों और दिशाओं को मोड़ना चाहते हैं ?

यह महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के अंदर वैचारिक, प्रादेशिक , जातीय और उपजातीय विभिन्नताये व्यापक रूप से अंतर्निहित हैं। कुछ अन्य दलों की तुलना में कांग्रेस में ऐसी विभिन्नता अधिक संस्था में पायी जाती हैं । इसी कारण कांग्रेस के प्रतिनिधित्व में अधिक भिन्नता पायी जाती है, उदाहरणार्थ पहले भारतीय क्रांतिदल की तुलना में कांग्रेस में जाट अधिक थे । पो. एस. पो. और एस. एस. पो. की तुलना में उनके पूर्व सदस्य कांग्रेस में अधिक थे । सबसे अधिक अनुसूचित जाति के सदस्य रिपब्लिकन याः झारखंड पार्टी को अपेक्षा कांग्रेस में हो सबसे अधिक हैं राजा सामंत, धनो, किसान, जमींदार, भूस्वामी और अभिजात व्यापारों दिलचस्पी रखते थे । अधिकांश रुढ़िवादो, पुरातनवादो, परंपरावादो, हिन्दू मुस्लिम और सिक्ख क्रमशः, संघ, भा. ज. पा. मुस्लिम लोग और अकाली दल भी कांग्रेस में हो रहे हैं ।³

1- फिर वही,

2- फिर वही,

3- फिर वही,

कांग्रेस का राजनैतिक समर्थन टाँचा बहुत व्यापक है, इसे वास्तविक रूप से भारत उप महाद्वीप के समस्त ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश प्रायः सभी नगर एवं कस्बे तथा देश के प्रत्येक प्रदेश से संसदीय चुनावों में संभक्तः निरन्तर व्यापक निर्वाचन समर्थन का आधार मिलता रहा है। पिछले नौ आम संसदीय चुनावों में कांग्रेस को प्राप्त व्यापक लोकप्रिय मत समर्थन को प्रतिसंख्या इस प्रकार रही।¹

1952 - 45%	1957 - 47.8%	1962 - 44.7%
1967 - 40.8%	1971 - 43.7%	1977 - 34.52%
1980 - 42.7%	1984 - 49.3%	1989 - 39.3%

यद्यपि कांग्रेस को हमेशा ही प्रत्येक चुनाव में 50% से कम हो मत मिलते रहे हैं फिर भी इसे अन्य दलों को अपेक्षा अधिक प्रतिशत मत प्राप्त हो रहे हैं।

कांग्रेस अपनी क्षमता के कारण व्यापक निर्वाचन समर्थन को आकर्षित करके केन्द्रीय सरकार के संघीय स्तर पर लोकसभा के सिवाय वर्ष 1977 एवं 1989 को छोड़कर बहुमत सौट प्राप्त करती रही है इसके फलस्वरूप वह भारतीय संसदीय प्रणाली को बहुदलीय स्थिति में केवल एक प्रभावो दल के स्वरूप में नहीं उभरा, अपितु अपने क्षेत्रीय विस्तार निर्वाचन अपोल और राजनैतिक शाखा विस्तार को दृष्टि से कांग्रेस एक एकल अखिल भारतीय दल बन गया। अन्य सभी दल कुछ हद तक पराक्षेत्रीय और बहु-राष्ट्रीय दल यों एकल राज्यीय और क्षेत्रीय दल हैं। इनमें नाम आकांक्षा के रूप में अधिकांश अपने आपको अखिल भारतीय दल होने के दावा करते हैं। कांग्रेस के सदस्य विभिन्न व्यावसायिक समूहों-डाक्टर, अभियंता, तकनीशियन, शिक्षक, सेवा कार्मिक और सभी तरह के श्रमिक वर्ग से नियुक्त किए जाते रहे हैं।

वामपंथी दल -

भारत में कांग्रेस के बाद सबसे पुराना दल कम्युनिस्ट पार्टी है । सन् 1917 में अक्टूबर क्रांति के शोष्य बाद साम्यवाद, समतावादो और शोषण विहीन समाज का आदर्श बन गया । सर्व प्रथम इसको प्रतिध्वनि भारत के साहित्य और कविताओं में हुई सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रकवि सुबहण्यम भारती ने इसी अग्रदूत लेनिन के अश्रिवादन में कविताये लिखीं । 17 अक्टूबर 1917 को ताशकंद के निर्वासित क्रांतिकारियों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापना की उसके बाद कुछ कम्युनिस्ट नेता भारतीय कांग्रेस के सम्पर्क में आए और दिसम्बर 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में उन्होंने एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। अपनी स्थापना के पाँच वर्ष के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को प्रमुख गतिविधियाँ बम्बई, मद्रास, कानपुर और अहमदाबाद, जैसे नगरीय औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक संघ के मोर्चे तक सीमित थी । इसके बाद इसको गतिविधियाँ श्रमिक संगठनों से बढ़कर किसान संगठनों और नगरीय बुद्धिजीवियों के बीच पहुँच गई । ¹

जब अगस्त 1947 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ तब कम्युनिस्टों ने इसे सच्ची आजादी के रूप में स्वीकार नहीं किया । सन् 1948 के भा. क. पा. के कलकत्ता सम्मेलन में सच्ची राष्ट्रीय आजादी प्राप्त करने के लिए सशस्त्र संघर्ष सहित सामंतवाद पूँजीवाद और साम्राज्यवाद पर आक्रमण की नीति का समर्थन किया गया । पूरे नेहरू युग में भा. क. पा. ही मुख्य विपक्षी दल था । प्रथम लोकसभा में 26 द्वितीय और तृतीय लोकसभा में क्रमशः 27 और 29 सदस्य थे । ²

सन् 1957 में भा. क. पा. केरल विधान सभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में सफल हुई और भारत में प्रथम कम्युनिस्ट सरकार बनी । सन् 1958 में भा. क. पा. के अमृतसर सम्मेलन में क्रांतिकारी उग्रावादो वामपंथियो

1- वोनर माइजर - पार्टी पालिटिक्स इन इंडिया, डेवलपमेंट आफ मल्टी पार्टी, सिस्टम पेज - 64

2- फिर वही, े.

और सुधारवादो वामपंथियों के बीच खुला विवाद पैदा हो गया। इस प्रकार विवाद की स्थिति में केन्द्रीय कांग्रेस सरकार ने सन् 1959 में केरल को कांग्रेस सरकार को भंग कर दिया। 1962 के चीनो आक्रमण ने साम्यवादो राजनीति को बुरी तरह प्रभावित किया, जिसका परिणाम था 1964 में भा. क. पा. में फूट। पश्चिम बंगाल और केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को शाखाओं को मजबूत जनाधार था। अतः केरल और पश्चिम बंगाल को शाखाएं हो भा. क. पा. मार्क्सवादो के निर्माण को प्रमुख केन्द्रक साबित हुई।

सन् 1967 के ग्रीष्मकाल में उग्रवादो मार्क्सवादो गुट, भा. क. पा. § मार्क्सवादो § से अलग हो गया और उसने भा. क. पा. § मार्क्स, लेनिनवादो § नाम से एक दल का निर्माण किया। चूंकि इस गुट ने पश्चिम बंगाल के नक्सलवादो क्षेत्र में जमींदारों के विरुद्ध व्यापक हिंसक गतिविधियों का आतंक फैलाया था और इसका व्यापक आधार नक्सलवादो ही था, इसलिए प्रायः इस गुट को नक्सलवादो या नक्सलो कहा जाता है। बाद में नक्सलवादो ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम क्षेत्र में अपना पांव जमा लिया।¹

भा. क. पा. और भा. क. पा. § मार्क्सवादो § के बीच कुछ विषयों जैसे - भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, राष्ट्रीय बुर्जुवा और बड़े बुर्जुवा की भूमिका के मूल्यांकन और भारत में लोकतांत्रिक क्रांति लाने के लक्ष्य की प्राप्ति में कांग्रेस दल के योगदान के प्रश्नों पर मतभेद है। इन दोनों दलों ने समाजवाद के लक्ष्य प्राप्त करने की रणनीति तथा राजनीतिक विकल्प के इस दौर में अन्य दलों के प्रति अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण के संदर्भ में भिन्न भिन्न मत हैं।²

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी § मार्क्सवादो § के प्रमुख समर्थन आधार पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में सबसे अधिक केन्द्रित है। इसका आंशिक

1- फिर वही,

2- फिर वही.

असम आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं पंजाब में है ।

भा. क. पा. का विस्तार क्षेत्र मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, मणिपुर, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हैं। इसके अलावा यह पश्चिम बंगाल और केरल के वाम मोर्चा के संविद सरकारों में भी शामिल है ।¹

नौ लोक सभा के आम चुनावों में कम्युनिस्ट पार्टियों की उपलब्धि के अंको पर एक नजर डाले तो स्पष्ट होगा कि अविभाजित भा. क. पा. सन् 1952 में 3.3% एवं 1962 के आम चुनाव में बढ़कर 9.94% हो गया था । सन् 1964 में विभाजन के पश्चात भा. क. पा. और भा. क. पा. §मार्क्सवादो§ को संयुक्त रूप से 1967 एवं 1971 में लगभग 10% मत प्राप्त हुए । 1977 में मत प्रतिशत घटकर 7.65% रह गया । पुनः इसमें आंशिक वृद्धि हुई और सन् 1980 में 8.7% 1984 में 8.63% तथा 1989 में 8.93% कुल प्राप्त हुए ।²

जनता पार्टी :

कांग्रेस के पुनरुत्थान और उसके राजनैतिक स्थायित्व की स्थिति में जो विपक्षी समूह कांग्रेस को सत्ता से बाहर निकालने के अवसरों के तलाश में थे, उन्होंने अपना कार्यक्रम बदल दो । उन्होंने सार्वजनिक प्रदर्शन, बाजारों एवं नगरों में बलपूर्वक बंद का आयोजन, छात्र आन्दोलन और युवाओं का विरोध, श्रमिक हड़ताल, किसान मार्च, सांसदों एवं विधायकों द्वारा त्यागपत्र इत्यादि के माध्यम से कांग्रेस विरोधी जन आन्दोलन का सहारा लिया । जनवरी सन् 1974 में भा. क. पा. §मा.§ और जनसंघ ने सामूहिक रूप से महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया । कांग्रेस §ओ§ और जनसंघ दोनों ने गुजरात में नव निमणि समिति का समर्थन किया उत्तर प्रदेश में भारतीय क्रांति दल, समाजवादो

1- फिर वहो,

2- रिपोर्ट्स आन् द जनरल इलेक्शन इन इंडिया, इलेक्शन कमोशन, इंडिया

सोशलिस्ट पार्टी एवं मुसलिम मणलिस ने एक चुनावी गठबंधन से कांग्रेस विरोधी मोर्चा बना लिया । बिहार में जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में सम्पूर्ण क्रांति के नारे के अंतर्गत एक जन आन्दोलन शुरू किया गया और मुरार जो देशाई की अध्यक्षता में एक लोक संघर्ष समिति गठित की गई । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर सभी विपक्षी दलों ने जय प्रकाश नारायण एवं मुरार जो देशाई के नेतृत्व को समर्थन प्रकृत किया इसी समय सन् 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लोक सभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द कर दिया । इस निर्णय के परिणाम स्वरूप सभी विरोधी दल इंदिरा सरकार के विरोध में संगठित हो गए । जिसके कारण कांग्रेस एवं इंदिरा गांधी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया । उन्होंने देश के विभिन्न भागों में अराजकता एवं व्यवस्था का हवाला देकर जन आन्दोलन को दबाने और अपने अस्तित्व को रक्षा के लिए 26 जून 1975 को देश में आंतरिक आपात स्थिति लागू कर दी ।¹

देश में कानून व्यवस्था को पुनः कायम करने, संसदीय प्रणाली के कार्य को सुरक्षा के लिए प्रशासन को कमियों को दूर करने के लिए, सुरक्षा के लिए आपात स्थिति लगाई गई । किन्तु इससे तो एकाधिकारवाद की कृति को स्थान मिल गया । इस परिवर्तन से सचेत एवं सामान्य स्थिति लागू करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी ने मार्च 1977 में आम चुनाव को घोषणा करके एक साहसिक कदम उठाया किन्तु पहली बार कांग्रेस को बुरी तरह पराजय का मुँह देखना पड़ा मतदाता का कांग्रेस के प्रति इतना मोह भंग और आक्रोश था कि न केवल कांग्रेस विरोधी मतदान हो किया गया बल्कि इंदिरा गांधी को भी अपने निर्वाचन क्षेत्र से हार का मुँह देखना पड़ा ।²

कांग्रेस के हटार जाने से जो स्थान रिक्त हुआ उसे भरने के लिए सात प्रमुख कांग्रेस विरोधी दलों के विलय से जनता पार्टी के रूप में एक नया दल

1- खान रशीउद्दोन -भारत में लोकतंत्र पृ० 101

2- फिर वही, पृ० 102

बनाने को आम सहमति हो गई, जिसे इसके शिल्पो जय प्रकाश नारायण का आशीर्वाद मिल चुका था। ये कांग्रेस विरोधी दल थे मोरारजी देसाई और नोलम संजोव रेड्डी के नेतृत्व वाला कांग्रेस {ओ} चौधरी चरणसिंह और राजनारायण के नेतृत्व वाला भारतीय लोकदल, आडवाणी के नेतृत्व वाला जनसंघ, मधुलिमर और जार्ज फर्नांडोज तथा मधु दंडवते वाली समाजवादी पार्टी जगजोवन और एच. एन. बहुगुणा के नेतृत्व वाला लोकतांत्रिक कांग्रेस। इसके अलावा स्वतंत्र पार्टी के कुछ प्रतिनिधि जैसे पोलू मोंदो और मोनू मसानो और पूर्व कांग्रेस के प्रतिनिधि जैसे चन्द्रशेखर, मोहन घारिया और रामधन को जनता पार्टी के निर्माण और उसमें शामिल होने के लिए तैयार थे।^१ इस प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के निर्माण के कुछ सप्ताह बाद हो। मई 1977 को जनता पार्टी के रूप में नई पार्टी को स्थापना की गई।

जनता पार्टी के समर्थन का जनाधार मुख्यतः हिन्दो प्रदेश में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार हरियाणा, राजस्थान, पंजाब {अकालियों से तालमेल के कारण { इस प्रकार हम देखते हैं कि इसको मतदाता शक्ति उन्होंने क्षेत्रों में अधिक थी, जिनमें सन् 1967 में कांग्रेस सत्ता से बहिष्कृत हुआ।

जनता पार्टी का शासन अल्पकालिक था यह केवल 28 महीने { 28 मार्च 1977 से जुलाई 1979 { तक चला, विभिन्न समूहों एवं दलों का एक संविद और समिश्रित दल कांग्रेस आई के स्थाई विकल्प के रूप में उभरने के बाद भी अपना विकास नहीं कर सका। अनेक नीति सम्बन्धी मुद्दे और कार्यक्रम पर जनता पार्टी के उपर से नीचे तक फूट और मतभेद व्याप्त था। इससे जनता पार्टी के शासन को सरकार अपनी उपलब्धियों में कमजोर बनने लगी। आंतरिक फूट इसको सबसे बड़ी सांठनिक कमजोरी थी। इसके कारण न तो जनता पार्टी के सांठनिक ढाँचे में परस्पर संमति थी और न ही कोई दूरगामी

तथा प्रासंगिक नोति हो थी । अतः आंतरिक फूट और मतभेद के कारण जनता पार्टी स्वयं अपने ही बोझ तले दब कर टूट गयी ।

लोकदल -

जनता पार्टी के विघटन के बाद तीन प्रमुख राजनीतिक दल लोकदल भारतीय जनता पार्टी एवं शेष जनता पार्टी अस्तित्व में आए । जनता पार्टी में फूट तथा मुरार जो देशाई को सरकार के त्याग पत्र देने के बाद चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में लोकदल में कांग्रेस की मदद से अगस्त सन् 1979 में सरकार बनायी। किन्तु यह सरकार लोकसभा में बहुमत सिद्धनकर सकी । अतः जनवरी 1980 के आम चुनाव तक यह सरकार एक कार्यकारी प्रभारों सरकार को हैसियत से अपना कार्य करती रही ।¹

लोकदल का निर्माण सितम्बर 1979 में हुआ । यह भारतीय लोकदल का ही एक नया स्थांतरण था जिसका कि जनता^{पार्टी} में विलय हुआ था । भारतीय क्रांति दल का एक पुर्नगठित संगठन था जिसे अनेक कांग्रेस विरोधी दलों तथा पुराने कांग्रेसियों को मिलाकर चौधरी चरण सिंह ने अगस्त सन् 1974 में बनाया था । भारतीय क्रांति दल में समाजवादो सोशलिस्ट पार्टी, उत्कल कांग्रेस, स्वतंत्र पार्टी, हरिजन संघर्ष समिति, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल, किसान मजदूर पार्टी तथा पंजाब खेती बारी, जमोंदार संघ शामिल थे। उस समय चौधरी चरण सिंह ने जनसंघ और कांग्रेस {ओ} को भी दल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था । यद्यपि उन्होंने दल को समर्थन देने का आश्वासन दिया था किन्तु वे उसमें विलय के लिए सहमत नहीं थे ।²

लोकदल ने हिन्दी क्षेत्र को भूमि मध्यम एवं पिछड़ी जातियों अहोर, गजर, जाट, ठाकुर कुर्मी और भूमिहार को संगठित किया जो दल के मुख्य

1- फिर वही, पृ० 103

2- फिर वही, पृ० 103

आधार थे । समाजवादियों के इसमें शामिल होने से इसका क्षेत्र प्रगतिशील वर्गों तक हो गया लोकदल के पास भूमिहीन खेत मजदूरों के लिए वास्तविक मजदूरों संबंधी कोई नीति नहीं थी । इसने प्रत्यक्षतः घनों किसानों तथा भूस्वामियों से हो अपील करो । लोकदल ने हिन्दो प्रदेश के माध्यम और खिचड़ी जातियों से अहोय, गूजर, जाट, ठाकुर, यादव कुर्मी तथा भूमिहीन को संगठित किया । ये ही उसके समर्थन के मुख्य आधार थे । इसके नेतृत्वकारी पदों पर समाजवादियों के आने से लोकदल प्रगतिशील वर्गों के समर्थन पाने की ओर ध्यान दिया गया । इसका चुनाव चिह्न हल जोतता किसान था ।¹

भारतीय जनता पार्टी -

भारतीय जनता पार्टी को स्थापना दिसम्बर 1980 में हुई । यह भारतीय जनसंघ 'जिसको स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में 21 अक्टूबर सन् 1951 में हुई थी' का एक नया पद और संशोधित रूप है । भारतीय जनता पार्टी अपने अनुशासन, सुसंगठन तथा पारम्परिक सामाजिक, सांस्कृतिक हिन्दू संगठनों § राष्ट्रीय स्वयं संघ, विश्व हिन्दू परिषद § से सम्बन्धित मामलों में जनसंघ जैसे हो लगती है तथा थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ राजनीतिक संदर्भ तथा नीति निर्धारण के लिए जनसंघ से घनिष्ठ रूप से जुड़ी है ।²

1 मई 1977 को जनसंघ ने अपने दल को स्वयं ही भंग कर दिया तथा नवगठित जनता पार्टी का एक प्रमुख घटक बन गया । अटल बिहारी वाजपेयी और एल. के. आडवाणी जैसे जनसंघ के नेता जनता पार्टी के मंत्रो मंडल में मंत्री बनाए गये सन् 1980 में लोक सभा चुनाव में इस दल के पराजित होने

1- फिर वही पृ. 103

2- फिर वही, पृ 107

के बाद पहले जनसंघ के अधिकांश नेता, जनता पार्टी से अलग हो गए और उन्होंने इसके बदले भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक अलग नए दल की स्थापना की। इसका एक कारण था कि जनता पार्टी के अनेक सदस्य स्वयं सेवक संघ के सदस्य बने रहने पर आपत्ति उठाते थे। जब जनता पार्टी के दूसरे घटकों ने जनसंघ के सदस्यों को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य बने रहने पर आरोप लगाया तो उनको दोहरी सदस्यता का यह विवाद जनता सरकार के पूरे कार्यकाल १९७७-७९ में लगातार उठता रहा।¹

अतः जब नये दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तब इस नवगठित पार्टी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ उनको दोहरी सदस्यता को उचित बताया। भारतीय संस्कृति और मर्यादा की रक्षा में संघ की वास्तविक भूमिका की सराहना की गई और घोषित किया गया कि यही गांधीवादो समाजवाद का आदर्श रूप है जिसको यथार्थ रूप देने की प्रेरणा गांधी जी से लेकर जय प्रकाश नारायण और दोन दयाल उपाध्याय में टूटने पर विशेष बल दिया गया। भारत में घोषणा और उपलब्धि के बीच व्यापक विचलन की दूरी कोई नई चीज नहीं है। वास्तव में यह व्यावहारिक रूप से प्रत्येक दल परिलक्षित है। दशकों से भारत समाजवाद शब्द का प्रयोग होता रहा।² सभी दल व्यावहारिक रूप से इसके अंतर्वस्तु और वैज्ञानिक अर्थ को ऐसी प्रफुल्लतापूर्ण महत्वहीनता की दृष्टि से प्रयोग करते रहे कि जनता के बीच अलग-अलग व्यक्ति में अलग-अलग अर्थ बोध का विकास हो गया है। एक बार सो.ई.एम. जोड़ ने कहा था कि - समाजवाद एक टोपी की तरह है जो अनेक भिन्न प्रकार के सिरों में पहनने के कारण अपना आकार खो चुकी है।

अपने पूर्ववर्ती जनसंघ की तरह भारतीय जनता पार्टी का आधार समर्थन विशेषतया हिन्दो प्रदेश में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के छोटे और मध्यम

स्तर के व्यापारों और दुकानदार, पारंपरिक व्यावसायिक समुदाय के वैश्य तथा जैन तथा पारंपरिक राजनीतिक दृष्टिकोण में विश्वास रखने वाले जनता है। मध्यम स्तर के व्यवसायों तथा नौकरी पेशा के कर्मियों के बीच भी इसके समर्थक हैं, विशेषतया सन् 1977 के कुछ मामलों में इसका प्रभाव दक्षिण भारत के प्रदेशों केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक फैल गया। यद्यपि 1962 से जनसंघ के रूप में इसका प्रभाव पहले से ही इन क्षेत्रों में विद्यमान था।¹ लोक सभा में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्राप्त मतों के प्रतिशत में परिवर्तन देखा जा सकता है। सन् 1952 में यह 3.1% तथा 1967 में 9.4% हो गया। अन्य चुनावों में यह 6% से 7% के बीच रहा है। सन् 1989 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 11.56% अधिक मत प्राप्त हुआ। यह लोक सभा में 88 सीटें प्राप्त करके कुल 16.41% मत प्राप्त करने में सफल रहा। यह इसको सबसे बड़े चुनावों में ~~अग्रणी~~ है और इसका प्रभाव मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में फैल चुका है।²

जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चा :

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को इस लम्बी पुष्टभूमि में सन् 1989 में एक नया और महत्वपूर्ण विकास हुआ जिसके दूरगामी परिणाम हुए। कांग्रेस दल के एक विकल्प के रूप में विपक्षी शक्ति के निर्माण की प्रक्रिया में पहले की अपेक्षा अधिक सुसंगठित प्रयास था। वास्तव में यह प्रभावों सकल दलों व प्रणाली के ढाँचे के निर्माण की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा प्रयास था।³

मार्च 1989 में चार राजनीतिक संगठनों ने जनता दल के नाम से एक नया दल बनाने का निश्चय किया। ये चार संगठन थे - जनता पार्टी का बहुसंख्यक गुट श्री चन्द्रशेखर, रामकृष्ण हेगड़े और मधुदंडवते के नेतृत्व वाली जनता पार्टी

1- फिर वही, पृष्ठ 108

2- फिर वही, पृष्ठ 112

3- फिर वही, 104,

लोकदल का बहुसंख्यक गुट § हरियाणा के मुख्य मंत्री चौधरी देवीलाल सहित अजोत सिंह गुट § जनमोर्चा § विश्वनाथ प्रताप सिंह आरिफ मोहम्मद खान, अरुण नेहरू और विद्याचरण शुक्ल § तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ § मेनका गाँधी द्वारा निर्मित § । जनता पार्टी के दूसरे गुट का नाम जनता पार्टी § सुबहण्यम स्वामी इंदुभाई पटेल और सरोजनी माहिमो के नेतृत्व वाली जनता पार्टी § है वह नव गठित जनता दल में शामिल नहीं हुई । शहाबुद्दीन और जनता पार्टी के अन्य नेताओं ने इंसफ पार्टी के नाम से एक अलग दल का गठन किया ।¹

कांग्रेस दल के राजनीतिक आधिपत्य के विरुद्ध जनता दल पुनः एक केन्द्र बिन्दु बन गया । जब जनता दल ने सितम्बर 1989 में तेलुगूदेशम पार्टी, कांग्रेस § समाजवादी §, असम गण परिषद ए.पी.पी. और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय मोर्चा के निर्माण को पहल की तो उसका उद्देश्य जनवरी 1990 में होने वाले लोक सभा के आम चुनाव के लिए गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाना था । हालांकि यह आम चुनाव नवम्बर 1989 में हो हो गए । पाँच दलों के राष्ट्रीय मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी और, वामपंथी मोर्चा § भा. क. पा. § मा. क. पा. § फारवर्ड ब्लाक § तथा आर. एस. पी. सहित § के साथ चुनावों समझौता किया तथा कांग्रेस दल के विरुद्ध मजबूत विपक्षी एकता के लिए सोटी का समझौता भी हो गया ।²

विपक्षी दलों की समन्वित रणनीति और एकता के कारण नौवों लोक सभा चुनाव में कांग्रेस दल बुरी तरह पराजित हुआ । सन् 1977 में जिस प्रकार कांग्रेस ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया था, लगभग वही स्थिति नौवो लोकसभा में कांग्रेस दल की थी । फिर भी कांग्रेस दल कुल मत 39.3% मत और 194 सीट प्राप्त करके सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आया।³

1- फिर वही, पृ० 104

2- फिर वही, पृ० 105

3- फिर वही, पृ० 105

सन् 1989 के नौवो लोकसभा के चुनाव मे जनता दल ने 17.7% मत प्राप्त करके 142 सीटो पर विजय प्राप्त की । इसके चुनावो सहयोग दल भारतीय जनता पार्टी को 11.56% मत एवं 88 सीटें मिली । जनता दल के दूसरे सहयोगी दल वामपंथी मोर्चा 10% मत प्राप्त करके 52 सीटो पर विजयी रहे ।¹

लोकदल. बो.जे.पो. और वामपंथी मोर्चा तीनों गुटों ने कुल 282 सीटो पर कब्जा किया था ।

इस चुनाव में किसी एक दल को बहुमत न मिलने से जनता दल को सरकार बनाने के लिए बो.जे.पो. 88 सीटें तथा वामपंथी मोर्चा 52 सीटें के समर्थन पर निर्भर होना पड़ा जो कि आर्थिक विकास के अनेक मुद्दों पर एक दूसरे के विरोधी हैं ।

नौवों लोकसभा में निर्मित सरकार एक विशेष परिस्थिति को उत्पन्न है, जो कि हमारे लिए नया अनुभव है । इस प्रकार को हम औपचारिक या बहुदलीय प्रणाली को कोटि में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वामपंथी मोर्चा और बो.जे.पो. ने सत्तारूढ़ दल को केवल बाहर से समर्थन दिया है ।

दलों में फूट, गुटबंदी पुनर्गठन सत्ता की राजनीति -

भारत में सत्तारूढ़ दल ने नए राजनीतिक ढाँचे के लिए संसदीय लोकतंत्र का नमूना स्वीकार किया । इस पद्धति में दो प्रतिद्वंद्वी दलों का होना जरूरी है जिनके अपने समर्थक वर्ग हों । परन्तु देश में ऐसे प्रतिद्वंद्वी दलों का अभाव था । यहाँ एक कांग्रेस दल की प्रधानता थी । इसलिए प्रतिद्वंद्विता का तत्त्व इसी दल के भीतर से आना था । इसके लिए कांग्रेस दल को अपनी रीति-रिवाज में परिवर्तन करना जरूरी था अब तक दल में अनुशासन और

एक मत पर जोर दिया गया था। अवश्य ही कांग्रेस का संगठन पहले से ही काफी व्यापक था और उसमें अनेक विचारों और वर्गों के लोग थे।¹

देश में दूसरे मजबूत प्रतिद्वंद्वी² दल के अभाव के कारण कांग्रेस को अपने संगठन के भीतर गुटबंदी को सहन करना पड़ा।

सन् 1967 से 1969 के बीच राजनीतिक दलों ने अपने अनुभव से नए सबक सीखे, जो आगे उसको ले जाने को नीति में परिवर्तन किया। इस अवधि में दल-बदल और अवसरवादिता का जोर रहा, उससे लोग विरक्त हुए और नए गठबंधन करते समय नए लोगों को दल में लेते समय कुछ अधिक सावधानी बरतने लगे। 1967 के बाद से कांग्रेस की नीति यह रही कि पार्टियों से विद्रोहियों को जाने दो और वह एक स्पष्ट नीति और विचार धारा ग्रहण करने तथा दल में अनुशासन रखने को बात करने लगे।³ इस नीति में कांग्रेस को 1968 के हरियाणा के मध्यावधि चुनाव में अच्छी सफलता मिली, और 1969 के उत्तर प्रदेश के मध्यावधि चुनाव में भी लाभ हुआ दूसरी ओर यह भी स्पष्ट हो गया कि गैर कांग्रेसी दलों के मोर्चों में 1967 के बाद केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट मोर्चा, मद्रास में द्र.मु.क. का मोर्चा और उड़ीसा में स्वतंत्र-जन कांग्रेस मोर्चा भी टिकाऊ रहा। क्योंकि ये दल अपने क्षेत्र में ज्यादा संगठित और एकता बद्ध थे और इनको काफी स्थानीय समर्थन भी मिला।⁴

इसके मुकाबले खिचड़ी दलों और भूतपूर्व कांग्रेसियों को संयुक्त सरकारें टिकाऊ नहीं सिद्ध हुईं। 1969 में चार राज्यों में मध्यावधि चुनाव हुए ४ जिसे छोटा आम चुनाव भी कहा जाता है। इसमें क्षेत्रीय पार्टियों के संयुक्त मोर्चे बंगाल एवं पंजाब में विजयी हुए और खिचड़ी दलों का मोर्चा बिहार एवं उत्तर प्रदेश में

1- कोठारी रजनी- द कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया पृष्ठ 64

2- कोठारी रजनी - भारत में राजनीति पृष्ठ 129

3- कांग्रेस ने अपनी आंतरिक स्थिति को दृढ़ करने के लिए प्रयत्न किए, देखें मारिस जॉन्स "द इंडियन कांग्रेस पार्टी-ए डिलेमा इन डार्मिनेस" माउन्ट एशियन स्टडीज नं० 2, 1967

4- कोठारी रजनी - भारत में राजनीति पृष्ठ 129

हार गया। केरल में नेबूदरोपाद एवं बंगाल में ज्योति वसु के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी अपने प्रदेश में बड़ी ताकत रखती है। ये अपनी अखिल भारतीय पार्टी या अन्य राज्यों को मार्क्सवादो कम्युनिस्ट पार्टी से भिन्न तरीके से काम करती है। यद्यपि इन राज्यों में मिली जुली सरकार है लेकिन प्रधानता उन्हीं की है। उड़ीसा की स्वतंत्र पार्टी पुरानो गणतंत्र परिषद का ही दूसरा रूप है। अस्तुष्ट कांग्रेस जनों ने कांग्रेस गण-परिषद से मिलकर टिकाऊ सरकार बना ली है। वास्तव में यह पुराने कांग्रेस गण-परिषद के गठजोड़ का ही दूसरा रूप है जिसने 1957 से 1961 तक उड़ीसा में राज्य किया है और जिसे विजया भेरू पटनायक के नेतृत्व में कांग्रेस के नए गुट ने अपदस्थ किया। पुराना गुट कांग्रेस से निकलकर जन कांग्रेस बन गया और गणतंत्र परिषद राज्य की स्वतंत्र पार्टी बन गई। सबसे मजबूत मद्रास का द्र. मु. क. & डॉ. एन. के. & है यह एक प्रान्तीय आन्दोलन का राजनैतिक रूप है। इसे दलों के समर्थन की जरूरत नहीं।

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस विरोधी संयुक्त मोर्चे & यूनाइटेड फ्रंट & की उल्लेखनीय सफलता मिली। चुनाव के पहले ही इस मोर्चे के सदस्यों ने आपस में बात-चीत करके चुनाव समझौता कर लिया था। इससे वोटरों को एक स्पष्ट विकल्प मिल गया। पश्चिमबंगाल तथा अनेक राज्यों में भी, कांग्रेस को कभी वोट का पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। इसके विरोधी वोट कई दलों में बट जाया करते थे। इस बार विरोधी दलों ने तगड़ा मोर्चा बनाकर कांग्रेस को कमजोरी का लाभ उठाया। 1969 के मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त वोटों की संख्या में कमी नहीं हुई फिर भी उसकी सोढ़े बहुत कम मिली। 1969 में बंगाल में दो विशेषताएँ लक्षित हुई एक तो संयुक्त मोर्चे के विभिन्न दलों के बीच सोढ़ों के बटवारे में आसानो हुई, दूसरे बंगाल में संयुक्त मोर्चे का विचार बहुत दिनों तक चला आ रहा था और जनता के बीच इसका प्रभाव बढ़ा। केरल में यही प्रवृत्ति 1965 से 1967 के बीच काम कर रही थी। दूसरे ओर जहाँ विभिन्न

दलों के प्रभाव क्षेत्र बँट नहो है और संयुक्त मोर्चे का विचार जनता में जोर नहो पकड़ पाया है। वहा संयुक्त मोर्चे को उतनी सफलता नहो मिल सकती। बंगाल और केरल में भी संयुक्त मोर्चे अंत में टूट गए।¹

पंजाब में अकाली दल ने आपसी धड़ों को मिलकार अपना तर्गड़ा मोर्चा बनाया। इससे उसके प्रतिद्वन्द्वी जनसंघ ने भी उसका साथ दिया बाद में पंजाब में अकाली-जनसंघ जोड़ टूट गया।

इन अस्थिरताओंकी वजह से 1969 के चुनाव में भारतीय जनता ने अपनी राजनैतिक समझदारों का परिचय देते हुए उत्तर, प्रदेश और बिहार में जनसंघ, संसोया जैसे गैर कांग्रेसी दलों को स्थिर सरकार न देने के कारण उनके विरोध में मतदान किया।²

चुनाव परिणाम का विश्लेषण करने से पता चलता है कि गैर कांग्रेसी दलों के उम्मीदवार बजाय एक दूसरे के कांग्रेसी वोटों को ज्यादा काटते हैं। यद्यपि जहा अधिक उम्मीदवार होते हैं वहाँ कांग्रेस को अधिक फायदा होता है और उनका उम्मीदवार जीत जाता है, लेकिन उसके वोटों की संख्या गिर जाती है। दूसरी ओर जहाँ कांग्रेस का दूसरे दल या संयुक्त उम्मीदवार से सीधा मुकाबला होता है वहाँ उसके तो बढ़ जाते हैं, मगर जरूरी नहो कि उसका उम्मीदवार जीत जाय। इस प्रकार केरल में 1969 में और बंगाल में 1969 में जहाँ कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली, वहाँ उसके वोट कम नहों हुए और केरल में तो बढ़ भी गए। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने अपने वोट 35 से 40 प्रतिशत तक कायम रखे हैं। केरल और पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों को और मद्रास में द्रमुक छोड़कर शेष गैर कांग्रेसी दलों का वोट इतना स्थिर नहो रहा है।³

1- फिर वही पृष्ठ 130

2- कोठारी रजनी - भारत में राजनीति पृष्ठ 131

3- मारिश जॉन्स एवं बी दास गुप्त का निष्कर्ष - इंडियाज पोलिटिकल इंटरिम रिपोर्ट आन एन एकोलाजिकल सेलक्टरल इन्वेस्टिगेशन एसियनर्स नं० 6 जून 1969 ।

1967 में कांग्रेस का एक भाग-प्राधान्य टूटने के बाद इनमें से बहुत सों दिक्कों खत्म हुई - लेकिन इसके बजाए कुछ नई दिक्को पैदा हो गई । जब अन्य पार्टियाँ सत्ता में आई तो उन्होंने सत्ता के बाहर रहने के निराशा के सालो को पूरा कसर निकाल ली । कुछ राज्यों में नई सरकारों के मंत्रियों ने हाथ-पैर मारने शुरू कर दिए । उन्हें अनेक वायदे पूरे करने थे, किन्तु मिली सरकारों के अस्थिरता के कारण उनको साफ पता लगता था कि उन्हें अधिक समय नहीं मिल पाएगा । ऐसी हालत में उन्होंने अपने मित्रों को पुरस्कार देने तथा शत्रुओं को प्रताड़ित करने के मामलों में जो कार्यवाही की उसकी तुलना अगर उनके पूर्ववर्ती कांग्रेसी मंत्रियों द्वारा की गई कार्यवाही से की जाए तो ऐसा लगेगा कि कांग्रेस के मंत्री सज्जन हो थे । जहाँ प्रशासन ने अपने आपको नए मंत्रियों के अधिक अनुकूल बना लिया वही निराशा का फायदा उठाने की भी कोशिश कर सकते थे । इस बात का प्रमाण था 1969 का चुनाव जिसमें जनता ने कांग्रेस को वोट दिया । लेकिन यह उस ढंग की तुलना में कुछ नहीं था, जिस ढंग से पश्चिम बंगाल और केरल में सो.पो.आई एम. ४ के मंत्रियों ने प्रशासन के स्वामी के रूप में सत्ता का प्रयोग किया । स्वयं वामपंथी लोग ही उनको आलोचना कर रहे थे कि वे संसदीय खेल-खेल रहे थे । सो.पो.आई एम. ४ की सरकारें यह प्रदर्शित करने के लिए वचन बद्ध थी कि किस प्रकार शासन में रहकर भी क्रांतिकारी संघर्ष कारगर तरीके से आगे चलाया जा सकता है। जिन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने सरकारें बनायी थी, उन्होंने जल्दी ही उन पर आरोप लगाने शुरू कर दिए । इन्हो कारणों से सो. पो. आई एम. एल४ के नेतृत्व में दरारे आई, जिसका परिणाम सरकारों के पतन तक पहुँचा ।¹ इसके कारण सो.पो.आई. एम. एल. ४ दो समूहों में बँट गयी तथा नागो रेड्डी के नेतृत्व वाले आंध्र माओवादियों को छोटे-छोटे गुटों में विभाजित हो गए चारु मजूमदार तथा नागोरेड्डी को बहुमत देने से इंकार कर दिया ।

घोर गुटवाद के इस काल के बाद जेल से छह उच्च कोर्ट के साझेदारी नेताओं ने एक छुले पत्र के द्वारा नई पहल की । यह पत्र अगस्त तथा अक्टूबर 1972 के बीच भारत की भिन्न-भिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ था । एकता के लिए ताजा प्रयत्नों के आह्वान के साथ, जिसमें भिन्न-भिन्न समूहों द्वारा अपनी-अपनी स्थिति का जायजा लिया गया ।¹ ये प्रयत्न आज तक भी जारी हैं और तेरह सौ.पो. आई. ४ एम.एल. ४ समूहों द्वारा 1981 के प्रारम्भ में मिले-जुले कार्यक्रम को घोषणा की गई ।

भारत में विरोधी दलीय प्रणाली विचित्र सी है। विचित्रता केवल इस बात को नहीं कि जितने आर्थिक गुट तथा हित हैं, लगभग उतने ही राजनीतिक दल हैं, ~~जिनमें से बहुत से राजनीतिक दल हैं, बल्कि~~ इसमें से बहुत से राजनीतिक दलों का जन-समर्थन आधार बहुत छोटा है, सामाजिक आधार संकुचित है तथा भौगोलिक आधार भी परिसीमित है । इनमें से बहुत से दलीय संप्रदायवादों तथा क्षेत्रीय हैं और इनका कांग्रेस के साथ पूरे तरह धुँवोकरण भी नहीं हुआ है ।

सन् 1970 में आरम्भ होने वाले दशक के आरंभिक वर्षों से पहले कांग्रेस का विरोध प्रायः संगठन के अन्तर्गत उसके विभिन्न हिस्सों में ही पाया जाता था, या फिर कभी-कभी शासक दल के वैचारिक दायरे में इसे व्यक्त किया जाता था । परन्तु 1969 में सिंडिकेट गुट के विकास और 1971 के चुनाव में कांग्रेस को व्यापक सफलता ने संगठन में आंतरिक विरोधी प्रक्रिया को एक प्रकार से समाप्त कर दिया । इसके द्वारा कांग्रेस व्यवस्था में शक्ति से अत्यधिक केन्द्रोत्थरण और प्रभुत्व को प्रक्रिया का आरम्भ हुआ निःसंदेह इनमें से कुछ प्रवृत्तियों का आर्थिक क्षेत्र की घटनाओं से निकट का संबंध था ।

सन् 1970 के दशक के शुरू के वर्षों में स्पष्ट होने लगा था कि अर्थ व्यवस्था इतनी अच्छी न थी वह भारत पाक युद्ध 1971-72, लगातार सूखा और सबसे अधिक पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के दबाव को सहन कर सकते थे। 1969-74 के मूल्य सूचकांक में 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि सहकारों कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों को आप में इतनी बढ़ोत्तरी रही हुई। कुल मिलाकर भारतीय अर्थ व्यवस्था गंभीर संकट की स्थिति में थी। 1970 के आरंभिक वर्षों में श्रमिक वर्ग और उनके संगठनों ने अनेक आन्दोलन और विरोध आयोजित किए। इन आन्दोलनों में 1974 की रेलवे हड़ताल और जय प्रकाश नारायण का आन्दोलन थे।¹

सन् 1974 के गुजरात आन्दोलन और 1974-75 के बिहार आन्दोलन ने कांग्रेस स्थानीय नैतिक और राजनीतिक प्रभुता को ओर ध्यान दिलाया। गुजरात और बिहार दोनों ही आन्दोलनों में मुख्य रूप से धनी किसान और मध्यम वर्ग के लोग सक्रिय थे। वास्तव में गुजरात में धनी किसानों ने इस आन्दोलन का उपयोग भूमि को अधिकतम सोमा और धान की उगाहो समाप्त करने के लिए किया।²

कांग्रेस सरकार के विरुद्ध असंतोष को इस स्थिति का फायदा उठाते हुए विरोधी दलों ने एक बरकतसेकंधा मिलाया और गुजरात में 1975 के चुनाव में विजय प्राप्त की।³ 1976 में होने वाले लोकसभा चुनावों को सामने रखकर और परिस्थितियों को देखते हुए गैर कांग्रेसी संगठन के निर्माण की गतिविधियाँ तीव्रता से आरम्भ हुईं। विरोधी दलों में सहयोग की प्रक्रिया को एक घटना ने और प्रोत्साहित किया। यह घटना थी 1975 में

1- 1976 के गुजरात विधान सभा चुनाव रणियन सर्वे -मार्च 1976

2- फिर वही,

3- फिर वही,

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती गाँधी के रायबरेली चुनाव क्षेत्र से चुनाव को अवैध घोषित करने का निर्णय ।

विरोधी दलों ने इस निर्णय को एक महान उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया । श्रीमती गाँधी के नेतृत्व में तथा कथित कांग्रेसी भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनके अभियान को जैसे न्यायिक वैधता प्राप्त हो गई थी । विजय के उल्लास में पाँच विरोधी दलों ने एक मोर्चा कायम किया और प्रधानमंत्री से तुरन्त त्यागपत्र की माँग को लेकर सत्याग्रह की योजना बनाई । लोक संघर्ष समिति के नाम से आरम्भ इस मोर्चे ने राष्ट्रव्यापी अवज्ञा आन्दोलन को विस्तृत योजना बनाई और जनता का आह्वान किया कि वह श्रीमती गाँधी के तुरन्त पद त्यागने की माँग मनवाने के लिए प्रत्येक निषेधाज्ञा, कानूनन गिरफ्तारों, पुलिस आक्रमण आदि का उल्लेखन करें । इस व्यापक योजना के क्रियान्वित होने से पहले ही इसे आपात स्थिति की घोषणा करके दबा दिया गया ।

श्रीमती इंदिरा गाँधी द्वारा मार्च 1977 में चुनाव करवाने के निर्णय के बाद जय प्रकाश नारायण जैसे साधक के कारण जनसंघ सहित सभी विरोधी दलों ने संयुक्त चुनाव मोर्चे की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया ।¹ परन्तु भारतीय लोकदल ने उत्तर भारत में संविद सरकारों की असफलता के अनुभव के आधार पर विरोधी दलों के बिखराव और बिस्तार को समाप्त करने की आवश्यकता को बतलाते हुए गैर साम्यवादो विरोधी दलों के विलय का प्रस्ताव रखा ।² समाजवादो पार्टों और कांग्रेस १स१ इतने कम समय की सूचना पर विलय की सफलता के बारे में संदिग्ध व्यक्त किए । उन्होंने विलय के विरुद्ध संचित किया और एक संघीय दल के निर्णय का प्रस्ताव रखा । कुछ सप्ताह की गंभीर बातचीत और विवाद के बाद तत्कालीन चुनाव के लिए सर्वदल मान्य उम्मीदवारों की सूची, एक ही चुनाव चिन्ह, झंडे और चुनाव

1- भाम्बरी सी. पी. - जनता पार्टी 1979

2- फिरवहो,

घोषणा पत्र पर सहमति हुई। इस संगठन ने 1977 के चुनाव के लिए नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन " जैसे विषयों को चुनावों में मुद्दा बनाया। इस संगठन ने मिलकर मार्च 1977 का लोक सभा चुनाव लड़ा और जीता तथा इसने मई 1977 को औपचारिक रूप से जनता पार्टी को स्थापना की।

जनता पार्टी द्वारा मार्च 1977 में राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार गैर-कंग्रेसी सरकार के निर्माण से भारत में द्वितीय व्यवस्था के उदय की जो आशाएँ बंधी थी वे दो वर्ष के भीतर ही समाप्त हो गईं। जुलाई 1979 में जनता पार्टी में सांप्रदायिकता और निष्ठा के प्रश्न को लेकर विघटन हो गया तथा दल दो भागों में बंट गया। लेकिन इस विघटन का मुख्य कारण गुटबंदी थी। जनता पार्टी के आंतरिक विरोधाभास, दल के विभिन्न घटकों द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के गुटबंदी के कारण और अधिक तीव्र हो गए और दल को पतन की ओर ले जा रहे थे। यह गुटबंदी भारतीय लोकदल एवं जनसंघ में विशेष थी। यही दोनों जनता पार्टी के अत्यधिक शक्तिशाली घटक थे और निश्चित तथा प्रभावशाली समर्थन पर आधारित थे। इसलिए दोनों ही दल को विचारधारा संगठन और शक्ति के ढोंघ को प्रभावित करने की होड़ थी। इस प्रकार से जनता शासन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा, जाति, प्रतिद्वंद्विता और भूमिहीन हरिजनों पर अत्याचार आदि इस गुटबंदी के परिणाम थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अलग करने में पूरी तरह से निष्फल रही। अंततः लोकदल तथा कुछ अन्य सदस्यों ने जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आपसी संबंधों को लेकर जनसंघ को दुर्बल करने का प्रयत्न किया, परन्तु यह प्रयत्न जनता पार्टी को ही खंडित कर बैठा।

1977 के लोक सभा चुनावों में जनता पार्टी के वैध मतों का प्रतिशत 43.17 था, जब कि लोकसभा में इसको सदस्य संख्या 54.93% रही। मत प्रतिशत के आधार पर जनता ने लगभग 1971 वाला कांग्रेस को स्थिति प्राप्त की। 1977 में हो राज्यों के विधान सभाओं के चुनावों में जनता पार्टी को उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में व्यापक बहुमत प्राप्त हुआ।¹

लेकिन विघटन के पश्चात्, 1980 के लोक सभा चुनावों में स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई। इस चुनावों में जनता पार्टी को मात्र 31 स्थान मिले, इसका मत प्रतिशत मात्र 19 था। जनता पार्टी से अलग हुए लोकदल को इस चुनाव में 9.4% मत और 41 स्थान प्राप्त हुए। इस प्रकार दोनों मिलाकर कुल 28.4% मत मिले, परन्तु बंटवारे के कारण इनके स्थानों में अधिक गिरावट आई। जहाँ जनता पार्टी को देश के कुछ प्रमुख नगरों में समर्थन प्राप्त हुआ, वही लोकदल को उत्तर प्रदेश के ग्रामीण कृषक मध्य वर्ग और बिहार तथा उड़ीसा में कुछ पिछड़े जातियों से समर्थन मिला। 1980 के लोकसभा चुनाव के बाद जनता पार्टी का एक और विघटन हुआ और जून 1980 में राज्यों के चुनाव में इसका तीसरा घटक यानि बो.जे.पा. भी अलग से प्रत्याशी थी। इस चुनाव में लोकदल और भा.ज.पा. दोनों ही जनता पार्टी से आगे रहे। दिसम्बर 1984 में भा.ज.पा. का समर्थन और कम हो गया और वह कुल मतों का 7.03% रह गया, इस प्रकार से लोकसभा में 10 स्थान केवल प्राप्त हुए। इन चुनावों में लोकदल को 5.94% मत तथा 4 स्थान प्राप्त हुए और भी0 ज0 पा0 को 4.72% मत तथा केवल दो स्थान मिले।

मई 1982 में चार राज्यों में विधान सभाओं के चुनाव ने फिर इन दलों के समर्थन और आधार को पुष्टि की। लोकदल और भारतीय जनता पार्टी को ही केवल उत्तर भारत में अर्थात् 1982 में हरियाणा तथा हिमाचल में ही

1- जी.जी. मोस्चंदानी -पोपुल वर्डिक्ट 1980 पेज- 33

2- फिर वही,

सफलता मिली । हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में लोकदल और कुछ नगरों में भा.ज. पा. सफल रहे । हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण एवं बाहरी क्षेत्रों में भा.ज.पा. सफल रही ।¹ दूसरी ओर पश्चिम बंगाल एवं केरल में इनका अस्तित्व न के बराबर रहा । जनता पार्टी सभी राज्यों में नाम मात्र के लिए रह गई । 1984 के लोकसभा चुनावों में इन पार्टियों की स्थिति और भी खराब हो गई जिसमें जनता को 11, लोकदल को 3 और भा.ज.पा. को दो स्थान मिले। जनता पार्टी कर्नाटक में सफल रही और अप्रैल 1989 तक इस प्रान्त में शासक दल के रूप में स्थापित थी । आंतरिक मतभेद विशेष रूप से जनता दल में सम्मिलित होने के पश्चात की गुटबंदी से इसमें दरारे आ गई और अन्त में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया ।

जनता पार्टी की तरह ही दिसम्बर 1984 में हार के पश्चात लोकदल ने क्षेत्रीय आधार पर स्वयं को सुदृढ़ करने के प्रयत्न किए । 1987 में हरियाणा में लोकदल और भा.ज.पा. ने मिलकर चुनाव लड़ा और सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की ।

इस प्रकार 1984 में कांग्रेस को अभूतपूर्व सफलता मिली तथा जनता, लोकदल और भा.ज.पा. निम्नतम बिन्दु पर आ गई । भारत में राष्ट्रीय स्तर पर एक सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था को कमो, क्षेत्रीय तथा विकास की प्रक्रिया के लाभों के असमान वितरण के कारण किसी भी राजनीतिक दल के लिए अधिक समय तक राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। एवं विरोधी दलों का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस² का एक विकल्प प्रस्तुत करना हो गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति का उदाहरण है जनता दल का 1988 में गठन अर्थात् किसी भी तरह की गुटबंदी से सत्ता को हासिल करना ।

1- टाइम्स ऑफ़ इंडिया , 20 नवम्बर 1984 ।

2- टाइम्स ऑफ़ इंडिया, 14 दिसम्बर 1984 ।

जनता दल को स्थापना ॥ अक्टूबर १९८८ को बंगलौर में हुई । जनता दल का नाम जनता पार्टी के शब्द जनता एवं लोकदल के शब्द दल को लेकर रखा गया । जनता पार्टी, लोकदल, जनमोर्चा तथा कुछ अन्य छोटे दल तथा गुट इसमें सम्मिलित हुए । निःसंदेह जनता पार्टी, लोकदल, जनमोर्चा के समस्त गुट जनता दल में सम्मिलित नहीं हुए तथा इस प्रकार औपचारिक रूप से अब भी जनता पार्टी, लोकदल तथा जनमोर्चा का अस्तित्व बना हुआ है । परन्तु इसमें संदेह नहीं कि इन दलों का प्रभावोद्भूत तथा वास्तविक भाग जनता दल में मिल गया । दल ने विश्वनाथ प्रताप सिंह & कांग्रेस द्वारा निष्कासित जनमोर्चा के नेता & को अपना अध्यक्ष बनाया, तथा मूल रूप से जनता पार्टी & १९७७ के संविधान को नए दल के संविधानिक आधार के रूप में अपनाया है । इसने जनता पार्टी के चुनाव चिह्न तथा ध्वज को अपनाया है ।^१

जनता दल के कार्यक्रम विश्लेषण & समाचार पत्रों को स्वतंत्रता, न्यायपालिका के निष्पक्षता नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, सत्ता के विकेन्द्रीकरण, भ्रष्टाचार समाप्ति & से स्पष्ट होता है कि यह मूलतः मध्य विचार वाला दल है। परन्तु कार्यक्रम पर दल में आंतरिक मतभेद है। मतभेद मुख्यतः व्यक्तित्व संघर्ष, जातीय मतभेद तथा तीसरा सामाजिक आर्थिक नीतियों में अंतर को लेकर है। दल के स्थापना के दिन से मतभेद तीव्र रूप से विकसित हो रहे हैं जिससे कि इस दल की सफलता पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। इसको देखकर प्रश्न यह उठता है कि जनता दल केवल कांग्रेस & का विरोधी है, यह वह राष्ट्र के सामने एक वैकल्पिक व्यवस्था का आधार प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है ? दल की प्रवृत्ति, क्षमता तथा सफलता भारत में विकसित होने वाली दलीय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

अध्याय - ३

क्षेत्रवाद

अध्याय - 3

क्षेत्रवाद

भारतीय समाज एक पारम्परिक पुरातन एवं प्रतिष्ठित समाज है। यह विश्व को सर्वाधिक प्रामाणिक और जटिल संघीय राज्य व्यवस्था है। मानव इतिहास में विश्व के किसी भी भाग में इतनी व्यापक महाद्विपीय विस्तार को भू-भागोय संप्रभुता नहीं थी और न अभी तक है जितना कि अपने सामाजिक सांस्कृतिक संघटन में आज के भारत में स्पष्टता प्रत्यक्ष रूप से संघीय राज्य व्यवस्था है। भारत में जातीय विभाजन सांस्कृतिक प्रतिमान, सामाजिक रीति-रिवाज, धार्मिक विश्वास, भाषा और बोलीयाँ, प्रादेशिक एवं उप प्रादेशिक पहचान की विभिन्नता एवं अनेकता का बहु आयामों स्वरूप स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। यद्यपि भारतीय जनमानस में एकता की स्पष्ट छाप बनी हुई है, फिर भी इन विद्यमान सामाजिक, सांस्कृतिक विभिन्नताओं और असमानताओं के बीच एक नये और स्थायी संघ राष्ट्र की पहचान बनाए रखने के लिए विशेष बल देने की आवश्यकता है।¹

स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राजनीति का प्रमुख तत्त्व क्षेत्रवाद रहा है, जिससे राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता प्रभावित हुई। आमतौर पर क्षेत्रवाद का अर्थ किसी क्षेत्र के लोगों की भावना एवं

1- खान, रशीउद्दीन - भारत में लोकतंत्र पृष्ठ 221

प्रयत्नों से है, जिसके द्वारा वे अपने क्षेत्र विशेष के लिए आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक शक्तियों में वृद्धि चाहते हैं। यहाँ क्षेत्र वह सामाजिक स्थिति है जो किसी एक भूभाग से सम्बन्धित सामाजिक समूह के लक्ष्यों को एकस्यता का केन्द्र है। किसी भी क्षेत्र के लोगों के पृथक स्वस्व के लिए प्रमुख बात वहाँ के लोगों में आपसी समानता और एकस्यता तथा अन्य क्षेत्रों से अलगवान को भावना है।¹

व्यापक अर्थ में क्षेत्रवाद "केन्द्रवाद" के विरुद्ध आन्दोलन है। संकीर्ण अर्थ में यह सम्पूर्ण देश को तुलना में स्थानीय या किसी क्षेत्र विशेष के प्रति लोगों के लगाव को प्रकट करता है। इस कारण क्षेत्रवाद को बहुधा स्थानीयवाद, संकीर्णवाद तथा पृथक्तावाद प्रादेशिकता से समीकृत किया जाता है। किन्तु यह नकारात्मक दृष्टिकोण है। क्षेत्रवाद स्वयं में, उभरती राष्ट्रिय संस्कृति के विभिन्न घटकों को अभिव्यक्ति के वैध मार्ग प्रस्तुत करके राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक योग दे सकता है।²

क्षेत्रवाद के आत्म निष्ठ घटक का सम्बन्ध किसी मानवीय सामूहिकता या समूह के सत्भागों मूल्यों, आस्थाओं, विश्वासों, परम्पराओं साहित्य और कला रूपों, भाषा, सामाजिक विरासत से होता है। यह मुख्यतया, मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक विशिष्टता है। वस्तु परक दृष्टि से इसके, संघटक भौगोलिक क्षेत्रीय व पर्यावरणीय जटिलता है। इसमें कोई क्षेत्रीय समूह विशेष रहता है। बहु आयामों घटना होने से यह हमारी ऐतिहासिक बहुलवाद के अंदर बैठा है।

1- भारतीय शासन एवं राजनीति ने सुशीला कौशिक ।

2- फिर वही,

भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रवाद से अभिप्राय है - राष्ट्र को तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रान्त को अपेक्षा एक छोटे क्षेत्र से लगाव, उसके प्रति भक्ति या विशेष आकर्षण का दिखाना। भारतीय राजनीति के संदर्भ में यह एक ऐसी धारणा है जो भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि पर आधारित है और जो विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देती है। क्षेत्रवाद को भावना सारे देश में व्याप्त है, जो कि प्रायः सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित आन्दोलनों तथा अभिमानों के रूप में प्रकट होते हैं।¹

भारत न केवल भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल देश है, अपितु वैचारिक, परम्परा, धर्म, संस्कृति से भी इसको विशालता प्रकट होती है। स्वतंत्रता की बेला पर भारत दो भागों में विभक्त था - ब्रिटिश भारत के प्रान्त एवं देशों रियासतें। ब्रिटिश भारत में राजनीतिक चेतना तो जागृह हुई किन्तु ब्रिटिश भारत के प्रान्तों का विभाजन अंग्रेजों के तार्किक आधार पर नहीं किया, अपितु अपने न्यस्त हितों को ध्यान में रखकर किया। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक एकीकरण की थी। इस प्रकार प्रारम्भिक रूप से दो समस्याएँ सामने आयें - राज्यों का भारतीय संघ में विलय और भारतीय संघ के अन्तर्गत केन्द्र राज्यों का निर्धारण। इन दोनों समस्याओं के सन्दर्भ में विभिन्न क्षेत्रों का भारतीय मानचित्र में पुनर्सोमंकिन एक चुनौती थी। इस तरह क्षेत्रवाद का उदय ब्रिटिश शासन की विरासत है। भाषा, राजस्व स्रोतों के

1- कौशिक सुशोला - भारतीय शासन एवं राजनीति से।

बैटवारे, स्वायत्ता को लेकर दिन प्रतिदिन क्षेत्रवाद को भावना को बढ़ोत्तरी हो रही है ।

भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद के कारण

१।१ भौगोलिक सांस्कृतिक :

भौगोलिक सांस्कृतिक तत्त्व भारत में सामाजिक विविधता को जड़ और क्षेत्रवाद तथा अन्य संकीर्ण प्रवृत्तियों के प्रमुख आधार है। ये तत्त्व स्वयं अनेक खंडों से मिलकर बनते हैं । सभी खण्ड न केवल अपने आपमें महत्वपूर्ण हैं बल्कि अन्य तत्वों के संदर्भ में काफी सक्रिय हैं । वास्तव में इनका सांस्कृतिक रूप हो इनको वास्तविक भूमिका को प्रकट करता है । इसका एक पहलू व्यक्तियों में पारंपरिक सामुदायिक भावनाओं के अस्तित्व का बना रहना है इससे तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति में सामाजिक मान्यताएँ और निष्ठा संबंधी दृष्टिकोण समाजोक्ति को प्रक्रिया द्वारा बचपन और किशोरावस्था में ही स्थापित हो जाते हैं । ये सुदृढ़ भावनाएँ बाद में आसानी से परिवर्तित नहीं की जा सकती हैं । समाजोक्ति को प्रक्रिया में परिवर्तन किए बिना व्यक्तियों में स्थापित होने वाले सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन यदि संभव नहीं तो कठिन अवश्य है । अनेक विकासशील देशों की भाँति भारत में भी जनसंख्या के अधिकतर भाग को समाजोक्ति को प्रक्रिया की आदिकालीन ढाँचे में सांस्कृतिक परिवर्तन अथवा बदलाव नहीं आया है परिणाम स्वरूप धर्म, जाति, भाषा तथा अन्य सामुदायिक संगठनों के प्रति निष्ठा और कर्तव्य के बारे में बचपन से ही स्थापित मूल्य अधिकतर जन समुदाय के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं, और देश की विविधता, क्षेत्रवाद, जातिवाद,

साम्प्रदायिकता आदि को जन्म देते हैं। ऐसा समाज जो जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के आधार पर जुड़ा है अपने अलग अस्तित्व को घेतना बढ़ाता है।¹

§2§ आर्थिक :

किसी भी क्षेत्र अथवा समुदाय के लोगों में व्यवसाय तथा आज के आधार पर पूर्ण समानता नहीं पाई जाती फिर भी ऐसे वर्ग व क्षेत्र हैं जिनसे अनेक तत्वों के आधार पर कम से कम लक्ष्यों में समानता और हितों के आधार पर एकस्यता पाई जाती है जो उनमें आपसी सहयोग और भाई चारे को सृष्ट करती है। वास्तव में भारत में क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने में आर्थिक और क्षेत्रीय आधार पर विकास विषमताओं और असंतुलन का विशेष योगदान है स्वतंत्रता के बाद विकास को धीमी गति तथा विकास के लिए अपनाई गई नीति से उत्पन्न विरोधाभासों ने क्षेत्रीय आधार पर हितों को समानता को बने रहने में सहायता प्रदान की है।²

भारत के कुछ राज्यों के कुछ क्षेत्रों में अधिक आर्थिक विकास हुआ और आर्थिक विकास के क्षेत्र में कुछ क्षेत्र पिछड़ गए। इससे इन क्षेत्रों में असंतोष फैलने लगा और क्षेत्रवाद की भावना फैलने लगी।³

1- कौशिक सुशोला -भारतीय शासन एवं राजनीति पृष्ठ 0

2- फिर वहीं,

राजनी कोठारो ने कहा है कि " आर्थिक प्रोत कम है और मांगों में निरन्तर वृद्धि हो रही है मांग और उत्पादन में अन्तर का प्रभाव यह है कि व्यक्त समुदाय, वर्ग और क्षेत्र सभी स्तरों पर प्रतिस्पर्धा होता है ।¹

ऐतिहासिक :

राज्य पुनर्गठन के बाद कई रियासतों को राज्यों में मिला लिया गया था । आज भी इन रियासतों के लोग महसूस करते रहे हैं कि यदि उनको रियासत का पृथक राज्य होता है तो वे अधिक लाभ को स्थिति में होते । भारत का इतिहास सामान्य न होकर क्षेत्रों के आधार पर भिन्न है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, लोक परंपराओं, सामाजिक मिथकों के आधार पर क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है । इसका सबसे अच्छा उदाहरण है तमिलनाडु में द्रविड कड़गम एवं द्रविड मुनेत्र कड़गम के विकास को हानि है । इसी प्रकार महाराष्ट्र और आन्ध्रप्रदेश में राज्य, गठन से पहले से चले आ रहे क्षेत्रीय अस्तित्व के कारण इस आधार पर बँटवारे की प्रक्रिया काम कर रही है ।²

राजनैतिक कारण -

राजनैतिक कारणों से है। राजनीतिज्ञ यह सोचते हैं कि पृथक राज्य बनजाने से उनको महत्वाकांक्षायें, आसानों से पूरी हो जायेंगी जैसे असम गण परिषद, अकाली दल, गोरखा बिलरेशन फ्रंट § जिनको चर्चा इसी अध्याय में आगे की गई है § इत्यादि ।

भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद के बारे में चर्चा करते हुए प्रो० रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक " भारत में राजनीति" में लिखा है¹ कि §1§ देश के सामने एकखतरा राज्यों के संघ से अलग हो जाने को था । §2§ कुछ लोगों ने आशंका प्रकट की थी कि प्रान्तीयता की भावना या प्रदेश के लिए अधिक अधिकार या स्वायत्ता की मांग बढ़ती गयी तो इससे या तो देश अनेक छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्यों में बँट जाएगा या वहाँ तानाशाही कायम हो जाएगी §3§ पृथक्ता की भावना उसने ज्यादा खतरनाक है, जहाँ ऐसी कार्यत्तर जातियाँ हैं जो भारतीय संस्कृति को धारा में पूरी तरह नहीं मिल पाई है जैसे उत्तर-पूर्व की आदिम जातियाँ §4§ कुछ क्षेत्रों में अभी भी असंतोष है जैसे उत्तर-पूर्व में मोजो -जॉति बिहार में छोटा नागपुर §5§ राज्यों के भीतर विशिष्ट क्षेत्रों के अलगाव के आन्दोलन उठ रहे हैं । दबे हुए वर्गों, समूहों के राजनैतिक क्षेत्र में आने से अधिकतर के लिए उनकी आकांक्षा से नई समस्याएँ खड़ी हो रही हैं ।²

भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद का विश्लेषण §1967-1989§ निम्न लिखित आधारों पर किया जा सकता है ।

§1§ क्षेत्रवाद और पृथक राज्यों की मांग :

क्षेत्रवाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष पृथक राज्यों की मांग है। आर्थिक पिछड़पन, जाति, भाषा, धर्म को लेकर विभिन्न क्षेत्रों द्वारा पृथक राज्य की मांग समय-समय पर उठाई गई तथा क्षेत्रीय आन्दोलन को शुरुआत की गई । पृथक राज्यों की मांग के पक्ष में

1- रजनी कोठारी - भारत में राजनीति पृ० 330

2- फिर वही,

पक्ष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य संघीय इकाईयों द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की मांग है।

भारत के विभिन्न आधार पर पृथक राज्य की मांग की जाती रही है। 1960 के दशक में आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र को पृथक राज्य बनाये की मांग की गई। तेलंगाना के लोगों का कहना था कि उनके क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो रहा है। जनवरी 1969 में पृथक राज्य के लिए आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। इसका नेतृत्व डॉ० चेन्ना रेड्डी एवं तेलंगाना प्रजा समिति जैसे संगठन ने किया।

पृथक तेलंगाना की मांग फिर जोर पकड़ने लगी है पृथक तेलंगाना की मांग करने वालों को डॉ० चेन्ना रेड्डी का परदे के पीछे से समर्थन प्राप्त है। 8 जुलाई 1985 को तेलंगाना के प्रबल समर्थक पूर्व पार्षद पद्मनाभन ने ध्वज पहनाकर आन्दोलन की शुरुआत की।

पृथक राज्य की मांग के कारण हो सितम्बर 1969 में असम पुनर्गठन की एक योजना घोषित की गई। इस योजना में राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पर्याप्त स्वायत्त शासन की व्यवस्था थी जिससे पहाड़ी लोगों की आकांक्षाएँ पूरी हो और विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप बढ़ सके। असम पुनर्गठन {मेघालय} बिल दिसम्बर 1968 में पारित होकर कानून बन गया, अतः 1969 में मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।¹

1- कोठारो रजनी- भवानल यूनिटो इन डैजर- केस फार, स्मालर यूनिट्स -टाइम्स आफ इंडिया 1968

मणिपुर तथा त्रिपुरा के लोग भी अधिक स्वायत्ता को मांग कर रहे थे । सरकार ने उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर, असम के मिजो जिले को जनता के लिए पृथक प्रशासनिक इकाई को मांग पर विचार किया । प्रदेश के विकास तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1972 में एक अधिनियम पारित कर त्रिपुरा एवं मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया ।¹

असम के दरांग जिले के उदलगुडो उपखंड से लेकर ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तटीय श्रीरामपुर से सदिया तक के क्षेत्र को बोडोलैंड नामक पृथक केन्द्र शासित क्षेत्र बनाने के मांग जैसे तो इसी सदी के प्रारम्भ से ही की जाते रहे हैं ।² लेकिन 1972 में बोडो साहित्य सभा द्वारा बोडो के भाषाई अधिकारों के रक्षा हेतु सत्याग्रह के कारण इस आन्दोलन ने नया मोड़ लिया । 1986 से बोडोलैंड को मांग को लेकर हमेशा आन्दोलन होते रहे हैं । 1987, 2 मार्च से अखिल बोडो छात्र संघ द्वारा विध्वत आन्दोलन की शुरुआत हुई जिसमें असम के मुख्यमंत्री को इस संगठन द्वारा 92 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया, 16 अगस्त 1987 से 1001 घंटे के बंद की घोषणा की गई । अंततः 8 अप्रैल 1993 को राज्य विधान सभा द्वारा बोडो लैंड स्वायत्त परिषद को मंजूर किया, 9 मई 1993 को राष्ट्रपति द्वारा बोडो लैंड स्वायत्त परिषद विधेयक को मंजूर दे दो गई ।³

1- फिर वहो,

2- नवभारत टाइम्स, अप्रैल 1993

3- टाइम्स ऑफ इंडिया, 17 अगस्त 1987 पृ 0 ।

पृथक झारखंड राज्य की मांग को लेकर बिहार के छोटानागपुर इलाके में झारखंड आन्दोलन वर्षों से होता रहा है। तेजी से बढ़ते औद्योगीकरण तथा बाहर से आकर बसने वालों की बढ़ती संख्या ने इस इलाके के आदिवासियों को दयनीय स्थिति में पहुँचा दिया और उन्हें अपनी मातृभूमि से अलग करने का कुचक्र चलाया। छोटा नागपुर के खनिज पदार्थों से तथा वन संपदा से वंचित होने के बाद जब आदिवासियों के सामने रोटों के लाले पड़ने लगे, जब कि भारत की कुल खनिज संपदा का 2/3 भाग इसी क्षेत्र से प्राप्त होता रहा है तब इस क्षेत्र के आदिवासी 1978 में संघीय नेता सोबू सोरेन के नेतृत्व में आन्दोलन प्रारम्भ कर, पृथक झारखंड राज्य की मांग करने लगे।

1986 अक्टूबर में आन्दोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया, तथा जमशेदपुर में 23 अक्टूबर को हुए सम्मेलन में 1 वर्ष के अन्दर पृथक राज्य ले लेने की घोषणा की गई। इसके पश्चात् पृथक राज्य की मांग को लेकर आन्दोलन दिन-प्रतिदिन उग्र रहा जिसमें बिहार में आवागमन तक ठक कर दिया गया, अंततः केन्द्र राज्य एवं झारखंड मुक्तिमोर्चा के बीच झारखंड स्वायत्त क्षेत्र परिषद के गठन पर सामयिक समझौता हो गया। प्रारूप के अनुसार पाँच वर्षों के लिए एक झारखंड सामान्य परिषद का गठन किया जाएगा। सामान्य परिषद के सदस्यों में एक झारखंड कार्यकारिणी समिति गठित की जाएगी, जो किमंत्रिमंडल की तरह कार्य करेगी।¹

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में गोरखालैंड नाम के पृथक राज्य को मांग वर्षों से होता रही थी। अलग राज्य को मांग भारत में रह रहे 70% लोग गरोब, पिछड़े, अशिक्षित नेपालियों के जीवन स्तर सुधारने के लिए को जातो थी। लेकिन गोरखा मुक्ति मोर्चा जिसके अध्यक्ष सुभाष घोषिंग है " को अध्यक्षता में 1986 में आन्दोलन ने उग्र रूप लिया और 1987 में ये आन्दोलन सरकार के सामने मुख्य चुनौती था। घोसिंग ने ये घोषणा की कि गोरखालैंड किसी कोमत पर लेकर रहेंगे अंततः केन्द्र, पश्चिम बंगाल सरकार एवं सुभाष घोसिंग के बीच त्रिपक्षीय वार्ता में गोरखा स्वायत्त परिषद के गठन पर समझौता हुआ।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों, कुमायूँ एवं टेहरी गढ़वाल ने भी पृथक राज्य की आकांक्षा प्रस्तुत की है। पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग का आधार आर्थिक पिछड़ापन है। यह मांग हाल के वर्षों में उठायी जाती रही है कि उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों को मिलाकर पृथक उत्तरखंड गठित किया जाय, जिससे कि इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास हो सके।

क्षेत्रवाद बनाम अन्तरजियोय झगड़े :

क्षेत्रवाद का एक महत्वपूर्ण पक्ष विभिन्न राज्यों के आपसी झगड़े हैं। राज्यों के बीच सीमा विवादों एवं नदी पानी विवादों को लेकर राज्यों में उग्र मतभेद एवं तनाव बढ़े हैं। विशेषतः पिछले दो दशकों में नदी जल बँटवारे को लेकर राज्यों के बीच तनाव काफी रहा है। राष्ट्रीय वितरण के प्रोत्तों के वितरण पर राज्यों के

तीन नदी जल-विवाद -

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और नदी जलो बँटवारे को लेकर विवाद वर्षों पुराना है। इन तीनों राज्यों के बीच 1973 में एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार मध्य प्रदेश में वाण सागर बांध परियोजना के निर्माण में मध्य प्रदेश को आधी जिम्मेदारी है, शेष आधा बिहार एवं उत्तर प्रदेश को खर्च का वहन करना है उनके बीच जल वितरण भी उसी अनुपात में होगा इधर कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश बिहार ने अपने बड़े-बड़े दावे पेश किए हैं । ¹

कृष्णा नदी जल विवाद :

महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के बीच कृष्णा नदी जल विवाद गत 1969 से चला आ रहा है। गत 1974 में न्यायाधिकरण ने इसका समाधान प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत नदी के 75 प्रतिशत जल का वितरण किया गया कर्नाटक और महाराष्ट्र ने अपने अंश को बढ़ाने को मांग की है । जो आंध्र प्रदेश को मंजूर नहीं है ।²

तेलुगु -गंगा परियोजना :

इस परियोजना का लक्ष्य मद्रास को पेयजल प्रदान करना है । इस काम के लिए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से 15-15 अरब घन फुट पानी मद्रास को मिलना है । तमिलनाडु और आन्ध्र

1- कौशिक सुशीला - भारतीय शासन एवं राजनीति ।

2- फिर वही,

प्रदेश के बीच जून 1985 में संयुक्त समझौते के अनुसार तमिलनाडु-आंध्र प्रदेश को 60 करोड़ रु० देने के लिए बाध्य था परन्तु अभी तक उसने केवल 47 करोड़ रु० का ही भुगतान किया है। उसे 92-93 से पानी मिलना था परन्तु अभी और कई वर्षों तक भुगतान में विलम्ब के कारण पानी मिलना संभव नहीं होगा। जिससे झगड़ा स्वाभाविक है।

कावेरी-विवाद -

भारत का सबसे बड़ा नदी जल बँटवारे का झगड़ा कावेरी नदी के पानी को लेकर है। यह झगड़ा इस नदी से पहले से चला आ रहा है यह झगड़ा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच नदी जल के बँटवारे को लेकर है। जिसको लेकर कई बार आपसी समझौते हुए फिर दोनों राज्यों के अड़ियल रवैये के कारण समझौते सफल नहीं होते हैं। 1976 में तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन के दौरान वे एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन बाद के कर्णानिधि को लोकप्रिय सरकार ने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया।¹

जून 1990 में केन्द्र सरकार ने इसके सर्वमान्य ढल के लिए अन्तराष्ट्रिय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत एक ट्रिब्यूनल को स्थापना कर दी।

न्यायमूर्ति चिंतातोष मुखर्जी को अध्यक्षता में गठित ट्रिब्यूनल ने 25 जून 1991 को अपनी रिपोर्ट जारी कर दी जिनको लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक को सरकार आपस में भिड़ो है।²

1- फिर वही,

2- टाइम्स ऑफ़ इंडिया- 26 जून 1993

क्षेत्रवाद और भारतीय संघ से पृथक होने की प्रवृत्ति :

§1.8 द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की मांग :

क्षेत्रवाद के आन्दोलन के प्रबल बनाने में तमिलनाडु के द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दल की भूमिका अहम रही है। जून 1960 में द्रमुक ने मद्रास राज्य भारतीय संघ से विलग करने की इच्छा प्रकार की इस प्रकार की विघटनकारी मांगों के फलस्वरूप अक्टूबर 1963 में संविधान का 16वाँ संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इसमें यह व्यवस्था है कि भारत की अखंडता के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं कर सकेगा। इसके फलस्वरूप द्रमुक ने भारतीय संघ से अलग होने की मांग छोड़ दी और भारतीय संघ में स्वायत्त राज्य की मांग प्रस्तुत की।¹ सन् 1970 में द्रमुक के नेतृत्व में राज्य स्वयत्ता सम्मेलन आयोजित किया गया और राज्य स्वयत्तता की मांग की गई। राज्य के तत्कालीन मुख्य मंत्री करुणानिधि ने चुनौती दी कि यदि उनकी मांग स्वीकार नहीं की जाती तो वे जन आन्दोलन का सहारा लेंगे। एक बार तो उन्होंने पृथक ध्वज की मांग की क्षेत्रीय दल होने के कारण द्रमुक ने सदैव क्षेत्रीय भावना को भड़काया है। करुणानिधि ने तो यहाँ तक कह डाला कि राज्य नौकरियों में 80% स्थान स्थानीय लोगों को दिए जायेंगे।²

1- राय रामाश्रय एवं दास चंडी- कटिक्तर ऑफ इलेक्ट्रोल चेंज

हिन्दू वोकलो-जुलाई 22, 1968

2- फिर वहाँ,

§2§ अकाली दल की मांग :

मास्टर तारासिंह के नेतृत्व में पंजाब के सिक्ख सम्प्रदाय ने स्वाधीनता के पूर्व खालिस्तान की मांग की थी। स्वतंत्रता के बाद मास्टर तारा सिंह ने पृथक सिक्ख राज्य की मांग की। सन् 1950 से 1969 के बीच सिक्खों ने हिंसात्मक आन्दोलन के माध्यम से पंजाबो सूबे की मांग और 1 नवम्बर 1966 को पंजाब का विभाजन हुआ। इससे भी सिक्ख समुदाय संतुष्ट नहीं हुआ और सिक्खों के लिए सिक्ख राज्य की मांग की। अकाली दल के महासचिव डॉ० जगजोत सिंह ने सिक्ख जनमत को जागृत करने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा की अकाली दल के कई नेता में धमकी देने लगे कि भारतीय संघ के अन्तर्गत सिक्ख राज्य की स्वायत्तता नहीं दी गई तो जन-आन्दोलन का सहारा लेगे।¹

सिक्खों के लिए पृथक राज्य खालिस्तान की मांग वर्षों पुरानी है। खालसा पंथ का कहना है कि सिक्खों को धोखा-धड़ी से भारतीय गणतंत्र में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। पन्थ का ये भी कहना है कि हिन्दु बहुमत ने एकजुट होकर इस बात पर जोर देते हुए कि सिख धर्म हिन्दू धर्म का ही अंग है, सिख धर्म को बर्बाद करने की कोशिश की और उनकी पंजाबी भाषा को एक बोली मात्र घोषित करके और पंजाब को द्विभाषी राज्य बनाकर उनकी भाषा को नोचा दिखाने की कोशिश की।

खालिस्तान की यह मांग भारतीय सरकार के लिए
 §खासतौर से 1980-1985 की अवधि में § एक ~~एक~~ चिन्ता का विषय

बनकर उभरो है । पहले इसका समर्थन कुछ मुदखी भर उग्र तत्त्व करते करते थे , लेकिन अब प्रत्यक्ष या पुरोक्ष रूप से इसके समर्थन में राजनीतिक दल तो आ ही गए हैं सिखों को वे संस्थायें भी अपने मंच का उपयोग इस प्रकार की गतिविधियों के लिए करने लगे जो केवल गुरुद्वारा और शिक्षा संस्थाओं के प्रबंध से ताल्लुक रखती थीं ।

17 अक्टूबर 1973 को अकाली दल की कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसे आगे चलकर आनंदपुर साहिब-प्रस्ताव कहा गया ¹ में पृथक सिख राज्य की मांग की गई । इसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटो ने जिसका गुरुद्वारा और विशाल सम्पत्ति पर नियंत्रण है, इसी प्रकार का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया । इस पर अकाली दल लोंगोवाल गुट का खियंत्रण है। आनन्दपुर साहिब में शैक्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मंगासिंह टिल्लो ने कहा कि खालिस्तान की मांग सिखों के हितों के लिए की जा रही है । आजादी के बाद भारत में सिखों के साथ भेदभाव बरता गया है । इसलिए जरूरी है कि सिखों के लिए पृथक राज्य हो जहाँ उन्होंने का बोलबाला हो ।² बाद में पृथक सिख कौम के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की सह-सदस्यता प्राप्त करने के बारे में अकाली दल के तलवण्डो गुट ने प्रस्ताव पास कर दिया । वे भारत संघ के अंदर पृथक सिख राज्य चाहते हैं ।

पंजाब की राजनीतिक स्थिति यह है कि अकाली सत्ता से हटने के पश्चात १९८० दिन प्रतिदिन अपना प्रभाव खोते जा रहे हैं

1- राजस्थान पत्रिका उदयपुर 12 दिसम्बर, 1982 पृ० 4

2- दिनमान 25-31 अक्टूबर, 1981 पृ० 47

परन्तु 1985 विधान सभा चुनावों में उनको सरकार बन गई परन्तु बाद में आपसो फूट के कारण उन्हें सरकार से हाथ धोना पड़ा एवं 1987 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया । 1989 के पश्चात अकाली दल को अपने धार्मिक द्विविधा के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा है। 1992 में इसी द्विविधा के कारण अकाली दल ने विधान सभा चुनावों का बहिष्कार किया एवं पंजाब क्रि.सं.३३ को लोकप्रिय सरकार बनने जो कि खालिस्तान को मांग कर रहे वाले उग्रवादोतत्वों को सबक सिखाने में सफल रहो है ।¹

असम में मिजों को मांग :

असम राज्य के मिजो पहाड़ों जिलों के नेता भारतीय संघ से पृथक होने को लगातार मांग करते रहे हैं । वे एक स्वाधीन मिजो राज्य की स्थापना चाहते हैं । इसी ध्येय को पूर्ति के लिए मिजो राष्ट्रीय फ्रंट की स्थापना की गयी एवं मिजो लोगों ने सशस्त्र आन्दोलन का मार्ग अपनाया । सन् 1971 में मिजो नेता मिजो राज्य की मांग के प्रश्न पर जनमत संग्रह कराने की मांग करने लगे ।² मिजो लोगों को राजनीतिक आकांक्षाओं को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने 27 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 मिजोरम संघीय राज्य क्षेत्र की स्थापना की एवं 53वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया ।²

1- टाइम्स ऑफ इंडिया- 6 नवम्बर 1992

2- भारत के संविधान से ।

काश्मीर समस्या अलगाववाद का नासूर :

भारत का धूर उत्तरवर्ती सोमा प्रान्त जिसके पश्चिम में पाकिस्तान सोमा प्रदेश, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान उत्तर-पूर्व में चीन का तिनक्यांग प्रान्त तथा पूर्व में तिब्बत स्थित है । 1947 में भारत का विभाजन होने पर काश्मीर भारत एवं पाकिस्तान दोनों से अलग रहना चाहता था 20 अक्टूबर 1947 को उत्तर-पश्चिमी सोमांचलों के कबोले वालो ने नव स्थापित पाकिस्तान सरकार को साजिश एवं सहायता से इस पर आक्रमण कर दिया फलस्वरूप महाराजा हरिसिंह ने भारत से सहायता की मांग की। भारत ने वायुयानों द्वारा अपनी सेनाएं भेजकर श्रीनगर को आक्रमणकारियों के हाथ से बचा लिया इसके पश्चात 20 अक्टूबर 1947 में महाराजा हरिसिंह के हस्ताक्षर के बाद काश्मीर का भारत में विलय हो गया ।¹

काश्मीर में अलगाववाद का जन्म 1985 में शुरू हुआ जब फारूख अब्दुला मुख्य मंत्री थे । और तब से अब तक काश्मीर को भारत से अलग करने के लिए विदेशी ताकतों को शह पर सशास्त्र आन्दोलन जारी है। पिछले कुछ वर्षों से काश्मीर की आर्थिक हालत अलगाववादो आन्दोलन के कारण क्षीण हो गई है, पर्यटकों के न आने से 1989 से अब तक 600 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है । 1991 तक काश्मीर घाटी से लगभग 40 हजार परिवार अपने घर-बार छोड़कर भाग चुके हैं एवं जम्मू एवं दिल्ली में विस्थापित का जीवन गुजार रहे हैं । भारत के लिए ये समस्या नासूर साबित हुई है ।²

1- हिन्दुस्तान -पटना, 16 सितम्बर 1992

2- फिर वही,

क्षेत्रवाद एवं क्षेत्रीय राजनीति दलों का उदय :

स्वतंत्र भारत को राजनीति के आरम्भिक वर्षों से ही क्षेत्रीय दल सामाजिक तथा भावुकतापूर्ण सामुदायिक आधार पर काफी शक्तिशाली हो रहे हैं, इनमें से कुछ दल जैसे अकाली, द्रविड़ मुनेत्र कडगम, नेशनल काँग्रेस, तेलुगुदेशम, आसाम गण परिषद तथा नागालैंड तथा मणिपुर में आदिवासियों के संगठन काफी संगठित और शक्तिशाली हैं तथा राज्य विशेष को राजनीति को एक विशिष्ट रूप देने में सहायक है। कुछ अन्य दल समस्या विशेष को लेकर बनते आए हैं। विशेष रूप से 1967 से भारत में विकास की प्रक्रिया के परिणाम सामने, आने जन साधारण में असंतोष बढ़ने तथा राजनीति में अनेक नए वर्गों के सम्मिलित होने से इन वर्गों का उदय हुआ है जिनसे क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता रहा है।

भारत में प्रमुख रूप से निम्न प्रकार के क्षेत्रीय दल हैं। पहले प्रकार के वे क्षेत्रीय दल हैं जो वास्तव में जाति, धर्म क्षेत्र अथवा सामुदायिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन पर आधारित हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हैं, तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कडगम पंजाब में अकाली दल, जम्मू काश्मीर में नेशनल काँग्रेस, आन्ध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम, आसाम में असम गण परिषद, बिहार में झारखण्ड पाटों, महाराष्ट्र में शिवसेना उत्तर-पूर्व में कुछ आदिवासी संगठन हैं।¹

द्रमुक और अन्ना द्रमुक :

आधुनिक भारत के इतिहास में स्वतंत्रता प्राप्ति से चालीस वर्ष पूर्व और उसके चालीस वर्ष बाद सबसे लम्बी तथा गहरी जड़ का

का क्षेत्रीय आन्दोलन द्रविड़ियन आन्दोलन रहा है जो अपने स्वायत्तता और नई लोकतांत्रिक पहचान के लिए सदैव किसी न किसी रूप में सक्रिय रहा है । इन आठ दशकों में इसने कई रूप ग्रहण किए तथा फूट और विघटन के कई चरणों से गुजरा । इसे कभी आम सहमति या जनमत के निर्माण तो कभी संविद राजनीतिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा । कभी उसके उग्रवादो समर्थकों ने भारत से पृथक एक स्वतंत्र राज्य की मांग उठाई तो कभी उदारवादो समर्थकों ने भारतीय संघ के अन्तर्गत ही अत्यधिक स्वायत्तता की मांग की । इसका प्रभाव कभी अधिक था कभी अत्यन्त शिथिल एवं हास को स्थिति में था यह आन्दोलन ज्वार-भाटा की तरह प्रभावों रहा है किन्तु इसका उपद्रवो जल तमिलोयन चेतना को सदा प्रभावित करता रहा है । इससे जातीय संदर्भों में वर्गीय चेतना का विकास हुआ जिसके कारण शिक्षित अच्छे नौकरो पेशे तथा वैभव विलास वाले ब्राह्मणों और सोमा तक शोषित तथा गैर ब्राह्मण जातियों के बीच बैर-भाव को बढ़ावा मिला । इस पृष्ठ भूमि में गैर ब्राह्मण आन्दोलन का जन्म हुआ । इसका आह्वान सन् 1916 के गैर ब्राह्मण घीषणा पत्र में किया गया ।¹

सन् 1967 के आम चुनाव इसने भाषा और अपने स्वायत्तता के मुद्दे हिन्दो को जबरन थोपने तथा विरोध तथा योजना संस्थाधनों के संकुचित आवंटन संबंधो मुद्दे पर लड़ा, जिसमें इसे बहुत अधिक सफलता मिली तथा उस समय यह मद्रास राज्य में सत्तारूढ़ दल बन गया । लोकसभा में भी यह तीसरे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आया । इस चुनाव द्र. मु. क. ने कमिंस के विरोध में सभी विपक्षी दलो मुस्लिम लोग, स्वतंत्रपाटी, पो. एस. पो. साम्यवादियों के साथ समझौता किया।²

§1971§ पांचवे आम चुनाव में यह पुनः सत्ता में आ गई और मंत्रिपरिषद् के गठन में दल के विभिन्न घटकों को उचित स्थान देने का यथाशक्ति प्रयत्न किया गया फिर भी दल में उभरते हुए आंतरिक मतभेद अधिक दिन तक न दबे रह सके । 1972 में दल के कोषाध्यक्ष एम. पी. रामचन्द्रन § सिने कलाकार§ को निलम्बित कर दिया गया । फलस्वरूप 1972 में दल का विघटन कर दिया गया, 1972 में ही एक नये दल अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को स्थापना को गई, जिसे बाद में ए. आई, ए. डी, एम . के. कहा गया, 1977 में आल इंडिया अन्ना डी. एम. के. ने अपने सहयोगी दलों कांग्रेस और भा. क. पा. के चुनावो गठजोड़े ने लोकसभा को 20 सीटो में 18 सीटों पर विजय प्राप्त की, उसी वर्ष विधान सभा चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त करके सत्तारूढ़ दल बन गया । 1984 में अन्ना द्रमुक ने कांग्रेस के साथ समझौता कर संसद में 12 तथा 1985 के विधान सभा चुनाव में 234 सीटो में 133 स्थान प्राप्त कर सरकार बना ली । 1988 में एम. जी. रामचंद्रन की मृत्यु के पश्चात् यह दल बिखर गया । जनवरी 1989 के चुनाव में 15 वर्षों के बाद डी. एम. के सत्ता में आया । कुछ समान मतलो पर इन दोनों के विचार अलग-अलग है परन्तु दोनों ही भारतीय संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक विशिष्ट स्वायत्ता बनाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं ।¹

तेलुगू देसम पार्टी -

आन्ध्र विधान सभा में लगभग तीस वर्षों के कार्यकाल के दौरान सात आम चुनावों में सदैव कांग्रेस दल प्रभावो रहा ।

यद्यपि सन् 1967 में सर्वत्र कांग्रेस का भाग्य खतरे में पड़ गया था, फिर भी कांग्रेस इसका गढ़ था, किन्तु 1983 में जब एन. टो. रामाराव को नेतृत्व में नवोदित तेलंग देशम पार्टी बनो तो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का तख्ता पलट गया। तेलंग देशम पार्टी ने आंतरिक घटकवाद और विघटन से पीड़ित कांग्रेस को चुनाव में बुरी तरह पराजित किया।¹

तेलंग देशम केवल विधान सभा में बहुमत हासिल करने में कामयाब नहीं रहो, बल्कि इसने लोकसभा एवं राज्य सभा में भी अपने सदस्य निर्वाचित करके भेजे। वास्तव में 1984 में यह सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में उभरकर सामने आयो। तेलंग देशम पार्टी नाम से केवल क्षेत्रीयता को ब्रू आती थी इसलिए एन. टो. रामाराव ने एक बार अपने दल को सोमा को व्यापक बनाने के लिए दल का बदलकर भारत देशम कर दिया। तेलंग देशम पार्टी का व्यापक जनाधार है तथा इसका सांठनिक ढाँचा अत्यन्त सुदृढ़ है। आंध्र अत्यन्त सुदृढ़ है। आंध्र प्रदेश के तीनो उपक्षेत्रों समुद्रो किनारे का क्षेत्र, रायलसोमा तथा तेलंगाना के गांवो तक इसका गहरा प्रभाव है। तेलंग देशम पार्टी को आसानी से किसी वैचारिक श्रेणी जैसे वाम, दक्षिण या मध्यम से नहीं रख सकते। सन् 1989 के चुनाव में तेलंग देशम पार्टी कांग्रेस से बुरी तरह पराजित हुई और उसने विधान सभा में अपना बहुमत खो दिया।²

शिरोमणि अकाली दल :

स्वतंत्रता से पूर्व के राजनैतिक दृश्य में अकाली दल के

1- फिर वही, 129

2- फिर वही, पृ० 129

पूर्ववर्ती अस्तित्व को देखा जा सकता है। अकाली दल की स्थापना १९२१ में हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंजाब के दो प्रमुख दलों में कांग्रेस के साथ अकाली दल एक प्रमुख दल बन गया।

सन् १९६७ के विधान सभा चुनाव में अकाली दल कांग्रेस के बाद दूसरे बड़े दल के रूप में उभर कर आया, विधान सभा में किसी भी दल का बहुमत न होने के कारण अकाली दलों और कांग्रेसी दलों के साथ संविद सरकार बनायी। मास्टर तारा सिंह ने १९६७ चुनाव में धार्मिक एवं सांस्कृतिक तत्वों को प्रमुखता दी।

सन् १९६८ में मास्टर तारा सिंह के मृत्यु के पश्चात् सन् १९६९ के मध्यावधि चुनाव के दौरान अकालियों ने संत फतेह सिंह के नेतृत्व में अपने समूह का पुनर्गठन किया तथा पहले के सभी सांगठनिक पदाधिकारों को निरस्त कर दिए। उस दौरान यह पंजाब में कांग्रेस को अपेक्षा बड़े दल के रूप में अवतरित हुआ। अकाली दल ने जनसंघ के साथ मिलकर संविद सरकार बनायी। सन् १९७२ में वहाँ कांग्रेस पुनः सत्ता में आई, तथा १९७७ तक कांग्रेस सत्ता में थी। सन् १९७५ में अकालियों ने आपात काल के विरोध में आन्दोलन किया। इससे सन् १९७७ में जनता पार्टी के गठजोड़ से पुनः सत्ता प्राप्त करने में सफल हुई। सन् १९८० के चुनाव में अकाली दल के बीच गुटबाजों झगड़ों के कारण, ये पार्टी बुरी तरह पराजित हुई। अक्टूबर १९७३ में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित होने के बाद पंजाब की राजनीति में एक मोड़ आया, जिसमें सभी पंजाबी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर पंजाबी सूबे के विस्तार की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव में असोमिता क्षेत्रीयता को भी आती थी।

सन् 1983 में पंजाब की राजनीति में हिंसक मोड़ आया। पंजाब के कुछेक वर्गों ने "खालिस्तान" की माँग की आवाज उठाई। राजनीतिक हत्या, आगजनी, आतंकवाद प्रतिदिन की आम बात हो गई। उग्रवादियों ने स्वर्ण मंदिर और अकाल तख्त अहाते के आस-पास के सभी भवनों पर कब्जा कर लिया। जब समझौते के सभी प्रयास विफल हो गए तो सरकार ने सेना को 5 जून 1984 को आतंकवादियों को किलेबंदों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। जिसे आपरेशन ब्लू स्टार कहा गया।¹

आपरेशन ब्लू स्टार का सबसे बड़ा दुष्परिणाम-श्रीमती गाँधी की 31 अक्टूबर 1984 की हत्या हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की संत लोगोँ-वाल्ल के साथ समझौता हुआ फिर भी शान्ति बहाल न हो सकी। समझौते के। महीने के अन्दर लोगोँवाल की हत्या कर दी गई। समझौते के तहत पंजाब में चुनाव कराना था चुनाव में अकाली दल ने 117 सीटों में से 75 सीटें जीतकर सरकार बनाई। बरनाला राज्य के मुख्य मंत्री बनाये गये किन्तु आतंकवाद पर काबू न पा सकने के कारण मई 1987 में बरनाला की सरकार बरखास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। तब से लेकर 1992 तक आतंकवाद का दौर पंजाब में चलता रहा। 1992 में कांग्रेस की सरकार के मुख्य मंत्री बेअंत सिंह ने आतंकवाद पर काबू पा लिया है। पंजाब के चुनावों आँकड़ों से ये दिखता है कि अकाली दल को 1977 के जनता लहर 1985 के अलावा कभी भी 30% से अधिक मत नहीं मिले। इसका कारण दल की केवल एक ही धार्मिक संप्रदाय से अपोल और आर्थिक कार्यक्रम में वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व है। इस कारण पंजाब में रहने वाले हिन्दू, हरिजन और एक सौमा तक शहरों सिख अकाली दल को समर्थन नहीं देते। इसका दूसरा पहलू

यह है कि अकाली दल अपनी संकीर्णता के बावजूद अकेले विधान पालिका में बहुमत नहीं प्राप्त कर सकता ।¹

नेशनल काँग्रेस :

पराक्रमी स्वतंत्रता सेनानी शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के प्रयास से सन् 1938 में जम्मू-काश्मीर में नेशनल काँग्रेस की स्थापना हुई । स्वतंत्रता आन्दोलन में शेख अब्दुल्ला के साहस और बहादुरी के कारण उन्हें "शेरि कश्मीर" के नाम से जाना जाता है । बीसवीं शताब्दी के चौथे दशक में नेशनल काँग्रेस की गौरवशाली शुरुवात हुई । 1932 में विकसित होकर अखिल जम्मू और कश्मीर काँग्रेस के रूप में अवतरित हुआ । सन् 1948 में कश्मीर का भारत में विलय हुआ । शेख अब्दुल्ला के "नया कश्मीर" सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत वास्तविक भूमि सुधार कार्यक्रम शामिल था, जो कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए एक क्रांतिकारी कदम था । नेशनल काँग्रेस में आन्तरिक विरोध के कारण शेख अब्दुल्ला को नजर बंद होना पड़ा । 1968 में उन्हें बिना शर्त पुनः रिहा किया गया । दीर्घकालीन वार्ता के बाद एक समझौता हुआ । जिसे मार्च 1975 में संसद ने अनुमोदित किया । इससे नेशनल काँग्रेस में नया जीवन तथा स्फूर्ति पैदा हुई । सन् 1977 के चुनाव में नेशनल काँग्रेस 48 प्रतिशत सोट प्राप्त करके पुनः सत्ता में आ गई । नेशनल काँग्रेस के फारूख अब्दुल्ला काँग्रेस आई के साथ जबरजस्त टक्कर के बाद 1983 में मुख्यमंत्री बने । नेशनल काँग्रेस की 46 स्थान प्राप्त । 1984 लोकसभा चुनाव में 3 स्थान प्राप्त किए ।²

1- ब्रास आर पाल - रोजिजन लैंग्वेज एंड पालिटिक्स इन नार्थ

इंडिया न्यू दिल्ली पृष्ठ 373-75

2- फिर वही,

असम गण परिषद :

असम गण परिषद एक नये प्रकार का दल है, जिसका उदय असम के छात्रों और नौजवानों की गतिविधियों और सक्रियता के कारण हुआ। 1980 के पूर्वार्द्ध में असम के छात्रों द्वारा आल असम स्टूडेंट्स यूनियन के तत्वाधान में प्रारम्भ किए गए आन्दोलन के फलस्वरूप यह दल विकसित हुआ।¹

यह आन्दोलन असम में नागरिकता के प्रश्न पर केन्द्र सरकार की नीतियों के विरोध में था। नागरिकता को यह समस्या पश्चिम बंगाल और बंगलादेश से आए शरणार्थियों के कारण और जटिल हो गयी थी। इस दल ने क्षेत्रीय स्वायत्तता तथा समुच्चय विकास पर जोर दिया। असम गण परिषद ने अपना जोर तब दिखाया जब इसने लोकसभा के चुनाव 1985 में भाग लिया और 33.53 प्रतिशत मत प्राप्त करते हुए लोकसभा में आसाम के लिए निर्धारित 14 स्थानों में से 7 स्थान जीत लिए। 1985 में हुए राज्य विधान सभा चुनावों में इसे 12। सदस्य संख्या वाले सदन में 67 स्थान मिले और 3 अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन का आश्वासन मिला। मुख्यतः यह मध्यम मार्गी व सुधारवादी दल है जिसने राज्य के अनेक भागों में कांग्रेस को हटाकर सत्ता प्राप्त की। वर्ष 1989 के केन्द्रीय चुनाव के बाद नेशनल फ्रंट की सरकार बनने में इसकी विशिष्ट भूमिका रही।²

1- खान रशी उद्दोन -भारत में लोकतंत्र पृ० 135

2- फिर वही,

एक या दूसरे क्षेत्र में अपनी प्रभावी भूमिका निभाने वाले पुराने दलों में अखिल भारतीय मुस्लिम लोग का उल्लेख करना आवश्यक है। यह केवल नाम से ही स्वतन्त्रता पूर्व में मुस्लिम लोग को उत्तराधिकारी माना जाता है इसने मालाबार जैसे बहुल इलाके में अपना स्थाई निवर्चन आधार बना लिया है। यह केरल अनेक संविद सरकारों में भागीदार रहो है। तथा राष्ट्रीय स्तर पर इसने कांग्रेस का साथ दिया है। अपने कार्यक्रम और लक्ष्य में यह समुदाय अभिमुखी दल है। जनवरी के चुनावों में लोकसभा को ३ सीटें जीतो।²

वामपंथी दलों में रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी बहुत छोटी है, किन्तु केरल और पश्चिम बंगाल में इसका स्थाई निवर्चन समर्थन आधार है। सुभाष चन्द्र बोस को फरवर्ड ब्लाक, पश्चिम बंगाल में वामपंथी गुटों तथा यूनाइटेड फ्रंट का एक प्रमुख घटक बना रहा है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में पेजट्स पार्टी और वर्क्स पार्टी भी काफी गंभीरता के साथ क्रान्तिकारी और प्रगतिशील मसलों का समर्थन करती रहो है, जो महाराष्ट्र को राजनीति के नियमित प्रभाव के साथ लोकप्रिय हो गयो है। राष्ट्रीय चेतना के विकास में गोवा और दमन द्वीप को महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी को अग्रणी भूमिका बहुत ही लोकप्रिय है। इसने मंत्रिमंडल के निर्माण में एक संतुलित भूमिका अदा की है। उड़ोसा में गणतंत्र परिषद का पारंपरिक समर्थन आधार है। इसके प्रमुख समर्थक पिछड़ी जातियाँ और जनजातियाँ है।

भारत के विभिन्न भागों में अन्य क्षेत्रीय और स्थानीय दल हैं जिसमें कुछ को मान्यता प्राप्त है कुछ को नहीं कुछ सांस्कृतिक संगठन

होने का दावा करते हैं । किन्तु बहुदलीय टक्कर में सत्ता के संतुलन को मोड़ने में ये प्रभावो रूप से सक्षम हैं और कुछ जातियों के मत भंडार पर पुरा नियंत्रण रखते हैं । वे वैचारिक और राजनीतिक प्रतिबिम्ब को विभिन्न धाराओं से जुड़े होते हैं । दक्षिण पंथी संगठनों के बीच महाराष्ट्र के बम्बई, पुणे , औरंगाबाद में शिवसेना, उत्तर प्रदेश में अखिलभारतीय राम राज्य परिषद हिन्दु महासभा, विश्व हिन्दु परिषद, मुस्लिम मजलिस हैदराबाद ॥आन्ध्र प्रदेश में ॥ मजजिस-ई-इतिहाबुल तथा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में बहुजन समाज-वादो पार्टी इत्यादि संगठन या क्षेत्रीय दल हैं । रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया, के दो घटक हैं ये हरिजनो तथा अछूतों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा सत्ता के साथ गठजोड़े में प्रायः मध्य मार्गों और प्रगतिशील भूमिका निभाते हैं । अभी हाल में चौधरो महेन्द्र सिंह टिकैत का भारतीय किसान यूनियन ,शरद जोशी का खेत कारो संगठन नेता अभिमुख और जाति आधारित जनसंगठन के उदाहरण हैं । इन दोनों संगठनों ने धनी और मध्यम वर्ग के किसानों को समस्याओं या अपना ध्यान केन्द्रित किया है। ये निश्चित रूप से दबाव समूह को भूमिका अदा करते हैं । बहुदलीय स्थिति में संतुलित भूमिका अदा करने में सक्षम हैं ।¹

क्षेत्रीय दलों में एक प्रकार के वे क्षेत्रीय दल हैं जो कि कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं का गुट रहा है जो अधिक अल्पकालिक तथा कांग्रेस के साथ राजनैतिक सौदेबाजी करने के लिए अस्थायी उद्देश्य से बनाए गए थे । इनमें बंगला कांग्रेस, केरल कांग्रेस, उत्कल कांग्रेस, विशाल हरियाणा परिषद तथा तेलंगाना प्रभा समिति हैं।

क्षेत्रीय दलों में एक प्रकार के वे क्षेत्रीय दल हैं जिनका आधार जनजातीय रहा है। इस प्रकार के दलों के निर्माण में केन्द्र में जनजातीय राजनैतिक पहचान बनाने तथा केन्द्र से अत्यधिक छूट प्राप्त करने का उद्देश्य निहित होता है। इस प्रकार के दल आल पार्टी हिल लोडर्स कॉमिंस ई. जे. एच. एल. सी. ई को मांग पर 1971 में मेघालय को राज्य का दर्जा मिला।¹

बिहार के पाँच जन जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले झारखंड पार्टी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही "झारखंड" भारत के अन्दर ही एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। इसने चुनावों में भाग लिया तथा स्वयं अपने और अपने सहयोगी दलों के समर्थन के आधार का व्यापक विकास किया।

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में गोरखा लोग धीरे-धीरे सुव्यवस्थित संगठन में परिवर्तित हो गई। इसे पश्चिम बंगाल के अन्दर संविधानिक परिषद की मान्यता प्राप्त हो गई है जिसने गोरखा स्वायत्ता और पहचान के अपने मांग संबंधी समझौते के लिए अलग-प्रशासनिक मंच प्राप्त कर लिया है।

क्षेत्रवाद एवं केन्द्र राज्य सम्बन्ध -

संविधान के लागू होने के प्रारंभिक वर्षों में केन्द्र एवं राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण एवं सहयोगात्मक संबंध थे। वस्तुतः स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् के प्रारंभिक दशकों की भारतीय राजनैतिक नेहरू के प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं उनके द्वारा दिए गए राष्ट्रिय नेतृत्व से ओत-प्रोत थी

जिस कारण केन्द्र एवं राज्यों में तनाव की स्थिति नहीं आई एवं केन्द्र क्रमशः शक्तिशाली होता गया फिर भी 1955-56 में राज्यों के पुनर्गठन के दौरान भाषायी एवं सांस्कृतिक स्तरों पर क्षेत्रीयता की भावनाएँ उभरी जिनकी परिणति उन्हें आधारों पर राज्यों के पुनर्गठन के रूप में हुई ।

1965-71 की अवधि में न केवल केन्द्र में नेतृत्व परिवर्तन हुए बल्कि कई राज्यों में भी गैर-कांग्रेसी सरकारें क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व में या संयुक्त दलों के नेतृत्व में आई । केन्द्र में कांग्रेस एवं कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का होना भी केन्द्र राज्य संबंधों के बीच तनाव का कारण बना । लोकसभा में बहुमत के संदर्भ में केन्द्र सरकार के मजबूत नहीं होने से, एवं क्षेत्रीय स्तर पर दलों के उदय से केन्द्र की सत्ता में हास इस अवधि में परिलक्षित हुआ । इसी समय के दौरान केन्द्र द्वारा तमिलनाडु की चावल की आपूर्ति के प्रश्न पर अजय मुखर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में शासन के अन्तर्गत कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के प्रश्न पर तथा केरल में ड.एम.एस. नंबूदरिपो-पाद.सरकार द्वारा चीन से सीधे खाद्यान्न मँगाने वाली बात पर केन्द्र एवं राज्यों के बीच तनाव की स्थिति बढ़ी । नंबूदरिपोपाद ने केन्द्रीय अध्यादेश को श्रमिक विरोधी कहकर उसे मानने से इंकार कर दिया । सन् 1968 के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और नक्सल-वादी क्षेत्रों में होने वाले उपद्रवों से चिन्तित होकर केन्द्रीय सरकार ने उपद्रव ग्रस्त क्षेत्रों में हथियार रखने पर प्रतिबन्ध लगा दिए जिसे राज्य सरकार ने राज्य के मामले में केन्द्र के हस्तक्षेप की संज्ञा दी ।

1971 के चुनावों में कांग्रेस के भारी बहुमत से केन्द्र में आने एवं अधिकांश राज्यों में कांग्रेस शासन स्थापित होने से केन्द्र की

शक्तियों में विस्तार होना प्रारम्भ हुआ। इसी समय 1971 में तमिलनाडु सरकार ने "राजमन्नार समिति" की स्थापना केन्द्र राज्य संबंधों का अध्ययन कर इससे संबंधित सुझाव देने के लिए की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में राज्यों की वास्तविक स्वायत्तता प्रदान करने एवं इसके लिए उन्हें अधिक वित्तीय शक्तियाँ दिए जाने पर जोर दिया। जून 1975 में राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् केन्द्र की शक्तियों में अत्याधिक वृद्धि हुई। मुख्यमंत्रियों की शक्ति का हास होना प्रारम्भ हुआ। एवं केन्द्र के कठोर नियंत्रण के अन्तर्गत अब्दुल गफ्फर एवं बहुगुणा जैसे मुख्यमंत्रियों को कार्य करना पड़ा। 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा न्यायिक प्रशासन, परिवार नियोजन आदि विषयों को राज्य सूची से बाहर कर दिया गया एवं राज्यों से टेलीविजन, रेडियों आदि से संबंधित कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। कुल मिलाकर यह केन्द्र की शक्तियों में अपार वृद्धि का काल था।

1977 के चुनावों के केन्द्र में जनता पार्टी सत्ता में आई एवं शक्ति के विकेन्द्रोकरण की एक प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। पर अपनी आन्तरिक समस्याओं के कारण जनता पार्टी का शासन अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। 1980 के चुनावों में कांग्रेस के पुनः सत्ता में स्थापित होने एवं श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने से केन्द्रो-करण की प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ हो गई जो राजीव गांधी ने प्रधानमंत्रित्व काल तक चली।

1980 के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों के उदय जैसे आंध्रप्रदेश में तेलुगु देशम, कर्नाटक में जनता पार्टी,

असम में असम गण परिषद, हरियाणा में लोकदल & एवं गैर-कग्रेसी सरकारों को स्थापना से केन्द्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में नए प्रश्न उभरे । इन राज्यों में प्रारम्भ से ही गैर-कग्रेसी दलों को सभाएं आयोजित करना प्रारम्भ किया जिनमें केन्द्र-राज्य संबंधों पर पुनर्विचार को माँग की गई । आर्थिक साधनों पर केन्द्र के प्रभुत्व एवं राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप को केन्द्र की प्रवृत्ति को आलोचना करते हुए इन राज्यों ने राज्यों को वास्तविक अर्थों में स्वायत्तता दिए जाने एवं इसके लिए केन्द्र-राज्य संबंधों के पुनर्निर्धारण की माँग की ।

इसी पृष्ठभूमि में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जस्टिस सरकारिया को अध्यक्षता में केन्द्र-राज्य संबंधों के अध्ययन करने तथा उपयुक्त सुझाव देने के लिए एक आयोग का गठन किया ।

सरकारिया आयोग ने अपना रिपोर्ट 1988 में प्रकाशित की जिसमें हमने संविधान में अवस्थित मजबूत केन्द्र की अवधारणा को मानते हुए साथ में केन्द्र से राज्यों को ओर शक्ति-विकेन्द्रीकरण का मार्ग भी दिखाया जिससे केन्द्र एवं राज्यों के बीच सदभावपूर्ण एवं मधुर संबंध रहे तथा सहयोगात्मक संघीय व्यवस्था का आदर्श प्राप्त किया जा सके ।

सर्वप्रथम, सरकारिया आयोग का यह सुझाव है कि किसी राज्य में राज्यपाल को नियुक्ति से पूर्व उस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्पर्कित ली जाय । राज्यपाल एक ऐसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाय जिसको उस राज्य की स्थानीय राजनीति में कोई भूमिका न रहे हो । अपना कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् या पद त्याग

के पश्चात् राज्यपाल पुनः सक्रिय राजनीति में नहीं कूटें । जहाँ तक राज्यपाल द्वारा राज्य विधानपालिका के बिलों को सुरक्षित करने एवं उसे राष्ट्रपति के पास भेजने का प्रश्न है आयोग का सुझाव है कि इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाय तथा बिल को रोकने जाने का कारण भी राज्य विधान पालिका को बताया जाय ।

अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के संदर्भ में भी सरकारिया आयोग ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं । यहाँ कहा गया है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन अपरिहार्य स्थितियों में ही लागू किया जाय । साथ ही यह भी सुझाव दिया गया है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद तब तक उस राज्य की विधान सभा भंग न की जाय जब तक संसद द्वारा इसकी स्विकृति नहीं दी जाती है ।

राज्यों में, केन्द्र द्वारा सशस्त्र बल भेजे जाने के संबंध में आयोग का विचार है कि यह अनिवार्य नहीं कि हर परिस्थिति में राज्यों को सम्मति लेकर ही वहाँ सशस्त्र बल भेजे जायें पर यह वांछनीय है कि सशस्त्र बल भेजे जाने से पूर्व एवं किसी राज्य में अशांति क्षेत्र की घोषणा से पूर्व राज्यों से उचित रूप से सलाह मशविरा कर लिया जाय ।

अनुच्छेद 256 एवं 257 के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा राज्यों को भेजे गए प्रशासनिक निर्देशों की सवोच्चता स्वीकार करते हुए आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि अनुच्छेद 258 के अन्तर्गत केन्द्र के कार्यों को राज्यों की हस्तान्तरित किए जाने की प्रक्रिया को गति दी जाय । साथ ही आयोग ने संसद द्वारा नियम बनाए जाने का सुझाव दिया है जिससे स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं में नियमित चुनाव हो सके और

वे अपनी उचित भूमिका निभा सके ।

केन्द्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय एवं आर्थिक साधनों के वितरण से संबंधित सुझावों के अन्तर्गत आयोग ने करों के वितरण में संशोधन कर विचार रखा है जिससे राज्यों को स्थिति कर विभाजन को वर्तमान व्यवस्था में मजबूत हो । वित्त आयोग के पास विचारार्थ भेजे जाने वाले विषयों के संबंध में केन्द्र एवं राज्यों के बीच पहले हो विचार किया जाय इससे संबंधित सुझाव भी आयोग ने दिए हैं । इसके अतिरिक्त सरकारिया आयोग ने योजना आयोग तथा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को कार्यकुशलता में वृद्धि करने में संबंधित सुझाव दिए हैं जिसके अन्तर्गत योजना-निर्धारण एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में राज्यों को महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया है।¹

अंततः आयोग ने अन्तर्राज्यीय परिषदों की भूमिका को महत्व देते हुए § जो संविधान के अनुच्छेद 263 में उल्लिखित है § स्थायी रूप में इसके गठन का सुझाव दिया है । इसको अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी एवं सभी कैबिनेट मंत्री एवं राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे । यह परिषद सामाजिक-आर्थिक विकास के विभिन्न मुद्दों पर विचार करेगा एवं केन्द्र राज्यों के बीच सामान्य हितों तथा परस्पर सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा । आयोग ने जोनल काउंसिलों के महत्व को भी स्पष्ट करते हुए इनकी भूमिका पर जोर दिया है।

विगत कुछ वर्षों में भारतीय राजनैतिक परिदृश्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जिन्होंने निश्चित रूप से केन्द्र-राज्य संबंधों को भी प्रभावित किया है। 1989 के अन्तिम महानो में केन्द्र में कांग्रेस का शासन

समाप्त हो गया तथा भारतीय जनता पार्टी एवं वामपंथ द्वारा समर्थित जनता दल की सरकार वी. पी. सिंह के प्रधानमंत्रित्व में सत्ता में आई। उन स्थितियों में जबकि लोक सभा में किसी भी दल का बहुमत नहीं था तथा राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें थी, भारतीय राजनैतिक व्यवस्था के वास्तविक संघीय स्वरूप को पुनः स्थापित करने हेतु व्यापक विचार विमर्श प्रारम्भ हुआ। जून 1990 में वी. पी. सिंह सरकार ने स्थायी रूप से अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना को जैसा कि सरकारिया आयोग द्वारा सुझाव दिया गया था। इसी वर्ष केन्द्र में सत्ता परिवर्तन तथा कांग्रेस के पुनः सत्ता में आने तथा पुनः लोक सभा में किसी भी दल को प्रभावशाली बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों में कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि इस प्रवृत्ति का नकारात्मक पहलू यह रहा है कि कई राज्यों ने अपने अधिकारों को अप्रत्याशित एवं अशोभनीय तरीकों से व्यक्त किया है। उड़ीसा के वृद्ध नेता मुख्यमंत्री श्री बीजू पटनायक को यह धमकी कि यदि केन्द्र द्वारा राज्य को उनके इच्छित आर्थिक साधनों को नहीं दिया गया तो उड़ीसा को जनता भारत से अलग होने के लिए विद्रोह कर देगी, बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा खनिज संपदा पर अधिक रायल्टी की मांग मनवाने हेतु दिल्ली में धरना देने की धमकी तथा केन्द्र के परामर्श के विरुद्ध कावेरी जल विवाद के प्रश्न पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बागारप्पा और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता द्वारा असमझौतावादी रुख अपनाया जाना इसके उदाहरण हैं।

एक राजनोतिक संस्कृति के रूप में संघवाद न केवल शासन को प्रजातांत्रिक भावना को अभिव्यक्ति का सच्चा माध्यम रहा है। बल्कि यह भाषा, प्रजाति एवं संस्कृति को विविधताओं से युक्त विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाले देशों में एक संयोजक तत्व के रूप में अत्याधिक राजनोतिक महत्व का सिद्ध हुआ है।

इस प्रकार राज्यों द्वारा केन्द्र को नोति का विरोध करना, केन्द्र के निर्देशों का पालन न करना क्षेत्रोपतावादो नोति के प्रमाण है। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ अनेको संस्कृतियों, नोति रिवाजों का मिश्रण है वहाँ क्षेत्रोपतावादो तत्वो का हावो रहना स्वाभाविक हैं ।

अध्याय - ५

दल - बदल एवं संविद सरकारी की राजनीति

अध्याय - 4

दल-बदल एवं संविद सरकारी को राजनीति

दल- बदल :

दल प्रणाली और दल-बदल की घटनाओं का सम्बन्ध न्यूनदोष का रहा है। दल-बदल का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि प्राचीनतम दलों का अस्तित्व। ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि लोकतांत्रिक देशों में दल-बदल की घटनाएँ लगातार होती रही हैं। दल बदल की परिभाषा के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है। अंग्रेजों में इसको अभिव्यक्त करने के लिए क्रॉसिंग आफ फ्लोर्स कार्पेट क्रॉसिंग पार्लिटिक्स आफ ओपरचुनिस्म, पार्लिटिक्स आफ डिफेक्शन शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है।¹ यदि कोई विधायक या संसद- सदस्य अपने दल का परित्याग करके, 1- किसी विधायक का दल- विशेष के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ दे तथा किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो जाए 2- अपने दल को छोड़कर बाद में निर्दलीय हो जाए 3- आम-चुनावों में निर्दलीय रूप से निर्वाचित हो और बाद में किसी दल विशेष में शामिल हो जाए 4- अपने दल के को बुनियादीनोटियों का विरोध करते हुए सचेतकों के निर्देशों को न माने 5- यदि मिली- जुली सरकार के घटक राजनीतिक दलों के सदस्य एक घटक छोड़कर अन्य घटक दल में शामिल हो जाए अथवा विरोधी दलों में से एक दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं 6- राजनीतिक पदों और स्वार्थ साधना के लिए

1- डॉ० कश्यप सुभाषा, दल-बदल और राज्यों की राजनीति § मेरठ

1971 § से ।

दूसरे दल में शामिल हो जाए, तो उसे दल-बदल शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। अर्थात् किसी विधायक का अपने दल अथवा निर्दलीय मंच का परित्याग कर किसी अन्य दल में जा मिलना तथा दल बना लेना या निर्दलीय स्थिति अपना लेना अथवा अपने दल को सदस्यता त्यागे बिना ही बुनियादी मामलों पर सदन में उसके विरुद्ध मतदान करना दल-बदल कहलाता है।¹ श्री जय प्रकाश नारायण ने दल बदल को अपनी परिभाषा में कहा था, एक विधान मंडल के लिए निर्वाचित कोई भी सदस्य, जिसे किसी राजनैतिक दल का सुरक्षित चुनाव-चिह्न मिला था, यदि वह चुने जाने के बाद उस राजनैतिक दल से अपने संबंध तोड़ लेने या उसमें अपनी आस्था समाप्त करने की घोषणा करता है तो उसे दल-बदल ही समझा जाना चाहिए, बशर्ते उसको कार्यवाही सम्बद्ध पार्टियों के फैसले के अनुसार हो।

भारतीय राजनीति के सर्वाधिक प्रचलित प्रवृत्ति का नाम है "दल-बदल"। सामान्य भाषा में इसे केमा बदलना कहा जा सकता है। भारतीय राजनीति में दल-बदल की घटनाएँ स्वतंत्रता के पश्चात से ही सामने आती रही हैं। 1947 के निर्वाचनों के पश्चात् संयुक्त प्रान्त के मुख्य मंत्री गोविन्द बल्लभ पन्त ने मुस्लिम लोग के कुछ सदस्यों को कांग्रेस में शामिल होने का प्रलोभन दिया और दल-बदलुओं में से हाफिज मुहम्मद इब्राहिम को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया।² सन् 1950 में उत्तर प्रदेश के 23 विधायकों ने दल-बदलकर "जन कांग्रेस" नामक नए दल का गठन किया। अगस्त 1958 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के 98 सदस्यों ने

1- डॉ० कश्यप सुभाष- दल -बदल और राज्यों की राजनीति

2- फिर वही पृ० 123

मुख्यमंत्री डॉ० सम्पूर्णानन्द ने अविश्वास व्यक्त किया, जिसके कुछ समय बाद मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा। सन् 1962 में मद्रास के राज्यपाल श्री श्रीप्रकाश ने श्री राजगोपालाचारि को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। कांग्रेस के अल्पमत होते हुए भी जैसे ही राजा जो को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जैसे ही 16 विरोधी सदस्यों ने कांग्रेसी दल में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया और इस प्रकार कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया। 1957 से 1967 तक की अवधि में अनुसन्धानों के अनुसार 542 बार लोगों ने अपने दल-बदले। 1967 में चौथे आम चुनाव के प्रथम वर्ष में भारत में 430 बार लोगों के दल-बदलों का रिकार्ड कायम हुआ है। 1967 के चुनावों के बाद दल-बदलों के कारण 16 महानों के भीतर 26 राज्य सरकारें गिरी। हरियाणा के विधायक श्री गया लाल ने 15 दिन में ही तीन बार दल-बदल करके राजनीति में नया रिकार्ड कायम किया। उनको राजनीति के कारण ही राजनीति को "आया राम गया राम" नामक शब्द प्राप्त हुआ।¹

चतुर्थ आम चुनाव से पूर्व प्रजा समाजवादो पार्टी के नेता अशोक मेहता को योजना आयोग का अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस में स्थान दिया गया। इस घटना से अनेक विधायक और संसद सदस्य भी प्रजा समाजवादो दल को छोड़कर कांग्रेस में जा मिले। ऐसा माना जाता है कि चतुर्थ आम चुनाव से पूर्व दल-बदल की प्रक्रिया के द्वारा प्रजा समाजवादो दल ने ही अधिकतम विधायक खोए और उसके विधायक कांग्रेस दल

1- डॉ० कश्यप सुभाष - दल-बदल और राज्यों की राजनीति

मेरठ 1971 पृ० 121

में हो शामिल हुए । दल-बदल का हो परिणाम है कि प्रजा समाजवादो दल, जिनमें कांग्रेस का विकल्प बनने की क्षमता भी टूटता गया और देश में सुदृढ़ प्रतिपक्ष का निर्माण नहीं हो सका ।¹

संविदा सरकार से अभिप्राय :

संविदा सरकार से अभिप्राय है कि कई दलों को मिलो-जुलो मिश्रित सरकार का बनना । चुनाव से पूर्व कुछ दल मिलकर के एक निश्चित कार्यक्रम बना लेते हैं, उस निश्चित कार्यक्रम के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, चुनावों में आपसी समंजस्य तथा तालमेल स्थापित करते हैं, एक दूसरे के विस्मयप्रत्ययांशों को नहीं खड़ा करते और नेता द्वारा निर्मित मंत्रिमंडल में सभी दलों को यथोचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। कभी-कभी आम चुनावों के बाद भी संयुक्त सरकार का गठन किया जाता है । यदि सदन में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और दो से अधिक दल हैं तो ऐसी स्थिति में दो से अधिक दल मिलकर एक संयुक्त कार्यक्रम तैयार कर लेते हैं, सर्वसम्मति नेता चुन लेते हैं और मंत्रिमंडल में सभी दलों को प्रतिनिधित्व दे दिया जाता है । वस्तुतः संयुक्त सरकार मिलो-जुलो सरकार है जिसमें दलीय सिद्धान्तों और कार्यक्रमों को अतिवादिता को त्यागते हुए विभिन्न दल या गुट निश्चित कार्यक्रम तय कर लेते हैं और उस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सरकार में शामिल होते हैं ।² ऐसे मिलो जुलो सरकार का प्रयास पूर्व में हुआ है । अंग्रेज सरकार पं० नेहरू के नेतृत्व में जब अन्तरिम सरकार की स्थापना का प्रयत्न किया गया तो कांग्रेस के साथ मुस्लिम लोग को भी सम्मिलित करने की व्यवस्था की गई

1- अकेजनाल पेपर, डेवलपिंग सोसाइटी । 970

2- काश्यप एवं गुप्त, राजनीति कोष, पृ० 57

थी । यह केन्द्र से मिलो-जुलो सरकार बनाने की योजना थी । यद्यपि लोग ने पहले असहयोग की नीति अपनायी और बाद में मंत्रिमंडल में शामिल हुए । लियाकत अली खाँ को वित्त विभाग दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य विभागों का कार्य चलना बंद हो गया था । ¹

स्वतन्त्र योत्तर भारतीय राजनीति में कांग्रेस, जनसंघ, स्वतंत्र, मुस्लिम लोग, हिन्दू महासभा, समाजवादो दल साम्यवादो दल अस्तित्व में आए। किन्तु कांग्रेस ही सुसंगठित और प्रभावशाली दल बना रहा । अनेक वर्षों तक कांग्रेस के ही मंत्रिमंडल केन्द्र एवं राज्य में बने । चुनाव में कांग्रेस को नियम होते रहते, तथा दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की संख्या में लगातार वृद्धि होती रहती । तृतीय आम चुनाव के बाद देश में असंतोष बढ़ने लगा । ऐसे समय डॉ० राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसी दलों को मिलाने के प्रयास प्रारम्भ किए । डॉ० लोहिया का मत था, चुनावों में कांग्रेस को विषय का कारण गैर कांग्रेसी दलों में एकता का अभाव है । उनके मत आपस में विशाजित हो जाते और ऐसी स्थिति में कम मत प्राप्त करके भी कांग्रेस सत्ता में आ जाता । विरोधी दलों ने देखा कि संयुक्त मोर्चा बनाकर वे कांग्रेस को हरा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस को कभी भी 45% से अधिक वोट नहीं मिले । डॉ० लोहिया ने सत्ता पर एकाधिकार खत्म करने के लिए विरोधी दलों को एक साथ लाने की कोशिश की । कांग्रेस के विरोधी किसी भी तत्त्व से हाथ मिलाने की तैयार रहते थे । ²

सन् 1954 में द्रावण केरको चोन के मध्य में मध्यावधि चुनाव के बाद कांग्रेस अपना मंत्रिमंडल न बना सकी थी क्योंकि 148

1- सत्या सम. राय. भारतीय राष्ट्रवाद से ।

2- कोठारी रजनी- भारत में राजनीति से ।

सदस्योप विधान सभा में कांग्रेस को केवल 44 स्थान प्राप्त हो सके । कांग्रेस के समर्थन से प्रजा समाजवादो दल ने पद्म धान पिल्लई के नेतृत्व में अपना मंत्रिमण्डल बनाया था ।¹

चतुर्थ आम चुनाव के बाद संयुक्त मंत्रिमण्डलों को राजनीति को स्वतंत्रता के पश्चात के भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कहा जा सकता है। अनेक राज्यों में संयुक्त मंत्रिमंडलों का निर्माण हुआ और कांग्रेस के विकल्प के रूप में इन मिश्रित मंत्रिमंडलों को कांग्रेस दल के राजनीतिक एकाधिकार का एकमात्र वांछनीय विकल्प समझा गया । जिस तत्परता से युक्त मंत्रिमंडलों का निर्माण हुआ, उतनी ही तत्परता से राजनीति में पतन शुरू हो गया ।²

राज्यों में दल-बदल एवं संविद सरकारें

हरियाणा :

हरियाणा दल-बदल की प्रयोगशाला रहा है । 1967 ई० के आम चुनाव के फलस्वरूप विधान सभा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला । कुल 81 स्थानों में कांग्रेस को 48 स्थान मिले और श्री भगवत दयाल शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसी मंत्रिमंडल कागठन हुआ किन्तु एक ही सप्ताह बाद कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में पराजित हो गई । सत्तारूढ़ दल का उम्मीदवार तीन मतों से हार गया और असंतुष्ट कांग्रेसी विधायक कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने नवीन हरियाणा दल बना लिया । फिर कांग्रेस ने

1-फिर वही,

2- पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड कोयलिसन गवर्नमेंट डू नाट गो टूगेदर-
असोन प्रेम, पार्लिटिक्स नेशनल एंड इंटरनेशनल पृ० 16

नवीन हरियाणा दल के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चे को सरकार बनायो। जिसके मुख्यमंत्री राव वीरेन्द्र सिंह बने। इस तरह उन्हें दल - बदलने का पुरस्कार मिला। विधान सभा के आठ महोत्सवों में कांग्रेस दल के 31 विधायकों ने दल-बदल किया। एक विधायक ने पाँच बार, दो ने चार तीन ने तीन बार दल-बदल किया। नवम्बर 1967 में कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा दोनों के प्रतिनिधि चौबोस घंटे इसी चक्कर में रहते थे कि विधायकों को जैसे भी हो अपना ओर तोड़-मोड़ लें। कभी कांग्रेस का विधायक संयुक्त मोर्चे में जा मिलता था तो कभी संयुक्त मोर्चे का कांग्रेस में। जो विधायक दल बदलता था उसे मंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिव आदि कुछ तो बना हो दिया जाता था। एक जाट नेता श्री रमधोर सिंह ने हरियाणा की स्थिति को शोचनीय बताते हुए कहा कि यह शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री राव वीरेन्द्र सिंह विधायकों को खरीद रहे हैं और प्रत्येक विधायक को नगद दहेज देकर मंत्री पद का लालच दिया जा रहा है ताकि वे मुख्यमंत्री बने रह सकें।¹

1969 मई में हरियाणा में पुनः चुनाव हुए और कांग्रेस विजयी हुई 9 दिसम्बर 1968 को छः विरोधी सदस्य कांग्रेस में मिल गये।² इस प्रकार दल-बदल के कारण पंद्रह महोत्सवों को कम अवधि में दो बार चुनावों को मुसोबत का सामना करना पड़ा। छः विरोधी सदस्यों के कांग्रेस में मिलने से वंशीलाल मंत्रिमंडल और मजबूत होगया। जनवरी 1972 में इस प्रकार के दल-बदल के कारण मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को विधान सभा भंग करने का सुझाव दिया, नये चुनावों के परिणाम स्वरूप कांग्रेस को 52 स्थान प्राप्त हुए। एवं इस प्रकार संयुक्त मोर्चे का

1- कश्यप सुभाष - दल-बदल और राज्यों की राजनीति

पृष्ठ 205

2- नव भारत टाइम्स 10 दिसम्बर 1968

अन्त हो गया ।

संयुक्त मोर्चा मंत्रिमंडल के काल में किसानों तथा व्यापारियों ने भारी मुनाफा कमाया । अपने आठ महीने के शासन काल में कोई विकास कार्यक्रम हाथ में नहीं लिया और सारो को सारो योजनाएं कागज पर धरो-को धरो रह गई । मोर्चा मंत्रिमंडल को सारो शक्ति और समय अपने अस्तित्व के लिए लड़ते रहने में बाँत गया । राज्य के प्रशासन में अराजकता आ गई । प्रशासन में भ्रष्टाचार तथा विधायकों का हस्तक्षेप बढ़ गया । मोर्चा सरकार ने दल-बदल को प्रोत्साहन दिया । दल बदलों को मंत्री मद दिए गए और लोकतंत्र एक तमाशा बन गया ।¹

जून 1977 के हरियाणा विधान सभा के चुनावों में जनता को स्पष्ट बहुमत हुआ । किन्तु देवोलाल के नेतृत्व में बनो सरकार एक मिलो-जुली सरकार हो गई । जिसमें भारतीय लोकदल और जनसंघ प्रमुख घटक थे । इन घटकों में सत्ता संघर्ष चलता रहा, अंततः जनसंघ ने देवोलाल को अपदस्थ करके हो चैन को साँस ली । कांग्रेस फार डेमोक्रेसी घटक में भजन लाल मुख्य मंत्री बने । किन्तु जनता §एस§ को स्थापना के बाद सरकार अत्यंत में आ गई । 1980 के चुनावों में भजन लाल सहित जनता पार्टी ने अपने आपको कांग्रेस §इ§ को सरकार में परिवर्तित कर लिया ।

उत्तर प्रदेश :

उत्तर प्रदेश को भारत का लघु स्प कहा जाता है । चौथे आम चुनाव में कांग्रेस दल को विधान सभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका ।

5 मार्च 1967 को सभी विरोधी दलों ने संयुक्त विधायक दल का निर्माण किया और रामचन्द्र विकल को नेता चुना, 19 मार्च को ही संविद ने एक न्यूनतम कार्यक्रम स्वीकार किया। 12 मार्च को कांग्रेस विधान मंडल के नेता चन्द्रभान गुप्त को राज्यपाल ने मंत्रिमंडल बनाने का आमंत्रण दिया, लेकिन गुप्त का मंत्रिमंडल केवल 18 दिन चला। चरण सिंह ने 17 विधान सभा सदस्यों को साथ लेकर विरोधी पक्ष में स्थान ग्रहण किया। संविद ने चरण सिंह को सर्व सम्मति से अपना नेता निर्वाचित किया। लेकिन जल्द ही संविदा में दरार पड़नी शुरू हो गई। कांग्रेस एवं संविद में दल-बदल का स्लिफ-सिला जारी रहा। संतोषा ने चेतनावती को कि यदि छः माह में यदि लगान माफी का प्रश्न हल नहीं हुआ तो वह सरकार का साथ छोड़ देंगे। जनसंघ ने कहा कि यदि संविद के अन्य घटकों ने अपनी उपेक्षा की तो संघ को कार्य समिति अपने मंत्रियों को आदेश देगा कि वे अपने पद से त्याग पत्र दे दें। अंततः संतोषा तथा साम्यवादो दलों ने सरकार का साथ छोड़ दिया। चरण सिंह ने दो-तीन बार संविद समन्वय समिति को इस्तोफा दिया संविद ने चरण सिंह के स्थान पर राम चन्द्र विकल को अपना दूसरा नेता निर्वाचित किया। लेकिन संविद के अन्य घटकों ने उन्हें नेता मानने से इंकार कर दिया। राष्ट्रपति ने अनिश्चय की स्थिति में विधान सभा को भंग कर दिया विधान सभा भंग होने के साथ ही संविद भी विघटित हो गया। उसके कुछ घटकों, जनसंघ, भारतीय क्रांति दल ने स्वतंत्र रूप से मध्यावधि चुनाव में भाग लिया। कांग्रेस को 211 स्थान मिले। चन्द्रभान गुप्त मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश में संविदा सरकार के असफलता का कारण संविद के घटकों के बीच नो तिगत मतभेद थे। वस्तुतः संविद सरकार

अपने अन्तर्विरोधों के कारण हो समाप्त हो गई ।

1977 जून के उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला । भारतीय लोकदल घटक के रामनरेश यादव मुख्य-मंत्री बने । यह जनता सरकार यथार्थ में लोकदल और जनसंघ को मिली-जुली सरकार ही थी । धीरे-धीरे गुटों में मतभेद बढ़ता गया । रामनरेश यादव ने चार जनसंघी मंत्रियों को बरखास्त कर दिया तो जनसंघ घटक ने रामनरेश यादव को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर दिया । बाद में कांग्रेस फार डेमोक्रेसी घटक को प्राथमिकता देकर बनारसोदास मुख्यमंत्री बनाए गए । उनको सरकार कुछ दिनों के लिए कांग्रेस & & का समर्थन प्राप्त रहो । जनवरी 1980 के चुनाव के कांग्रेस आई को बहुमत प्राप्त हुआ । 1989 के निर्वाचन के पश्चात् कांग्रेस &आई& के अल्पमत आने के बाद जनता दल & जो कि लोकदल और जनता दल &अ& का संविद रूप था & के मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने ।

राजस्थान :

भारत के मानचित्र पर राजनीतिक इकाई के रूप में राजस्थान का आविर्भाव 1948-50 में देशी रियासतों के एकीकरण के फलस्वरूप हुआ चौथे आम चुनाव से पूर्व कांग्रेस को पराजित करने के लिए जनसंघ और स्वतंत्र दल ने आपस में चुनाव-समझौता कर लिया । कुम्भ राम आर्य को जनता पार्टी भी इस समझौते में शामिल हो गयो । 184 सदस्यीय विधान सभा में कांग्रेस को 80 स्थान प्राप्त हुए , 16 सदस्य निर्दलीय थे जिनमे से 11 जनता पार्टी से अस्तुष्ट कांग्रेसी थे । 1 मार्च 1967 को

जनसंघ स्वतंत्र, संसोपा और जनता पार्टी के विधायकों ने तथा 22 निर्दलीय विधायकों ने आपस में मिलकर महारावल लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया सुखाड़िया ने भी 94 विधायकों को सूची राज्यपाल को दो तथा मोर्चे ने 96 विधायकों को । राज्यपाल ने 21 विधायकों से मुलाकात की और यह निर्णय लिया कि कांग्रेस को हो बहुमत प्राप्त है । सुखाड़िया ने मंत्रिमंडल का गठन किया और उसके बाद संयुक्त मोर्चा टूटता गया और दल-बदल के कारण कांग्रेस दल की संख्या 110 हो गयी इस प्रकार राजस्थान में संयुक्त मोर्चे की सरकार सत्ता में आने से पूर्व ही टूट गयी । यह सच है कि संयुक्त मोर्चे की राजनीति को असफल बनाने में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण थी, लेकिन दल बदल में मोर्चे के नेता उतने कुशल साबित नहीं हुए, जितने, उनके प्रतिद्वन्द्वी नेता ।¹

जून 1977 के चुनाव के बाद राजस्थान विधान सभा में जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और जनसंघ घटक के मैरो-सिंह शेखावत मुख्य मंत्री बने ।² भारतीय लोकदल घटक के नेता महारावल लक्ष्मण सिंह और दौलत राम असंतुष्ट हुए थे । जिसके कारण जनसंघ एवं भारतीय लोकदल के बीच सत्ता की प्रतिस्पर्धा चलती रही लोकदल के गठन के बाद महारावल लक्ष्मण सिंह, मास्टर आदितेन्द्र प्रो० केदार आदि ने इस्तोफा देकर सरकार को अल्पमत में लाने की कोशिश की । चूंकि जनसंघ घटक के विधायकों की संख्या काफी अधिक थी, अतः सरकार को अपदस्थ नहीं किया जा सका, और फरवरी 1980 तक यह सरकार चलती रही ।

1- 16 मार्च 1967 नवभारत टाइम्स पृ० 3

2- राजस्थान पत्रिका उदयपुर, जून 1977

हस्तक्षेप करते हैं। इन कारणों से संविद नेता राजमाता ने भी त्यागपत्र दिया एवं मुख्यमंत्री ने भी। प्रसोपा ने तय किया संविद सरकार को समर्थन बंद कर दिया जाय।

जनसंघ को मांग एवं नरेश के पक्ष में गोंविंद नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। इस बीच सिंह के साथ 20 सदस्य कांग्रेस से जा मिले और श्यामाचरण शुक्ल के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार ने शपथ ग्रहण की। जब कांग्रेस के दल-बदल संविद सरकार का मजा-लूटकर पुनः कांग्रेस में मिल गए तो संविद सरकार का अस्तित्व समाप्त हो गया संविद सरकार के पतन का मुख्य कारण उसके छंटकों में एकता का अभाव और मुख्यमंत्री को दुर्बल स्थिति थी।¹

जून 1977 में मध्य प्रदेश विधान सभा चुनावों में जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। जनता पार्टी को यह सरकार मोटे रूप से जनसंघ और सोशलिस्ट छंटकों को मिली—जुली सरकार हो थी। दोनों छंटकों में आए दिन तनाव एवं मतभेद उत्पन्न होते रहे सोशलिस्ट छंटकों ने मुख्यमंत्री वीरेन्द्र कुमार सकलेश का लगातार विरोध किया। विरोध की स्थिति यहाँ तक पहुँच गयी कि 1980 के लोक सभा चुनाव के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। फरवरी 1980 तक यह सरकार इसलिए चलती रही क्योंकि जनसंघ की सदन में स्थिति मजबूत थी।

केरल :

केरल में प्रथम आम चुनाव के बाद से ही संविद सरकारें बनती रहीं। चतुर्थ आम चुनाव के बाद केरल में बामपंथी दलों तथा

मुस्लिम लोग का संयुक्त मोर्चा बना । 133 सदस्यीय विधान सभा में मार्क्सवादो साम्यवादो दल को 52 तथा साम्यवादो दल को 19 स्थान मिले । नम्बूदरो पाद के नेतृत्व में वामपंथी मोर्चे को सरकार बनो । लेकिन सरकार को नीतियों का क्रियान्वयन न हो पाने खाद्य समस्या के विवट हो जाने, मार्क्सवादो -साम्यवादो दल द्वारा "गोपाल सेना" गठित करके लोगों को सताये जाने के कारण संविद सरकार में मतभेद बढ़ता गया एवं 1969 में नम्बूदरोपाद ने इस्तोफा दे दिया । अच्युत मेनन के नेतृत्व में साम्यवादो दल का नया मंत्रिमंडल बना जो केवल 9 महीने चला । 17 सितम्बर 1970 को राज्य में पुनः चुनाव हुए राज्य के 21 दलों ने तीन मोर्चे बनाए । प्रथम मोर्चे में प्रजा समाजवादो दल, कांग्रेस समाजवादो दल, के.आई.पो. दल थे इसका नेतृत्व मार्क्सवादो साम्यवादो दल ने किया । दूसरे मोर्चे का नेतृत्व साम्यवादो दल ने किया जिसमें आर.एस.पो., पो.एस.पो. तथा मुस्लिम लोग थे, तीसरे मोर्चे में कांग्रेस, जनसंघ, स्वतंत्र, द्रमुक इत्यादि दल थे । चुनावों के बाद कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरा उसे 133 में 32 स्थान सदन में मिले ।¹ अच्युत मेनन के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बना । जिसमें कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया । जुलाई 1975 को केन्द्रीय सरकार ने इस मंत्रिमंडल का कार्यक्रम अनु 172 के अनुसार छः माह के लिए बढ़ा दिया बाद में कांग्रेस भी भी सरकार में शामिल हो गई ।

मार्च 1977 के चुनाव काफिरल को राजनीति कर कोई विशेष प्रभाव नही पड़ा, लोकसभा एवं विधान सभा दानो में सत्ताधारी संयुक्त मोर्चे की सफलता मिली । मुख्य बात यह रही कि कांग्रेस को

पहले के मुकाबले अधिक सोंठें मिलीं । सबसे बड़े विधायक दल के नेता करुणा करन, मुख्यमंत्री बने । राजन मामले के राजनीतिक विवाद के कारण करुणाकरन को इस्तीफा देना पड़ा, फिर ए.के. एंटीनी मुख्यमंत्री बने । बाद में कांग्रेस विभोजन के बाद एंटीनी को इस्तीफा देना पड़ा । इसके बाद साम्यवादो दल के पो.के. वासुदेवन मुख्य मंत्री बने, परन्तु मोर्चे में मतभेद के कारण उन्हें भी कुरसी त्यागनी पड़ी । 12 अक्टूबर 1979 को मुस्लिम लोग के सौ एव मोहम्मद कोमा के तीन सदस्योय मंत्री मंडल ने शपथ ली, लेकिन सदन में बहुमति सिद्ध न हो पाने के कारण कोमा ने त्याग पत्र दे दिया । 30 नवम्बर 1979 को राज्य विधान सभा भंग कर दो गई एवं 4 दिसम्बर 1979 को यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया । 20 जनवरी 1980 को विधान सभा चुनाव हुए । मार्क्स-वादो साम्यवादो दल के सात सदस्योय मोर्चे को 140 में से 93 स्थान मिले । ई. के नयनार मुख्यमंत्री बने । लेकिन 16 अक्टूबर 1981 को ए.के. एण्टनी गुट काँग्रेस शरद तथा बाद में 9 सदस्योय मर्णिसुट के सरकार से समर्थन वापस लेने के कारण नयनार सरकार अल्पमत में आ गई एवं 20 अक्टूबर 1981 राज्य में छठो बार राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया । इसके पश्चात् काँग्रेस ईई नेता करुणाकरन के नेतृत्व में एक अन्य मिली-जुली सरकार ने सत्ता संभाली, किन्तु केरल काँग्रेस के विधायक लोत्वन नेबाइन के सरकारी पक्ष से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेने से सरकार अल्पमत में आ गई । मई 1982 के मध्यावधि चुनाव में काँग्रेस ईई के नेतृत्व वाले लोकतांत्रिक मोर्चे को 140 में से 77 स्थान मिले । करुणाकरन मंत्रिमंडल को सरकार बनो इस सरकार को स्थिति भी घटकी

के आपसी तालमेल के कारण डगमगाती रहो । इस प्रकार केरल में अच्युत मेनन को सरकार के अलावा बनो संयुक्त मोर्चे को सरकारे ज्यादा दिन तक न चल पायो ।

पश्चिम बंगाल :

चतुर्थ आम चुनाव से पूर्व पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सरकार लगातार बन्ती रहो, चतुर्थ आम चुनाव में कांग्रेस को एक बड़ी पराजय का मुह देखना पड़ा । 25 फरवरी 1967 को संयुक्त वामपंथी मोर्चे और जनवादी संयुक्त वामपंथी मोर्चे के कुछ गुटों ने मिलकर एक संयुक्त लोक-तन्त्रात्मक मोर्चे की स्थापना की । बंगाल कांग्रेस जो कि कांग्रेस के दल-बदल नेताओं को पाटी थी, के अजय मुखर्जी इस मोर्चे के नेता बने । लेकिन वामपंथी साम्यवादियों को राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कारवाहियों नक्सलवादो विद्रोह, धराव, हड़तालों की वजह से मोर्चे में दरार पड़ गयी । बंगाल कांग्रेस के अनुसूचित जाति के 18 विधायकों ने अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को मंत्री मंडल में न शामिल किए जाने के प्रश्न पर मोर्चे से अलग होने की धमकी दी । मंत्रीमंडल की बैठक में मुख्य मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री ज्योतिबसु के बीच झड़प हो गयी । डॉ० पी. सी. घोष के संयुक्त मोर्चा मंत्रीमंडल से इस्तीफा दे देने के कारण तथा 17 अन्य विधायकों को मोर्चा छोड़ देने के कारण संयुक्त मोर्चा सरकार अल्पमत में आ गई । राज्यपाल ने संयुक्त मोर्चा सरकार को बरखास्त कर दिया । डॉ० घोष ने कांग्रेस दल के सहयोग से युक्त मोर्चे से दल बदलकर अलग हुए सदस्यों को लेकर एक अल्पसंख्यक मंत्रीमंडल बना लिया । बाद में कुछ कांग्रेसी भी सरकार में शामिल हो

गए , लेकिन मंत्रिपरिषद के वितरण के कारण कांग्रेस सदस्यों में मतभेद हो गया । ऐसे स्थिति में राज्यपाल ने विधान सभा भंगकर राष्ट्रपति शासन को सिफारिश की ।

फरवरी 1969 में विधान सभा के मध्यावधि चुनाव हुए 12 दलों के संयुक्त मोर्चे 280 में से 214 स्थान मिले अजय मुखर्जी के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चे ने सरकार बनायी । इसके बाद से ही राज्य में नक्सलवादीयों की गतिविधियाँ बढ़ गई । मुख्यमंत्री तथा बंगला कांग्रेस ने राज्य से अव्यवस्था समाप्त करने के लिए 1 दिसम्बर 1969 को सत्याग्रह शुरू कर दिया ।¹ अजय मुखर्जी एवं ज्योतिवसु के बीच का मतभेद शिखर तक पहुँच गया। विधान सभा में मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया कि मोर्चा सरकार ने बहुत सारे असम्यक्तापूर्ण कार्य किए हैं। अराजकता, हिंसा के कारण मुख्यमंत्री ने स्वयं त्याग पत्र दे दिया । राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और संयुक्त मोर्चा अपने ही मतभेदों से टूट गया।

मार्च 1971 के चुनाव के पश्चात् अजय मुखर्जी कांग्रेस के साथ मिलकर लोकतंत्रात्मक संयुक्त मोर्चे का गठन करते हैं । लेकिन बंगला देश के संदर्भ को लेकर पुनः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। मार्च 1972 में पुनः विधान सभा चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला । सिद्धार्थोंकररे के नेतृत्व में 1975 के आपातकाल तक कांग्रेस सरकार चलती रही जून 1977 के चुनाव के बाद कांग्रेस का स्थान मार्क्सवादो साम्यवादो दल ने ले लिया । साम्यवादो दल को 244 में 177 स्थान मिले । 1979 से लेकर 1984 तक लगातार तीन बार मार्क्सवादो साम्यवादो दल को ज्योति वसु की सरकार चल रही है। पहले स्पष्ट बहुमत न होने के कारण सरकारें असफल रही, लेकिन 1977

के पश्चात् स्पष्ट बहुमत मिलने से संयुक्त मोर्चे को सरकार निर्विघ्न चलते चलो आ रहो है ।

बिहार :

चतुर्थ आम चुनाव में बिहार में कांग्रेस को पराजय हुई । विधान सभा में गैर कांग्रेसी दलों में संतोषा के सदस्य सबसे अधिक थे । उसने गैर कांग्रेसी दलों के साथ गठजोड़ किया और 31 सूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर संविद सरकार का निर्माण किया । इस संविद में संतोषा, प्रतोषा, जनसंघ, जन क्रांति दल, साम्यवादो दल शामिल हुए । महा-माया प्रसाद सिन्हा को नेता तथा कपूरो ठाकुर को उप नेता चुना गया । राज्यपाल ने सिन्हा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया ।

दल-बदल के द्वारा संविद सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश की गई । मुख्य मंत्री ने मोर्चे को सरकार के लिए कुछ कांग्रेसी विधायकों को वचन दिया कि वे कांग्रेस को छोड़कर यदि मोर्चे में शामिल हो जाए तो उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा । संयुक्त मोर्चे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने से सिन्हा ने अपने मंत्रिमंडल का त्याग पत्र दे दिया ।

इसके बाद वो पो मंडल के नेतृत्व में 47 दिन का अत्यकालिक मंत्रिमंडल बना जिसे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था । लेकिन इसके विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया । श्री मोला पासवान के नेतृत्व में 95 दिन के लिए एक मंत्रिमंडल बना, लेकिन अंततः इसे भी दल-बदल के कारण इस्तीफा देना पड़ा एवं राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया ।¹

फरवरी 1969 में मध्यावधि चुनाव हुए इसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिल सका कांग्रेस दल के नेता सरदार हरिहर सिंह ने सरकार बनायी लेकिन जल्द ही दल-बदल के कारण बजट मांगो पर उनकी सरकार गिर गयी, इसके बाद उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इसके पश्चात् विपक्ष के नेता भोला पासवान ने संयुक्त मोर्चा मंत्रिमंडल बनाया, लेकिन नाटकीय ढंग से 34 सदस्यीय जनसंघ ने पासवान सरकार से 7 दिन बाद ही समर्थन वापस ले लिया। राज्यपाल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने को सिफारिश की लेकिन विधान सभा को भंग नहीं किया। इस प्रकार बिहार में मार्च 1967 से अगस्त 1969 के बीच दल-बदल के कारण छः मुख्यमंत्री बदले। ये सभी मुख्यमंत्री स्वयं दल-बदल थे। 1967-69 में सौ विधायकों ने लगभग दो बार कुछ ने चार बार दल बदला कुल मिलाकर दल-बदल की घटनाएं 200 से अधिक रहीं। जो सरकार सबसे अधिक दिन चली उसकी अवधि थी 9 महीने 25 दिन।¹ अक्टूबर-नवम्बर 1969 में कांग्रेस विभाजन के श्री दरोगा प्रसाद राय को कांग्रेस का नेता चुना गया। राय ने राज्यपाल से संयुक्त मोर्चा सरकार बनाने की प्रार्थना की। साम्यवादो दल, प्र.सो.पा., भा.क्रा.द, शोषित दल झारखण्ड पार्टी से विचार करने के बाद 35 सूत्रीय कार्यक्रम बना और एक बार फिर 16 फरवरी 1970 को संयुक्त मोर्चा सरकार कायम कर दी गई। 26 मई 1970 को लोकतांत्रिक कांग्रेस गुट अलग हो गया व प्र.सो.पा. के कुछ सदस्य भी अलग हो गए। 10 अक्टूबर 1970 को कांग्रेस के दो कुछ विधायकों राय के विरुद्ध शिकायत पेश की और नेता बदलो अभियान शुरू कर दिया। 18 दिसम्बर 1970 को विधान सभा में राय सरकार पराजित होगई और कपूरी ठाकुर के नेतृत्व में नई संविद

1- डॉ० कल्याण सुभाष - दल-बदल और राज्यों की राजनीति ४ मेरठ

सरकार बन गई ।

कंग्रेस, साम्यवादी, प्र.सो.पा., भा. का. द. तथा झारखंड पार्टी ने मिलकर प्रगतिवादी विधायक फ्रंट, बनाया तथा कर्पूरो ठाकुर के संविद सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास करने लगे । परन्तु 1 जून 1971 को कर्पूरो ठाकुर ने त्याग पत्र दे दिया ।¹ इसके बाद प्रगतिवादी विधायक फ्रंट के नेता ने राज्यापाल के आमंत्रण पर सरकार बना ली लेकिन यह सरकार भी अधिक न चल सकी । राष्ट्रपति को विधान सभा भंग करनी पड़ी । मार्च 1972 के चुनाव में कंग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ ।

जून 1977 के विधान सभा चुनावों में जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, लोकदल, घटक के कर्पूरो ठाकुर मुख्यमंत्री बने । उत्तर प्रदेश में जनसंघ घटक को मंत्रिमंडल में न शामिल किए जाने के फलस्वरूप बिहार में जनसंघ ने लोकदल के मंत्रिमंडल को सत्ता से हटाने के लिए कोई कसर बाकी न रखी । राम सुन्दर दास मुख्यमंत्री बने । राष्ट्रीय स्तर पर जनता पार्टी का विभाजन होने के बाद जनसंघ का ये सत्ताधारी घटक कंग्रेस² के समर्थन से सत्ता से बना रहा ।

उड़ीसा -

चतुर्थ आम चुनाव में उड़ीसा विधान सभा में से 140 सदस्यों में 49 स्थान स्वतंत्र दल, 30 कंग्रेस, 26 जन कंग्रेस, 7 सो.पो.आई. 2 सं. सो. पा. तथा 1 स्थान सो.पो.एम. को मिला । स्वतंत्र दल के नेता आर. एन. सिंह देव ने 8 मार्च 1967 को जन कंग्रेस के समर्थन से संविद सरकार का गठन किया।² दोनों दल ने संयुक्त रूप से चुनाव

1- फिर वही,

3- 9 मार्च 1967 नवभारत टाइम्स पृष्ठ 1 ।

लड़ा था एवं 75 स्थान दोनों ने मिलकर प्राप्त किया था । यह सरकार जनवरी 1971 तक अच्छी तरह काम करती रही । जनवरी 1971 में जन कांग्रेस ने स्वतंत्र दल के मंत्रियों के भ्रष्टाचार के कारण समर्थन वापस ले लिया । सदन में अल्पमत होने से 9 जनवरी 1971 को मुख्य मंत्री ने त्याग पत्र दे दिया ।¹ 5 मार्च 1971 को चुनाव हुए जिसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला उत्कल कांग्रेस ने स्वतंत्र पार्टी, झारखण्ड पार्टी तथा निर्दलीय सदस्यों को साथ लेकर संयुक्त मोर्चा बनाया जिसके नेता विश्वनाथ दास चुने गए । 3 अप्रैल 1972 को नई सरकार अस्तित्व में आयी । शीघ्र ही उत्कल कांग्रेस सरकार से हट गयी, जून 1972 नन्दनी सत्यधी के नेतृत्व में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना । बोजू पटनायक ने प्रगति दल बनाकर बगावत कर दो सत्यधी सरकार के कई विधायक भी अलग हो गए, जिसके कारण सत्यधी सरकार ने बहुमत खो दिया एवं मंत्रिमण्डल ने इस्तीफा दे दिया । राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया ।

1974 में उड़ीसा फिर चुनाव हुए । भारतीय साम्यवादी दल ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव समझौता किया तथा कांग्रेस को सरकार बनाने की मदद की । भारतीय साम्यवादी नन्दनी सत्यधी सरकार में शामिल न होकर बाहर से समर्थन दिया । बाद में कुछ निर्दलीय सदस्यों के कांग्रेस में मिल जाने के कारण सरकार टिकाऊ हो गयी ।

गुजरात :

गुजरात में कांग्रेस को सरकार मार्च 1974 में राष्ट्रपति

शासन लागू होने तक चलो आ रहो थे । पहली बार जून 1975 में हुए गुजरात विधान सभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला । वस्तुतः गुजरात का यह चुनाव तीन राजनीतिक शक्तियों के हार्द-गिर्द घूमता रहा -इन्दिरा गाँधी, मुरार जी देशाई और चिन्न भाई पटेल कांग्रेस को 182 सदस्योप विधान सभा में 75 स्थान प्राप्त हुए, जनता मोर्चे को 86 स्थान जिसमें संगठन कांग्रेस 56, जनसंघ को 18, भारतीय लोकदल को दो सो पा को 21 एवं मोर्चे द्वारा समर्थित दो निर्दलीय भी चुनाव जीत गये, तथा किसान मजदूर लोकपक्ष को 12 स्थान मिले ।

गुजरात में जनता मोर्चा को सरकार पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी । गैर साम्यवादो दलों ने जनता मोर्चे का निर्माण कर सत्ताधारो कांग्रेस के लिए विकल्प तैयार करने को जोरदार पहल की । वैसे तो जनता मोर्चे को स्पष्ट बहुमत इस चुनाव में नहीं मिला , किन्तु किसान मजदूर लोकपक्ष के बाहरी समर्थन से मोर्चे ने सरकार बनायी । लेकिन दल-बदल के कारण 9 महीने में ही इस सरकार का अंत हो गया । मार्च 1979 में दल-बदल के फलस्वरूप मोर्चे को सरकार फिर बनी ।²

जनता मोर्चे में पाँच दल शामिल थे , संगठन कांग्रेस, जनसंघ सोशलिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय मजदूर पार्टी और भारतीय लोकदल , लेकिन शुरू से ही वास्तविक सत्ता जनसंघ के हाथों में थी । मार्च 1977 के लोकसभा चुनावो के बाद जनता मोर्चे को सरकार जनता पार्टी के नाम से जानी जाने लगी । जनता पार्टी के केन्द्रीय स्तर पर उभरते घटकवाद का प्रभाव बाबू भाई पटेल के मंत्रिमंडल पर भी पड़ने लगा । यदा-कदा

1- टाइम्स व्यूरो ।

2- फिर वही,

जनसंघ घटक एवं संगठन कांग्रेस के मध्य रस्सा-कस्सा होता रहता था । फिर भी यह संविद सरकार 1980 तक सफलता पूर्वक कार्य करती रही ।

केन्द्र में मिली जुली सरकार को राजनीति एवं दल-बदल :

मार्च 1977 के चुनावों से भारतीय राजनीति को एक नया आयाम मिला । चार विरोधी दलों के संगठन कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी ने आपसमें समझौता करके तथा अपनी पार्टी को समाप्त करके जनता पार्टी नाम से नये पार्टी का गठन किया । बाद में जगजोवन राम को कांग्रेस फार डेमो-क्रेसी का भी जनता पार्टी में विलय हो गया । 24 मार्च 1977 को मुरार जो देशाई के नेतृत्व में जनता पार्टी को केन्द्र में सरकार बनी जो कि मात्र 28 महीनों तक ही चल पाई । ये सरकार वस्तुतः संविद सरकार ही थी जिसके ऊपर जनता पार्टी का आवरण था । जनता पार्टी के पाँच छः घटक अधिकतम लाभ एवं अपना वर्चस्व पार्टी पर अधिक रहे, के लिए आपस में मतभेद लगातार चलता रहे । प्रधान मंत्री के पद पर मोरार जो देशाई एवं पार्टी अध्यक्ष के पद पर चन्द्रशेखर का चयन भी राजनैतिक सौदेबाजी का परिणाम था । 1977 के चुनावों में जनता पार्टी के चुने सदस्यों की संख्या 301 थी । घटकों के चुने सदस्यों की संख्या के आधार पर ये अनुपात था ।¹

1- 31 मार्च 1977 टाइम्स ऑफ इंडिया पृष्ठ 3

बिषय - 1977 लोकसभा में जनता पार्टी में घटकों का प्रतिनिधित्व तथा मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या आंक डे परिशिष्ट में देखें ।

शुरू के कुछ दिनों के बाद से मतभेद उभर कर सामने आने लगे । क्योंकि एक तो चरण सिंह एवं जगजीवन राम दोनों को देशाई को अपदस्थ करके प्रधानमंत्रों बनने का सपना संजोए हुए थे दूसरे जनसंघ एवं लोकदल को अपने वर्चस्व को लेकर छोटाकंसी । अंततः 843 दिनों के बाद इस सरकार का मुरार जो देशाई के त्यागपत्र के साथ अन्त हुआ । 29 जुलाई 1979 को जेम्स एस तथा कंग्रेस अर्से ने चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में संविदा सरकार बनायी । बाद में इसमें अन्नाद्रमुक भी शामिल हो गया, धीरे-धीरे एक गुट पुनः इस सरकार से अलग होगया । यह सरकार संसद का विश्वास अर्जित नहीं कर सकी । 20 अगस्त को चरण सिंह के त्यागपत्र एवं राष्ट्रपति से मध्यावधि चुनाव कराने की सिफारिश के साथ इस संविदा सरकार का अन्त हो गया ।

नौवो लोक सभा के निर्वाचन के पश्चात् राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार:

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को लम्बी पृष्ठभूमि में सन् 1989 में एक नया एवं महत्वपूर्ण विकास हुआ । मार्च 1989 में चार राजनीतिक संगठनों ने नया दल बनाने का निश्चय किया । वे चार संगठन थे - चन्द्रशेखर मधु दंडवते, रामकृष्ण हेगड़े का बहुसंख्यक गुट को जनता पार्टी, लोकदल का बहुसंख्यक गुट जे. देवीलाल, अजितसिंह गुट, कंग्रेस से निष्कासित सदस्यों, वी.पी. सिंह, अरुण नेहरू, विद्या-चरण शुक्ल का जनमोर्चा एवं राष्ट्रीय संजय मंच जे. मेनका गांधी द्वारा निर्मित । इन संगठनों ने मिलकर जनता दल का निर्माण किया ।

नवों लोक सभा चुनाव में जनता दल को 525 में से 141 स्थान मिले, कांग्रेस को 195, भा.ज.पा. को 86 सो.पो.एम को 32 एवं सो.पो.आई को 28 स्थान मिले। इस प्रकार 1989 का लोक सभा के चुनाव परिणाम मोल के पत्थर साबित हुए।¹ जनता दल ने भा. जा. पा. एवं सो.पो. आईईएम के बाहरी समर्थन एवं तेलंगदेशम असम गण परिषद तथा डो.एम. के आन्तरिक सहयोग से सरकार बनायी जिसे राष्ट्रीय मोर्चे को सरकार कहा गया।

नौवों लोक सभा के चुनाव परिणाम से किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं था जो कि सरकार बना सके। सन् 1977 में सात दलों के विलय से बनो जनता पार्टी को 41.32% मत था 54.43% सोटे मिली जबकि 1989 में जनता दल 17.73% मत था 27.10% सोटे 141 मिली। कांग्रेस को किसी भी दल का समर्थन न मिलने के कारण जनता दल ने, भारतीय जनता पार्टी 86 सोटें तथा वाम-पंथी मोर्चे 52 सदस्यों के साथ के समर्थन से सरकार का गठन किया जो कि राष्ट्रीय निर्माण एवं विकास के अनेक प्रमुख मुद्दों और रणनीतियों पर एक दूसरे के विरोधी हैं। राष्ट्रीय मोर्चे को सरकार भारतीय राजनौतिक व्यवस्था के लिए नया अनुभव है क्योंकि समर्थन देने वाले पार्टियों ने सरकार में हिस्सा नहीं लिया।² दो विरोधी विचारधारा के पार्टियों द्वारा समर्थित सरकार के अस्तित्व पर पहले ही दिन से संदेह प्रकट किया जाने लगा - क्योंकि दो विरोधी पार्टियों का

1- भारतीय शासन एवं राजनीति पृष्ठ 639-640

सुशीला कौशिक 1990।

2- खान रशी उद्दीन - भारत में लोकतंत्र - 1990 पृष्ठ 105

समर्थन कब तक मिलेगा यह नीतियों पर निर्भर करेगा ।

दल-बदल की राजनीति एवं संविद सरकारों का मूल्यांकन -

भारतीय राजनीति के 1967 के बाद के अध्ययन से मुख्यतः एक तो ये बात पता लगती है कि केन्द्र की अपेक्षा राज्यों में दल-बदल अधिक हुआ, एवं इससे विरोधी दलों को अधिक लाभ हुआ एवं 1971 के बाद के दल-बदल से कांग्रेस को अधिक लाभ पहुँचा, लेकिन इन दल-बदल से बनी संविद सरकारों का जल्द ही पतन शुरू हो गया । मिली जुली सरकारों के पतन का दूसरा कारण वैचारिक मतभेद था ।

प्रो० रजनी कोठारी के अनुसार दल-बदल के मुख्य कारण चुनाव के पहले टिकट का बँटवारा और चुनाव के बाद मंत्रिमण्डल का गठन ।¹

चतुर्थ आम चुनाव के बाद कांग्रेसी दल एवं विरोधी दलों के सदस्यों को संख्या लगभग सन्तुलित होने के कारण प्रत्येक विधायक को स्थिति इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि वह अपने को मंत्रिमण्डल की कुर्सी समझने लगा, उदाहरणार्थ 1969 के मध्यावधि चुनाव के बाद चार सदस्यों द्वारा कांग्रेस छोड़कर विपक्ष में जा मिलने से उत्तर प्रदेश के चन्द्रभानु गुप्त को सरकार धराशायी हो सकती थी । इस संतुलित स्थिति के कारण दल-बदल के द्वारा वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करने लगे ।²

1- कोठारी रजनी, भारत में राजनीति पृ० 126

2- फिर वही,

स्वार्थ और पद लोलुपता को भावनायें मिली-जुली सरकारों को असफलता के कारण बने जोगुट अथवा व्यक्ति सरकार में पद पाने में सफल रहे वे दूसरी सरकार बनाने की तरकीबें सोचने लगते । राज्यों में संविद सरकारें उन राजनोतिज्ञों का तमाशा बन गयी जो सत्ता के भूखे थे और अनैतिक थे जिन्हें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के अलावा कुछ और नहीं दिखता था मंत्रिपद पाने वाले दल- बदलुओं के आंकड़े ¹।

भारत में जो दल-बदलुओं के प्रति उदासीन दिखता है ये दल-बदल के बावजूद, भारतीय राजनोति में नेताओं मालाये पहनाये जाते रहते हैं । हरियाणा के चुनावों में 32% तक दल-बदले नेता चुनाव जीतते रहे हैं।

भारत में विभिन्न राजनोतिक दलों में विचारात्मक ध्रुवों का अभाव दिखता है। कोई भी विधायक किसी भी दल में मिल जाए तो उसके सिद्धान्तों पर कोई खास जवाब नहीं दिखता । जिस आसानी से वे एक दल त्याग कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि वे किसी राजनोतिक सिद्धान्त अथवा किसी दल की राजनोतिक विचारधारा को अधिक महत्व नहीं देते इसके साथ-साथ चूंकि विभिन्न दलों में कोई विचारात्मक ध्रुवों का अभाव नहीं है और उनके मतभेदों का स्वरूप धुंधला है अतः जब कोई व्यक्ति एक दल से सम्बन्ध-विच्छेद कर दूसरे किसी दल में मिल जाता है तो उनमें विचारधारा के परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं उठता ।²

1- कोठारी राजनो- भारत में राजनोति पृ० 46

विशेष - दल-बदलुओं के आंकड़े परिशिष्ट में देखें ।

2- डॉ० कृष्ण सुभाष - दल-बदल और राज्यों की राजनोति

दल-बदल के कारण जो भी संविद सरकारें बनी वो अपने मतभेदों के कारण दुर्बल सिद्ध हुईं, दूसरे क्योंकि उनका अन्तिम उद्देश्य मात्र कांग्रेस को सरकार न बनाने देना ही रहा है। मंत्रिमण्डल बनाने के बाद उनमें किसी नीति पर समझौता नहीं हो पाता रहा है। इस मिली-जुली सरकारों के घटक सुपर कैबिनेट की तरह आचरण करती रहे हैं जिससे मुख्यमंत्रियों के पद का हास होता रहा है एवं उसकी स्थिति मात्र एक कठपुतली की रही है।¹ मुख्यमंत्री पद के हास, मंत्रिमंडल के अनिश्चित भविष्य के कारण नौकरशाही के प्रभाव तथा दबाव में अप्रतिम बुद्धि हुई है।²

दल-बदल रोकने के उपाय :

चतुर्थ आम चुनाव के बाद दल-बदल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर चिन्ता का विषय बन गया। तत्कालीन गृहमंत्री की अध्यक्षता में भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की। इस समिति 18 फरवरी 1969 को संसद के सामने दल-बदल रोकने हेतु एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति सिफारशें इस प्रकार थी।³

- 1- सभी राजनीतिक दल ऐसी व्यवहार संहिता को स्वीकार करें जिसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं के मूल औचित्य और शालीनताओं का समावेश किया गया हो ऐसी व्यवहार

1- जौहरी जे. सी. - रिफ्लेक्सन आन इंडियन पार्लिटिक्स, 1974
पृष्ठ 28

2- सी. पी. भाम्बरनी - ट्यूरोक्रेसी एण्ड पार्लिटिक्स इन इंडिया
1973, पृष्ठ 54

3- जौहरी जे. सी. - रिफ्लेक्सन आन इंडियन पार्लिटिक्स 1974

संहिता का पालन कराने के लिए समिति अथवा मण्डल का गठन किया जाय जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और विधिक पृष्ठ भूमि वाले लोग हों ।

- 2- प्रतिनिधि को उस राजनीतिक दल से सम्बन्ध समझा जाना चाहिए जिसके तत्त्वाधान में उसने निर्वाचन जीता हो ।
- 3- ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो न्यूनतम सदस्य न हो प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री न बनाया जाए ।
- 4- दल-बदल करने वाले विधायक को तब तक कोई सरकारी लाभ का पद न दिया जाए जब तक वह अपने स्थान से पद त्याग कर पुनः निर्वाचित नहीं हो जाता ।
- 5- अगर कोई दल राजनीतिक दल-बदल करने वाले विधायक को स्वीकार करता है तो उस दल को दो गयी मान्यता और उस दल के लिए सुरक्षित किया गया चुनाव निशान कम से कम दो वर्षों के लिए वापस ले लिया जाना चाहिए ।
- 6- मंत्रिमण्डल सीमित आकार का होना चाहिए ।
- 7- अगर कोई विधायक उस दल को छोड़ता है जिससे चुनाव चिह्न पर चुना गया था तो वह संसद या राज्य विधान सभा का सदस्य रहने के अयोग्य होगा । चाहे तो वह दुबारा चुनाव लड़ सकता है।

चाहवाण समिति के समक्ष रखे गये अन्य प्रस्तावों पर गहरा मतभेद हुआ । फिर भी 16मई 1973 को गृहमंत्री उमाशंकर दौक्षित ने दल-बदल को रोकने के लिए लोकसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे बत्तोसवा संविधान संशोधन विधेयक कहा जाता है, यह विधेयक पारित

न हो सका ।

मार्च 1977 में जनता पार्टी के सत्ता रूढ़ होने के बाद अनेक सदस्यों ने दल-बदल रोक विधेयक लाने पर बल दिया । 1978 के मध्य दल-बदल विधेयक पेश किया गया लेकिन सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ने से ये विधेयक वापस ले लिया गया ।

26 सितम्बर 1979 को दल-बदल विरोधी विधेयक पारित जम्मू-काश्मीर विधान सभा ने पहल तो की लेकिन एक ओर इससे दल-बदल पर रोक तो लगती है लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी इससे बाधित होती है । विधेयक की धारा ४अ के अनुसार कोई भी विधायक अगर अपनी पार्टी से इस्तीफा देता है तो उसकी विधान सभा सदस्यता समाप्त हो जाएगी । इस पर सभी सहमत थे । विवाद का मुद्दा धारा ४ब जिसके अनुसार यदि कोई विधायक अपने पार्टी से मतदान के विरुद्ध मतदान करता है या मतदान में भाग नहीं लेता तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी । विपक्ष का कहना था कि इससे पार्टी में किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद के लिए जगह नहीं रहती । इससे केन्द्रीयकरण को बढ़ावा मिलता है। धारा 19 का इससे अलंघन होता है।¹ इस दल-बदल कानून को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई उच्च न्यायालय के वैध स्वीकार करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई ।

भारत सरकार को संसद ने दल-बदल पर रोक लगाने के लिए 52वाँ संविधान संशोधन विधेयक १९८५ सर्व सम्मति से पारित कर दिया इस एक्ट में निम्न प्रावधान किए गये हैं ।²

1- दिनमान - 14-20 अक्टूबर 1979 पृ० 21

2- भारतीय संविधान , एक्ट पृ०

- 1- §1§ यदि वह स्वेच्छा से दल त्याग दे 2- यदि वह अपने दल या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अनुमति के बिना सदन में उसके किसी निर्देश के प्रतिकूल मतदान करे या मतदान में अनुपस्थित रहे, यदि प्रन्द्दह दिन के अन्दर दल उसे इस उल्लंघन के लिए क्षमाकर दे तो उसको सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा §3§ यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य दल में शामिल हो जाए §4§ यदि कोई मनोनोति सदस्य शपथ लेने के छह माह बाद किसी राजनैतिक दल में शामिल हो जाए । तो उसको सदस्यता सदन से समाप्त समझी जाएगी ।
- 2- किसी राजनैतिक दल के विघटन पर सदस्यता समाप्त नहीं होगी । यदि मूल दल एक तिहाई सदस्य दल छोड़ दे ।
- 3- इसी प्रकार विलय की स्थिति में दल-बदल नहीं माना जाएगा । यदि किसी दल के कम से कम दो तिहाई सदस्य उसको स्वोक्ति दे दें ।
- 4- दल-बदल पर उठे किसी भी प्रश्न पर अन्तिम निर्णय सदन के अध्यक्ष का होगा ।
- 5- सदन के अध्यक्ष को इस विधेयक के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने का अधिकार होगा ।

दल-बदल के दो पहलू हैं एक नैतिक दूसरा वैधानिक ।

यह समस्या दिनों-दिन बढ़ती गयी क्योंकि राजनैतिक दल अपने नैतिक दायित्व को भूल गये । राजनैतिक दलों को आचरण संहिता तैयार करनी चाहिए । ऐसा राजनैतिक दलों ने क्यों नहीं किया ? क्यों कि इसमें

उनको स्वार्थपतरा छियो थे । इस क्रिया से बनो संविद सरकारे भी इसी कारण सफल न हो सकी । संयुक्त मोर्चा सरकारो के पतन के बीच उनके जन्म में ही विहित थे । दल-बदलुओ के कुनबे निर्मित सरकार अधिक दिनो नही चल सक्यो । इस प्रकार भारतीय राजनीति में मिली-जुली सरकारो का प्रयोग पूर्णतया असफल रहा ।¹ लार्ड ब्राइस का यह कथन सही लगता है कि संविद मंत्रिमंडलों की सरकार कमजोर होती है । जब सरकार को अपनी सुदृढ़ स्थिति पर भरोसा नही होगा तो विभिन्न घटकों से निर्मित मंत्रिमंडल प्रशासन की ओर क्या ध्यान देगा एवं कैसे जन कल्याण को योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकेगा ?

अध्याय - 5

जातिवाद एवं सम्प्रदायवाद

अध्याय- 5

जातिवाद एवं सम्प्रदायवाद

जातिवाद :

जाति प्रथा किसी न किसी रूप में संसार के हर कोने में पायी जाती है । जाति व्यवस्था को ठोक उत्पत्ति की खोज नहीं की जा सकी है । इस व्यवस्था का जन्म भारत में हुआ । ऐसा कहा जाता है कि भारत आर्य संस्कृति के अभिलेखों में उसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तथा उन तत्वों का निरन्तर इतिहास कभी मिलता है । जिससे जाति-व्यवस्था का निर्माण हुआ ।¹ ब्लंट ने जाति को परिभाषा देते हुए कहा कि जाति एक अन्तर्विवाही समूह या समूहों का संकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है जिसकी सदस्यता पैतृक होती है और जो अपने सदस्यों पर सामाजिक सहवास के संबंध में कुछ प्रतिबंध लगाती है । जो एक परम्परागत सामान्य पेशे को करती है या एक सामान्य उत्पत्ति का दावा करती है और सामान्यतया एक सजातीय समुदाय को बनाने वाली समझी जाती है ।² जाति व्यवस्था के अन्तर्गत समाज अनेक जातियों में विभक्त होता है । प्रत्येक जाति का अपना जीवन ढाँचा है जिसकी सदस्यता जन्म के आधार पर निर्धारित होती है व्यक्ति की परिस्थिति पर नहीं, अपितु उस जाति के परम्परागत महत्त्व पर निर्भर करती है । जिसमें उसे जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।³

1- सचदेव डो.आर- समाज शास्त्र के सिद्धान्त पृ० 367

2- ब्लंट ई. ए. एम्, -सोशल सर्विस इन इंडिया पृ० 150

3- मैकाइवर आप सिट पृ० 124

प्रो० घरे ने लिखा है - " जाति भारत-आर्य संस्कृति का ब्राम्हणिक बच्चा है, जिसका पालन गंगा के मैदान में हुआ है जो वहाँ से भारत के दूसरे भागों में हस्तान्तरित किया गया ।¹ सामान्यतया यह माना जाता है कि इसको उत्पत्ति वैदिक काल में हुई । ब्राम्हण धार्मिक और वैदिक कार्यों का सम्पादन करते थे । क्षत्रियों का कार्य देवा को रक्षा और शासन प्रबंध करना था। वैश्य कृषि एवं वाणिज्य सम्भालते थे तथा शूद्रों को अब तीन वर्णों को चाकरो करनी पड़ती थी। शुरू-शुरू में जाति प्रथा के प्रबंध कठोर न थे, वह जन्मपर नहो कर्म पर आधारित थे, बाद में जाति प्रथा में कठोरता आती गयी वह पूरे जन्म पर आधारित हो गई तथा एक जाति से दूसरी जाति में अन्तः क्रिया असम्भव हो गई ।² प्रो० घरे ने जाति व्यवस्था को छः विशेष-ताये बताये है ।³

§1§ भारत में जाति ऐसे समुदाय है जिनका अपना विकसित जीवन है और इसको सदस्यता जन्म से ही निश्चित होती है।

§2§ भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति जानता है और जातियों के पद सोपान में ब्राम्हण सबसे ऊपर माना जाता है ।

§3§ जातियों के आधार पर खान-पान और सामाजिक आदान-प्रदान के प्रतिबंध लगे रहते हैं ।

§4§ गाँवों तथा शहरों में जाति के आधार पर पृथक्ता बनो रहती है ।

1- घरे जो, एस. - आप सोट पृ० 178

2- फिर वही, पृ० 265-55

§5§ कुछ जातियों का तत्पय कुछ विशेष प्रकार के व्यवसायों को अपना पुत्रैनी अधिकार समझती है।

§6§ जातियों के हो परिधि में वैवाहिक आदान-प्रदान होता है और जातियाँ कई उप-जातियों में विभक्त होती हैं। उप जातियों में भी वैवाहिक परिसीमों हैं।

परम्परावादो भारतीय समाज में आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं को स्थापना भारतीय राजनीति को एक अद्भुत विशेषता है। भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रारम्भ होने के पश्चात् यह धारणा विकसित हुई कि पश्चिमी ढंग की राजनीतिक संस्थाएँ और लोकतन्त्रात्मक मूल्यों को अपनाने में फलस्वरूप पारम्परिक संस्था-जातिवाद का अन्त हो जाएगा किन्तु स्वाधीनता के बाद भारत को राजनीति में जाति का प्रभाव निरन्तर बढ़ता गया। जैसे राजनीति पर जातिगत प्रभाव, प्रतिनिधि व्यवस्था को लागू होने के समय से हो शुरू हो गया था, किन्तु यह प्रभाव नगण्य हो था। इसके लिए उत्तरदायी थे ब्रिटिश प्रशासन राष्ट्रीय आन्दोलन तथा सीमित मताधिकार। स्वतंत्रता को प्राप्ति ने प्रथम दो का निराकरण कर दिया और नए संविधान में अपनाया गया व्यक्त मताधिकार व्यवस्था से तोसरे का। फलतः जातियों के प्रभाव क्षेत्र में आशातीत वृद्धि हो गयी आरम्भ में तो उच्च एवं श्रेष्ठ जातियाँ राजनीति पर हावी रही और राजनीतिक लाभ उन्हीं तक सीमित रहे। समय के साथ-साथ मध्यम एवं निम्न जातियाँ भी आगे आने लगी।¹ और अपने राजनीतिक

प्रभाव को बढ़ाने में प्रयत्नशील रहने लगे । प्रो० रुडात्फ के शब्दों में भारत के राजनोतिक लोकतंत्र के सन्दर्भ में जाति वह धुरोह है जिसके माध्यम से नवीन मूल्यों और तरीकों को खोज को जा रहो है । यथार्थ में यह ऐसा माध्यम बन गया है कि इसके जरिये भारतीय जनता को लोकतांत्रिक राजनोति को प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है ।¹

प्रो० रजनो कोठारो का मत है कि अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है क्या भारत में जाति प्रथा खत्म हो रहो है- इस प्रश्न के पोछे यह धारण है कि मानो जाति एवं राजनोति परस्पर विरोधी संस्थायें हैं, कोठारो- कोई भी सामाजिक तंत्र कभी पूर्णतया समाप्त नहो हो सकता, अतः यह प्रश्न अर्थ शून्य है ।² ज्यादा सहो प्रश्न यह होगो कि जाति प्रथा पर राजनोति का क्या प्रभाव पड़ रहा है और जाति-पॉलिसि बल्ले समाज में राजनोति का रूप ले रहो है ? जो लोग राजनोति में जाति को शिकायत करते हैं वे न तो राजनोति के प्रकृति को ठोक समझ पाए है और न जाति के स्वरूप को । भारत को जनता जातियों के आधार पर संगठित है और न चाहते हुए भी राजनोति को जाति संस्था का उपयोग करना हो पड़ेगा । अतः राजनोति में जातिवाद का अर्थ जाति का राजनोतिकरण है । जाति व्यवस्था आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन में रुकावट नहीं डालती बल्कि इसको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।³

1- रुडात्फ एंड एडात्फ - द माडर्निटी आफ ट्रेडिसन द डेमोक्रेटिक इन कारनेशन आफ कास्ट इन इंडिया वे ।

2- कोठारो रजनो- कास्ट इन इंडियन पार्लिटिक्स । 970 पृ० 4

3- कोठारो रजनो- पार्लिटिक्स इन इंडिया पृ० 41

राजनैतिक नेता सत्ता प्राप्त करने के लिए जातीय संगठन का उपयोग करते हैं और जातियों के रूप में उन्हें बना बनाया संगठन मिल जाता है जिससे राजनैतिक संगठन में आसानी होती है। स्थानीय और राज्य स्तर को राजनैति जातीय संगठन निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में उसी प्रकार को भूमिका अदा करते हैं जैसे पश्चिमी देशों में दबाव-समूह।¹

जाति व्यवस्था और राजनैति में अन्तः क्रिया के संबंध में प्रो० रजनो कोठारो ने जाति प्रथा के तीन रूप प्रस्तुत किये हैं।¹
1- लौकिक रूप 2- एकीकरण रूप 3- चैतन्य रूप।

रजनो कोठारो ने जाति व्यवस्था के लौकिक रूप को व्यापक दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया है। जाति व्यवस्था को कुछ बातों पर सबका ध्यान गया है जैसे जाति के अन्दर विवाह छुआछूत रीति-रिवाज के द्वारा जाति को पृथक इकाई को कायम रखने का प्रयत्न। लेकिन इस बात को ओर बहुत ही कम लोगों का ध्यान गया है कि जातियों में आपसी प्रतिठिदिता एवं गुट-बन्दो रहती है, प्रत्येक जाति प्रतिष्ठा और सत्ता को प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहती है उदाहरणार्थ आजकल बिहार में उच्च जातियों और पिछड़ी जातियों के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा है। यही कारण है कि 1977 से 1980 के बीच दोनों ही मुख्यमंत्री अनुसूचित जातियों से आए एवं 1989 के बाद से लालू प्रसाद यादव भी पिछड़ी जाति से है।

1- मैनिवल आस्टिन - द इंडियन कोन्स्टिट्यूशन - कर्नर स्टोन

ऑफ ए नेशन § आक्सफोर्ड 1976 § पृ० 47

2- कोठारो रजनो- पार्लिटिक्स इन इंडिया पृ० 155-58

जाति व्यवस्था के इस लौकिक पक्ष के दो रूप थे । एक शासकीय रूप यानि गाँव की पंचायत और चौधराहट दूसरा रूप राजनोति था यानि जाति की आन्तरिक गुटबन्दी और अन्य जातियों से गठ-जोड़ या प्रतिद्वन्द्विता । इन संगठनों का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता था कि स्थानीय नेताओं के समाज की केन्द्रस्थ सत्ता से किस प्रकार के संबंध थे । धर्म, व्यवसाय और प्रेक्षा के आधार पर इन जातियों की स्थिति बनती एवं विगड़ती थी । पहले इन जातियों का संबंध जाति या गाँव की पंचायत और जमोदार से रहता था । प्रेक्षा की राजनोति पर किसी एक जाति का प्राधान्य नहीं हो सका क्योंकि कुछ स्थानों पर ब्राम्हणों का वर्चस्व था तो कुछ प्रदेशों में जैसे गुजरात और मारवाड़ में जैन, वैष्णव जैसे सम्प्रदायों के हाथ में आर्थिक शक्ति थी ।¹

जाति का दूसरा रूप एकीकरण है अर्थात् व्यक्ति को समाज से बांधने का है । जाति प्रथा जन्म के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का समाज में स्थान नियत कर देती है जाति के आधार पर ही उस व्यक्ति का व्यवसाय और आर्थिक भूमिका निश्चित हो जाती है। चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो उसका अपने समाज से लगाव पैदा हो जाता है । जाति के प्रति उसको निष्ठा बढ़ने लगती है। यही निष्ठा आगे चलकर बड़ी निष्ठाओं अर्थात् लोकतंत्र एवं राजनोतिक व्यवस्था के प्रति भी विकसित हो सकती है। इस प्रकार जातियाँ जोड़ने वाली कड़ियाँ बन जाती हैं। लोकतंत्र के अन्दर विभिन्न समूहों में शक्ति के लिए प्रतिद्वन्द्विता होती है और विभिन्न जातियाँ आपस में मिल जुलकर गठ जोड़ बनाने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है ताकि वे सत्ता का लाभ

1- राव के एन, रोजनल एंड कास्ट फैक्टर्स इन इंडियाज डेवलपमेंट

प्राप्त कर सकें ।¹

जाति व्यवस्था का तीसरा रूप चेतना बोध है। कुछ जातियाँ अपने को उच्च समझती हैं । इस कारण समाज में उनको विशेष प्रतिष्ठा होती है । जैसे क्षत्रीय एवं ब्राम्हण इस कारण समाज में निम्न जातियों अपने को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती हैं ।

प्रो० रजनो कोठारी ने जाति के राजनोतिकरण की चर्चा करते हुए कहा है कि इससे पुराना समाज नयी राजनोतिक व्यवस्था के करीब आया है। इससे सबसे पहले शक्ति एवं प्रभाव की प्रतिस्पर्धा उँची जातियों तक सीमित रही । जिन जातियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करके आधुनिक बनने का प्रयत्न किया वे प्रतिष्ठित जातियों के समक्ष आने लगे । इन जातियों ने अधिकार और पद प्राप्त करने के लिए अपना राजनोतिक संगठन बनाया जिससे दो उँची जातियों में प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वन्द्वता बढ़ने लगे । मद्रास और महाराष्ट्र में ब्राम्हण अब्राह्मण , राजस्थान में राजपूत, जाट, गुजरात में बनियाँ ब्राम्हण पाटोदार, आंध्र प्रदेश में कम्मा रेड्डो और केरल में इजवा नायर द्वन्द्व इसके उदाहरण हैं।²

जाति के राजनोतिकरण के दूसरे चरण में भिन्न-भिन्न जातियों की प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ जाति के अन्दर भी प्रतिस्पर्धी गुट बने गये । प्रतिद्वन्द्वी नेताओं के पीछे गुट बन गये । इन गुटों में विभिन्न जातियों के लोग हैं। अपना गुट मजबूत करने के लिए उन जातियों की सहायता ली जाती है । जो अब तक दायरे से बाहर रहती हैं। चुनाव में समर्थन प्राप्त करने के लिए नीची जातियों के प्रमुख

लोगों को छोटे राजनीतिक पद और लाभ में कुछ हिस्सा देकर प्रतिस्पर्धा नेता अपना गुट मजबूत करने की कोशिश करते हैं । जहाँ इस प्रकार मुखियों को इनाम देकर इन जातियों का समर्थन प्राप्त करना सम्भव नहीं होता । वहाँ इनमें प्रतिस्पर्धा पैदा करके , विचित्रियों के माध्यम से समझौता करने की कोशिश की जाती रहती है और इस प्रकार की राजनीति भारत में स्वतंत्रता के उपरान्त देखने को मिलती है ।

भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका -

जाति व्यवस्था भारतीय समाज का परम्परागत पक्ष है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद संविधान और राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण से आधुनिक प्रभावों ने भारतीय समाज में धीरे-धीरे प्रवेश करना आरम्भ कर दिया। आधुनिक प्रभावों के फलस्वरूप व्यक्ति मताधिकार के आधार पर विचार प्रारम्भ हुए और जातिगत संस्थायें यकायक महत्वपूर्ण बन गयीं, क्योंकि उनके पास भारी संख्या में मत थे और लोकतंत्र में सत्ता प्राप्ति हेतु इन की आवश्यकता थी । जिन्हें सत्ता की आकांक्षा थी उन्हें सामान्य जनता को अपने पक्ष में मिलाने के लिए यह भी जरूरी था कि उनसे उस भाषा में बात की जाय, जो उनकी समझ में आ सके । जाति व्यवस्था इस बात को प्रकट करती थी इस कारण राजनीति में जाति अधिका-धिक महत्वपूर्ण होती गई । जय प्रकाश नारायण ने एक बार कहा था कि जाति भारत की अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है अर्थात् यदि मुख्य राजनीति की दुनियाँ उँचा उठना चाहता है तो उसे अपने साथ अपनी जाति को लेकर चलना

होगा । भारत में राजनीतिज्ञ जातीय समुदायों को इसलिए संगठित करते हैं ताकि उनके समर्थन में उन्हें सत्ता तक पहुँचने में सहायता मिल सके । क्योंकि जातियाँ ही संगठित होकर प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग लेती हैं और बाद में राजनीतिक शक्तियाँ बन जाती हैं । भारतीय राजनीति में जाति को निम्न भूमिकाओं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है।

१।१ निर्णय प्रक्रिया में जाति को प्रभावक भूमिका :

भारत में जातियाँ संगठित होकर राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती रहो हैं, राजनीतिक दल इनको अनदेखा नहीं कर पाते , क्योंकि इन्हो संगठनों को बदौलत को सत्ता में रह सकते हैं ।

उदाहरणार्थ , भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, अन्य जातियाँ चाहती हैं कि ये आरक्षण समाप्त कर दिया जाय अथवा इसका आधार सामाजिक आर्थिक स्थिति हो ताकि वे इनके लाभ से वंचित न रह जाए, लेकिन इनके संगठनात्मक दबाव के कारण तथा राजनीतिक अपने स्वार्थ वश इसको समाप्त नहीं करते बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ाते जा रहे हैं । 1989 कि चुनाव सेव पहले सत्ता धारी पार्टी कांग्रेस ने अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के आरक्षण प्रावधान को आगे बढ़ाये जाने को जोर देकर कहा । 1989 में जनता दल की सरकार बनने के बाद प्रधान मंत्री कार्यालय में एक विशेष सेल के जातियों के प्रतिशत के बारे में लगातार अध्ययन करता रहा है । गुजरात में १985१

विधान सभा चुनाव के पूर्व सोलकी ने पिछड़ों के लिए 18% आरक्षण को घोषणा की एवं अंततः 1991 के मध्यावधि चुनाव के पूर्व विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजनैतिक स्वार्थका १ डॉ. बो. सो. १ दूसरे पिछड़े वर्गों १ जो कि कुल भारतीय जनसंख्या के 43.7% है १ के लिए केन्द्रीय सरकार को नौकरियों में 27% आरक्षण को व्यवस्था लागू करने की घोषणा की । जिससे कि पूरे देश में जातिवादो कदतरता भड़क उठी एवं भारतीय समाज उच्च वर्ग एवं पिछड़े वर्गों में बंट गया एवं जिसके कारण सारे देश में दंगे हुए ।²

भारत में राजनैतिक दल अपने प्रत्याशियों का चयन करते समय जातिगत आधार पर निर्णय लेते है। प्रत्येक दल किसीभी चुनाव क्षेत्र में प्रत्याशी मनोनीत करते समय जातिगत गणित का अवश्य विश्लेषण कर लेते रहे है । 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ने हरिजन + मुसलमान + ब्राम्हण शक्ति पुंज बनाकर ही चुनाव जीता था ।

जनवरी 1980 के सातवें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस^१आई^१ को विजय प्राप्त होने का कारण है कि श्रीमती गान्धी हरिजनों ब्राम्हणों और मुसलमानों का जातीय समर्थन जुटाने में सफल हो गई । कांग्रेस सहित सभी राजनैतिक दलों में जातीय आधार पर अनेक गुट पाए जाते हैं । कुछ राजनैतिक दल तो मुख्यतः जातियों के आधार पर बने । लोकदल का मुख्य आधार हिन्दो प्रदेश के मध्यम और पिछड़ो जातियों जैसे अहोर, गुजर, जाट, ठाकुर, यादव, कुर्मी थे । इसके

1- इन फैक्ट मिसेज गान्धी सक्सीडेड इन बिल्डिंग आफ इलेक्टोरल कोपलिसन ह्वोच ब्राट हर टू पावर इन 1971 - फ्रांडिया
बो. एल. प्रेसर गुप्स इन इंडियन पार्लिटिक्स -1980

अलावा जातियों पर आधारित पार्टियाँ भी बनी जैसे हरिजन संघर्ष समिति किसान मजदूर पार्टी इत्यादि ।

§ 3§ जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार -

भारत में चुनाव अभियान में जातिवाद को साधन के रूप में अपनाया जाता है और प्रत्याशी जिस चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है उस निवचिन क्षेत्र में जातिवाद की भावना को प्रायः उकसाया जाता है ताकि सम्बन्धित प्रत्याशी को जाति के मतदाताओं का पूर्ण समर्थन प्राप्त किया जा सके । जनवरी 1980 के चुनाव में उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में लोकदल की सफलता पिछड़ी जातियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में चरण सिंह की सफलता सदैव ही जाट जाति के मतों के एक जुटता पर निर्भर रही । केरल के चुनावों में साम्यवादियों ने वोट जुटाने के लिए सदैव जाति का सहारा लिया । लालू प्रसाद यादव की सरकार पिछड़े वर्गों के संगठन का ही नतीजा है। ²

राजनीतिक जीवन जातीयता का सिद्धान्त इस हद तक धँस गया है कि राज्यों के मंत्रिमंडल में प्रत्येक प्रमुख जाति का मंत्री होना चाहिए । यह सिद्धान्त प्रान्तों की राजधानियों से ग्राम पंचायतों तक स्वीकृत हो गया कि प्रत्येक स्तर पर प्रधान जाति के प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए । राज्य स्तर से लेकर केन्द्रोप मंत्रिमंडल में भी हरिजनो जन जातियों सिक्खों, मुसलमानों, ब्राम्हणों,

1- नवभारत टाइम्स- 17 जुलाई 85 पृष्ठ 6

2- फिर वही,

जाटो, राजपूतों और कायस्थों को किसी न किसी रूप में स्थान अवश्य दिया जाता है ।

§4§ जातिगत दबाव समूह :

मेयर के अनुसार जातीय संगठन राजनीतिक महत्व के दबाव समूह के रूप में प्रवृत्त हैं । जातिगत दबाव समूह अपने न्यस्त स्वार्थों एवं हितों को पूर्ति के लिए नीति निर्माताओं को जिस ढंग से प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं उससे तो उसकी तुलना यूरोप एवं अमेरिका में पाये जाने वाले ऐच्छिक समुदायों से की जा सकती है ।¹

अनेक जातीय संगठन और समुदाय जैसे तमिलनाडु में नाडार जाति संघ गुजरात में क्षत्रिय महासभा, बिहार में कायस्थ सभा आदि राजनीतिक मामलों में रुचि लेने लगते हैं और अपने-अपने संगठित बल के आधार पर राजनीतिक सौदेबाजो भी करते हैं । यद्यपि देश को प्रमुख जातियों को इस प्रकार पूर्णतया संगठित नहीं किया जा सकता है। मगर जो जातियाँ इस प्रकार संगठित नहीं रहो वे राजनीतिक सौदेबाजो में सफल नहीं रहो और उनके सदस्यों को अपनी आवाज उठाने के लिए उपद्रव और तोड़-फोड़ का सहारा लेना पड़ा ।²

राज्य राजनीति में जाति :

माइकेल ब्रेघर के अनुसार अखिल भारतीय राजनीति को अपेक्षा राज्य स्तर को राजनीति पर जातिवाद का प्रभाव अधिक है । यद्यपि किसी भी राज्य को राजनीति जातिगत प्रभावों से अछूती नहीं रहो है फिर भी

1- जोहरो जे.सो. - रिफ्लेक्सन आन इंडियन पार्लिटिक्स पृ० 73

2- फिर वही,

बिहार, केरल, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, महाराष्ट्र एवं राजस्थान राज्यों को राजनीति का अध्ययन बिना जातिगत गति के विश्लेषण के कर हो नही सकते। बिहार को राजनीति में राजपूत, ब्राम्हण कायस्थ, यादव और जन जाति प्रमुख प्रतिस्पर्धी जातियाँ हैं। पृथक झारखण्ड राज्य की मांग वस्तुतः एक जातीय मांग हो है। केरल में साम्यवादियों को सफलता का राय यहो है कि उन्होंने इजवाहा जाति को अपने पोछे संगठित कर लिया। आंध्र प्रदेश को राजनीति काम्मा और रेड्डो जातियों के संघर्ष की कहानी है। काम्माओं ने साम्यवादो दल का समर्थन किया तो रेड्डो जाति ने कांग्रेस दल का। महाराष्ट्र को राजनीति में मराठो, ब्राम्हणो और महरो में प्रतिस्पर्धा रही है।¹ गुजरात को राजनीति में दो हो जातियाँ प्रभावो है, पाटोदार और क्षत्रिय। केरल को राजनीति अपने तीन समुदायों के ईद-गिर्द घूमती रही है।-हिन्दू, क्रिश्चियन एवं मुसलमान। केरल को राजनीति में अंतिम दो प्रमुख राजनीतिक शक्तियों के रूप में सक्रिय है। वैसे तो वहाँ सभी प्रकार के राजनीतिक दल है किन्तु उन्हें ध्यानपूर्वक देखा जाय तो पता चलेगा कि वे सब जातीय संगठन है। मुस्लिम लोग मुसलमानों की है। दोनों केरल कांग्रेस के अधिसंख्य सदस्य ईसाई हैं रा. प्रा. में नायर लोगों की संख्या है। कांग्रेस १९४१ और साम्यवादो दलों में इजवा जाति के अलावा हिन्दुओं के कुछ प्रमुख वर्गों का प्रभाव देखा जा सकता है। राजस्थान को राजनीति के जाट-राजपूत जातियों की प्रतिस्पर्धा प्रमुख रही है। राज्यों को राजनीति में जाति के प्रभाव को देखते हुए टिंकर ने राज्यों को राजनीति की जातियों को

1- जोहरो जे. सी. - रिफ्लेक्सन आन इंडिया पार्लिटिक्स

राजनोति को संज्ञा दे डालो है।¹ हाल के दशक में उत्तर प्रदेश में राजनोतिक पार्टियों में जातीय धुवोकरण होने से यादव, जाट, लोधी पिछड़े वर्गों का समर्थन चौधरी चरण सिंह को 1970, 1974, 1977, 1980, 1984 तक मिला तथा उत्तर प्रदेश के राजनोति में इन जातियों का खासा वर्चस्व बना हुआ है। एवं ये सशक्त भूमिका निभाते रहे हैं।

वास्तव में यह निश्चित करना कठिन है कि जातियों को राजनोति विभाजित करती है अथवा एकता के सूत्र में बाँधती है। क्योंकि भारत में ये दोनों बातें सहो दिखाई देती हैं। रुडाल्फ एवं रुडाल्फ लेखकों का मत है कि भारत को जाति व्यवस्था ने राजनोतिक जागृति और विभिन्न जातियों के राजनोतिकरण में सहयोग दिया है और इस अर्थों में जाति व्यवस्था अभिशाप होने के बजाय वरदान सिद्ध हुई है।²

जाति ने भारतीय संस्कृति के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाई है। रुडाल्फ दय के अनुसार जातीय संघ संघार सरणियाँ तथा नेतृत्व संगठन का आधार प्रस्तुत करते हैं। जो परम्परागत समाज में अब तक दुबे लोगों को तकनीकी राजनोतिक निरस्तता से उबारते हैं जो कि अन्यथा लोकतांत्रिक राजनोति में भागीदारों को उनकी क्षमता को प्रभावित करती है प्रति योगी राजनोति के वातावरण में विभिन्न जातियाँ समानता तथा सहयोग को अपनाकर एकीकरण को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जातीय भावना तथा हित पर आधारित, अधिजाति राजनोतिक, सत्ता, सामाजिक स्थिति तथा आर्थिक हितों को प्राप्ति के लिए एवं संरचना प्रस्तुत करती है

1- स्टेट पालिटिक्स वोल वी ए कास्ट पालिटिक्स थू आउट मोस्ट आफ इंडिया फार मेनो डियर्स टू कम - टिंकर

2- रुडाल्फ एंड रुडाल्फ -माडोनेटो आफ ट्रेडिसन पृ० 9

जो प्रतिनिधिक जन्तंत्र तथा धर्म निरपेक्षता को सामान्य भारतीयों के लिए सहज एवं साध्य बनाते हैं ।¹

किन्तु एक सामाजिक क्षेत्र के रूप में भी जाति का आकलन जरूरी है रूडाल्फ द्वय के विचार कि जातिवाद से राजनोतिक आधुनिकीकरण को प्रक्रिया में सहायता मिली है सत्य नहीं है । वास्तविकता है कि इससे जातिवाद को भावना को प्रबलता मिली है । जातीय भेदभाव पर आधारित राजनोतिक गतिविधियाँ वास्तव में देश के राजनोतिक आधुनिकीकरण के लिए घातक और राष्ट्रिय एकीकरण में बाधक सिद्ध हुई है। जातीय जागरूकता ने एक ओर विभिन्न जाति समूहों को एकता के सूत्रों में बाँधो उनमें जागरूकता उत्पन्न की तो दूसरी ओर सम्पूर्ण समाज को और भी छोटे-छोटे समूहों में विभाजित कर दिया । इसने विवेक पर आधारित वैयक्तिकता, तर्क संगतता उपलब्धि अभिमुखी स्तर से इंकार कर समानता और सामाजिक न्याय को अवधारणा को पूर्णतया नष्ट कर दिया वंश तथा रक्त सम्बन्धों को समाज और राष्ट्र से ज्यादा प्राथमिकता देकर राजनोतिक आधुनिकीकरण एवं राष्ट्रिय एकता में बाधा उत्पन्न कर रही है । लौकिकीकृत होने के बजाय जाति ने समाज ने बहुतेरे तनावों को बढ़ाया है तथा सत्ता से वंचित समूहों को शिकायत में वृद्धि की है । उच्च जातियाँ समानता को स्वीकार करके भी मौका पाते हों पुरानोप्रतिष्ठा को याद में पक्षपात करते हैं तो अब तक कुचलो गये जातियों बदले की भावना से प्रेरित हैं । जातिय एवं वर्गीय भावना सम्पूर्ण राजनोतिक व्यवस्था को ध्वस्त कर सकती है । विशेषतः समानता एवं सामाजिक न्याय को हमारी उपलब्धियों को । एम एन श्री-निवास का कहना है कि परंपरावादो जाति व्यवस्था ने प्रगतिशील और

1- रूडाल्फ ए वं सडाल्फ दि माइनिटी ऑफ देडोशन, 1969,

आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को इस तरह प्रभावित किया है कि ये राजनीतिक संस्थाएँ अपने मूल रूप में कार्य करने में समर्थ नहीं रहो है । डॉ. आर. गाडगिल ने भी जातिवाद को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हानिकारक मानते हुए यह कहा है कि क्षेत्रीय दबावों से वही अधिक खतरनाक बात यह है कि वर्तमान काल में जाति व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने में बाधक सिद्ध हुई है ।¹

भविष्य में जातिवाद का भारतीय राजनीति में क्या स्वरूप होगा और भारतीय राजनीति कहीं तक अपने को जाति के प्रभाव से मुक्त रख सकेगी । यह तो समय ही बताएगा ।

संप्रदायवाद :

धर्म की अवधारणा -

धर्म रस है, चेतना स्पंदित है, वही धर्म का स्थान है। व्यक्ति समाज और सत्ता के मूलहेतु वही से संपादित होता है जहाँ अंतस्थल में धर्म का दोष आलोकित है ।² धर्म यह धुरी है जहाँ से विकास का पहिया मानव कल्याण की यात्रा के लिए गति पाता है। इसके बिना पहिया सिर्फ घूमता प्रतीत होता है।

वाणक्य ने धर्म और राजनीति को भाई-भाई की संज्ञा देते हुए कहा है कि धर्म की सुखी का मूल और राजनीति को संचालक शक्ति है ।³

1- फिर वही,

2- राष्ट्रीय सहारा, जुलाई 93 पृष्ठ 6

3- कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ।

एक-राज्य धर्म विरोधी हो, उनको अपनी विचारधारा हो तथा यह उसी पर आचरण करे । दूसरा-राज्य धर्मों को ओर उदासीन हो कि कसो धर्म को संरक्षण न दे । लेकिन भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता से तात्पर्य धर्म विरोधी, धर्म रहित अथवा अनोश्वरवादो नहीं है इसका अर्थ है राजनैतिक मामलों में धर्म के प्रभाव से मुक्त होना, राज्य का धार्मिक क्षेत्र में तटस्थ होना और किसी धर्म विशेष के साथ कोई पक्षपात न करना । डॉनाल्ड यूजोनस्मिथ के अनुसार धर्म निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता को गारंटी देता है - संवैधानिक रूप से किसी धर्म विशेष से न तो सम्बन्धित है न हो वह किसी धर्म को बढ़ावा देता है अथवा उसमें हस्तक्षेप करता है।¹

भारत में लोकतंत्र को स्थापना करते समय धर्म-निरपेक्षता के सिद्धान्त को अपनाने का मुख्य कारण, धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित को रखा हो, जो आदर्श रखकर किया गया है । भारतीय संस्कृति का मूलमंत्र हो धर्म रहा है, उनका सम्पूर्ण जीवन धर्म से ओत प्रोत रहा है। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत में लिखा है कि धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है, फिर ऐसे धर्म का सेवन क्यों न किया जाए ? पाकिस्तान निर्माण के बाद भारत में 11 करोड़ मुसलमानों के अलावा सिख, पारसो, जैन, बौद्ध आदि अन्य अल्पसंख्यक धर्मावलम्बी हैं। अतः भारत में धर्म निरपेक्ष राज्य की नींव डाली गयी।² डॉनाल्ड यूजोनस्मिथ के अनुसार- चूंकि भारत में अनेक सम्प्रदाय और मत मतात्तर है, इसलिए भारत में राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को मान्यता देना अच्छा नहीं समझा गया ।

1- नवभारत टाइम्स- सम्पादकीय 24 जुलाई 92 पृ06

2- फिर वही,

भारतीय गणतंत्रिय संविधान में स्वतंत्रता आन्दोलन के आदर्शों और बहुत से देशों को अच्छी बातों को शामिल किया गया है। इसमें सभी तरह के अल्पसंख्यकों - धार्मिक भाषायों और सांस्कृतिक आदि को अनेक तरह से रक्षा की व्यवस्था की गयी है। अनुच्छेद 25 के अनुसार अन्तःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म को मानने, उस पर आचरण करने और धार्मिक प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारण्टी देता है। अनु 26 में धार्मिक मामलों का प्रबन्ध बिना किसी प्रकार के हस्तक्षेप के साथ करने की गारण्टी दी गयी है। अनु 27 में किसी विशेष धर्म की उन्नति प्रचार प्रसार के लिए करो की वसुली पर प्रतिबंध लगाया गया है और अनुच्छेद 28 में सरकारो धन से चलने वाली शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा न देने की गारण्टी दी गई है और धार्मिक उपासना में उपस्थित न होने की छुट दी गई है। संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण दिया गया है और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपने पसन्द की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है।¹

भारतीय संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता सम्बन्धी ये उपबंध धर्म निरपेक्ष अथवा अताम्प्रदायिक राज्य की आधारशिला है। डॉ० सुभाष कश्यप लिखते हैं - भारत जैसे देश में जहाँ अनेक धर्म जन्मे और आज भी फले-फूल रहे हैं, धर्म निरपेक्षता का सिद्धान्त विशेष महत्व रखता है।¹

भारत में सरकार भारतीय संविधान में उल्लेखित अल्पसंख्यकों के हितों के प्रति पूर्ण रूप से बचन बद्ध है।

साम्प्रदायिकता :

साम्प्रदायिकता के अन्तर्गत वे सभी भावनाएँ व क्रिया-कलाप आ जाते हैं जिसमें किसी धर्म अथवा भाषा के आधार पर किसी समूह विशेष के हितों पर बल दिया जाता है तथा उन हितों को राष्ट्रिय हितों के ऊपर प्राथमिकता दी जाती है तथा उस समूह में पृथक्ता की भावना उत्पन्न की जाती है तथा प्रोत्साहन किया जाता है। भारत में पारसियों, बौद्धों, जैनो तथा ईसाइयों के अपने-अपने संगठन हैं साथ ही वे अपने सदस्यों के हितों को साधना में लिप्त रहते हैं, परन्तु ऐसे संगठनों को प्रायः साम्प्रदायिक नहीं कहा जाता है क्योंकि वे पृथक्ता की भावना से प्रेरित नहीं हैं। इसके विपरीत, मुस्लिम लोग, हिन्दु महासभा तथा अन्य कुछ संस्थाओं को साम्प्रदायिक कहा जाएगा क्योंकि धार्मिक अथवा भाषा समूहों के अधिकारों तथा हितों को राष्ट्रिय हितों के ऊपर रखते हैं। विलेड स्मिथ " के शब्दों में एक साम्प्रदायिक व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह वह है जो कि प्रत्येक धार्मिक अथवा भाषायी समूह को एक ऐसे पृथक सामाजिक तथा राजनीतिक इकाई मानता है, जिसके हित अन्य समूहों से पृथक होते हैं और उनके विरोधी भी हो सकते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूह को विचार धारा को साम्प्रदायिकता या सम्प्रदायवाद कहा जाएगा। सामान्यतः सम्प्रदायवाद का दृष्टिकोण संकीर्ण होता है। साम्प्रदायिक समुदाय जानबूझकर धार्मिक सांस्कृतिक भेदों के आधार पर राजनीतिक मणि रखने का निर्णय करता है तब साम्प्रदायिक चेतना सम्प्रदाय के रूप में एक राजनीतिक सिद्धान्त बन जाती है। राजनीतिक स्वायत्तता को तब सांस्कृतिक स्वायत्ता सुरक्षित रखने की अनिवार्य शर्त घोषित कर दिया जाता है। बहुसांस्कृतिक समाज में सामाजिक तनाव तथा टकराव वास्तव में विभिन्न समूहों के बीच चल रहे सत्ता

द्वन्द्व के लक्षण है । इस पारस्परिक द्वन्द्व को सैद्धान्तिक स्तर पर धर्म की शिला पर खड़ा करना एक राजनैतिक विचारधारा के रूप में सम्प्रदायवाद का मूल सार है ।¹

भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता का उदय :

मानव इतिहास में धर्म के नाम पर अनेक विवाद उठते रहते हैं । धर्म की दृष्टि से भारत विशेष रूप से हतभाग्य रहा है स्वाधीनता आन्दोलन के समय अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन बनाए रखने के लिए धार्मिक भेद-भावों का विशेष लाभ उठाया । अंग्रेजी शासन काल में साम्प्रदायिक भावनाओं को राजनैतिक रूप मिलने का एक कारण यहाँ प्रतिनिधित्व या निर्वाचित संस्थाओं की स्थापना थी । अंग्रेज लोग प्रतिनिधित्व का अर्थ अलग-अलग समूहों, वर्गों, हिंदु, क्षेत्रों, संस्थाओं और सम्प्रदायों का प्रतिनिधित्व समझते थे । उन्होंने भारत में अनेक सम्प्रदायों और जातियों को समस्या को अनेक स्वाभाविक अस्तित्व बोध और एक दूसरे को आपसो वैमनस्यता की समस्या समझा और उसका उपाय अलग-अलग धार्मिक समूहों को पृथक-पृथक प्रतिनिधित्व देने में समझा । भारत में साम्प्रदायिकता की समस्या ब्रिटिश शासन के समकालीन है । अंग्रेजों में भारत में फूट डालो और शासन करो " की नीति अपनायी ताकि वे हिन्दुओं और मुसलमानों को लड़ते रहे और भारत पर अपना हुकूमत चलाते रहे । अपनी इसी नीति के तहत 1905 में कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया । भारतीय मुसलमानों के राजनैतिक एवं अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए 1906 में ढाका में मुस्लिम लोग की स्थापना हुई । 1908 में लोग ने मुसलमानों को आबादों से अधिक स्थान दिए जाने की मांग की । 1909 में मार्ले मिन्टो सुधारों

1- दीक्षित प्रभा - साम्प्रदायिकता का ऐतिहासिक सन्दर्भ, मेकमिलन

में साम्प्रदायिक आधार पर पृथक चुनावों की व्यवस्था की गई । 1910 के लखनऊ पैक्ट के अन्तर्गत मुसलमानों के लिए प्रतिनिधित्व गुरुरता के सिद्धान्त को स्विकार कर लिया, जो एक दम गलत था ।¹ 1919 के एक्ट में साम्प्रदायिक निर्वचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए सिद्धांत किया गया । वरन सिक्खों यूरोपियनों और आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए भी इसे अपना लिया गया । तन् 1928 के बाद जिन्ना साम्प्रदायिक राजनीति के खलनायक बन गये । तन् 1935 के अधिनियम द्वारा साम्प्रदायिक निर्वचन पद्धति का विकास किया गया तन् 1940 में जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धान्त का प्रतिपादन किया और अन्त में 1949 में साम्प्रदायिकता के आधार पर भारत का विभाजन हुआ । भारत की संविधान निर्मात्री सभा का शुरू में गठन § 1946§ प्रान्तों की विधान सभाओं के सदस्यों के साम्प्रदायिक समूहों द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से हुआ ।²

साम्प्रदायिकता की समस्या के कारण :

स्वाधीनता से पूर्व अंग्रेजों ने फूट डालों एवं राज्यकारों की नीति अपनायी थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के पश्चात् की साम्प्रदायिकता भारत के लिए विशेष समस्या रही है स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई चुनावों की राजनीति में धर्म एवं संप्रदाय के नकारात्मक महत्व की उभार है।

ऐसा माना जाता रहा है कि देश में कुछ मुसलमानों में पृथक्करण की भावना आज भी विद्यमान है और वे अपने को आज भी राष्ट्रीय धारा में समाविष्ट नहीं कर पाये । कुछ मुस्लिम नेताओं ने स्वाधीनता

1- एम. सत्या राय - भारत में राष्ट्रवाद पृ० 124

2- फिर वही,

के बाद इस बात का प्रचार किया कि उन्हें मुख्य राष्ट्रीय प्रवाह में शामिल होने के लिए ऐसे राज्यनौतिक दलों को सहयोग देना चाहिए जिसका विश्वास धर्म निरपेक्षता, समाजवाद तथा आर्थिक स्थाय में हो परन्तु इन विचारों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा और कुछ मुस्लिम नेताओं ने इस बात का प्रचार किया कि मुस्लिम सम्प्रदाय के हितों के लिए उन्हें पृथक रूप से भाग लेना चाहिए।¹ ऐसे ही एक दूसरे संगठन जमोमत उल-उलेमा-ए-हिन्द ने भी मुसलमानों को राष्ट्रीय राजनीति से पृथक रहने की सलाह दी। 1948 में मुस्लिम लोग ने पृथक निवचिन की मांग की। 1961 में अखिल भारतीय मुस्लिम लोग की स्थापना की गई और यह प्रचार किया गया कि भारत में मुस्लिम लोग ही मुस्लिम हितों का संरक्षण कर सकते हैं। सन् 1971 के मध्यावधि चुनावों के समय नई दिल्ली में ~~इस~~ के अधिकांश भागों के मुस्लिम प्रतिनिधियों ने अखिल भारतीय राजनौतिक सम्मेलन आयोजित किया। इसके पीछे जमायत-ए-इस्लाम का हाथ था। इस प्रकार कुछ ध्वनिध मुस्लिम संगठनों ने सम्प्रदायवाद का कभी उन्मूलन नहीं होने दिया।

अंग्रेजों काल से ही मुसलमान आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए रहे हैं। स्वाधीनता के बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो पायी। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण सरकारी नौकरियों व्यापार एवं उद्योग धन्यों में उनकी स्थिति नहीं सुधर पाई। आज भी उनका आधुनिकीकरण नहीं हो पाया है इससे उसमें असंतोष बढ़ा एवं उनका मनोबल भी गिरा है। कभी-कभी यह असंतोष उग्र रूप ले लेता है और कभी-कभी यह असंतोष हिंसा का रूप ले लेता है।²

1- फिर वही,

2- राष्ट्रीय सहारा 18 जुलाई 93, पृष्ठ 6

भारत के हिन्दु संप्रदाय में भी ऐसे लोग तथा गुट हैं जो धमन्धता तथा संकोर्ष भावनाओं से ओत-प्रोत हैं। हिन्दु महासभा तथा राष्ट्रिय सेवक संघ विश्व हिन्दु परिषद, शिव सेना, जैसे संगठनों ने हिन्दुओं को धार्मिक भावनाओं को बराबर उत्तेजित किया है। ये लोग यहाँ तक कहते रहे हैं कि भारत हिन्दुओं का देश है और हिन्दु धर्म के अनुयायियों को होइस देश में निवास करने का अधिकार है। राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ मुसलमानों का कट्टर विरोधी रहा है। इसके समर्थकों का मत है कि भारतीय भारतीय राष्ट्रियता का मत हिन्दुत्व हो हो सकता है। इस प्रकार को मनोवृत्ति सांप्रदायिकता उत्पन्न करती है।

सरकार एवं प्रशासन को उदासीनता के कारण भी कभी-कभी साम्प्रदायिक दंगे हो जाते हैं। सामान्य सौ घटना प्रशासन को असावधानों के कई बार साम्प्रदायिक दंगे का रूप ले लेती है।

स्वतंत्रता के बाद हुए साम्प्रदायिक उपद्रवों के अध्ययन से पता चलता है कि उन्में वृद्धि हो रही है किन्तु इस विषय में स्थिति विभिन्न क्षेत्रों एवं नगरों में भिन्न-भिन्न है। ऐसे नगर जिनमें बड़े साम्प्रदायिक उपद्रव हुए हैं दो प्रकार के हैं। एक प्रकार के वे नगर हैं जो औद्योगिक हैं जैसे जमशेदपुर, राउर केला, तथा दूसरे प्रकार जो उद्योग एवं व्यापार के आधुनिक केन्द्रों के रूप में विकसित होने का प्रयत्न कर रहे हैं - जैसे मुराबाद, अलोगढ़, बनारस।¹

साम्प्रदायिक घटनाओं के पोछे विरोधी हाथ होने का आरोप भी आजकल जोर-शोर से सुनाई दे रहा है मुस्लिम देशों और इस्लामो संगठनों को ओर से पिछले एक दशक से इस कार्य के लिए धनराशि प्राप्त होती रही है।² इस क्षेत्र के समृद्ध और सम्पन्न मुसलमानों ने जिनके

छाड़ो के देशों और दक्षिण-पूर्व में स्थित मुस्लिम देशों के साथ सम्बन्ध है मुस्लिम संगठनों के प्रयासों को बढ़ावा दिया है ।¹

इस प्रकार भय, अविश्वास और दोनों सम्प्रदायों के बीच सन्देह साम्प्रदायिक वैमनस्य का मुख्य कारण रहा है और जब सरकार समस्याके भूल कारणों के चर्चा के बजाय विद्वानों धन, विद्वानों हाथ करके सन्तुष्ट हो जाते हैं तो समस्या का भयावह रूप धारण कर लेना स्वाभाविक है ।²

सामयिक राजनीति में धर्म और राजनीतिक दल :

भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्वों में धर्म और साम्प्रदायिकता अत्यन्त प्रभावशाली तत्व है । धर्म का प्रयोग राजनीति में जहाँ एक ओर तनाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता रहा है वही दूसरी ओर प्रभाव और शक्ति अर्जित करने का भी धर्म माध्यम बन गया है । जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुला बुखारी और जय गुरुदेव को राजनीतिक शक्ति को आधार शिला अपने-अपने सम्प्रदायों अनुयायियों को संख्या बल है । धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण होता है चुनावों में समर्थन एवं मत प्राप्त करने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है। जनता से को जाने वाली अपोलों उन्हें दिए जाने वाले आश्वासनों , निवचनों में प्रत्याशियों के चयन तथा मतदान व्यवहार में धर्म का राजनीतिक स्वरूप देखने को मिलता है। स्वतंत्रता के 47 वर्षों बाद भी हिन्दू और मुसलमानों के बीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण दिखाई नहीं पड़ता । वस्तुतः जिन सम्प्रदायों के बीच ऐसा एकीकरण

1- साम्प्रदायिक दंगों में विद्वानों हाथ - कुलदोष नायर - राजस्थान पत्रिका ।

2- फिर वही,

विद्यमान था, उदाहरणार्थ हिन्दुओं और सिक्खों में वहाँ भी रुढ़िवाद एवं साम्प्रदायिकता के बढ़ते हुए विरोध का खतरा पैदा हो गया है। सम्प्रदाय के आधार पर आधारित राजनीतिक दल जैसे मुस्लिम लोग, शिरोमणि अकाली दल, राम राज्य परिषद हिन्दु महासभा आदि में साम्प्रदायिक तत्वों का वर्चस्व रहा है। यदि साम्प्रदायिकता एक रोग है तो वह भी संक्रामक¹ तो इन दलों के शासन और राजनीति पर प्रभाव सहज ही आका जा सकता है। ये साम्प्रदायिक दल धर्म को राजनीति में प्रधानता देते हैं, धर्म के आधार पर चुनावों में प्रत्याशियों का चुनाव करते हैं और सम्प्रदाय के आधार पर वोट मांगते हैं।

प्रो. मारिस् जोन्स ने लिखा है - यदि साम्प्रदायिकता को संकुचित अर्थ में लिया जाए अर्थात् कोई राजनीतिक पार्टी किसी विशेष धार्मिक समुदाय के राजनीतिक दावों को रक्षा के लिए बनो हो तो कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं जो स्पष्ट रूप से अपने को साम्प्रदायिक कहती हैं, जैसे मुस्लिम लोग जो भारत में सिर्फ दक्षिण भारत में रह गये हैं और जो मालाबार मोपला समुदाय के बल पर केवल केरल में ही शक्तिशाली हैं, सिक्खों को अकाली पार्टी तो सिर्फ पंजाब में है, हिन्दु महासभा तो सिद्धान्त रूप से अखिल भारतीय पार्टी है किन्तु मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और उसके आस-पास के इलाकों में शक्तिशाली है।² जनसंघ दल के बारे में मारिस् जोन्स लिखते हैं " जब तक कट्टरता को मनोवृत्ति से पूर्ण आर, एस. एस. जिसमें हिन्दू सांस्कृतिक जोश और सैन्यवादो ट्रेनिंग दोनों का संयोग है, जनसंघ को आड़ में जुटकर काम करता रहेगा, तब तक साम्प्रदायिकता इस पार्टी का महत्वपूर्ण पहलू बनो रहेगा।"³

1- रामधारी सिंह दिनकर ने इसे संक्रामक रोग कहा है

संस्कृत के चार अध्याय " पृ० 638

2- जोन्स मारिस् - भारतीय शासन पद्धति §अनुवाद§ पृ० 190

यदि साम्प्रदायिकता को व्यापक अर्थ में लिया जाए अर्थात् सम्पूर्ण हिन्दू समाज के हों भीतर किसी सामाजिक-धार्मिक समुदाय के साथ सम्बन्ध के रूप में लिया जाए तो सभी पार्टियों में किसी न किसी स्तर पर कुछ न कुछ मात्रा में ऐसी साम्प्रदायिकता अवश्य मिलेगी यहाँ तक कि कांग्रेस भी इससे मुक्त नहीं है केरल में कांग्रेस का ईसाई समुदाय के साथ ऐसा गठजोड़ रहा है कि इसे संकुचित दृष्टि से भी साम्प्रदायिक कहा गया है। यहाँ तक कि साम्यवादियों ने भी कुछ जगहों पर कतिपय प्रयोजनों के लिए साम्प्रदायिक क्षेत्र तैयार कर लिए हैं।¹

अल्प संख्यक वोट की राजनीति -

भारत में अधिकांश राजनीतिक दल और उनके नेता चुनावों में धर्म और समुदाय के आधार वोट मांगते रहे हैं। वोट वटोरने के लिए मठाधीशों, इमामों, पादरियों के साथ-गोठ की जाती है।²

स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने मुसलमानों में धर्म निरपेक्ष दल के रूप में अपनी छवि बनायी। धर्म-निरपेक्षता के सिद्धान्त को स्विकार कर लेने के बावजूद भी कांग्रेस ने कुर्सी बनाए रखने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को सोने से चिपकाए रखा जिसके कारण 1955 में जनसंघ पार्टी का उदय हुआ। राष्ट्रीय सेवक संघ ने जनसंघ के राजनीतिक आधार को मजबूत किया एवं फैलाया। इन दोनों संगठनों से खतरा महसूस होने के कारण मुसलमानों में यह भावना बलवती हुई कि केवल कांग्रेस ही उनकी रक्षक है। इससे मुस्लिम मतदाताओं ने चुनावों में उसे अखि बंद में समर्थन दिया। 1952, 1957, 1967 तक के चुनावों में तत्कालीन

1- फिर वहो,

2- नवभारत टाइम्स पृष्ठ 743

सत्ताधारी कांग्रेस मुस्लिम समाज के अधिकांश वोट बटोरती रही। लेकिन 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन कम होने का झटका महसूस हुआ। साम्यवादो दलों के शुरू होते प्रभाव ने पढ़े-लिखे प्रगतिशील मुसलमानों को आकर्षित किया। मुस्लिम दलों और संगठनों ने क्षेत्रीय दलों के साथ समर्थन किया। कांग्रेस में आन्तरिक खोच-तान, आर्थिक नीतियों को आंशिक असफलता तथा कानून एवं व्यवस्था में गिरावट आदि से आम जनता के साथ मुस्लिम मतदाताओं का भी कांग्रेस में विश्वास कम हुआ।¹

1968 में देश में 346 बार दंगे हुए, जबकि 1970 में साम्प्रदायिक दंगों की संख्या 521 थी।² इन साम्प्रदायिक दंगों एवं राष्ट्रीय स्तर पर सेवक संघ का हौवा खड़ा करके श्रीमती इंदिरा गान्धी ने मुस्लिम अधिकारों का ठेका लेने की बागडोर बड़ी चतुराई से संभाली। जिसका परिणाम हुआ 1971 एवं 1972 के चुनावों में मुस्लिमों का कांग्रेस को समर्थन एवं कांग्रेस की अद्भुत विजय। 1975 में थोपे गये आपातकाल में जबरन नसबंदों के कार्यक्रम से मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस से एकदम नाराज हो गया। 1977 के चुनाव में दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम जैसे अनेक मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस के विरुद्ध नवगठित जनता पार्टी के पक्ष में खुल्लम खुल्ला प्रचार से मुस्लिम मतदाताओं को नाराजगी की आग में घोंघा का काम किया। इस चुनाव में कांग्रेस को हार में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

1- फिर वही,

2- फिर वही,

जनवरी 1980 के चुनाव में शाही इमाम को मांग थी कि लोक सभा, राज्य सभा तथा मंत्रिमंडल में मुसलमानों को बस प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिले व राज्यों में वहाँ की जनसंख्या के अनुसार उन्हें प्रतिनिधित्व मिले। पुलिस एवं सेना में उनके बस प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहे। मुसलमानों के वोट प्राप्त करने के लिए जनता पार्टी और कांग्रेस §आई§ ने अपने-अपने चुनाव घोषणा पत्रों में अल्पसंख्यकों कई प्रावधान किए। कांग्रेस §इ§ के चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया §1§ अल्प संख्यक आयोग को कांग्रेस मजबूत करेगी। §2§ अलोगढ़ विश्वविद्यालय के मुस्लिम स्वरूप को सुनिश्चित किया जाएगा। §3§ अल्प संख्यकों की विधि व्यवस्था तथा रक्षा कार्मिक सहित सभी सरकारी सेवाओं में नौकरों में उचित अवसर दिये जायेंगे §4§ उर्दू को उसका उचित स्थान दिया जाएगा तथा खास-खास क्षेत्रों में सरकारी राज-काज के व्यवहार के लिए दूसरी भाषा के रूप में उर्दू को मान्यता दी जाएगी।¹

1980 के लोक सभा चुनावों में जनता पार्टी के पराजय का एक कारण उसे अधिसंख्य मुस्लिम वोटों का न मिलना था। मुसलमानों की जनता पार्टी के प्रति नाराजगी का मुख्य कारण उसके शासन के दौरान अलोगढ़ विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक स्वरूप न प्रदान करना न उर्दू को संवैधानिक संरक्षण मिलना था। इसके साथ साम्प्रदायिक दंगे भी 1977 में 108 बार 1978 में 230 बार, 1979, 304 भी हुए जिसको रोक पाने में जनता पार्टी सरकार असफल रही।² ऐसी स्थिति में कांग्रेस §आई§ लोकदल तथा समाजवादी गुट ने जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वर्चस्व का हौवा खड़ा करके उसके मुस्लिम विरोधी होने की छवि बना दी।

1- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस §इ§ चुनाव घोषणा पत्र, 1980

2- खान खां उद्दोन -भारत में लोकतंत्र पृ० 212

1984 के चुनाव में एवं इसके पश्चात् के सभी चुनावों में प्रत्येक राजनैतिक पार्टियों ने वोटों को राजनीति के चलते अपने चुनाव घोषणा पत्रों में अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में कहती रही है क्योंकि अल्पसंख्यक होने के नाते वे प्रायः बहुसंख्यक हिन्दु समाज के वर्चस्व के डर से एक जुट होकर मतदान करते हैं ।

मुस्लिम समाज में राजनैतिक नेताओं को अपेक्षा धार्मिक नेता ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए चुनाव से पहले पार्टियों के नेता इन धर्म के शुभचिंतक शाहो इमामों से अपने पार्टियों के पक्ष में मत दिलवाने की याचना करते हैं । 1984 के चुनाव से पूर्व विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जामा मस्जिद के शाहो इमाम अब्दुल्ला बुखारो से जनता दल के लिए याचना की । अब्दुल्ला बुखारो ने मुस्लिम समुदाय से जनता दल को वोट देने की बात कही, जिसका परिणाम था जनता दल को बहुसंख्यक मुस्लिम वोट का मिलना। मुस्लिम शाहो इमामों के इसरूख को देखकर कितने संवाद-दाता ने लिखा है कि " सवाल उठता है कि समाजवाद और गणतंत्र की बात करने वाले अगर इमाम के नाम से वोट पाना चाहें तो हो सकता है कि बलराज मधीक जैसे लोग शंकराचार्य के नाम पर वोट मांगने लगे । फिर क्या इस देश को इमाम और शंकराचार्य के बीच चुनाव करना पड़गा । "

राज्यों की राजनीति में धर्म की प्रभावक भूमिका :

धर्म और धार्मिक समुदायों का केरल एवं पंजाब की राजनीति पर भरपूर प्रभाव देखने को मिलता है।

केरल को राजनीति का उमरो आवरण भले हो वामपंथी रंग में रंगा हुआ नजर आए किन्तु अन्तरंग धार्मिक एवं सामुदायिक गठजोड़ से बनता है ।¹

राज्य राजनीति में दो प्रकार के दबाव समूह पाए जाते हैं साम्प्रदाय और व्यावसायिक । साम्प्रदायिक दबाव समूहों में मे नय्यर सर्विस सोसायटी, श्री नारायण धर्म परिपालन युगम् और अनेक इसाई संगठन प्रमुख हैं प्रगतिशील समझे जाने वाले साम्यवादो दल भी केरल में धार्मिक दबाव गुटों से अपना तालमेल बिठाकर चुनावो रणनीति तैयार करते हैं ।

धर्म और राजनीति का सम्बन्ध पंजाब राज्य को राजनीति में विशिष्ट स्थान रखता है।² पंजाब को राजनीति सदा ही अकालो दलों को आन्तरिक राजनीति तथा सशक्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटो के ईद-गिर्द घुमती रहती है । शिरामणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटो के चुनाव प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अकालो दल को राजनीति को प्रभावित करते हैं, और अकालो दल पंजाब को राजनीति को । सिक्ख जाति के सर्वोच्च धार्मिक नेताओं द्वारा अकाल तख्त से जारी किए गए फरमान ने अकालो दल के प्रधान का चुनाव रोक दिया।³ स्वर्ण मन्दिर के सामने अकाल तख्त को स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने एक राजनीतिक शक्ति के रूप में की थी । पंजाब को राजनीति में अकाल तख्त का स्वरूप एवं भूमिका

1- द पार्लिटिक्स आफ केरला, सेंटर्स राउंड इट्स थो कम्युनिटीज

एंड देअर इंटर कास्ट एलाइमेंट - नारायण इकबाल -

स्टेट पार्लिटिक्स पृ० 258-59

2- आनन्द जे. सो. - पंजाब पार्लिटिक्स -सर्वे ।

3- दिनमान 25-31 मार्च, 1979 पृ० 22

एक समानांतर सरकार की है जिस पर समकालीन सरकार के आदेश लागू नहीं होते धार्मिक विवादों के साथ-साथ राजनैतिक विवादों का फैसला अकाल तख्त, अनेकोंबार करता रहा है।

सन् 1979 में अकाली दल विभाजित सा था इस बात को लेकर मतभेद था कि केन्द्र में चरण सिंह गुट § जनता एस § को समर्थन दिया जाए या जनता पार्टी को। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और अकाली दल के अध्यक्ष जगदेव सिंह तलवण्डो एक - दूसरे के विरोधी नजर आ रहे थे। अकाल तख्त के पंज प्यारों ने अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष तलवण्डो को यह सजा सुनाई कि वह एक सप्ताह तक लंगर के जूठे बर्तन साफ करें, अकाल तख्त पर 21 रुपये कड़ाह प्रसाद तथा 101 रुपये नगद गोलक के लिए चढ़ाये सितम्बर 1985 के लोक सभा एवं विधान सभा चुनावों में अकाली दल ने चुनाव प्रचार में गुरूदारों का भी उपयोग किया।¹ इस प्रकार पंजाब की राजनीति पर अकाली दल एवं अकाल तख्त का प्रभाव रहता है।

इस प्रकार भारतीय राजनीति अभी धर्म निरपेक्ष नहीं हो पाई है भले ही भारत का संविधान धर्म निरपेक्ष हो। इसका तात्पर्य यह है कि व्यवहारिक रूप से धर्म का प्रभाव भारतीय जनता के मस्तिष्क से नहीं मिटा है और आज भी राजनैतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। राजनीतिज्ञ एवं राजनैतिक दल धर्म एवं सम्प्रदाय को वोट बैंक मानकर राजनैतिक सफलता के लिए साधन के रूप में इस्तेमाल करते रहें हैं। मंत्रिमंडल के निर्माण में तथा चुनावों के समय टिकट के बँटवारे के लिए धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व की माँग की जाती रही है।

1- ई. पो. डब्लू डो - कोस्ट * हिन्दु मतदाता के मानस परिवर्तन में अकाली दल विजयो, राजस्थान पत्रिका उदयपुर 29 सितम्बर, 1985 पृ 0।

धर्म निरपेक्ष हिन्दु नेताओं ने मतदाताओं के रूप में मुसलमानों को हैसियत समाप्त करके उन्हें मजबूत वोटों में बदल दिया है तो सम्प्रदायवादी मुस्लिम नेताओं ने इस वोट शक्ति को अपने सोमित लक्ष्यों को प्राप्ति का साधन बना लिया है। राजनीतिक दल इस डर से साम्प्रदायिकता से बचना चाहते हैं कि वे एक दूसरे सम्प्रदायों का वोट खो दें, परन्तु उनके स्थानीय संगठन स्थानीय झगड़ों का लाभ उठाने के प्रलोभन में पड़ जाते हैं। साम्प्रदायिक झगड़े भले हों छुट पुट एवं स्थानीय हों लेकिन उससे देश को बदनाम होतो है और उसका लोकतंत्रो धर्म निरपेक्ष स्वरूप कलंकित होता है।¹

इस प्रकार भारतीय राजनीति में धर्म एवं साम्प्रदायिकता बढ़ने से धर्म निरपेक्ष राजनीति के विकास का मार्ग अवरोध हुआ है। साम्प्रदायिक मत प्राप्त करने के लिए दलों में तुष्टीकरण की नीति से जनमानस के मन में भारतीय राजनीतिक दलों के प्रति घृणा पैदा हुई है। यह दायित्व अब राष्ट्रीय नेताओं का बनता है कि वे समुदाय के सोमित तथा राष्ट्र के बृहतर हितों के प्रति सन्तुलन पैदा करें, प्रत्येक समुदाय के सामने अपने को निष्पक्ष साबित करें तथा समुदाय को राष्ट्र में बदलें।

अध्याय - 6

राजनोति का अपराधीकरण

अध्याय - 6

राजनैति का अपराधोकरण

भारतीय राजनैति में धन एवं अपराध की भूमिका-

पिछले दो दशकों से भारतीय राजनैति में अपराधोकरण की प्रवृत्ति का व्यापक स्तर पर विस्तार हुआ है। वर्तमान में हालत यह है कि देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ संगठित अपराधियों का गिरोह परोक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर राजनैतिक गतिविधियों में लिप्त न हो। यही वजह है कि विदेशी भाषा का शब्द "मार्फिया" अब भारतीय समाज में अत्यंत प्रचलित हो चुका है जो वास्तव में सिसली इटली के अपराधी गिरोहों के लिए प्रयुक्त होता है। दरअसल राजनैतिक दल या उसके उम्मीदवार सरकार पर दबाव डालने के लिए मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए, जाली मतदान के लिए अपराधियों का सहारा लेते हैं। इसके बखले में उपहार स्वरूप वे अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण देते हैं। आगे चलकर अपराधियों को यही जमात सीधे तौर पर राजनैति में प्रवेश करती है और यही से शुरू होता है राजनैति का अपराधोकरण।

विगत कुछ वर्षों से भारतीय राजनैति के अपराधोकरण के मुख्य कारकों में रैली, बंद, भीड़, जन-आन्दोलन उग्र प्रदर्शन जुलूस, हड़ताल एवं धन का बढ़ता प्रभाव आदि रहे हैं। निर्वाचित सरकार का सार्वजनिक विरोध और प्रत्यक्ष कार्यवाही हमारे संसदीय लोकतन्त्र के सहचर प्रतीत होते थे।¹

भारत में जन आन्दोलन की राजनैति के सूत्रपात का श्रेय महात्मा गाँधी को जाता है जिन्होंने परतंत्र भारत की बेड़ियों को तोड़ने के लिए सत्याग्रह के माध्यम से सुपुष्ट जनता में चेतना का संचार किया। गाँधी जी द्वारा संचालित असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन और भारत

1- महेन्द्र के. सी. : पब्लिक प्रोटेस्ट्स एण्ड सिविल डिस्अबेडिअन्स इन इंडिया पार्लिटिकल साइंस रिव्यू अंक -1-4, दिसम्बर जनवरी 1979, पृष्ठ संख्या 195

छोड़ो आन्दोलन ब्रिटिश सरकार को दबाने के महान्तम अस्त्र थे जिनके प्रबलतम जन समर्थन के कारण उसे झुकना पड़ा एवं भारत को आजादी मिली । स्वातन्त्र्योत्तर भारत में उग्र प्रदर्शन, हिंसा एवं आन्दोलन को राजनीति की शुरूआत का श्रेय भारतीय साम्यवादो दल को है । 1948 ई० में कलकत्ता में भारतीय साम्यवादो दल का जो सम्मेलन हुआ उसमें पारित प्रमुख राजनीतिक प्रस्ताव जिसे "कलकत्ता थोसिस" कहा जाता है घोषित किया गया कि भारत में क्रांति की लहर गतिशील है, क्रांति की अन्तिम अवस्था सशस्त्र संघर्ष की अवस्था में आ गई है । यह क्रांति जनतांत्रिक विप्लव का कार्य पूरा कर देगी और उसके साथ ही समाजवाद की स्थापना हो जाएगी । कलकत्ता थोसिस में यह भी कहा गया है कि भारत सरकार को । तदनुसार सम्पूर्ण भारत में ह्दयरंजित क्रांति प्रारम्भ कर दी गयी, बैकों में डाके डाले गये, ट्रेनों में डकैती एवं लूटपाट की अनेक घटनाएँ हुई ।¹

चतुर्थ आम चुनावों के बाद विरोधी राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक सत्ता अनेक पार्टियों और समूहों के बाँटे जाने के पश्चात् कांग्रेस सरकार को हटाने के लिए आन्दोलन का सहारा लिया जिनमें से मुख्य हैं ।

1- गुजरात आन्दोलन :

1 जनवरी 1973 से भारतीय जनसंघ और संगठन कांग्रेस ने गुजरात में आन्दोलनात्मक रवैये का सहारा लिया । राजकोट में बंद का आयोजन किया गया और इस सिल-सिले में निकाला गया जुलूस हिंसा पर उतारू हो गया और पुलिस को इसे तितर-बितर करने के लिए गोली चलाना पड़ी । इसके बाद सुरेन्द्रनगर में "बन्द" का आयोजन किया । इस बीच छात्र समुदाय को भी आन्दोलन में शामिल कर लिया गया । छात्रों ने प्रदर्शन किए और आगे चलकर हिंसात्मक हरकतों की । जिसके कारण 10 जनवरी को अहमदाबाद बन्द का आयोजन हुआ । विभिन्न राजनीतिक दलों ने गुजरात के अनेक नगरों में बन्द

1- फिर वही,

का आह्वान किया, जुलूस निकाले और कई स्थानों पर धरना दिया । अहमदाबाद के छात्रों ने " नव निर्माण " समिति" का निर्माण किया जिसने आन्दोलन का नेतृत्व करने का निश्चय किया । विरोधी दल एक तरफ राज्य विधान सभा को भंग करने और नये चुनाव कराने को अपनी मांग पर जोर देते रहे तो दूसरी तरफ आन्दोलन के नेताओं ने कांग्रेस मंत्रिमंडल विशेषकर मुख्यमंत्री को अपने आक्रमण का मुख्य निशाना बनाया । जिसके कारण चिमन भाई पटेल को त्याग पत्र देना पड़ा एवं राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ । इस आन्दोलन के माध्यम से विधान सभा भंग कराने के लिए विरोध स्वरूप लूट एवं आगजनों को घटनाएँ हुई, बंसो पर पथराव जारी रहे । गुजरात आन्दोलन के परिणाम स्वरूप बहुत से निर्दोष लोग मारे गये और बहुतों को छोटे आयों जिनमें कुछ पुलिस के आँखों भी शामिल थे । 95 व्यक्ति मरे और 933 व्यक्ति घायल हुए । लूट और आगजनों के 896 मामले हुए जिनके परिणाम स्वरूप 2.5 करोड़ रुपये से अधिक को सरकारों एवं निजी सम्पत्ति नष्ट हुई ।¹

बिहार आन्दोलन :

बिहार में आन्दोलन मुख्यतः छात्रों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्य बेरोजगारों को बढ़ती समस्या आदि से सम्बन्धित अपने रोष को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया था । परन्तु गुजरात में मिली सफलता के उन्माद में विभिन्न राजनैतिक दलों और असमाजिक तत्वों ने 10 मार्च 1974 को पटना में प्रदर्शन को एक महायोजना बनायी । इस प्रदर्शन का उद्देश्य विधान मंडल के संयुक्त सत्र में वार्षिक अभिभाषण देने के लिए राज्यपाल को विधान भवन में जाने से रोकना बताया गया । बाद में प्रदर्शन व्यापक हिंसा और तोड़-फोड़े में परिवर्तित हो गया जिसमें 20 व्यक्तियों को जाने गये और सम्पत्ति को भारी हानि हुई ।² विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं ने श्री जय प्रकाश

नारायण से भेंट को और इस आन्दोलन का नेतृत्व संभालने के लिए अनुरोध किया और अप्रैल 1974 के शुरू में वे उनके अनुमति पाने में सफल हो गये। जय प्रकाश नारायण को राजनीतिक दलों द्वारा सम्भवतः ये आश्वासन दिया गया कि विधान मंडल को भंग कराने के समर्थन में उनके सदस्य पूर्ण रूप विधान सभा से त्याग पत्र दे देंगे लेकिन सभी सदस्यों द्वारा इस्तोफा न देने पर उन्हें बल प्रयोग द्वारा उन्हें त्याग पत्र देने के लिए बाध्य किया गया।¹

छात्रों से कहा गया कि वे परीक्षाओं का बहिष्कार करें एवं। वर्ष के लिए कालेजों का बहिष्कार करे। परीक्षार्थियों में आतंक फैलाने के लिए एक विद्यार्थी को गोली मार दो गयी आन्दोलन की गति तेज करने के लिए 3-5 अक्टूबर 1974 तक बिहार बंद का आह्वान किया गया।

बन्द के दौरान हिंसा को अनेक घटनाएँ हुईं। 4 नवम्बर को एक विशाल प्रदर्शन के लिए, विधान सभा एवं विधान सभा सदस्यों के घेराव के लिए भारी भीड़ इकट्ठी हुई, सचिवालय के सामने धरना दिया गया। उदिसम्बर 1974 से इस आन्दोलन के नेताओं ने ग्रामों में छात्र संघर्ष समिति * जन संघर्ष समिति आदि स्थापित करने और समानान्तर सरकार स्थापित करने जैसे कार्यों को ओर ध्यान दिया गया। 19 फरवरी 1975 को पटना में एक रैली का आयोजन किया गया। बिहार में इस दीर्घकालीन आन्दोलन के दौरान हिंसा के 544 मामले हुए। पुलिस को 54 बार गोली चलाने पड़ी। हिंसा की घटनाओं के परिणामस्वरूप 500 से अधिक लोगों को चोटे आयो और 70 व्यक्ति मरे। पुलिस के अनेक कर्मचारियों को चोटे आयो। बिहार आन्दोलन के माध्यम से जनप्रकाश नारायण ने लोक-तंत्रात्मक कार्यों को सभी स्तरों पर खत्म करने और संवैधानिक अधिकार के अधीन गठित व्यवस्था को भंग करने के लिए, आपराधिक राजनीति की परम्परा को अंगे बढ़ाया।²

1- नवभारत टाइम्स - 27 सितम्बर 1974

2- टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूरो

रेल्वे हड़ताल :

मई 1974 को रेल्वे हड़ताल वास्तविक रूप से राष्ट्रीय विनाश के आन्दोलन के एक अंग थी। रेल्वे को हड़ताल से आवश्यक चोजों और औद्योगिक उत्पादनों आदि के लाने ले जाने के कार्यों में रुकावट पड़ने के कारण देश में दुर्घवस्था और गड़बड़ो पैदा हुई। जार्ज फर्नण्डोज ने कहा कि रेलवे परिवहन को पूरी तरह ठप्प करके कितने भी समय सरकार को गिरा सकते हैं..... भारतीय रेल्वे के 15 दिनों के हड़ताल का अर्थ होगा - देश भूख से मर जायगा। अपनी योजना को ठपापक बनाने के लिए जार्ज फर्नण्डोज ने रेलवे कर्मचारों राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन किया और हड़ताल का वातावरण बनाने के लिए देश का दूर-दूर तक दौरा किया। प्रशासन तन्त्र को पूर्णतः बन्द करने के लिए मार्क्सवादो साम्यवादो दल ने "रेल्वे हड़ताल" के समर्थन में उसी समय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा एक सहानुभूति पूर्ण हड़ताल करवायी। रेल्वे हड़ताल के समय अनेक जगह तोड़-फोड़े को गयो।¹

गुजरात में आरक्षण विरोधी आन्दोलन -

राज्य विधान सभा निवचिन १ फरवरी 1985 से पूर्व गुजरात को सोलंकोसरकार ने 11 जनवरी 1985 को पिछड़े वर्गों के लिए 18 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण और सहूलियतों को घोषणा की। ऐसा समझा गया था कि यह घोषणा राणे आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गयी है। 18 प्रतिशत के इस आरक्षण के फलस्वरूप आरक्षण का कुल प्रतिशत बढ़कर 49% हो गया। क्योंकि 21% आरक्षण तो संवैधानिक प्राविधानों के तहत पहले से था।²

सोलंको पिछड़े वर्गों को खुश करने को कोशिश कर रहे थे, जो राज्य को कुल आबादी का 70 प्रतिशत है और जिन्हे आमतौर पर कग्रेसईई का वोट

1- टाइम्स ऑफ इण्डिया ब्यूरो

2- नवभारत टाइम्स पृष्ठ 1, 22 जनवरी 1985

बैक माना जाता है । वस्तुतः राणे आयोग को सिफारिश सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के बारे में है और इसके तहत वो सभी लोग आते हैं जिसकी वार्षिक आय दस हजार से कम है ।¹

इस आरक्षण के खिलाफ आन्दोलन को शुरूआत छात्रों एवं अभिभावकों ने की । भारतीय जनता पार्टी ने बाद में इस आन्दोलन का समर्थन कर दिया । गुजरात में हिंसा, अराजकता, साम्प्रदायिक एवं जातीय दंगों की आग जलने लगी और करीब एक सौ से अधिक लोग मारे गये । आरक्षण विरोधी आन्दोलन से उपजी हिंसा, अराजकता को आग जातीय संघर्ष, पंचायत कर्मचारियों को हड़ताल राज्य कर्मचारियों को हड़ताल ने असुरक्षा एवं अराजकता फैला दी । सोलंकी सरकार ने आरक्षण के बड़े हुए कोटे को वापस ले लिया ।²

हिंसा को राजनीतिक शस्त्र के रूप में प्रयोग :

8 वें दशक के प्रारम्भ से भारतीय राजनीति हिंसक हो गई है । इसका तात्पर्य यह है कि हिंसा को राजनीतिक शस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसका मुख्य कारण यह है कि देश की जनता में यह विश्वास घर कर गया है कि हमारी सरकार केवल दबाव की भाषा जानती है। यदि सरकार के सामने न्यायोचित मांग प्रस्तुत की जाती है तो उसके कान मर जूँ नहीं रेंगती जब तक तोड़-फोड़ और आन्दोलन के द्वारा आँधी नहीं खड़ी कर दी जाती । जैसा कि माइनर वोनर ने लिखा है " सरकार कोई रियायत तभी देने को तैयार होती है जब किसी जन आन्दोलन में शक्ति एवं व्यवस्था का खतरा होता है, यह इसलिए नहीं कि सरकार आन्दोलनकारियों को मांगों को उचित मानती है, बल्कि इसलिए इससे सरकार को मांग करने वाले समुदाय की ताकत और उनकी विनाशिता की धमती का आभास होता है।³

1- नव भारत टाइम्स 22 जनवरी 1985 पृष्ठ 1

2- नव भारत टाइम्स 22 जनवरी 1985 पृष्ठ 1

3- वोनर माइनर -अपने ग्रंथ पार्लिटिक्स ऑफ स्करसिटो में लिखते हैं

हिंसा को राजनैतिक अस्त्र के रूप में विशेषतः उत्तर पूर्व के राज्यों एवं उत्तर भारत के जम्मू-काश्मीर एवं पंजाब राज्यों में विशेषतः इस्तेमाल किया गया है। असम में 1979 से गण सत्याग्रह आयोजित किया गया । आन्दोलन को शुरूआत अखिल असम विद्यार्थी संघ ने किया । जगह-जगह असम बन्द आयोजित किये गये । सरकार के असम में 1980 का लोक सभा चुनाव करवाना कठिन हो गया और चुनाव स्थगित करने पड़े । 19, 20 एवं 30 नवम्बर 1981 को असम में आन्दोलन कार्यियों द्वारा आयोजित बंद तथा रास्ता रोको अभियान को जोरदार सफलता यहाँ को जनता के जोश एवं हिंसक आन्दोलन के प्रति आस्था का परिचायक था । इस प्रकार के हिंसक आन्दोलन आगे भी होते रहे जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1985 को असम समझौता हुआ ।

सन् 1980 के बाद से अकाली नेताओं और अंग्रेजो पट्टे-लिखे कुर्सी लोभी राजनेताओं के प्रयासों से पंजाब में खालिस्तान आन्दोलन को लागू लगाई गई शहरों एवं कस्बों में खतरे में हैं के नारे लगाकर सिक्खों को भड़काया गया। पंजाब में यह प्रचार किया गया कि सिख हिन्दु नहीं बल्कि अलग कौम है । अपने राजनैतिक इच्छाओं को तृप्ति के लिए सन्त जनरैल सिंह भिंडरवाले जैसे कट्टर सिक्खों ने गुरुद्वारों तक को अछुता नहीं छोड़ा , इन्होंने सिख आतंकवादियों को प्रश्रय दिया एवं उन्हें गुरुद्वारों में शरण दिया जिन्होंने पूरे पंजाब में हिंसक आतंकवादियों कारवाइयों को बढ़ावा दे दिया । जिसके कारण पंजाब में आपरेशन ब्लू स्टार जैसी शर्मनाक कारवाइयाँ करने पड़ी । जिसके पल्लवस्वरूप देश के प्रधान मंत्रों को हो आतंकवादियों का शिकार होना पड़ा एवं इसके पश्चात देश भर में हिंसा को आग लग गई एवं पंजाब में हिंसक वारदातों का ताँता लग गया एवं पंजाब में जन सामान्य असुरक्षित हो गया । केवल 1986 में पंजाब में 600 लोगों को आतंकवादियों ने मौत को नोंद सुला दिया ।² एवं यह प्रक्रिया उत्तरोत्तर में अनवरत रूप से चल रही है दिन प्रतिदिन बस यात्रियों, ट्रेन

यात्रियों को आतंकवादियों का शिकार होना पड़ रहा है । राजनीतिक पार्टियों सत्ता के लालच में जोड़ तोड़ को कोशिश करती रहो है ।

इसी प्रकार पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में गोरखालैंड को मांग को हिंसक वारदातों की गई हैं असम के ब्रम्हपुत्र के उत्तर तटीय श्रीरामपुर से सदिया तक के क्षेत्र को बोडोलैंड नामक अलग राज्य केगठन के लिए बोडो छात्र संघ एवं बोडो पीपुल्स एक्शन कमेटी ने हिंसा का रास्ता अपनाया । 16 अगस्त 1987 को बोडो नेतृत्व ने एक हजार घंटे बंद का आह्वान किया जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हस्तक्षेप पर 18 अगस्त 1987 को समाप्त कर दिया । 20 अगस्त 1987 को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं बोडो प्रतिनिधियों के बीच बोडो समस्या के समाधान हेतु प्रथम त्रिपक्षीय बातचीत प्रारम्भ हुई ।¹ लेकिन आन्दोलन ने 1989 में गंभीर हिंसक रूप धारण कर लिया मार्च 1989 तक सरकारों आँकड़ों के अनुसार 96 बोडो आन्दोलनकारियों की मौत हुई ।

8वें दशक के मध्य से लेकर वर्तमान तक काश्मीर में राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसक वारदातों का दौर जारी है। काश्मीर में सक्रिय उग्रवादियों के अनेकों गुट हैं जो कि अपने-अपने को काश्मीर में शांति - व्यवस्था कायम करने में प्रमुख रूप से मानते हैं । इन हिंसक वारदातों के कारण काश्मीर का जन सामान्य काश्मीर से पलायन को मजबूर हुआ है । भारत के पड़ोसियों से सम्बन्ध मधुर न रहने के कारण तो भी इन सक्रिय उग्रवादियों को हर तरह से सहायता देते हैं जिससे कि भारत की आंतरिक स्थिति अशांत रहे।

राजनीति में धन एवं अपराधियों का दबदबा :

लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव एक यज्ञ माना जाता है जिसके माध्यम से न केवल जन प्रतिनिधित्व निर्धारित होता है अपितु जनता द्वारा जनता को

सरकार का चयन होता है आज के समय में चुनाव संविधान को कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं क्योंकि यहाँ वोट धन शक्ति से खरोदे जाते हैं एवं विजय बाहुबल से प्राप्त की जाती है। चुनाव में धन शक्ति का उपयोग कोई नयी बात नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टियाँ अपना चुनाव अभियान चलाने के लिये उद्योगपतियों के दरवाजे पर दस्तक देती हैं।¹

चुनाव प्रणाली में विसंगतियों को शुरूवात 1962 से हुए पूलपुर संसदीय आम चुनाव से होती है। यहाँ से पंडित जवाहर लाल नेहरू काग्रेसी उम्मीदवार थे। इनके खिलाफ लोहिया चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव के दौरान हंडिया, पूलपुर, सोरॉव तहसीलों को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण हेतु 33 लाख रुपया मंजूर किया गया।²

इंदिरा गाँधी के कार्यकाल में तो हालत और बदतर हो गई।

पूँजीपतियों एवं सत्ताधारियों के बीच एक नापाक गड़जोड़ कायम हुआ जो आज भी प्रमुख भूमिका निभा रहा है। दरअसल जहाँ एक ओर पूँजीपति वर्ग सत्ताधारो दल के पार्टों कोष में चुपचाप मोटो रकमे जमा करने लगे। वही इस चुपचाप दो ग. मदद के एवज में वे कोटा परमिट लाइसेंस हाथियाने लगे संजय गाँधी के दिनों में यह खेल खुब परवान चढ़ा और इस हाथ दे उस हाथ ले, की शुद्ध व्यापारिक परम्परा कायम हुई। नतीजतन, इस बेनामी पैसे से चुनाव व्यवस्था केवल पैसे का खेल बनकर रह गया राजीव गाँधी के सत्ता में आने के बाद भी यह परम्परा कायम रही।

आज की नयी राजनीतिक शैली में प्रणाली चुनाव खर्च में जो दशति है उसका चौगुना तो टिकट हासिल करने में लग जाता है। चुनाव में नामांकन के दिन से लेकर जीत तक कोई भी गंभीर चुनाव लड़ने वाला विधान सभा प्रत्याशी न्यूनतम दो लाख रुपये तक खर्च करता है क्योंकि मौजूदा चुनावी व्यवस्था में कुछ

1- नवभारत टाइम्स

2- राष्ट्रीय संहारा, हस्तक्षेप 31 अक्टूबर 1993 पृष्ठ 4

चोजे लाजिमी है। दलीप उम्मीदवारों को पार्टियाँ भी अच्छी खासो रकम और गारडियाँ उपलब्ध कराती है। पूरे चुनाव भर नैतिकता और सिद्धान्तों परभाषण देने वाले लोग धनराशि के सहारे हो चुनाव लड़ते हैं। 1984 में अभिताभ बच्चन ने इलाहाबाद चुनाव में बहुगुणा के मुकाबले पानी की तरह पैसा बहाया था। अभिताभ के चुनाव में महेन्द्रा को लगभग 100 जोपे प्रचार में आयी थी।

हाल के चुनावों में धन शक्ति प्रदर्शन में भाजपा ने कांग्रेस को पछाड़ दिया है, इसका कारण यह है भी है कि टिकट पाने का एक प्रतिभान पैसा भी हो गया है। चुनावों में धन शक्ति के प्रयोग में वामपंथियों को छोड़कर कोई भी दल पोछे नहीं रह गया है। भाजपा के प्रत्याशी विश्वनाथ शास्त्री कहते हैं कि राजनीति को बुनियाद हो झूठ पर आधारित है। जब हम झूठो शपथ लेते हैं झूठे चुनाव खर्च देते हैं तो फिर किस सच्चाई की बात हम कर सकते हैं। आज कोई सांसद दिन पर हाथ रखकर नहीं कह सकता है कि उसने जो चुनाव खर्च का ब्यौरा दिया है वह सच है।

चुनाव खर्च का उपलब्ध ब्यौरा¹

वर्ष	मतदाता सूची में सशोधन पर खर्च	चुनाव कराने में खर्च	कुल खर्च
1967	3 करोड़ 54 लाख	7 करोड़, 41 लाख	10 करोड़ 95 लाख
1977	7 करोड़ 9 लाख	22 करोड़ 3 लाख	29 करोड़ 82 लाख
1984	15 करोड़ 80 लाख	62 करोड़ 48 लाख	78 करोड़, 28 लाख
1989	14 करोड़ 33 $\frac{1}{2}$ -लाख	95 करोड़ 81 लाख	110 करोड़ 15 लाख

चुनाव खर्च का आकलन एक कठिन काम है । अगर श्रम दिवसों को हानि तथा सरकारों व गैर सरकारों खर्च को जोड़ा जाय तो चुनाव खर्च देश पर बोझ साबित होंगे । लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए यह जरूरी है । पहले आम चुनाव 1951-52 में प्रति संसदीय क्षेत्र के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 35 हजार रु० तय की गयी थी । कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रो. एन. जी. रंगा आंध्र प्रदेश से पहला चुनाव केवल 1400 रुपये में लड़े थे । लेकिन बाद में चुनाव खर्च बढ़ते गये । 1979 में चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये और 1984 में 1.5 लाख कर दी गयी । अब यह सीमा 2 लाख रुपये । विधान सभाओं में यह सीमा अलग है । 3000 में विधान सभा खर्च की सीमा 50 हजार, राजस्थान की 40 हजार, हिमाचल की बीस हजार तथा म०प्र० की 40 हजार है ।¹ मौजूदा चुनाव खर्च सीमा में प्रत्याशी को एक लाभ यह भी है कि पार्टी द्वारा किये जाने वाले खर्च उसके अपने खर्च में नहीं जुड़ते । इतिहास गवाह है कि जैसे-जैसे चुनाव करोब आता जाता है, राजनीतिक दलों के खजाने का मुँह खुलता चला जाता है । मतदान के पूर्व धन से मतदाता को प्रभावित किया जाता है । कम्बल, कपड़े बाँटे जाते हैं शराब पानी की तरह बहायो जाते हैं।

यदि धन का प्रयोग विफल हो जाता है तो आज की राजनीति का सबसे अनोखा रंग देखने में आता है जिसे मतदान के दिन प्रयोग में लाया जाता है वह है भुजबल जिससे जीत निश्चित हो सके एवं यही से शुरू हुआ है राजनीति में अपराधियों का पदपिण ।

आज की भारतीय राजनीति में अपराधियों का दम दबा हर स्तर पर दिखायी पड़ता है जिसका प्रारम्भ मुख्यतः 80वें दशक के प्रारम्भ से शुरू होता है । एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तमाम राष्ट्र विरोधी तत्व पंचायतों का प्रमुख, विधान सभाओं के सदस्य बनाकर नियंत्रण प्राप्त करते

आ रहे हैं । इस प्रकार के अपराधिक चरित्र वाले सदस्य अपना जीवन एक अपराधी को हैसियत से शुरू करते हैं । राजनीतिक दल या उसके उम्मीदवार चुनावों में मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने, चुनावों हिंसा फैलाने जाली मतदान करने के लिए इन अपराधियों का सहारा लेते हैं । इसके बदले में चुनाव में जोते सदस्य इनको संरक्षण देते हैं । आगे चलकर यही अपराधी चुनाव सीधे तौर पर चुनाव में भाग लेने लगे हैं जिससे कि चुनाव प्रक्रिया में विकृतियाँ पैदा होने लगी हैं ।

आज भारतीय राजनीति में तहसीलदार सिंह, मदन भैया, डो. पो. यादव, वीरेन्द्र साहो, हरिशंकर तिवारी, राजा भैया, पप्पू यादव, आनंद मोहन सिंह, किंग महेन्द्र जैसे अपराधिक चरित्र वाले को लम्बो सूची हैं जो कि वर्तमान में विभिन्न सर्वेक्षणों के सदस्य हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जब एक अपराधी राजनेता बन जाता है तो उस स्थिति में उसका अपराधी चरित्र पर्दे के पीछे छुप जाता है और वह जनता एक हिस्से के मसोहा के रूप में अपने आपको पेश करता है उसका अतीत वाला अपराधिक जीवन उसे सशक्त राजनीतिक आधार प्रदान करता है ।

राजनीति और उससे जुड़े चेहरों के अपराधीकरण को एक बजह यह भी है कि जब-जब सामाजिक न्याय एवं सामाजिक परिवर्तन के प्रवाह को रोकने का उसके राजनीतिकरण का प्रयास होता है, समाज को लंपट ताकते, मुखर होकर सामने आ जाते हैं और संवाद और सहमति के स्वर इस शोरगुल में लिप्त हो जाते हैं । इसका ज्वलंत उदाहरण अस्सी के दशक के पूर्वार्द्ध में उत्तर प्रदेश को विश्व-नाथ प्रताप सिंह को सरकार है जब इस प्रकार ने बी.पो. सिंह को शह पर अपना पुलिस से पिछड़ो-हरिजनो का राज्य भर में कत्ले आम करवाया, तो पिछड़े वर्गों में प्रतिक्रिया हुई और उनमें विक्रम मल्लाह और पुलन सरोखे चेहरे

एक खुबार छवि के साथ उभरकर सामने आये । इसी तरह बिहार में हुआ कर्पूरो ठाकुर वहाँ के सामाजिक आन्दोलन के वाहक थे और पिछड़ों एवं हरिजनों के उत्थान के लिए सामाजिक न्याय का संघर्ष गाँधीवादो तौर तरीके से लड़ रहे थे, लेकिन भाजपा, जनता पार्टी एवं कांग्रेस के अगड़ो नेताओं ने कर्पूरो के विरोध में अगड़ो जातियों का गठबंधन करके वातावरण को कटु बनाया ।¹ इस गुडागर्दी के प्रतिरोध में पिछड़ों को राजनीति में भी अपराधी प्रवृत्ति के चेहरे का प्रभाव बढ़ा । लालू यादव तमाम कमियों के बावजूद बिहार में पिछड़ों के हीरो हैं ।

इस प्रकार के अपराधी चरित्र के नेताओं का न तो कोई आदर्श है नहीं कोई नीति है न हो देश के हित के लिए कोई कार्यक्रम लागू करने की इच्छा है न हो ये लोग राष्ट्र के प्रति वफादार हैं । ये राजनीति के अखाड़े में मात्र अपने आपराधिक चरित्र को छुपाने एवं बड़ी धनराशि कमाने के लिए आए हैं। वे अब पुलिस दल एवं सरकारों तानाशाहों पर नियंत्रण करने लगे हैं क्योंकि वे अपने विरोधियों को समाप्त करने एवं हिंसा में विश्वास रखते हैं एवं अपने क्रिया कलापों द्वारा व्यवस्था को दूषित करते जा रहे हैं ।

अध्याय - 7

नौकरशाहों की भूमिका

अध्याय - 7

नौकरशाहों को भूमिका

लोकसेवा को " नौकरशाहों" भी कहा जाता है। नौकरशाहों लोक सेवाओं के दोषों को ओर संकेत करते हैं। साधारणतः इससे यह अभिप्राय व्यक्त होता है कि नागरिक सेवा के कर्मचारों लालफीताशाहों के दोष से घिरे रहते हैं तथा वे जनहित को उपेक्षा करते हैं। नौकरशाहों उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अन्तर्गत सरकारों कर्मचारों अपने को जनता का सेवक न समझकर स्वामी समझने लगते हैं जनहित को उपेक्षा करते हैं, नियमों और विनियमों का कठोरता से पालनकरते हैं और कार्य में विलम्ब होता है। वस्तुतः नौकरशाहों के तौरके अन्मनोय, यान्त्रिक, हृदयहीन एवं औपचारिक हो जाते हैं। वे जनता से अपना तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाते और अपनी श्रेष्ठता का दावा करते हैं। फाइनर ने इसे "मेज का शासन" कहकर पुकारा है। संक्षेप में, नौकरशाहों एक कार्यकुशल, प्रशिक्षित तथा कर्तव्य परायण सरकारों कर्मचारियों का विशिष्ट संगठन है जिसमें पद सोपान " तथा " आज्ञा की एकता" के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किया जाता है।¹

ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय प्रशासनिक सेवाएं बहुत ही अधिक तीव्र गति से बदली और विकसित हुई हैं। इसका प्रमुख कारण यह माना जा सकता है कि ब्रिटिश शासन में साम्राज्यवाद तथा प्रशासनिक सुधार दोनों ही दृष्टियों से भारतीय लोक सेवाओं को एक प्रमुख क्षेत्र माना था। मैकाले, इन्सिगटन तथा लो फर्नहाम आदि प्रसिद्ध अंग्रेजों ने भारत को प्रशासनिक सेवाओं को एक विशिष्ट ढाँचे में डालने के लिए गम्भीर प्रयत्न किये और आज भी भारतीय प्रशासन में जिस अखिल भारतवर्षीय सामान्य सेवाओं का

1- सिन्धो डा० नरेन्द्र कुमार, ब्यूरोक्रेसी पोजीसन एंड पर्सनल अड्मिनिव

वर्चस्व है वह इन्होंने महानुभावों को बौद्धिक परिकल्पना का परिणाम है। लम्बे विकास ने इस सेवाओं को अनाम-बेनाम, तटस्थ एवं स्वाभिभक्ति को विशेषताओं से सुदृढ़ बनाया है। भारतीय सेवाओं के इतिहास में सन् 1854 सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ष था, जबकि लार्ड मैकाले की अध्यक्षता में कमेटी ऑन इण्डियन सिविल सर्विसेज का गठन हुआ। इस कमेटी में आई०एस० एस० के लिए जो सिफारिशें की थी वे न्यूनाधिक रूप में आज भी भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के गठन और कार्य-प्रणाली को आधार-स्तम्भ है।¹

भारत के गणतन्त्रोप संविधान ने अखिल भारतीय सेवाओं अर्थात् आई० एस० एस० आई पो०एस० सेवाओं को इसी रूप में कार्य करते रहने का निश्चय किया और इन सेवाओं की व्यवस्था संविधान की संघीय सूची में सातवो अनुसूची के अन्तर्गत की और राज्यसभा को यह अधिकार प्रदान किया कि भविष्य में यदि अखिल भारतीय सेवाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता पड़े तो वह ऐसा कर सकती है। इसी प्रकार संविधान ने यह भी व्यवस्था कर दी है कि इन सेवाओं के चयन हेतु केन्द्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग तथा राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य का अपना लोक सेवा आयोग। वर्तमान समय में भारत में चार अखिल भारतीय सेवाएँ हैं दस सुसंगठित केन्द्रीय हैं § भारतीय विदेश सेवा के अतिरिक्त § और अनेक प्रथम श्रेणी की प्रान्तीय सेवाएँ हैं। ये निम्न प्रकार हैं -

अखिल भारतीय सेवाएँ -

- 1- भारतीय प्रशासनिक सेवा।
- 2- भारतीय पुलिस सेवा।
- 3- भारतीय वन सेवा।
- 4- भारतीय आर्थिक और भारतीय सांख्यिकी सेवा।

केन्द्रीय सेवा प्रथम श्रेणी -

1- भारतीय रेल्वे अकाउण्ट्स सर्विस 2- भारतीय आयकर सेवा 3- भारतीय चुगो और केन्द्रीय एक्साइज सेवा 4- भारतीय आडिट एवं अकाउण्ट्स सेवा 5- भारतीय प्रतिरक्षा अकाउण्ट्स सेवा 6- भारतीय डाक सेवा 7- भारतीय रेल्वे ट्रैफिक सेवा 8- मिलिट्री भूमि एवं छावनो सेवा । 9- भारतीय अध्यापिका फैक्ट्रोज सेवा 10- भारतीय सूचना एवं प्रसारण सेवा ।

राज्यों में पायः निम्न सेवाएं पायी जाती है -

1- राज्य प्रशासनिक सेवा 2- राज्य पुलिस सेवा 3- राज्य आडिट एवं अकाउण्ट्स सेवा 4- राज्य शिक्षा सेवा 5- राज्य कोऑपरेटिव सेवा 6- राज्य नियोजन सेवा 7- राज्य वाणिज्यिक कर सेवा।¹

भारतीय नौकरशाही को विशेषताएँ -

§1§ स्थायित्व - लोक सेवा के सदस्य स्थायी रूप से अपने पदों पर रहते हैं । लोक सेवा के सदस्य युवाकाल में सेवा में प्रवेश करते हैं और एक निश्चित आयु के बाद पद-निवृत्त हो जाते हैं।

§2§ राजनीति से सदस्यता - लोक सेवा के सदस्य राजनीतिक दलबन्धों से सक्रिय भाग नहीं लेते । वे राजनीतिक दलों के सदस्य नहीं होते, राजनीतिक आन्दोलन और निवर्चन में भाग नहीं लेते । किसी भी दल को सरकार सत्ता में हो, उनका कार्य तो सरकार को नीतियों का कियान्वयन है।

§3§ व्यावसायिक- लोक सेवा के सदस्य पेशेवर कहे जा सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों का मुख्य कार्य सरकारी सेवा करना है जिसके लिए सामान्य दक्षता की आवश्यकता पड़ती है यद्यपि व्यावसायिक एवं प्राविधिक सरकारी सेवाओं के हेतु विशिष्ट तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है ।²

§4§ पदसोपान - लोक सेवाओं का संगठन पदसोपान के सिद्धान्त पर होता है। पदसोपान का शाब्दिक अर्थ है उच्चतर व्यक्ति द्वारा निम्नतम व्यक्तियों पर शासन। यह एककृमिक संगठन है जिसमें निम्नस्तरोय व्यक्ति, उच्च - स्तरोय व्यक्ति या पदाधिकारो के प्रति उत्तरदायी रहते हैं।

§5§ प्रतिबद्धता- प्रतिबद्ध नौकरशाहो का दृष्टिकोण नौकरशाहो के परम्परागत दृष्टिकोण "तटस्थता" से जुड़ा हुआ है। भारत में लोक सेवा का परम्परागत गुणतटस्थता है। तटस्थता एवं निष्पक्षता ब्रिटिश लोक सेवा को प्रमुख विशेषता रही है। इसके अन्तर्गत तीन बातें शामिल हैं- प्रथम, जनता को विश्वास होना चाहिए कि लोक सेवा सभी प्रकार के राजनीतिक पक्षपात एवं दबाव से मुक्त है। द्वितीय, मंत्रियों को यह विश्वास होना चाहिए कि सत्ता में चाहे जो दल आये, लोकसेवा को उन्हें निष्ठा प्राप्त रहेगी। तृतीय लोक सेवाओं के नैतिक साहस का आधार यह मान्यता है कि पदोन्नति या अन्य पुरस्कार राजनीतिक मान्यताओं या पक्षपातपूर्ण कार्यों पर नहीं निर्भर करते बल्कि योग्यता एवं कुशलता पर निर्भर करते हैं।

नौकरशाहो को "प्रतिबद्धता" से दो अर्थ लिये जा सकते हैं, प्रथम नौतियों और संवैधानिक आदर्शों के प्रति, प्रतिबद्धता और द्वितीय, राजनीतिक दल एवं राजनेता के प्रति प्रतिबद्धता ?

सभी प्रशासक यह चाहेंगे कि कार्यकुशलता, दक्षता, परिणाम-प्राप्ति या उत्पादन आदि क्षेत्रों में वे सम्पूर्ण निष्ठा के साथ प्रतिबद्ध हों। लोक सेवक सरकार को आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक नौतियों के सम्बन्ध में अपने निष्पक्ष विचार रखें और जब नौतियों का निर्माण हो जाये तो निष्ठा के साथ भावात्मक रूप से जुड़ जाये। यदि "प्रतिबद्धता" शब्द

से यही आशय है तो उस पर कोई विवाद नहीं हो सकता है । संविधान के मूल आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध होने से प्रशासकों को क्या आपत्ति हो सकती है 9 किन्तु प्रतिबद्धता के क्षेत्र में वास्तविक विरोध जिस प्रश्न पर है वह यह है कि क्या प्रतिबद्धता पद विशेष से मुड़कर व्यक्ति विशेष के प्रति हो सकती है 9 अथवा क्या प्रतिबद्धता के नाम पर प्रशासकों को जानबूझकर किसी विशेष विचारधारा के अनुसार काम करने के लिए विवश किया जा सकता है 9 क्या प्रतिबद्धता से अभिप्राय अपने राजनीतिक स्वामी को इच्छा और आकांक्षा के अनुसार अपने विचारों को ढालते हुए उन्हें केवल वही परामर्श है जो उन्हें पसन्द हो 9¹

दिसम्बर 1969 से श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने नौकरशाही से प्रतिबद्धता को माँग को 2 प्रतिबद्ध नौकरशाही के औचित्य को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने कहा कि §1§ चूँकि भारत ने समाजवादो ढाँचि का लक्ष्य बनाया है इसलिए प्रशासकीय मशीनरी में परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे वह समाजवादो नोतियों को लागू करने का प्रभावशाली यन्त्र बन सके । §2§ भारत को प्रशासकीय पद्धति में क्रान्ति की आवश्यकता है जिसके बिना किसी क्षेत्र में कोई भी साहसिक परिवर्तन नहीं किया जा सकता । वे समस्त लोग जिन पर प्रशासन और उन्नति की जिम्मेदारी है, जनता को सेवा और उसके कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध हो । उन्हें जनता को केवल आँकड़ों के रूप में नहीं मानव मात्र के रूप में देखना चाहिए । §3§ योजनाओं के अन्तर्गत धन के एक बड़े भाग का प्रयोग नहीं हो पाया और इसका उत्तरदायित्व प्रशासन पर है। हमें राष्ट्रीय उद्देश्यों से प्रतिबद्ध और सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति चेतन नौकरशाही की आवश्यकता है । §4§ अशिक्षा-वर्गीय और

अनुदारवादो § आई० सो०एस०§ नेतृत्व में वर्तमान नौकरशाही समाजवादो रास्ते और लाइन के लिए समुचित आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन को आवश्यकताओं को मुश्किल से पूरा कर सकते हैं। §5§ एक देश जो सदियों से स्थिर और गतिहीन रहा हो, जहाँ सदियों से रूको तरक्की को दशकों में पूरा करना है तथाकथित तटस्थ प्रशासकीय मशीनरी मदद नहीं करेगी, बाधा कहेगी। §6§ जब मैं प्रतिबद्ध शब्द का प्रयोग करता हूँ तो मेरा तात्पर्य होता है कि उनको §लोक सेवको को§ संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों और उद्देश्यों के प्रति निष्ठावानहोना चाहिए।

वस्तुतः प्रतिबद्धता नौकरशाही को किसी निश्चित उद्देश्य को पूर्ति के लिए साधन के रूप में परिणत कर देती है न कि साध्य के रूप में। प्रतिबद्ध नौकरशाही को व्यवस्था से अनेक लाभ हैं- प्रथम, इस तरह की व्यवस्था में प्रशासक सत्तारूढ़ दल की नीतियों के निष्पत्ति में और उनको क्रियान्विति में अधिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करेंगे, अर्थात् वे असफलताओं से अपने आपको मुक्त नहीं रख सकेंगे। अतः यह व्यवस्था प्रशासनिक उत्तरदायित्व, अर्थमत्ता, अनुशासनहीनता और अकर्मण्यता की स्थिति भंग करने में सहायक होगी। द्वितीय, राजनीतिक नेतृत्व अपने घोषणा-पत्र में निहित के क्रियान्वयन में बाधक प्रशासकों को हटाने में भी स्वतन्त्र होगा। इससे प्रशासनिक नेतृत्व और राजनीतिक नेतृत्व के बीच आरोप-प्रत्यारोप की भावना का अन्त होने से प्रशासन से गतिरोध का अन्त होगा। तृतीय इस व्यवस्था में प्रशासन से वरिष्ठ पदों से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के एकाधिकार वाली स्थिति का भी अन्त होगा। द्वितीय श्रेणी के वैअधिकारी, जो सत्तारूढ़ राजनीतिक

यदि प्रतिमान टूटे जायें तो इंग्लैण्ड, अमरीका, फ्रांस तथा रूस को चार विभिन्न मॉडलों के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। इन देशों में सरकार को प्रकृति के अनुसार प्रशासनतन्त्र की प्रकृति का निमण हुआ है। भारत में, जहाँ ब्रिटिश पद्धति की राजनीति व प्रशासन लम्बे काल से रहा है, लोक सेवक विशेषतः एवं अपरिपक्व रूप से अपनी भूमिकाएँ निभाते रहे हैं। स्वतन्त्रता के बाद उस सम्बन्ध में जो जटिलताएँ आयी हैं उसके अनेक कारण हैं। प्रशासन का भौमकाय विस्तार, मंत्रियों की दुर्बल स्थिति, प्रशासन का केन्द्रोप स्वरूप, राजनीतिकरण का जोश, विशेषज्ञ का प्रशासन में पदार्पण आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्होंने मंत्रो-प्रशासक के सम्बन्ध में कुछ उल्झने पैदा की है। मंत्रो यह मांग करने लगे हैं कि प्रशासक उसके इतने अधीन होने चाहिए कि वे अपनी नीतियों को उनसे क्रियान्वित कर सकें और उसको तटस्थता या योग्यता राजनीतिक विकास के मार्ग में बाधा न बने। इसी प्रकार राजनीतिक विकास के बाद अपनी केन्द्रोप स्थिति से अपदस्थ किये जाने वाले प्रशासक ये कहने लगे हैं कि राजनीतिक नियन्त्रण का अर्थ राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

प्रशासनिक स्वायत्तता का नारा राजनीतिज्ञों द्वारा प्रशासनिक और गैर-जिम्मेदारों कहा जा रहा है और इसी प्रकार कठोर नियंत्रण की बात प्रशासकों द्वारा राजनीतिक अराजकता कहाँ जाने लगी है। इस प्रकार मंत्रो का यह नियंत्रण प्रशासनिक दृष्टि से यद्यपि आवश्यक व व्यावहारिक माना जाता है किन्तु इससे जो समस्याएँ जन्म लेती हैं वे राजनीतिक प्रकार की अधिक हैं। प्रशासकों का कहना है कि मंत्रो का नियन्त्रण उनको तटस्थता को तोड़ता है, उनमें अनुशासनहीनता को जगाता है और उन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप का शिकार बनाकर अधमता एवं भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त करता है। इसके विपरीत मंत्रो का पक्ष यह कहकर समर्थ

है। ऐसी स्थिति में वे जनतन्त्र को प्रगति को धोमा करते हैं और समाज को राजनीतिक हास को ओर ले जाते हैं।

किन्तु यह नियंत्रण और सम्बन्ध किस प्रकार का हो १ और उसकी प्रकृति क्या हो १ आदि प्रश्न सदैव जटिल रहे हैं। ए.डो. गोरवाला, पॉल एच० एपलबी, अशोक चन्दा, प्रशासनिक सुधार आयोग तथा अन्य संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा किये गये अध्ययन इस दिशा में महत्वपूर्ण माने गये हैं, परन्तु अभी भी निश्चित रूप से वह नहीं कहा जा सकता है कि मंत्रो तथा लोक सेवकों के सम्बन्ध वर्तमान में किस प्रकार के हैं तथा वे कैसे होने चाहिए।¹

राजनीतिक- नौकरशाही सम्बन्ध निम्नलिखित कारकों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं -

§1§ राजनीतिक दल की प्रकृति - मंत्रो अपने राजनीतिक दल का एक प्रभावशाली नेता होता है। उसका नौकरशाही पर बहुत कुछ प्रभाव इस बात पर निर्भर होता है कि वहों कहां तक संगठित है तथा उसकी विचारधारा विभिन्न विषयों पर कहां तक स्फुट है तथा उसकी जनता के मध्य कितनी मान्यता है १ यह विभिन्न दलों के सहयोग से सत्तारूढ़ हुआ है या उसका विधान मण्डल में स्फुट बहुमत है।

§2§ मन्त्रिमण्डल में स्थिति - यदि मन्त्रिमण्डल में सम्बन्ध मंत्रो की स्थिति प्रभावपूर्ण है तथा उसके पोछे राजनीतिक समर्थन विद्यमान है तो वह अपने सचिव या अन्य विभागीय अधिकारियों से समक्ष प्रभावशाली सिद्ध होगा किन्तु इन सबसे पहले स्वयं प्रधानमंत्री की स्थिति का शक्तिशाली होना आवश्यक है।²

1- प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्मिक प्रशासन प्रवर्तितवेदन 1969 पृ० 24

2- फिर वही,

§3§ सामाजिक एवं आर्थिक कारक - प्रायः मंत्रो तथा लोक सेवको के मध्य मतभेद उनको विभिन्न सामाजिक संस्कृतियों के कारण होते है।

§4§ लोक सेवकों को परिस्थिति-ताब, कोठारो व राँय के अध्ययनो से पता चलता है कि राजनेताओं तथा नौकरशाहो के मध्य नतो लक्ष्य सम्बन्धो समरूपता होती है और न हो वे एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखते है। नौकरशाहो अभी भी पुरानो मान्यताओं पर आधारित है। प्रशासक समझते है कि वे एक उच्च शिक्षा प्राप्त वर्ग के प्रतिनिधि है तथा वे हो समग्र राष्ट्रिय दृष्टिकोण तथा जनहित को समझते है। उनका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनोतिक स्तर उनके मंत्रो के साथ सम्बन्धो को प्राप्त करता है।¹

§5§ वैयक्तिक विशेषताएँ एवं लक्ष्य - जाति, धर्म, भाषा, विचार व पृष्ठभूमि सम्बन्धो एकता मंत्रो एवं प्रशासक के पारस्परिक सम्बन्धो को बड़ा प्रभावित करती है, भारतीय मंत्रो वह प्रयास करते रहते है कि किसी तरह अपने जानकर प्रशासकों को लाया जाय ताकि उन पर भरोसा किया जा सके। स्वयं लोक सेवक के अपने उद्देश्य उसको प्रेरित करते है और वह शोध पदोन्नतियों सेवा-निवृत्ति के पश्चात् नियुक्तियों आर्थिक लाभ, स्वजनो को नियुक्तियों आदि को दृष्टि से मंत्रो का अनुगामी बन जाये²।

§6§ नीति निर्माण का स्तर तथा अभिकरणो का प्रकार - मंत्रो एवं लोक सेवकों के सम्बन्ध विभागीय नीति या निर्णय निर्माण के स्तरो पर भी निर्भर करते है। उच्च स्तर पर उनके सम्बन्ध बराबरो और सहयोग, मध्य स्तर पर आदेश-अनुपालक तथा निम्न स्तर पर स्वामी सेवक जैसे होते है।

1- भाम्बरो सो० पो० ब्यूरोक्रेसी एण्ड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया विकास

1971 पृ० 114

2- फिर वही,

प्रोफेसर सौ. पी. भाम्भरो ने प्रधानमंत्री एवं नौकरशाहों के सम्बन्धों तथा अन्य राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं का विश्लेषण करते हुए बताया है कि मंत्रों की राजनैतिक स्थिति दुर्बल होने पर नौकरशाहों हावी हो जाते हैं। शक्तिशाली नौकरशाहों ने दलीय नेताओं के साथ पारस्परिक लाभों के लिए समझौता कर लिया है। स्वयं नौकरशाहों ने अपने आपको कांग्रेस दल के उद्देश्यों की पूर्ति का एक साधन बनने दिया। असन्तुष्ट एवं अवमानित अधिकारियों ने प्रेस, संसद तथा विरोधी दलों का भी सहारा लिया है।¹

यह भी अनुभव किया गया है कि सत्ता परिवर्तन होने, सरकारों के अस्थायित्व तथा मिले-जुले रूप के कारण और मंत्रियों के अज्ञान के कारण लोक सेवक हावी हो जाते हैं। इटली, फ्रांस, तथा 1967 को मिली-जुली सरकारों का अनुभव तथा भारत में जनता पार्टी का शासन नौकरशाहों को बढ़ती हुई शक्तियों का परिचायक रहा है। अपने अवांछनीय सम्बन्धों को छिपाने के लिए सरकारों के बनने से पूर्व पुराने पत्रावलियों का जल दिया जाता है। इसका मूल कारण मंत्रों लोक सेवक के मध्य स्वार्थपूर्ण सौंठ-गौंठ है। इस सौंठ-गौंठ का कारण यह दोषपूर्ण धारणा है कि उनमें परस्पर पूर्ण, सहयोग या लगाव होना चाहिए। उनमें एकता व प्रतिबद्धता राजनोतिज्ञ का नौकरशाहोकरण तथा नौकरशाहों का राजनोतिकरण कर देती है।²

प्रोफेसर भाम्भरो की मान्यता है कि "भारत की नौकरशाहों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीकों से राजनोति में दखल देती रहती हैं। भारत में

1- फिर वही,

2- फिर वही,

नौकरशाहों ने केवल तटस्थ है अपितु कानून से भी आगे बढ़कर राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करती है। बहुत बार तो यह देखा गया है कि मंत्रों लोग अपने विभागीय अधिकारियों को भी नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं।¹ इसी प्रकार प्रोफेसर शान्ति कोठारो ने जिला स्तर पर राजनीतिज्ञों और प्रशासकों के सम्बन्धों का अध्ययन करते हुए पाया है कि " राजनीतिज्ञ और प्रशासक के कार्यों में विभाजन का रुढ़िवादो दृष्टिकोण अब व्यवहार में देखने को नहीं मिलता है।²

प्रोफेसर भाम्भरो का कहना है कि सेवा निवृत्ति के तुरन्त बाद भारत के अनेक उच्चस्तरीय प्रशासकों ने किसी न किसी राजनीतिक दल को सदस्यता ग्रहण करके सक्रिय राजनीति में पदार्पण किया और यह तथ्य इस धारणा को पुष्ट करता है कि स्वाधीनता के बाद में भारतीय नौकरशाहों राजनीति में हस्तक्षेप करती रहती है। सी.सी. देसाई, एन. डडिकर, एच. एम. पटेल, लोबो प्रभु आदि स्वतन्त्र पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे, जबकि वे सभी एक समय सरकार के उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन थे। वी. शंकर जिन्होंने कि सरदार पटेल के साथ रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी, राजाओं के साथ मिलकर बाद के दिनों में सरकारों की नीति का विरोध करने लग गये³। ऐसा भी कहा जाता है कि स्वाधीनता के बाद अनेक प्रशासकों ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से गहरी मित्रता कर ली और अपने न्यस्त स्वार्थों को पूर्ति करने लगे। इन लोगों में आर.के. धवन जो कि इंदिरा गाँधी प्रधान मंत्री रहते उनके निजी सहायक से पदोन्नति पाकर विशेष सचिव बने वर्तमान में वे राज्यसभा के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के शासन काल में भारतीय विदेश सेवा से सम्बन्धित मणि शंकर अय्यर इस समय संसद के सदस्य हैं।

1- माहेश्वरी श्रीराम - रोजगार समाचार 7 से 14 जुलाई 1992 पृष्ठ 1

2- फिर वही,

इंदिरा गाँधी के शासन के अन्तिम दिनों में भारत के गृह सचिव रहे और राजीव गाँधी एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह के शासन काल में भारत के कन्ट्रोलर एवं आडिटर जनरल रहे टो. एन. चतुर्वेदो वर्तमान में संसद के सदस्य है एवं भारतीय जनता पार्टी से सम्बन्ध है । इन्दिरा गाँधी के शासन काल में उनके प्रमुख सचिव डॉ० पो०सो० अलकजेडर इस समय मडाराष्ट्र के राज्यपाल है । इन सब लोगों को देखकर यह लगता है कि कहीं न कहीं इनके मन में राजनौतिक पार्टियों से जुड़ने की महत्वाकांक्षी रही होगी ।

मोर्गिस जोन्स के अनुसार मंत्रियों और प्रशासकों के सम्बन्धों में विकार पैदा हो सकते हैं यदि प्रशासक मंत्रों को जो-हुजुरो करता है , प्रत्येक कार्य मंत्रों को खुश रखने के लिए करता है । उचित कार्य को भी मंत्रों की नाराजगी के डर से नहीं करता, और इस प्रकार प्रशासन के मान-दण्डों को गिरा देता है। भारत में ऐसे अप्सरों की कमी नहीं जो अपने दरबारों दृष्टिकोण के कारण मंत्रियों के पैर छूते हैं और उनके गलत कामों की आलोचना न करके उनका बड़ा भी गर्व कर देते हैं ।

भारतीय नौकरशाही का गिरता स्तर -

समकालीन भारतीय नौकरशाही का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है और उनमें निम्नांकित कमियाँ आसानी से देखी जा सकती हैं ।

§1§ भ्रष्टाचार - हमारे देश के अधिकांश शासकीय कार्य नागरिक सेवा के कर्मचारियों के द्वारा ही किये जाते हैं। गाँवों की अशिक्षित जनता अपने-अपने-छोटे-छोटे कार्यों के लिए पटवारी, ग्राम सेवक, तहसील कार्यालय के

क्लकों तथा जिले के अधिकारियों को तरफ देखते हैं। कृषि के लिए खाद लेना हो या सहकारो बैक से कर्ज या पटवारो से कोई पट्टा तो रिश्वत का सहारा लेना हो पड़ता है। यदि किसी असावधानो से पुलिस के चंगुल में कोई फँस जाता है तो उसको कमर टूट जाता है।

§2§ राजनीति में संलग्नता - सर्वोच्च स्तर पर बड़े-बड़े अफसर उमर से तटस्थ दिखलायो देते हैं किन्तु उनका राजनीति से कहीं न कहीं तादात्म्य भी रहता है। वे अपने विचारो को छिपाकर सरकारो निर्णयों पर प्रभाव डालते रहते हैं।¹

§3§ लालफोताशाहो - भारत को प्रशासनिक सेवाओं में लालफोताशाहो अथवा अनावश्यक औपचारिकता पायो जातो है। अधिकारोण प्रक्रिया को औपचारिकता में विश्वास करते हुए नियमों और विनियमों का पालन कठोरता के साथ करते हैं। इसके परिणामस्वरूप कार्य को सम्पन्नता में विलम्ब होता है और महत्वपूर्ण निर्णय शीघ्र नहो लिये जा सकते। नौकर-शाहो प्रक्रिया को औपचारिकताओं को अपना उद्देश्य बना लेतो है और जनता को सेवा को उपेक्षा करतो रहतो है। औपचारिकता का अत्यधिक पालन करते-करते कर्मचारो तन्त्र मशीन की तरह बन गया है और इसको निर्णय क्षमता क्षीण हो गयी है। अधिकारोण उत्तरदायित्व वहन करना पसन्द नहीं करते, हर बात का उत्तरदायित्व दूसरो पर डालते रहते हैं।²

1- दारड़ा डॉ० रणजोत सिंह - इण्डियन पब्लिक एडमिनीट्रेशन मैक मिलन

1975, पृ० 374

2- फिर वही,

§4§ शासन करनेको अह वृत्ति- भारत को नौकरशाहों में एक झूठा अहं आज भी समाया हुआ है कि वे जनता के स्वामी हैं न कि सेवक । शासन करने के लिए हो वे बड़े-बड़े पद धारण कर रहे हैं न कि जनता की सेवा करने के लिए आजादों के बाद भी नौकरशाहों देश को जनता से अपना तादात्म्य स्थापित नहीं कर सको । सामान्य जनता के सुख-दुख से अधिकारोपण कितने अलग-अलग रहते हैं इसका अवलोकन गाँवों में जाकर आसानी से किया जा सकता है ।¹

§5§ विशेषज्ञों को उपेक्षा - भारतीय प्रशासन विविधज्ञ प्रधान है । उद्धार शिक्षा प्राप्त अधिकारियों का एक विशिष्ट वर्ग हो समूचे शासन में प्रशासकीय पदों को ग्रहण करता है। ऐसे विविधज्ञ प्रशासक कभी वित्त विभाग के उच्च पदों पर नियुक्त किये जाते हैं तो कभी सिविल, बिजली, यातायात, शिक्षा आदि अन्य विभागों को देखभाल करते हैं। यदि आज वे जिलाधीश के रूप में कार्य करते हैं तो कल उन्हें शिक्षा संचालक अथवा सहकारो विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया जा सकता है । संक्षेप में विविधज्ञ प्रशासक को सब मर्ज को एकमात्र दवा मान लिया गया है?

नौकरशाहों संगठित होकर के भारतीय राज व्यवस्था में क्रियाशील है। उच्च सेवा में कार्यरत अफसरों के अपने संघ है जो उनके हितों को सुरक्षा करते हैं। भारतीय नागरिक सेवा प्रशासनिक सेवा संघ कहा जाता है। यह एक अखिल भारतीय संघ है जिसे भारतीय नागरिक सेवा प्रशासनिक सेवा संघ कहा जाता है । यह एक अखिल भारतीय संघ है जिसकी शाखाएँ राज्यों की राजधानियों में भी है । राज्यों की राजधानियों में यह संघ कितना शक्तिशाली है जिसकी पुष्टि एक उदाहरण से की जा सकती है । एक बार

१- फिर वही,

2- फिर वही,

मध्य प्रदेश के एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने एक कनिष्ठ मंत्री के होने पर आई० ए० एस० वर्ग के कमिशनर पद पर कार्यरत अधिकारी को निलम्बित कर दिया था। शीघ्र ही सचिवालय में आई०एस० अधिकारियों को बैठक होता है और यह निश्चय किया जाता है कि मुख्यमंत्री को इस मामले में अपना निर्णय बदलने के लिए तैयार किया जायेगा। अन्ततोगत्वा मुख्यमंत्री को अपना निर्णय बदलना पड़ता है।¹

ऐसा माना जाता है कि नेहरू के पश्चात् निर्णय प्रक्रिया में नौकरशाही का प्रभाव लगातार बढ़ा है। शास्त्री जो के युग में शक्तिशाली प्रधानमंत्री सचिवालय का गठन किया गया और उसका अध्यक्ष श्री लक्ष्मी-कान्त झा को बनाया गया। कुछ ही समय में सचिवालय देश को राजनीतिक गतिविधि तथा प्रशासकीय सत्ता का मुख्य केन्द्र बन गया।² प्रो० चन्द्रप्रकाश भाम्भरो के शब्दों में "शीघ्र ही झा सभी स्थानों पर पाये गये। चाहे वे सरकारी समितियाँ हो या शास्त्री जो के नेतृत्व में विदेश में जाने वाले शिष्टमंडल हों या शास्त्री जो से भेंट करने वाले विदेशी अतिथियों को बैठक हो, झा सभी जगह मौजूद थे। महत्वपूर्ण विदेशी राजदूतों ने, जो जल्दी ही सब कुछ ताड़ गये झा से मिलने जाने लगे और झा भी अपने हाथ-पाँव फैलाते गये, चाहे वह निदेश नोति हो या सुरक्षा या विदेशी से बातचीत या सारे आर्थिक मामले। शास्त्रीजो के काल में वरिष्ठ आई०एस० अधिकारियों का प्रभाव बढ़ा। अपने प्रभाव के कारण ही इन अधिकारियों ने अपने वेतन में वृद्धि करवा ली। शास्त्री जो के समक्ष नौकरशाही ने सिर उठाना प्रारम्भ किया और श्रीमती गाँधी के युग में तो यह और भी ऊँच उठ गयी। श्री पी०एन० हक्सर के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सचिवालय का पुनर्गठन किया गया इसके नियंत्रण में रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग और नामक गुप्तचर विभाग गठित किया गया और सभी विभागों एवं

मन्त्रालयों के लिए आवश्यक हो गया कि वे महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व प्रधानमंत्री सचिवालय से स्वीकृति प्राप्त करें। इस प्रकार श्रीमती गंधी के शासन काल में प्रधानमंत्री सचिवालय और उनके सचिव पी०एन० हक्तर एवं धर को छाप समस्त विभागों के निर्णयों पर झलकती रही। सन् 1980 के चुनावों के बाद भी ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को अपेक्षा अपने सचिवालयों अधिकारियों पर अधिक विश्वास करती थी। राजीव गंधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सर्वश्री मणिशंकर अय्यर, आस्कर फर्नांडोज, विजयशंकर त्रिपाठी आदि प्रधानमंत्री सचिवालय को संचालन शक्ति के रूप में रहें तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधान मंत्री बनने के बाद विनोद चन्द्र पाण्डेय एवं पी०सी० चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री सचिवालय को बागडोर सम्भाला है और आज भी श्री०बी० नरसिंहा राव के प्रधान मंत्री बनने के बाद ए० एन० वर्मा, आर०के० खण्डेकर इत्यादि प्रधान मंत्री सचिवालय को संचालन शक्ति हैं।

इस प्रकार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को बनाये रखने में नौकरशाही या प्रशासनतंत्र का बड़ा हाथ है। विशेषतः प्रधानमंत्री सचिवालय के नौकरशाहों का दर्जा तो केन्द्रीय मंत्रियों से भी उँचा रहा है यह सर्व विदित है कि नौकरशाही मंत्रियों की तुलना में शक्तिशाली रहती है क्योंकि मंत्रोगण प्रत्येक कार्य को लोक सेवा के विशेषज्ञों से परामर्श लेकर करना ही अधिक अच्छा समझते हैं। मंत्री नये होते हैं और लोक सेवक अनुभव के कारण पेशेवर। फलस्वरूप अनेक मंत्रियों को लोकसेवकों के प्रभाव में ही कार्य करना पड़ता है²। गुलजारी लाल नन्दा जैसे अनुभवों मंत्रों को भी यह शिकायत थी कि उन्हें अपने विभागीय सचिव से उपयुक्त

1- नय्यर कुलदोष: दि इक्पोर्टेन्स आफ डेलिगेशन दि इण्डियन एक्सप्रेस

अप्रैल 7, 1976।

2- प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्मिक प्रशासन प्रतिवेदन 1969, पृ० 16-27

सहयोग व समर्थन नहीं मिल रहा है । ऐसे असहयोगी सचिव को गृहमंत्री नन्दा नहीं हटा पाये ।

राज्यों में नौकरशाही अत्यन्त शक्तिशाली रही है। संयुक्त मोर्चा सरकारों के कारण मंत्रोगण अपनी कुर्सी तथा अस्तित्व की रक्षा के संकट से जूझते रहे थे और नौकरशाही के प्रभाव क्षेत्रों में वृद्धि हुई । कांग्रेसी सरकारों के युग में मुख्यमंत्री नयी दिल्ली के पत्रवाहक के रूप में कार्यरत थे और कांग्रेस दल की मोलरो गुटबन्दों के कारण भी नौकरशाही ने अपनी शक्तियाँ बढ़ा ली - भाम्भरी¹ सो.पो. ।

भारत में जिला उपजिला और ग्राम स्तर परभी नौकरशाही का राज है। गाँवों में आज भी पटवारों धानेदार और तहसीलदार सरकार के प्रतीक माने जाते हैं । इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारतीय राजनीति पर नौकरशाहों का आधिपत्य रहा है एवं समकालीन भारतीय राजनीति में इनका प्रभाव चरम सीमा पर है । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि नौकरशाही समकालीन भारतीय राजनीति का अभिन्न भाग है ।

1- सुब्रह्मण्यमः रिप्रेसेटेटिव ब्यूरोक्रेसी एंड एसेसमेंट , द अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू खण्ड 4, पृष्ठ 119 ,

अध्याय - 8

उपसंहार

अध्याय-8

उपसंहार

1967 से 1989 तक का समय भारतीय राजनीति में काफी उथल-पुथल कर रहा है क्योंकि इस अंतराल में भारतीय राजनीति में अनेक परिवर्तन हुए एक परम्परा का अन्त हुआ तो दूसरे का प्रारम्भ । इन परिवर्तनों की गति काफी तीव्र रही है, इन परिवर्तनों के मुख्य कारक राजनीतिक दल हो रहे हैं जिसका एक मात्र उद्देश्य येन केन प्रकारेण सत्ता की प्राप्ति रहा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् के तीन आम चुनावों में राष्ट्रीय एवं राज्यों में सत्ता पर कांग्रेस दल का एकाधिकार था, लेकिन चौथे आम चुनाव के द्वारा राज्यों की सत्ता पर कांग्रेस के इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया । कांग्रेस उस समय के 17 में से 8 राज्यों में बहुमत प्राप्त करने में असफल रही, ये 8 राज्य थे बिहार, केरल, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान उत्तर प्रदेश और पं० बंगाल । नार्मन डो पामर ने लिखा - चतुर्थ आम चुनाव अवसाद, निराशा, अनिश्चितता और लगभग लगातार आन्दोलन के वातावरण में सम्पन्न हुए ।¹ एफ. पी. डब्लू. डो कोस्टा ने लिखा है कि चतुर्थ आम चुनाव में भारतीय जनता द्वारा मतदान के आधार पर क्रांति लाने का कार्य किया गया ।² इन चुनावों में जनता ने पर्याप्त परिपक्वता का परिचय दिया और इस दृष्टि में रखते हुए ही इन्हे प्रथम वास्तविक आम चुनाव और द्वितीय क्रांति जैसी संज्ञा दी गयी । 19६७ से 70 के बीच के समय में 17 में से 10 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें थी । अतः 1967 से ही राज्यों में एक दल की प्रमुखता के स्थान पर

1- नार्मन डो पामर: इंडियाज फोर्श जनरल इलेक्सन रूरेशियन सर्वे, वालुम 7, 1967, पृ० 277

2- एफ. पी. डब्लू. डो. कोस्टा- रूड्स आफ चेंज इन पापुलर वोट ड्र हिन्दू 17 मार्च 1967 ।

प्रतियोगी दलीय व्यवस्था स्थापित हुई। डॉ० सुभाष कश्यप के अनुसार इस समय को राज्य राजनीति का सबसे प्रमुख लक्षण है कांग्रेस की शक्ति का हास और गैर कांग्रेसी दलों की बढ़ती हुई शक्ति।¹

इस प्रकार 1967 का आम चुनाव भारतीय राजनीति के लिए मोल का पत्थर साबित हुआ क्योंकि इस चुनाव में परम्परागत मतदान व्यवहार में परिवर्तन हुआ जिसका प्रभाव उत्तरोत्तर भारतीय राजनीति पर पड़ा।

1967 से 1989 के बीच कांग्रेस एवं अन्य राजनैतिक दलों की स्थिति -

1967 के चुनाव के पूर्व से ही कांग्रेस में गुटबंदी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गयी थी जिसका परिणाम था 1967 के चुनाव में कांग्रेस की हार। इस गुटबंदी का परिणाम यह हुआ कि 1969 में कांग्रेस दो पक्षों में विभाजित हो गई सत्ता कांग्रेस एवं संगठन कांग्रेस। जिसके कारण 27 दिसम्बर 1970 को लोक सभा भंग कर मध्यावधि चुनाव की घोषणा की गयी।²

इन चुनावों में संगठन कांग्रेस, जनसंघ, स्वतंत्र दल और संयुक्त समाजवादी दल के द्वारा चार दलीय मोर्चे का निर्माण किया गया। यह चार दलीय मोर्चा केन्द्र में अपनी सरकार की स्थापना या पर्याप्त शक्तिशाली विरोधी दल का स्थान ग्रहण करने के प्रति बहुत अधिक आशान्वित था लेकिन चुनाव परिणाम सत्ता कांग्रेस {इंदिरा गांधी के नेतृत्व} के पक्ष में गया। सत्ता कांग्रेस को लोक सभा में 350 स्थानों पर अपूर्व सफलता मिली। संगठन कांग्रेस को 16, जनसंघ को 22, संयुक्त समाजवादी दल को 3 स्वतंत्र को 8 हो स्थान मिले।³ 1971 के लोक सभा चुनाव परिणामों ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया

1- डॉ० कश्यप सुभाष, दल बदल और राज्यों की राजनीति मेरठ 1970 पृ० 164

2- नवभारत टाइम्स 28 दिसम्बर 1970, पृ० 1

3- रिपोर्ट आन फोफ़थ जनरल इलेक्सन, इलेक्सन कमोशन, इंडिया, न्यू दिल्ली।

क्योंकि किसी को ये आशा नहीं थी कि सत्ता कांग्रेस को लोकसभा में 2/3 बहुमत मिल पायेगा। इस चुनाव परिणाम से चुनाव पूर्व संगठन कांग्रेस जनसंघ स्वतंत्र दल और संयुक्त समाजवादी दल के द्वारा बनाया गया मोर्चा टूट गया।

मार्च 1971 के लोक सभा चुनाव एवं फरवरी 1972 के विधान सभा चुनावों के बीच विश्व राजनीति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी - स्वाधीन बंगला देश की स्थापना। इस घटना ने श्रीमती गाँधी और सत्ता कांग्रेस को प्रतिष्ठा में बहुत अधिक वृद्धि कर दी, जिसका परिणाम मिला 1972 के विधान सभा चुनावों में 70.4 प्रतिशत 48.5 प्रतिशत मत के द्वारा अप्रत्याशित जीत के रूप में। यह एक मात्र श्रीमती इंदिरा गाँधी की विजय थी। के. आर. मल्हानी ने लिखा है, 1971 में यदि इंदिरा लहर थी तो 1972 में इंदिरा ज्वार था।¹

1971 के लोक सभा चुनाव परिणाम से श्रीमती गाँधी के रूप में फिर से नेहरू के बाद करिश्माई नेतृत्व का उदय हुआ क्योंकि इस चुनाव में श्रीमती इंदिरा गाँधी ने नारा दिया कि चुनाव का मुद्दा मैं हूँ। जिससे कि व्यक्ति विशेष में सत्ता का केन्द्रोत्थरण हुआ एवं इंदिरा गाँधी तानाशाह के रूप में उभरीं।

छठी लोकसभा के चुनाव परिणाम से पहली बार केन्द्र में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। विरोधी दल भारतीय लोकदल, जनसंघ, संगठन कांग्रेस समाजवादी दल ने मिलकर कांग्रेस को चुनौती को स्वीकार करने के लिए जनता पार्टी का गठन किया, जिसे कि चुनावों में विजय मिली उसे लोकसभा में 270 स्थान मिले।² जिसने कांग्रेस के विद्रोही गुट के लोकतंत्रोपकारी कांग्रेस जिसको लोक

1- डफ़ देअर वाज एन इंदिरा घेव इन 1971, देअर डज इंदिरा टाइड इन 1972 - मल्हानी के. आर. कांग्रेस डज किंग एंड डट डज वचोन इन मदर हेंड न्यू दिल्ली 15 मार्च 1975

2- छठें जनरल इलेक्शन की रिपोर्ट -इलेक्शन कमोशन 1977, न्यू दिल्ली।

सभा में 28 स्थान प्राप्त थे § के साथ मिलकर सरकार का गठन किया । इस चुनाव में जनता पार्टी के विजय के मुख्य कारकों में जय प्रकाश नारायण का विरोधी दलों को समर्थन था क्योंकि इस समय श्रीमती गान्धी को तत्त्वोर प्रेस, संसरसिप एवं नसबन्दो कार्यक्रम, आपातकाल लागू करने के कारण जितनी धूमिल थी जय प्रकाश नारायण को तत्त्वोर उतनी ही उज्जवल थी । 1977 के चुनाव परिणाम बहुत कुछ जय प्रकाश विजय के रूप में हो थे ।

जून 1977 के विधान सभा चुनावो के परिणाम भी लोकसभा चुनाव परिणाम के समान हो थे । लेकिन जनता पार्टी का शासन कुल मिलाकर असफल हो जिसके परिणाम स्वरूप 1980 में मध्यावधि चुनाव करना पड़ा । जनवरी 1980 के लोकसभा के चुनाव में इंदिरा काँग्रेस को 2/3 से अधिक स्थान प्राप्त हुए इसका प्रमुख कारण इंदिरा गान्धी का प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं जनता पार्टी को गुटबंदी से कमजोर सरकार, जो कि अपना समय भी पूरा न कर सकी, था। इस चुनाव में काँग्रेस को 351 स्थान एवं 42.66 प्रतिशत मत प्राप्त हुए, जबकि जनता पार्टी को 31 स्थान हो मिले । 1977 एवं 1980 के चुनावो में एक प्रमुख अंतर यह था कि 1977 में श्रीमती गान्धी के समस्त विरोधी मतों ने एकराजनोतिक इकाई का रूप प्राप्त कर लिया था, लेकिन 1980 में श्रीमती गान्धी के विरोधी मत विभाजित हो गये । प्रमुख रूप से यह विभाजन जनता पार्टी और लोकदल में था और इसका लाभ इंदिरा काँग्रेस को मिला ।

विधान सभा चुनाव §मई 1980§ में इंदिरा काँग्रेस को तमिलनाडु को छोड़कर शेष 8 राज्यों में विजय मिली । 1982 के चार विधान सभाओं के चुनाव में पश्चिम बंगाल को छोड़कर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल में इंदिरा काँग्रेस को सरकारें बनी । लेकिन 1983 जनवरी के विधान सभा चुनावों में काँग्रेस को हार का सामना करना पड़ा ।

1- 7 वें जनरल इलेक्शन को रिपोर्ट इलेक्शन कमिशन इंडिया, 1980

न्यू दिल्ली ।

अठिंवाे लोकसभा के चुनाव परिणाम ,इंदिरा कांग्रेस को अभूतपूर्व विजय थी इसमें इंदिरा कांग्रेस को लोकसभा में 401 स्थान एवं 41.3 प्रतिशत मत प्राप्त हुए ।¹ इसका मुख्य कारण इंदिरा गाँधी को हत्या के कारण इंदिरा कांग्रेस के प्रति जनता के मन में उपजी सहानुभूति की लहर थी । टाइम्स ऑफ इंडिया के सम्पादक गिरोलाल जैन ने इस चुनाव को प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के लिए जनमत संग्रह² का नाम दिया । इस चुनाव को इंदिरा कांग्रेस एवं राजीव गाँधी के लिए अपूर्व विजय कहा जा सकता है। राजीव गाँधी के शासन में भ्रष्टाचार का बोल बाला रहा जिसके कारण 1989 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा का १९८९ का चुनाव एक बार फिर 1977 की पुनरावृत्ति के रूप में था । इसमें चार राजनीतिक संगठनों जनता पार्टी चन्द्रशेखर गुट, लोकदल १ देवलाल गुट १ इंदिरा कांग्रेस से निष्कासित १ वो.पो. सिंह गुट १ राष्ट्रीय संजय मंच १ मेनका १ गाँधी ने मिलकर इंदिरा कांग्रेस के विकल्प के रूप में जनता दल बनाया । जनता दल ने कांग्रेस के अधिपत्य को समाप्त करने के लिए तेलंग देशम अंसम गण परिषद एवं डो.एम. के. से मिलकर राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया, जिसे नौवाे लोकसभा में 17.7% प्रतिशत मत एवं 141 सीट मिली, इसने मार्क्सवादियों एवं भारतीय जनता पार्टी के सहारे सरकार का गठन किया लेकिन आपसी खोचतान एवं गुटबाजी के कारण इसका भी वही हाल हुआ जो कि 1977 की जनता पार्टी सरकार का हुआ था । परन्तु इस चुनाव परिणाम से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि कांग्रेस के एकदलीय प्रभुत्व वाला साम्राज्य अब वह नहीं रहा जो कि 1984 तक किसी न किसी कारण से बना रहा ।

इस प्रकार 1967 से 1989 के अंतराल में विपक्षी पार्टियों के एकीकरण का मात्र उद्देश्य कांग्रेस का विकल्प तैयार करना रहा है जिससे वे जोड़-तोड़

- 1- 8वे जनरल इलेक्शन की रिपोर्ट 1989 इलेक्शन कमिशन इंडिया, न्यू दिल्ली ।
- 2- द इलेक्शन टू द एर्थ लोकसभा हैज टर्नड आउट टू बी ए रिफ्लेक्शन । द इंडियन पोपुल हैव वोटड फार राजीव गाँधी एंड कांग्रेस पार्टी- न्यू ट्रेड विहाइंड द पोल- गिरोलाल जैन - द टाइम्स ऑफ इंडिया 30 दिसम्बर 1984 पृ06

करके सत्ता पर अधिकार पा सके । इसके कारण हो कोई भी राजनैतिक दल अकेले इस अवधि में सशक्त विपक्ष के रूप में नहीं उभर सका या अकेले सरकार बनाने को स्थिति में नहीं पहुँच सका ।

क्षेत्र आधारित राजनीति एवं क्षेत्रीय दलों की भूमिका-

नेहरू के अन्तिम दिनों में राजसत्ता केन्द्र से राज्यों को ओर उन्मुख हो गयी थी । नेहरू के पश्चात कांग्रेस में शिखर व्यक्तित्व के अभाव आदि कारणों से राज्यों में गुटबंदी बहुत तीव्र हो गयी थी । जिसके कारण राज्यों की राजनीति में क्षेत्रीयतावादो प्रवृत्तियाँ भी बहुत अधिक प्रबल हो गयीं । विभिन्न राज्यों में कांग्रेस के हो एक वर्ग ने कांग्रेस से सम्बन्ध विच्छेद कर क्षेत्रीय दलों का निर्माण किया । जनता पार्टी राजस्थान, केरल कांग्रेस {केरल}, बंगला कांग्रेस {पं. बंगाल} आदि कुछ प्रमुख दल थे । कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा तो ऐसी असंगत बातें की जाने लगी जिनका तार्किक निष्कर्ष भारतीय संघ से सम्बन्ध विच्छेद होता । इन प्रवृत्तियों की प्रबलता तमिलनाडु, पंजाब और असम जैसे राज्यों में देखी गयीं ।

1967 के चुनाव परिणामों से क्षेत्र आधारित राजनीति एवं क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण स्थिति का अवलोकन होता है जिसमें 17 में 8 राज्यों में { बिहार, केरल, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल } क्षेत्र आधारित राजनीतिक दलों ने गठजोड़े से सरकारें बनायीं । इन सरकारों का केन्द्रीय कांग्रेस सरकार से हमेशा विवाद बना रहा ।

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का महत्त्व 1982-83 के चुनावों से बढ़ने लगा । 1982-83 में पश्चिम बंगाल, केरल, हरियाणा, त्रिपुरा, हिमाचल, नागालैण्ड, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राज्यों में क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को शिकस्त दे दी । जम्मू कश्मीर में नेशनल काँग्रेस, आंध्र प्रदेश में तेलगुदेशम्, कर्नाटक में जनता पार्टी को सरकारें सत्तासूट हुई । राज्यों में क्षेत्रीय दलों का

तत्त्व उभरने लगा । ये क्षेत्रीय दल राज्य स्वयंश्रिता को माँग करने लगे । क्षेत्रीय दलों के मुख्य मंत्रों केन्द्र राज्य सम्बन्धों में परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर देने लगे । फलस्वरूप केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर पुनर्विचार करने के लिए सरकारिया आयोग को नियुक्ति की गयी । क्षेत्रीय दलों के प्रभाव का हो परिणाम है, असम में असम गण परिषद द्वारा 1985 में सरकार का गठन ।

इस प्रकार 1967 से 1984 की अवधि में क्षेत्रीय राजनीति ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया । इसके बढ़ते प्रभाव का प्रमुख कारण जनता के मन में इनके प्रति बढ़ता विश्वास है एवं इसके द्वारा क्षेत्र विशेष का स्वस्थ विकास करना है। अतः क्षेत्रीय राजनीति एवं क्षेत्रीय दलों में राज्य राजनीति के स्वस्थ विकास हेतु कुछ चिन्तन नितान्त आवश्यक है ।

संविद सरकारों एवं दल-बदल की राजनीतिक भूमिका -

दल-बदल भारतीय राजनीति में विशेषतया राज्य राजनीति में सदैव से रहा है लेकिन 1967 के आम चुनाव के पश्चात् दल परिवर्तन इतनी तेजी से होना शुरू हुआ कि इसने गम्भीर राजनैतिक समस्या का रूप धारण कर लिया । उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार मार्च 1967 से दिसम्बर 1967 तक केवल नौ मास की अवधि में राज्य विधान मण्डलों के कुल 3447 में से 314 सदस्यों ने दल परिवर्तन किया । बहुत से विधायकों ने एक से अधिक बार दल परिवर्तन किया । इसके पश्चात् सत्ता सुख एवं धन लोभ में यह एक राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में अनवरत रूप से चल रहा है।

1971 में बिहार में दल-बदल की निरन्तर प्रक्रिया को न रोक पाने के कारण कर्पूरी ठाकुर ने विव्हा होकर अपने संयुक्त विधायक दल के मंत्रिमंडल का त्याग पत्र दे दिया । कर्नाटक में संगठन कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री वोरेन्द्र पाटिल को 34 महोने पुराने मंत्रिमंडल का त्याग-पत्र देने के लिए विवश होना पड़ा ।

1967 से 1972 तक दल-बदल से विरोधी दलों को अधिक लाभ हुआ और 1971 के बाद दल-बदल से कांग्रेस को ही अधिक लाभ मिला। 1977 के लोकसभा चुनावों के बाद पूरे वर्ष भर जनता पार्टी के पक्ष में दल-बदल होता रहा और 1980 के लोक सभा चुनावों के बाद तीव्र गति से कांग्रेस आई के पक्ष में दल बदल होता रहा। राजीव गाँधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद, इन सत्ता एवं धनलोभियों के उमर अंकुश लगाने के लिए संविधान में संशोधन करके दल-बदल विधेयक पारित करवाया। क्यों कि ये सत्य है कि भारत में दल-बदल सैद्धान्तिक आधार पर न होकर स्वार्थ-सिद्धि हेतु हुआ है।

दल-बदल कानून बन जाने के पश्चात भी सत्ता लोभी कानून को प्राथमिक आवश्यकता पूरा करके दल-बदल कर लेते हैं जिसका सबसे ताजा उदाहरण है जनता दल के नेता अजित सिंह के कुछ सदस्यों को लेकर सत्ताधारो दल कांग्रेस में मिल जाना एवं अपने हितों को पूर्ति कर लेना।

चतुर्थ आम चुनाव के बाद मिली जुली सरकारों को राजनीति भारतीय राजनीति को एक महत्वपूर्ण पूर्ण प्रवृत्ति कहा जा सकता है। लेकिन दल-बदल से बनो ये संविद सरकारें पूर्णतः अस्थिर रहें क्योंकि इन सरकारों का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस का विरोध हो रहा। राजनीतिक अस्थिरता का परिचय इस तथ्य से मिलता है कि फरवरी 1967 से फरवरी 1969 के दो वर्ष के काल में बिहार में 6 सरकारें बनो। इसमें सर्वाधिक चलने वाली सरकार का कार्यकाल 9 माह 25 दिन रहा।

संविद सरकारों को राजनीति में केरल को साम्यवादो दल के नेतृत्व वाला मोर्चा तथा पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादो दल के नेतृत्व वाला हो मोर्चा हो स्थिर सरकार दे पाया क्योंकि ये दल अपने क्षेत्र में ज्यादा संगठित और एकताबद्ध रहे। अधिकांश राज्यों में परस्पर विरोधी दलों के मोर्चे धीरे-धीरे टूट गये। परस्पर विरोधी विचारों वाली पार्टियों के एक होने के कारण हो

केन्द्र में 1977 एवं 1989 को जनता पार्टी एवं जनता दल की सरकारें स्थिर सरकार न दे सकी। मिली जुली सरकारों के प्रयोग ने भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का काफी हद तक प्रभावित किया है। सर्व प्रथम इससे संसदीय प्रणाली एवं प्रचलित संसदीय अभिसमयों पर प्रतिकूल प्रहार हुए हैं। मिश्रित सरकारों वाले राज्यों के राज्यपालों के पद विवादास्पद एवं बहुचर्चित बन गये। कहीं-कहीं विषम परिस्थितियों में "राज्यपाल" की सक्रिय भूमिका का निर्वाह करना पड़ा है। मुख्यमंत्रियों के पद का अबमूल्यन हुआ है, उसकी सत्ता का हास हुआ है एवं उसे सरकार में शामिल दलों की समन्वय समिति की देख-रेख में कार्य करना पड़ा, उनके बराबर वालों में "प्रथम" जैसी स्थिति का भी हास हुआ है।

भारत में केन्द्र एवं राज्य की संविद सरकारों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है मिली जुली सरकारें राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से अस्थिर होती हैं। इससे लार्ड ब्राडस का कथन ठीक प्रतीत होता है कि मिश्रित मंत्रों मंडलों की सरकार कमजोर होती है। जब सरकार की अपनी सुदृढ़ स्थिति पर भरोसा नहीं होगा, विभिन्न घटकों के परस्पर मतभेद और तनाव के कारण मंत्रिमंडल की स्थिति डौंवा डोल बनो रहेगी तो वह प्रशासन की ओर कैसे ध्यान दे सकेगी और कैसे जन कल्याण की योजनाओं का कार्यान्वयन कर सकेगी ?

भारतीय राजनीति में जाति एवं धर्म का दुष्प्रयोग -

समकालीन भारतीय राजनीति जातीय प्रवृत्तियों, राष्ट्र निर्माताओं की लाख कोशिशों के बावजूद खत्म होने की जगह गहरे पैठ चुकी है। कोई भी राजनीतिक दल इसके महत्व को झुठला नहीं सकते क्योंकि इस भावना को वोट के लिए उन्माद रूप में राजनीतिक दलों ने उभारा है।

भारत में सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का चयन करते समय जातिगत आधार पर निर्णय लेते हैं। प्रत्येक दल किसी भी चुनाव क्षेत्र में प्रत्याशियों

मनोनीत करते समय जातिगत गठित का अवश्य विश्लेषण करते हैं । 1971 का आम चुनाव कांग्रेस ने हरिजन-मुसलमान -ब्राम्हण शक्ति पुँज बनाकर ही जीता था । 1980 में भी इंदिरा कांग्रेस ने इन्ही जातियों का समर्थन प्राप्त करके चुनाव जीता था ।

हाल के वर्षों में पिछड़ी जातियों के संगठनों ने इनको एक करके कांग्रेस के सत्ता के एकाधिकार पर प्रश्न चिह्न लगा दिया है। 1980 के चुनावों में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के कुछ क्षेत्रों में लोकदल की सफलता पिछड़ी जातियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक है । उत्तर प्रदेश के चुनावों में चरण सिंह की सफलता सदैव ही जाट जाति के मतों की एकजुटता पर निर्भर रही है।

समकालीन भारतीय राजनीति में जातीयता का सिद्धान्त इतना गहरा घँस गया है कि राज्यों के मंत्रिमण्डल में प्रत्येक प्रमुख जाति का मंत्री होना चाहिए । यह सिद्धान्त ग्राम स्तर से लेकर प्रत्येक स्तर तक फैल गया है।

राजनीतिक दल प्रमुख जातियों को खुश करने के लिए विशेष सुविधाओं का प्रबंध करते रहे हैं । इन्ही वोट बैंकों को ध्यान में रखकर संविधान में आरक्षण की व्यवस्था कागलत स्पष्टीकरण देकर उनको लुभाने के लिए सरकारों नौकरियों तक में संविधान में वर्णित 50% से अधिक आरक्षण नहीं की सोमा की लोभकर आरक्षण की व्यवस्था कर दो जा रही है। जिसका प्रमाण तमिलनाडु एवं कर्नाटक की सरकारें हैं जिन्होंने अपने राज्यों में पिछड़ी जातियों के लिए 80 प्रतिशत तक आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है।

यह जातिगत वोट की राजनीति समाज को सैकड़ों टुकड़ों में बाँट रही है बजाय उसे जोड़ने के । जब हम समाज को बाँट रहे हैं तो राष्ट्र प्रेम की बात करना पाखंड से कम नहीं । अतः भारतीय राजनीति में जाति एक अभिशाप बनकर उभर रही है क्योंकि इससे लोगों के मन में पृथक्तावाद की भावना जग रही है राष्ट्रीय हित की अपेक्षा जातिगत हित प्राथमिक होते जा

रहे हैं। समकालीन उत्तर प्रदेश को मुलायम सिंह सरकार एवं बिहार को लालू सरकार इसके उदाहरण हैं जिन्होंने जातिगत हितों के लिए कितने ही नरसंहार करा डाले। यह लगता नहीं है कि सत्ता को चाह में देश एवं समाज को भूले ये राजनीतिज्ञ कभी घेते हैं, एवं उन्हें सभी के लिए विकास, शिक्षा व सुशाहली याद आसगी या नहीं।

स्वतंत्रता के पश्चात् राजनीतिक नेताओं ने साम्प्रदायिकता को सत्ता प्राप्ति के निमित्त निर्वाचन में सहायक समर्थक आधार को व्यापक करने और निर्वाचन संघर्ष में सहयोगियों को सुदृढ़ करने में देखा। समकालीन भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता या समुदायवाद ने अपना स्थान बना लिया है। इसका मुख्य कारण लोगों में सामुदायिक एकीकरण है जिसके कारण वे राजनीतिक दलों से ब्लैक मेलिंग करते हैं। कोई भी राजनीतिक दल उनको उपेक्षा या उनको अप्रसन्न करने का दुस्ताहस नहीं करता है बल्कि इसके विपरीत वे सभी इन वर्गों को चाटुकारिता प्रतिस्पर्धी स्तर पर करते हैं। क्योंकि राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य है सत्ता गठन एवं इसको प्राप्त करने के लिए वे बाटों और राज करो, अल्पसंख्यक का पक्ष लेकर शासन करो के चुनावी गठित के अनुसार कार्य करते रहे हैं। वे जानते हैं कि ये मतकोष जमा पूजो हैं।

भारत में अधिकांश राजनीतिक दल धर्म के आधार पर एवं संप्रदाय के आधार पर वोट मांगते रहे हैं। वोट बटोरने के लिए इमामों, पादरियों और साधुओं के साथ सौठ-गौठ की जाती रही है। मार्च 1977, जनवरी 1980 दिसम्बर 89 के लोक सभा चुनावों के दिनों में दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम की भूमिका से आसानी से यह समझा जा सकता है कि धार्मिक नेता राजनीतिक दलों से मुस्लिम संप्रदाय के वोटों को किस प्रकार सौदा करते हैं? किसी भी चुनाव के प्रचार में भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व को भावना को उभारना एवं हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगना इत्यादि से राजनीतिक दलों के मनः स्थिति का अंकलन आसानी से किया जा सकता है। दिनमान में किसी संवाददाता का लिखा कथन सहो प्रतीत होता है

कि समाजवाद एवं गणतंत्र को बात करने वाले यदि इमाम के नाम पर वोट मांगे तो हो सकता है कि बसराज मधोक जैसे लोग शंकराचार्य नाम के नाम पर वोट मांगेंगे, फिर क्या इस देश को इमाम और शंकराचार्य के बीच चुनाव करना पड़ेगा ?¹

भारतीय राजनीति में धर्म के गलत उपयोग के कारण हो सांप्रदायिकता को घटनाये जन्म लेती रहती है जिसका उदाहरण है राँची, बनारस, अलोगढ़ जमशेदपुर तथा अहमदाबाद को हिंसक घटनायें। सांप्रदायिकता एक अभिशाप है अतः राजनीतिक दलों को देश के बंटवारे को याद रखते हुए सांप्रदायिक राजनीति के द्वारा संप्रदायों के बीच की खाई को भरना चाहिए बजाय इसके कि सत्ता के लिए इनके बीच और आग भड़कायी जाय।

भारतीय राजनीति में अपराध एवं धन के वर्चस्व का मूल्यांकन :

भारतीय राजनीति में आन्दोलन को राजनीति का सूत्रपात 1971 के चुनावों में विपक्षी पार्टियों के हार के बाद से शुरू होता है। इस आन्दोलनों का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष कारवाई द्वारा सरकारों को विचलित करना एवं जन सामान्य का ध्यान आकर्षित करना रहा है। जिससे किसी भी प्रकार से सरकार को कमजोर करके चुनाव करवाया जाय एवं सत्ता प्राप्ति का रास्ता प्रशस्त किया जा सके। 1971 के बाद से हिंसक आन्दोलन एवं हड़ताल भारतीय राजनीति के प्रमुख तत्वों में से रहे हैं, चाहे ये आन्दोलन राजनीतिक मांगों को लेकर हो चाहे सरकार के पक्ष में रैलियों के रूप में हो।

आन्दोलन को राजनीति न केवल आर्थिक विकास को प्रभावित करती रही है बल्कि वे अर्थ-व्यवस्था और प्रशासन के सभी सामान्य कार्यों में रुकावट डालती रही हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि आन्दोलन को

राजनिति विषय कन्या सदृश है जिसके साथ सहवास करने से लोकतन्त्रोप शासन अपने विनाश का निमंत्रण देता है ।¹

लेकिन राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने अँख-कान पर पट्टी बाँध रखी है, उनका एक मात्र उद्देश्य सत्ता स्वरूप दल को पदच्युत करना रह गया है, बजाय रचनात्मक सहयोग देने के ।

इन राजनीतिक हिंसक आन्दोलनों के लिए राजनीतिक दल पेशेवर अपराधियों तक का सहयोग लेने में नहीं हिचक रहे हैं । वे पेशेवर अपराधियों से कानून व्यवस्था का उल्लंघन करवाते रहे हैं एवं सत्ता के लोभ में सामूहिक वरसंहार तक की घटनाएँ करवाना आजकल की भारतीय राजनीति में आम बातें हो गयी है। इसको ताजा-मिसाल भारत के उत्तर पूर्व में बोडो लैंड की माँग बिहार में झारखंड की माँग को लेकर चलाए जा रहे हिंसक आन्दोलन है। इस प्रकार समकालीन भारतीय राजनीति का हर तरह से अपराधीकरण होता जा रहा है ।

आज भारतीय राजनीति में काले धन की एक समानान्तर तथा त्नाशक्त अर्थव्यवस्था बढ रही है जो आम जनता को सहो राय जानने के बाधक रही है। चुनाव में काले धन की भूमिका ने लोक शक्ति को अंदर से खोखला बना दिया है। आज एक भी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जो चुनाव लड़ने के लिए धैली-शाही से लम्बी चौड़ी रकम न हासिल करता हो ।

राजनीतिक दल इस रकम का उपयोग चुनावों में व्यापक प्रचार के लिए करते हैं अपराधियों से साठ-गँठ करके उन्हें पैसों के बल पर खरीद लिया जाता है जो कि चुनाव के दौरान मतदान केन्द्रों पर कब्जा करते हैं, जाली मतदान उनके लिए आम बात हो गयी है। चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दल उनको राजनीतिक संरक्षण देते हैं जिससे कि धैलीशाह राजनीतिक दलों से

अपने हित के अनुसार कार्य करवाते हैं एवं अपराधी अपने हितों के अनुसार । बाद में सीधे तौर पर अपराधियों का एक वर्ग चुनाव के लिए चुनाव मैदान में उतरता है, एवं चुनाव जीतकर व्यवस्था का भाग बन जाता है जिससे किसी भी प्रकार के सही आचरण की अपेक्षा करना गलत है। इस प्रकार वर्तमान भारतीय चुनाव व्यवस्था एवं राजनीतिक व्यवस्था पूर्णतः दोषपूर्ण हो गयी है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक दाग है ।

नौकरशाही का मूल्यांकन :

पिछले दो दशक में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था जिसे नौकरशाही के नामसे जाना जाता है, इसके ढाँचे में व्यापक परिवर्तन हुआ है जिसका मुख्य कारण प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है । इसी के कारण भारतीय नौकरशाही की संस्कृति एवं मूल्यों में गिरावट आयी है । भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन लाल बहादुर शास्त्री के शासन से दिखाई पड़ता है उनके समय में लक्ष्मीकान्त झा जैसे अधिकारी उनके आँखें एवं कान हुआ करते थे एवं किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में उनका बहुत अधिक हाथ रहा करता था एवं यही प्रक्रिया इंदिरा गाँधी, राजीव गाँधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, से लेकर नरसिंहाराम तक चली आ रही है । इनके शासन काल में डॉ० पी० सी० अलैकजेण्डर, आर०के० धवन, गोपी कृष्ण अरोरा, मणि शंकर अयर विनोद चन्द्र पाण्डेय एवं वर्तमान समय में ए०एन० वर्मा एवं आर०के० खन्डेकर प्रधान मंत्री सचिवालय में अहम भूमिका निभा रहे हैं । वर्तमान समय में मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं प्रधान मंत्री के सचिवालय का बढ़ता हुआ महत्व किसी से छिपा नहीं है । ये दोनों कार्यालय प्रधान मंत्री के आँखें एवं कान थे एवं हैं । भारतीय नौकरशाही भी दिनो-दिन वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से तादात्म्य में स्थापित करती जा रही है । एवं इसका भी दिनो-दिन राजनीतिकरण होता जा रहा है क्योंकि राजनीतिक नेताओं के

स्वार्थ से निहित सही एवं गलत आदेशों का उल्लंघन करने पर उन्हें सजा भुगतनी पड़ रही है ये सजायें स्थानान्तरण के रूप में, उन पर रेंवे उनके परिवार पर हमलों के रूप में पैसे देकर खरोदने के रूप में होती हैं इसके परिणामस्वरूप नौकरशाहों का मनोबल काफी गिर गया है। नौकरशाहों के बोचरे में ईमानदार अप्सरों को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा है इसी कारण वर्तमान समय में अधिकतर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारों परोध रूप से किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं।

इस प्रकार 1967 से 1989 के बीच उभरती राजनीतिक प्रवृत्तियों से जिस प्रकार की भारतीय राजनीतिक संस्कृति का उद्भव हो रहा है उसके विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है राजनीतिक संस्कृति जो किसी समाज के निर्माण का साधन है वस्तुतः राजनीतिक दलों की लोलुप्पता का साधन बन कर रह गयी है इसलिए -

1- हमारे राजनीतिक जीवन में सत्ता की राजनीति का वर्चस्व स्थापित हो गया है। राजनीतिक नेताओं का सत्ता तक पहुँचना एक मात्र लक्ष्य बन गया है देश के विधान मण्डलों में पाँच हजार स्थान प्राप्त करने की छीना-झपटो और उसके लिए होने वाली सौदेबाजी ही राजनीति कहलाने लगी है। सारे राजनीतिक कार्य कलाप का नियोड़ यह रह गया है कि येन केन प्रकारेण चुनाव जीत लिया जाय और संसद या विधान सभा में प्रविष्ट होते ही मंत्रों की गद्दों की ओर दौड़ा जाय। एक बार सत्तासुद्ध होने के बाद उनको भरपूर चेष्टा यह रहती है कि कुर्सी बने रहे। राजनीतिक सत्ता लोकप्रियता प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, विरोध के लिए विरोध करते हैं और अन्य दलों के साथ सॉठ-गॉठ और जोड़-तोड़ के माध्यम से चुनाव जीतने की चेष्टा करते हैं। वे कभी ऐसा ढाँचा नहीं खड़ा करते कि ऐसा ढाँचा खड़ा किया जाय जिसमें सामाजिक और आर्थिक सम्भव हो।

2- समकालीन भारतीय राजनीति एक व्यवसाय बन कर रह गयी है। यहाँ

राजनोतिज्ञों के लिए राजनोति हो उनको रोजो रोटो है। भारत में अधिकतर लोग दूसरे व्यवसाय में असफलता के बाद ही राजनोति में आते-रहे हैं। आजकल राजनोति के सेवा के माध्यम के बजाय एक व्यवसाय और धंधे के रूप में विकसित होने के कारण बड़ी संख्या में लोग चुनावी प्रक्रिया की ओर आकर्षित हुए हैं। राजनोति के काफी हद तक सत्ता और आर्थिक सम्पन्नता के साथ जुड़ जाने के कारण लोगों की राजनोतिक आकांक्षाएं बढ़ गयी हैं और उन्हें लगता है राजनोति में उतर कर कम मेहनत से अधिक अर्जित किया जा सकता है। इसी कारण टिकटार्थियों की भोड़ पार्टी मुख्यालयों की ओर बढ़ो है।

- 3- पिछले तीन दशकों से लगातार भारतीय राजनोति में अविश्वास की भावना बढ़ी है। जिन लोगों को उत्तरदायी माना जाता है उन्होंने की बात पर जनता को भरोसा नहीं रहा है। राजनोतिक नेताओं के झूठे आचरण ने इस भावना को बहुत बढ़ाया है। आज की राजनैतिक नैतिकता का साम्य इस उक्ति में है कि राजनोति में सब कुछ चलता है। दूसरे शब्दों में झूठ धोखाधड़ी और सभी घासाराजनोति के नाम पर किए जा सकते हैं। चौधरी चरणसिंह का उदाहरण लिया जा सकता है, जिनको जीवन भर की प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा अधिकार पूरी हो गई। 15 अगस्त 1979 को ताल किले के प्राचौर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार मध्यावधि चुनाव के पक्ष में नहीं है क्योंकि उससे भारी खर्च होगा, और उसका बोझ जनता पर हो पड़ेगा। परन्तु पाँच ही दिन बाद उसी प्रधानमंत्री ने राय दी कि लोकसभा का विघटन करके चुनाव कराये जायें। इससे केवल यही कहा जा सकता है कि भारत में जनसाधारण का नैतिक स्तर देश में तथ्यांकित राजनेताओं की तुलना में कहीं अधिक उँचा है। साधारण व्यक्ति इस प्रकार आचरण करते हुए शिक्षकता है। क्योंकि उसे बदनामी का डर होता है। परन्तु जहाँ तक राजनोतिज्ञों

का संबंध है, उनमें तनिक भी द्विचक नहीं है।

- 4- 1967 के पश्चात् राजनीतिक संस्कृति में नारी व प्रतीको का विशेष महत्त्व रहा है। समाजवाद न लाने पर भी वर्षों तक कांग्रेस "समाजवाद" के नारे के नाम से चुनाव जीतती रही। 1967 में चुनावों में डॉ० लोहिया का गैर कांग्रेसवाद, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा काम कर गया। 1971 के चुनावों में गरीबों हटाओ का श्रीमती गांधी का नारा प्रभावोत्पन्न हुआ। मार्च 1977 में चुनावों में जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र बनाम तानाशाहों का नारा दिया। जनवरी 1980 में श्रीमती गांधी का नारा था वह सरकार चुनिए जो काम कर सके। 1984 में राजीव गांधी ने राष्ट्रीय एकता खतरे में है का नारा दिया। 1989 में बो.पो. सिंह ने भ्रष्टाचार हटाओ का नारा दिया। जबकि 1991 के चुनाव में कांग्रेस आई ने स्थिर सरकार व आर्थिक विकास के मुद्दों को प्रचार का माध्यम बनाया।
- 5- समकालीन भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष कार्यवाही के तरीकों का व्यापक प्रयोग होता है। यहाँ हम अक्सर अन्धान, बंद, हड़ताल, धराव, सत्याग्रह आदि के बारे में सुनते रहते हैं। इन साधनों का प्रयोग विरोध प्रदर्शित करने के लिए या दबाव डालने के लिए होता है। लगभग सभी हित समूह और राजनीति दल इन साधनों को वैध मानते रहे हैं।
- 6- 1971 के पश्चात् भारतीय राजनीति में वोट के महत्त्व के कारण निम्न समझी जाने वाली जातियों का महत्त्व कई स्थानों पर बेरतहा बढ़ा है। हाल के वर्षों में पिछड़ी जातियाँ न केवल अपने राजनीति स्तर के प्रति जागरूक हुई हैं, बल्कि सत्ता को भी ग्रहण कर रही हैं, जिनका प्रत्यक्ष प्रमाण 30प्र० में मुन्नायक सिंह यादव को सरकार व बिहार में लालू प्रसाद यादव को सरकार हैं। इन सरकारों को सत्ता निम्न जातियों के बढ़ते प्रभाव के कारण स्थापित हुई है।

7- आज को भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार घुल-मिल गया है। राजनीतिक नेता अपनी पार्टियों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए सरकारों कर्मचारियों को नियुक्ति स्थानान्तरण पदोन्नति आदि छोटे-बड़े मामले में गहरो दिलचस्पी लेने लगे हैं जिससे कि वो इन कार्यों को कराके धन इकट्ठा कर सकें। चुनाव लड़ने के लिए विभिन्न पार्टियाँ पूजोपतियों एवं कम्पनियों से पैसा इकट्ठा करती है एवं सत्तारूढ़ होने पर उन्हें अनुचित लाभ पहुँचाने का प्रयत्न करती हैं। कुलदोप नायर का कथन आज को भारतीय राजनीति के लिए शत प्रतिशत खरा उतरता है कि प्रश्न यह है कि रिश्वत खोरी का दौर चल रहा है क्योंकि रिश्वत आज अपने आप में कोई समाचार नहीं है।

इस प्रकार भारत में समतावादी, सहभागो राजनीतिक संस्कृति का विकास हो रहा है। जिसमें पिछले परम्परागत मूल्यों का हास हो रहा है एवं नये मूल्य स्थापित हो रहे हैं एवं उनको पुनः परिभाषित किया जा रहा है।

राजनीतिक संस्कृति में यह परिवर्तन स्वाभाविक है क्योंकि सामाजिक विकास दण्डवादो होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में जिस प्रकार को राजनीतिक संस्कृति का विकास हुआ था उसे वोनर ने विशिष्ट वर्गीय राजनीतिक संस्कृति कहा। यह उन व्यक्तियों को राजनीतिक संस्कृति थी जो राष्ट्रीय राजनीति में क्रियाशील थे एवं जिनका दृष्टिकोण विस्तृत था एवं रजो राष्ट्रीय हितों को महत्व देते थे। विशेषतः यह आधुनिक वर्ग के लोगों को राजनीतिक संस्कृति थी जो सामाजिक एवं वैचारिक रूप से अधिक पश्चिमाभिमुख थे, एवं इस संस्कृति को नेहरू माडल का नाम दिया गया।

1- नायर कुलदोप : भ्रष्टाचार को दुर्गन्ध में सड़ता बिहार, राजस्थान पत्रिका §जयपुर§, 8 दिसम्बर 1981

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सत्ता के जन्तरोकरण से जनसाधारण को राजनीति में भाग लेने का अधिक अवसर मिला एवं धीरे-धीरे समाज के निम्न वर्ग के लोग भी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। जिनका दृष्टिकोण पूर्णतः परंपरावादो है जो कि राष्ट्रीय हितों को अपेक्षा स्थानीय हितों जैसे जातिवाद, संप्रदायवाद एवं प्रांतियता को भावना को अधिक महत्व देते रहे हैं। धीरे-धीरे इन भावनाओं से ओत प्रोत समाज के निचले वर्ग के इन लोगों के राजनीति में सक्रिय सहभागिता ने राजनीति का रूप परिवर्तित कर दिया है एवं वर्तमान भारतीय राजनीतिक संस्कृति इसी को देन है। जिसमें सामाजिक एकता को आकांक्षा प्रधान है और जो विशेषकर आरक्षण के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए संघर्षरत है परन्तु विडम्बना यह है कि आर्थिक ढाँचा इस प्रकार का है जिससे समाज में केवल असमानता को ही पोषण मिलता है आर्थिक समानता लाने के लिए पिछले 5 दशकों में भूमि सुधार सम्बन्धी कानून अपनाए गये हैं जिनसे निश्चय ही ग्रामीण क्षेत्रों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। कुल मिलाकर धन एवं संपत्ति का केन्द्रोकरण हो हुआ है। अतः सामाजिक क्रान्ति के साथ आर्थिक क्रान्ति की आवश्यकता है। जिसके प्रति हमारे संविधान निर्माता जागरूक थे लेकिन जिसका प्रावधान वे संविधान में अपने विवशताओं के कारण नहीं कर पाये थे और जिन अभावों को दूर करने के लिए संविधान में अनेक परिवर्तन हुए। जिनमें संविधान संशोधन 1, 4, 17, 44वाँ, प्रमुख हैं। परन्तु 1990 के पश्चात् प्रगति का चक्र विपरीत दिशा में घूम गया है जो उदारोकरण, बाजार अर्थव्यवस्था को ओर ले जाता है जो पूंजीवाद को पुष्टि करता है जो आर्थिक न्याय का आश्वासन नहीं देता।

अतः समकालीन भारतीय राजनीतिक संस्कृति विरोधाभास से ग्रस्त है एक ओर जहाँ सामाजिक समानता और न्यायकेसर्वोपरि मूल्य के रूप में मान्यता प्राप्त हैं जिनको साकार बनाने के लिए सरकारें आरक्षण को नीति का पालन कर रही है परन्तु सामाजिक समानता के साथ-साथ आर्थिक समानता का कोई कार्यक्रम नहीं है। वास्तव में प्रवृत्ति विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच आर्थिक खाई को और अधिक बढ़ाने की है अतः जहाँ सामाजिक संस्कृति समता को ओर ले जाती है वही आर्थिक विकास असमानता को ओर ले जाने वाला है। ऐसी स्थिति में हिंसा, भ्रष्टाचार अपराधीकरण स्वाभाविक है। यही कारण है कि भारतीय राजनीतिक संस्कृति जहाँ सामाजिक दृष्टि से समता वादी है, सहभागो है वहीं इसमें अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और हिंसा को भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्थिक असमानताओं के रहते हुए इन प्रवृत्तियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यही इस समय भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को मूल विडम्बना है।

... ..

1967 के चुनाव से सम्बन्धित सारणियाँ

सारणी - 1

§ अखिल भारतीय पार्टियाँ लोकसभा §

पार्टियों के नाम	उम्मीदवार प्राप्त सीटें	सीटों का प्रतिशत	प्राप्त वोट	वोटों का प्रतिशत	उम्मीदवारों का प्रतिशत
कांग्रेस	516	284	54.9	59402754	40.7
स्वतंत्र	179	44	8.5	12659540	8.7
सो. पो. आई	110	23	4.4	7584180	5.2
सो. पो. आई § सम् §	58	19	3.7	6140738	4.2
सो. पो. § योग §	168	42	8.1	13104918	9.4
पो. रस. पो.	109	13	2.5	4456487	3.1
रस. रस. पो.	122	23	4.4	71715931	4.9
जे. रस.	251	35	6.7	13715931	9.4
रस. सम्.					
आर. पो. आई	70	1	0.2	3607711	2.5
आर. आर. पो.					
अन्य पार्टियाँ	89	43	8.3	11096342	7.2
निर्दल	865	35	6.7	20051200	13.8
योग		520		145866510	

सारणी - 2

॥ राज्य विधान सभायें ॥

पार्टियों के नाम उम्मीदवार प्राप्त सीटें	सीटों का प्राप्त वोट प्रतिशत	सीटों का प्राप्त वोट प्रतिशत	वोटों का प्रतिशत
कांग्रेस	3446	1693	48.5
स्वतंत्र	978	257	7.4
सो. पो. आई	625	121	3.5
सो. पो. आई एम	511	128	3.7
सो. पो. योग	1136	249	7.2
पो. एस. पो.	768	106	3.04
जे. एस.	1607	268	7.7
एस. एस. पो.	813	180	5.2
एम. एस.			
आर. पो. आई	378	23	0.7
अन्य पार्टियाँ	826	333	9.5
निर्दलीय	5554	376	10.8
योग		3487	143256509

चुनाव का स्वरूप : 1967 में राज्यों को विधान सभाओं में दलों की स्थिति

राज्य	कॉंग्रेस	कॉम्युनिस्ट	सोशलिस्ट	स्वतंत्र	जनसंघ	अन्य	निर्दलीय
असम	73	7	9	2	-	9	25
आंध्र प्रदेश	165	20	1	29	3	1	68
उड़ीसा	31	8	23	49	-	26	3
उत्तर प्रदेश	199	14	55	12	98	10	37
केरल	9	71	19	-	-	19	15
गुजरात	93	-	3	66	1	1	5
जम्मू कश्मीर	61	-	-	-	3	8	3
पंजाब	47	8	1	-	9	29	10
पं. बंगाल	127	59	14	1	1	47	31
बिहार	128	28	86	3	26	14	33
मद्रास	50	13	6	20	-	138	7
मध्य प्रदेश	167	1	19	7	78	2	22
महाराष्ट्र	203	11	12	-	84	24	16
मैसूर	126	2	26	16	4	1	41

राजस्थान	89	1	8	48	22	-	16
हरियाणा	48	-	-	3	12	2	16
केन्द्र शासित	77	6	4	1	7	28	27
योग	1693	249	286	257	268	359	375

नोट - आकड़ों का आधार चुनाव आयोग की रिपोर्ट तथा भारत सरकार
कोर्थ जेन, एलेक्सन: इन अनार्लिसिस - 1967

1967 में चुनाव का रुख : लोकसभा में दलों की स्थिति

राज्य	कांग्रेस	कम्युनिस्ट	सोशलिस्ट	स्वतंत्र	जनसंघ	अन्य दल	निर्दलीय
असम	10	1	2	-	-	1	-
आंध्र प्रदेश	35	1	-	3	-	-	2
उड़ीसा	6	-	5	8	-	-	1
उत्तर प्रदेश	47	6	10	1	12	1	8
केरल	1	12	3	-	-	2	1
गुजरात	11	-	-	12	-	-	1
जम्मू कश्मीर	5	-	-	-	-	1	-
नागालैंड	1	-	-	-	-	-	-
पं. बंगाल	14	10	2	-	-	7	7
पंजाब	9	-	-	-	1	3	-
बिहार	34	5	8	-	1	1	5
मद्रास	3	4	-	6	-	25	1
मध्य प्रदेश	37	2	3	1	10	-	2
मैसूर	18	-	3	5	-	2	1

सारणी - 5

पार्टी पसंद 1967 ई प्रतिशत

कॉमिंस	जनसंघ	स्वतंत्र	सोशलिस्ट	कॉम्युनिस्ट	द्र. मुक	अन्य	निर्दल	कोई नहीं	पता नहीं
			दोनो	दोनो					नहीं इनकार
सब से ज्यादा लगाव	43.1	7.1	5.1	4.9	4.1	3.0	2.5	3.4	26.2
सन् 67 में जिस	43.1	7.1	5.2	7.4	5.5	4.1	2.3	7.0	11.
दल को लोट दिया									0.5
राज्य चुनाव									वोट नहीं दिया
1967 में वास्तविक	40.0	8.8	6.8	8.7	8.7	4.4	6.0	16.7	6.6
वोट प्राप्त									-
राज्य चुनाव									-

226

क- यह संख्या वैध वोटों की है इसलिए वोट न देने वालों की संख्या नहीं दी गई । पर वास्तव में 38 प्र.शं.

ख- चूंकि बाकी संख्या वैध वोटों की है इसलिए वोट न देने वालों की संख्या नहीं दी गई ।
मतदाताओं ने वोट नहीं दिया ।

सूत्र- सेटर फार स्टडी डेव. सोसा. दिल्ली "नेशनल एलम्यन्स स्टडी 1967 ।

पाँच राज्यों में मध्यावधि चुनाव 1967 और 1968-69

राज्य	कंग्रेस	कम्युनिस्ट			सोशलिस्ट			जनसंघ	अन्य दल			निर्दल	
	67 -	69	67-	69	67-	69	69	67-	69	67-	69	67-	69
हरियाणा स्थान	48	48	-	-	-	-	7	5	20वि.	16	6		
वोट प्र.श.	41.33	43.88	1.44	0.46	3.79	0.97	14.39	10.45	6.08	27.14	32.97	17.10	
उत्तर प्रदेश स्थान	199	211	14	5	55	35	98	49	22स्व.	107भा	37	17	
वोट प्र.श.	32.20	33.98	4.50	3.55	14.07	9.58	21.67	17.26	8.27	25.93	18.69	9.70	
बिहार स्थान	128	118	28	28	86	70	26	34	17जक	49	33	19	
वोट प्र.श.	33.09	30.30	8.19	11.31	24.58	19.21	10.41	15.91	5.84	2.16	17.88	21.11	
पं. बंगालस्थान	127	55	59	110	14	14	1	-	48भा.	78वा.	31	23दिव	
वोट प्र.श.	41.13	41.31	24.64	26.96	4.01	3.17	1.33	0.83	15.41	12.97	13.49	14.76	
पंजाब स्थान	47	38	8	6	1	3	9	8	29भा.	45अल	10	4	
वोट प्र.श.	37.74	39.19	8.46	7.91	1.23	1.33	9.84	9.2	26.98	32.34	15.76	10.21	

नोट - हरियाणा में मध्यावधि चुनाव 1968 में हुए थे। कम्युनिस्ट में मार्क्सवादों तथा सोशलिस्ट में सं. सो. तथा प्र. सो. दोनों शामिल

वि. विशाल हरियाणा 16 स्थान 14.86 बोट प्र.श.

स्व. स्वतंत्र 12 स्थान 4.73 बोट, रिपब्लिकन पार्टी 10 स्थान 4.14 बोट

भा. भा.कान्द 99 स्थान 21.22 बोट

ज. क्र. जनक्रांति दल 13 स्थान 3.33 बोट

जन. जनता पार्टी 14 स्थान 0.28 प्र.श. बोट

- फा. 4 फारवर्ड ब्लाक 13 स्थान 4.43 प्र.श. बांगला कांग्रेस 34 स्था. 10.16 प्र.श।
 बां. बांगला कां. 33 स्थान 8.01 वोट फार ब्लाक 21 स्थान 4.69 प्र.श.
 रिच. रिचो ल्युनरो सोशलिस्ट पार्टी 12 स्थान
 अ. अकाली 43 सीट 29.59 वोट
 आंक्डे - रिपोर्ट फोर्थ जेन. एलेक्शन 1967 खंड 2 एलेक्शन कमीशन 1967 नई दिल्ली
 पी.आई.बी. भारत सरकार मध्यावधि चुनाव विज्ञप्ति ।

सारणी - 7

कांग्रेस के विरुद्ध शिकायत से सहमति या असहमति

शिकायत	जोर से हाँ	हाँ	नहीं	जोर से नहीं	नहीं जानता
कांग्रेस मूल्यवृद्धि नहीं रोक सकी	61.0	23.4	6.8	1.7	7.1
कांग्रेस खाद्य का वितरण ठीक न कर सकी	51.8	23.7	13.4	3.1	8.0
कांग्रेस भ्रष्टाचार का उन्मूलन न कर सकी	55.5	22.6	7.1	2.0	12.8
कांग्रेस अमन कानून कायम न रख सकी	36.9	28.5	15.7	4.5	14.4
कांग्रेस ने किसानों को मदद नहीं की	38.3	21.6	21.9	8.0	10.2
कांग्रेस देश को दुर्द्ध नेतृत्व न दे सकी	35.4	27.5	13.7	3.7	19.7

नोट - ये प्रारम्भिक आंकड़े हैं अधिकतर उत्तरदाता मर्द थे §।

सूत्र - से. स्ट. डेव. सोसा. दिल्ली * नेशनल एलेक्शन स्टडी 1967

पार्टीवार तथा पेशेवार संसद सदस्यों का विवरण, I
चौथी लोकसभा, प्रतिशत में

	जमीन	राजनैतिक सामाजिक मजदूर संगठनकार्य	वकालत	डाक्टर इन्जीनियर	शिक्षा पत्रकारी	व्यापार उद्योग	भूतपूर्व राजा	प्रशासन सेवा	अन्य
कटिप	36.8	17.0	22.2	3.9	9.8	5.1	2.5	2.9	1.7
स्वतंत्र	40.5	2.4	22	4.8	2.4	16.7	7.1	7.1	7.1
जनसंघ	22.9	19.4	13	3.3	12.9	12.9	0.0	6.5	6.5
कम्यु. इं.	10.5	73.7	0.0	0.0	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0
कम्यु. मार्क्स	0.0	80.0	5.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0
संतोषा	42.1	42.1	5.3	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0
प्रसोपा	23.1	15.4	38.5	0.0	15.4	0.0	0.0	7.7	0.0
द्रमुक	37.5	8.3	16.7	0.0	16.7	16.7	0.0	4.2	8.3
अन्य दल	13	21.7	21.7	0.0	26.1	17.4	0.0	0.0	0.0
निर्दल	19.3	12.1	19.4	6.5	12.1	16.1	12.9	3.3	0.0
योग	31.3	21.1	17.3	3.2	11.2	7.8	2.8	3.0	2.2

सूत्र- रत्न दत्त द पार्टी रिप्रेजेंटेशन इन फोर्थ लोकसभा इंड, ऐड पोलि. वीकली, चार.सं. 1-2 जून 1969

पेशेवार पार्टीवार वोट प्रतिशत में

	कंग्रेस	स्वतंत्र	जनसंघ	कम्प्यु. डी.	कम्यु. संसदीय प्रोत्सापार्द्रमुक	अन्य	निर्दल	वोट नहीं दिया	मालूम नहीं
पेशेवर	39.5	0.0	13.2	2.6	5.3	7.9	2.6	13.2	7.9
व्यापारी	47.0	1.7	7.7	0.9	1.7	5.1	3.4	2.6	3.4
बुद्धिजीवी	31.2	1.4	12.1	2.8	2.8	2.8	3.5	0.7	10.6
कुशल कामगार	39.9	1.3	4.8	1.8	5.3	3.9	8.3	5.3	5.3
मामूली कामगार	42.6	2.2	4.9	3.3	3.8	5.5	2.7	1.1	6.6
खुद काशत	46.1	8.4	8.1	3.6	1.3	2.0	2.8	4.9	6.7
खेत मजदूर	44.3	4.7	4.0	3.6	2.0	5.9	4.3	4.7	4.7
बेरोजगार	29.4	3.9	8.8	2.9	2.9	6.9	2.0	4.9	14.7

सूत्र- सै. फार. स्ट. डेव. सोसा. दिल्ली, नेशनल एलेक्शन स्टडी 1967 । कच्चे आंकड़े ।

पार्टीवोट, पेशवार & प्रतिशत में

पेशवार	व्यापारी	बुद्धिजीवी	कुशल कामगार	मामूलो कामगार	सुद कामत	खेजमजदूर	बेरोजगार
कांग्रेस	1.8	5.3	10.9	9.3	49.2	13.4	3.6
स्वतंत्र	0.0	2.0	2.9	3.9	73.5	11.8	3.6
जनसंघ	3.5	12.0	7.7	6.3	50.7	7.0	6.3
कम्यु. डं.	1.7	6.7	6.7	10.0	53.3	15.0	5.0
कम्यु. मा.	4.3	8.5	25.5	14.9	25.5	10.6	6.4
संसोपा	4.2	5.6	12.5	13.9	25.0	20.8	9.7
प्रसोपा	1.4	6.9	26.4	6.9	34.7	15.3	2.8
द्रमुक	1.2	1.2	15.0	6.2	55.0	15.0	2.5
अन्य	2.2	21.7	28.3	4.3	12.0	4.2	10.0
निर्दल	.7	7.5	20.4	10.4	46.3	12.7	5.2
वोट नहीं दिया	2.2	10.9	12.2	13.5	32.6	15.7	6.5
नहीं जानते	2.3	11.3	9.0	9.0	45.1	9.0	11.3

232

सूत्र से. फार. स्ट. डेव. सो. सा. दिल्ली. नेशनल एलेक्शन स्टडी 1967 । कच्चे आंकड़े

पॉपुलेशन आम चुनावों के बाद राज्यों में राजनैतिक दलों की स्थिति

राज्य	विधान सभा में कुल स्थान	कांग्रेस	स्वतंत्र जनसंघ	भारतीय माकसवादी दल	साम्यवादी दल	अन्य दल	निर्दलीय सदस्य
आन्ध्र प्रदेश	287	219	-	2	7	5	53
महाराष्ट्र	270	222	-	5	1	12	25
कर्नाटक	216	135	24	-	3	6	15
गुजरात	167	139	16	3	1	-	8
गोवा	30	1	-	-	-	28	1
दिल्ली	56	44	2	-	5	3	1
मैट्रोपोलिटन कौंसिल						सम. जो. ली. ४	
हिमाचल प्रदेश	65	51	-	-	5	-	13
बिहार	318	167	30	-	26	35	12
हरियाणा	81	66	-	-	10	24	3
						अस. ली. ४	
मध्य प्रदेश	297	220	-	-	48	3	18
राजस्थान	184	145	1	11	8	4	11

असम	114	95	-	1	-	3	-	4	6	5
मणिपुर	60	17	1	-	-	5	-	3	18	16
मेघालय	60	9	-	-	-	-	-	-	32	19
								8		
पश्चिमो बंगाल	280	216	2	-	-	35	14	-	8	5
त्रिपुरा	60	41	-	-	-	1	16	-	5	2
जम्मू कश्मीर	74	57	-	-	3	-	-	-	-	9
योग	272	1926	88	16	105	112	33	57	163	231

- महाराष्ट्र गोमान्त्रिक दल ।

सारणी- 12

भारत में चुनावी राजनीति और मतदान व्यवहार

राजनैतिक दल	1970 में लोकसभा में प्राप्त स्थानों की संख्या	1971 के चुनाव में लोकसभा में प्राप्त स्थानों की संख्या	कुल वैध मतों का प्राप्त प्रतिशत
सत्ता काग्रेस	220	350	43.6
संगठन काग्रेस	65	16	10.6
मार्क्सवादी-साम्यवादी दल	19	25	4.9
भारतीय साम्यवादी दल	24	23	4.5
द्रविड़ मुन्नेत्रकड़म	24	23	4.9
जनसंघ	33	22	7.5
भारतीय क्रान्ति दल	10	1	1
संयुक्त समाजवादी दल	17	3	2.4
प्रजा समाजवादी दल	15	2	2
अन्य दल व निर्दलीय	57	43	18.5
योग	519	516	100

1235

सारणी- 13

दल का नाम	मार्च 1977 के चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या	लोकसभा में प्राप्त स्थान	प्राप्त मता का प्रतिशत
कंग्रेस	493	153	34.54
जनता पार्टी/लोकतांत्रिक कंग्रेस	423	298	43.12
	8391+ 328	8 270+ 288	
भारतीय साम्यवादी दल	92	7	2.87
मार्क्सवादी दल	53	22	4.30
क्षेत्रीय दल और अन्य निर्दलीय	1278	59	15.17

सारणी - 14

छठे लोकसभा में जनता पार्टी के घटकों का प्रतिनिधित्व

संख्या	घटक का नाम	लोक सभा सदस्यों की संख्या
1-	जनसंघ	94
2-	भारतीय लोकदल	71
3-	संगठन कांग्रेस	50
4-	सोशलिस्ट पार्टी	28
5-	कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी	28
6-	चन्द्रशेखर गुट	5
7-	अन्य	25
कुल		301

घटकवाद के आधार पर निर्मित जनता मंत्रिमण्डल

संख्या	घटक का नाम	मंत्रियों की संख्या
1-	भारतीय लोकदल	12
2-	जनसंघ	11
3-	संगठन कांग्रेस	10
4-	सोशलिस्ट	4
5-	कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी	3
6-	अकाली दल	2
7-	चन्द्रशेखर	2

1980 के लोकसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों को स्थिति का परिचय निम्न तालिका के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है ।

राजनीतिक दल	चुनाव में खड़े किये गये उम्मीदवारों की संख्या	प्राप्त किये गये स्थानों की संख्या	मत प्रतिशत, जो प्राप्त किया गया
इन्दिरा काँग्रेस	488	351	42.66
जनता पार्टी	431	31	18.94
जनता"एस" लोकदल	291	41	9.43
भारतीय साम्यवादी दल	48	11	2.61
मार्क्सवादी दल	62	35	6.05
डो0एम0के0	16	16	2.15
अन्ना डी. एम. के.	24	2	2.38
अकाली दल	7	1	0.7
अन्य दल	200	16	3.25
निर्दलीय	2,828	8	6.55

अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा जो 16 स्थान प्राप्त किये गये, उनका विवरण निम्न

प्रकार है :

मुस्लिम लोग

केरल कमिश्नर ऑफ़ गूफ़

क्रान्तिकारी समाजवादी दल

महाराष्ट्रवादी गोमातक पार्टी

अखिल भारतीय फ़ारवर्ड ब्लॉक

सिक्किम जनता परिषद

सारणी- 16

मई 1980 में सम्पन्न 9 राज्यों को विधानसभाओं के चुनाव परिणाम

राज्य का नाम	कुल स्थान	वर्तमान में चुनाव	इन्दिरा कान्ति	भारतीय जनता पार्टी	जनता जे. पी. चरणसिंह	राज. ना. जे. अर्जुन वादोदल	कान्ति जनता एस	भारतीय माकसवादो अन्य क्षेत्रीय दल			
उत्तर प्रदेश	425	419	305	11	4	58	4	13	7	-	-
मध्य प्रदेश	320	320	246	60	2	1	-	-	2	-	-
बिहार	324	321	167	21	13	43	1	14	24	6	भारखण्डमुक्तिम 12
राजस्थान	200	200	133	32	8	7	-	6	1	1	-
महाराष्ट्र	288	288	186	14	17	-	-	47	2	2	रिपब्लिकन-1 कृषक कामगारदल-5
गुजरात	182	180	141	9	21	1	-	-	-	-	-
उड़ीसा	187	146	117	-	3	13	-	2	4	-	-
तमिलनाडु	234	234	20	-	2	-	-	-	10	11	अन्ना डो. एस. के.- डो. एम. के.- 38
पंजाब	177	177	63	1	-	-	-	-	9	5	अकाली दल- 37
	2,237	2,225	1,388	148	70	123	5	82	59	25	231

आठवों लोकसभा के चुनाव परिणाम

राजनैतिक दल	चुनाव के पूर्व की स्थिति	उम्मीदवारों की संख्या	प्राप्त स्थान	प्राप्त मतों
इन्दिरा कांग्रेस	339	481 तमिलनाडु में अन्ना डी.एम. के. और केरल में सहयोगी दलों का समर्थन	401	51.90 डी.सो.एम. विश्लेषण के अनुसार 49.38 पाधिक पत्रिका टूट्टे के अनुसार 7.03
जनता पार्टी	21	207	10	5.91
दलित मजदूर किसान पार्टी लोकरक्ष	8	168	3	7.71
भारतीय जनता पार्टी	16	226	2	4.14
तेलुगु देशम्	2	32	28	-
कांग्रेस लक्ष	5	32	4	-
कांग्रेस लक्ष	2	-	1	-
मार्क्सवादी दल	36	56	22	5.80
भारतीय साम्यवादी	-	62	6	-
द्र.मु. क.	14	-	1	-
अन्ना द्र.मु. क.	3	-	12	1.72
नेशनल काँग्रेस लक्ष	3	-	3	-

पारवर्ड ब्लाक	3	-	2	-
मुस्लिम लोग	3	-	2	-
आर.एस.पी.	4	-	3	-
अन्य दल	5४	राष्ट्रीय संजय मंच-3४	3४	केरल कांग्रेस-2, कृष्ण कामगार दल- 1४
निर्दलीय	18	निर्वाचित और 2 मनोनित	लगभग 4 हजार ४५०	7 ४5 निर्वाचित और 2 मनोनित

दिसम्बर 1984 में लोकसभा के 508 स्थानों पर चुनाव हुए थे ।

सारणी - 18

मार्च 1985 में सम्पन्न 11 राज्यों और एक केन्द्रशासित प्रदेश को विधान सभाओं के चुनाव परिणाम

राज्य का नाम	कुल स्थान	इन्दिरा कांग्रेस	भारतीय जनता पार्टी	दलित मजदूर किसानपार्टी लोकदल	जनता पार्टी	भारतीय कांग्रेस साम्यवादी-स. दल	मार्क्सवादी दल	अन्य क्षेत्रीय दल
आन्ध्र प्रदेश	294	49	8	-	2	11	-	तेलगू देशम्-205
उत्तर प्रदेश	425	266	16	86	19	-	2	-
कर्नाटक	224	66	2	-	139	4	2	-
बिहार	324	193	15	44	14	13	1	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा-1
उड़ीसा	147	117	1	-	21	1	-	-
गुजरात	182	149	11	-	14	-	-	-
राजस्थान	200	115	38	27	10	-	1	-
महाराष्ट्र	288	161	16	-	20	2	56	2 कृषक कामगार दल-12
मध्य प्रदेश	320	250	58	-	5	-	1	-
हिमाचल प्रदेश	68	55	7	1	-	-	-	-
सिक्किम	32	1	-	-	-	-	-	- सिक्किम संगम पार.-30
पार्किण्डेरो	30	15	-	-	2	-	-	- भन्ना प्र.मु.क.-6 प्र.मु.क.-5

योग

2,534

1,437

158

246

31

59

18

296

सारणी - १९

निम्न दलों द्वारा 1967 से 1989 के बीच लोकसभा चुनाव में प्राप्त मतों का विवरण

चुनाव	क ग्रेस	भा. कण्डो भारत	भा 10 क 0 प 10 मा कर्सवा दौ	प 10 0 एस 0 प 10 एस 0 एस 0 प 10	स्वतंत्र पार्टी 1903	क ग्रेस	जनसंघ	जनता/ लोकदल
चौथा चुनाव 1967								
कुल स्थान 520	73.08	5.87	-	2.43	-	3.64	2.83	-
क- स्थानों का प्रतिशत								
ख- मतों का प्रतिशत	44.73	9.94	-	6.81	2.70	7.90	6.44	-
पँचवा, 1971 कुल								
स्थान 518	67.95	4.42	4.83	0.39	0.58	1.54	3.09	4.25
क- स्थानों का प्रतिशत								
ख- मतों का प्रतिशत	43.70	4.73	5.12	2.04	2.42	3.10	10.42	7.40

छठा गुनाव

1977, कुल स्थान 542

क- स्थानों का प्रतिशत	28.71	1.29	4.06	-	-	-	0.55	54.43
ख- मतों का प्रतिशत	34.52	2.82	4.30	-	-	-	1.72	41.32

1980, 542 स्थान

क- स्थानों का प्रतिशत	66.07	2.09	6.67	-	-	-	-	7.80
ख- मतों का प्रतिशत	42.70	2.61	6.10	-	-	-	5.30	9.40

चुनाव 1984 कुल

स्थान 542

क- स्थानों का प्रतिशत	78.64	1.17	4.32	-	-	0.39	-	0.78
ख- मतों का प्रतिशत	49.10	2.75	5.88	-	-	7.75	-	1.52

चुनाव 1989

कुल स्थान 543

क- स्थानों का प्रतिशत	57.02	2.10	6.11	-	-	16.41	-	0.19
ख- मतों का प्रतिशत	39.33	2.61	6.32	-	-	11.56	-	0.33

1- वर्ष 1977 से कांग्रेस दल को कांग्रेस आर्द्ध नाम से जाना गया। वर्ष 1984 में "आर्द्ध शब्द" निकाल दिया गया।

2- वर्ष 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय जनता में पाटों हुआ, परन्तु 1980 भा.ज.पा. के रूप उदय हुआ।

3- 1977 से कांग्रेस संगठन का विलय कई दलों में हो चुका है। जैसे कांग्रेस यू.ए.ए. जे.ए.ए.एम.बी.

मन्त्रिपद पाने वाले दल-बदलों के विस्मयकारी आँकड़े

क्र०स०	राज्य का नाम	दल में दल- बदलों को सं०	मन्त्रियों को कुल संख्या	दल-बदल मंजो संख्या और प्रतिशत	मुख्यमंत्री दल-बदल या नहीं
1-	राजस्थान:				
	सुभाषिड़िया मन्त्रिमण्डल	18	35	5 ११4 प्रतिशत	नहीं
2-	हरियाणा:				
	राव वीरेन्द्रसिंह का मोर्चा मन्त्रिमण्डल	29	23	22 १95 प्रतिशत	हाँ
3-	पंजाब :				
	१००० गुरुनामसिंह का सं. मो. मन्त्रिमण्डल	7	17	6१35 प्रतिशत	नहीं
	१००० कश्मिर समर्थित मन्त्रिमण्डल	18	16	16१100 प्रतिशत	हाँ
4-	बिहार:				
	१००० एम. पी. सिन्हा का. सं. मो. मन्त्रिमण्डल	12	34	5१17 प्रतिशत	नहीं
	१००० कश्मिर समर्थित मण्डल मन्त्रिमण्डल	38	38	38१100 प्रतिशत	हाँ
	१००० भोला पासवानका. सं. मो. मन्त्रिमण्डल	51	13	7१53 प्रतिशत	हाँ
5-	मध्यप्रदेश :				
	गोविन्द नारायण सिंह मन्त्रिमण्डल	36	34	21१62 प्रतिशत	हाँ
6-	उत्तर प्रदेश:				
	चरण सिंह का सं. मो० मन्त्रिमण्डल	17	28	7 १25 प्रतिशत	हाँ
7-	पश्चिमो बंगाल :				
	कश्मिर समर्थित घोष मन्त्रिमण्डल	17	11	11१100 प्रतिशत	हाँ

BIBLIOGRAPHY

Primary Sources

A) Official Publications

- i) Report on fourth General Election in India Vol. II , Election Commission ,Government of India Press,1967.
 - ii) Report on 5th Lok Sabha Election in India, Commission Election Government of India Press,1971.
 - iii) Report on 6th general Election, Election in India ,Election Commission ,Government of India Press ,1977.
 - iv) Report on 7th general Election,Election in India,Election Commission ,Government of India Press, 1980.
 - v) Report on 8th Lok Sabha Election, Election in India,Election Commission ,Government of India Press- 1984.
 - vi) Report on 9th Lok Sabha Election,Election in India,Election Commission,Government of India Press - 1990.
-
- i) Fourth Parliament - a souvenir , 1967-72 ,Parliament New Delhi- 72.
 - ii) Fifth Parliament - a souvenir, 1972- 77.,Parliament New Delhi- 72.
 - iii) Sixth Parliament - a souvenir, 1977 - 80 ,Parliament New Delhi- 72.
 - iv) Seventh Parliament- a souvenir, 1980-84 ,Parliament New Delhi- 72.
 - v) 8th Parliament- a souvenir, 1984- 90 ,Parliament New Delhi- 72.

3. i) Report on Raghubir Dayal Commission 1967.
 - ii) Report on Dutta Commission - 1970.
 - iii) Report on Huber Commission -
 - iv) Report on Sarkaria Commission 1988.
 - v) Report on Administrative reforms commission 1969.
4. Report on Lok Sabha debate (Eight Session) Vol -36.
Contains numbers 1-10 ,Monday July 30 ,1969 .
Lok Sabha Secretariat, New Delhi

International Encyclopidia of Social Sciences Vol. 26.

JOURNALS

- 1) Asian Survey
- 2) Economic & Political Weekly
- 3) Dinman
- 4) South Asian Review.
- 5) Arth Shastri
- 6) General of Constitutions and Parliamentry studies.
- 7) India Today
- 8) Lok Tantra Samikasha
- 9) Indian Journal of Social Science

NEWS PAPERS

- 1) Hindustan
- 2) The Hindu
- 3) Navbharat Times.
- 4) Times of India
- 5) Rajasthan Patrika
- 6) Rastriya Sahara

SECONDARY SOURCES

Books/Report/Thesis

1. Almond G.A.- comparative POLITICAL System in Roy C.
Macridis and Bernard E.Brown ,comperative Politics,The
Dorsey Press, 1968.
2. Almond -G.A. -Comperative Politics,1972.
3. Asharef Ali & Sharma L.N.-Political Sociology : A new
Grammer of Politics .
4. Ahmad Basiruddin - Congress depeat in Amroha ,A case study
in one party dominance- Party system and Election Studies.
5. Auti, V.N.
A comparative study of Urban and rural political participat
An empirical study of local communities in Maharastra 1979,
Thesis: Shivaji University.

- 6) Anand J.C. - Punjab Politics -A survey
- 7) Brass R Paul- Political Participation, Institutionalization and Stability in India, Government and opposition .
- 8) Bhasin Prem- Politics National and International Associated New Delhi 1978.
- 9) Brass R Paul- Politics in Indian States.
- 10) Bhambari C.P. Public Administration in India 1973.
- 11) Ball A.R. - Modern Politics and Government -1971.
- 12) Balgopal K- Telangan Movement revisited , 1983.
- 13) Barthwal, C.P. and others- Political Participation in Garhwal A report 1986.
Research Project sponsored by Garhwal University .
- 14) Charles E. Lind Blam- Political Democracy and Disciplined Development the case in India.
- 15) Chand Ashok- Federalism in India - London , 1968.
- 16) Chand Phul - Federalism and Indian Political Parties.
- 17) Chatarji Sharad Kumar- The coalition Government- 1976.
- 18) Chopra Sukhwarsha - Political Socialisation of the Secondary School , Pupils in India. New Delhi. 1985.
- 19) Dahl A Robert- The Emergence of oppositions .
- 20) Dutt R.P. - India Today.
- 21) Dixit - Prabha Communadism - A struggle for Power New Delhi
22. Das Chandi R- The fourth General Election .1967.

- 23) Das ,V.C. Political Development in India .
- 24) Dharm Vir -Political efficacy : The concept and its applicability, 1979 .
Research Project sponsored by ICSSR.
25. Dutt Ratna : The Party representative in Fourth Lok Sabha
- 26) Davis Kavangh - Political culture.
- 27) Dinker Ramdhari Singh - Sanskriti Ke char Adhyay .
- 28) Darda Ranjit Singh - Bhartiya Lok Tantra Aur Andolan Ki Rajniti - 1973.
- 29) De Costa F.P.V. -Roots of Change in popular vote
The Hindu 17 March 1967.
- 30) Desai A.R. Bhartiya Rastravad Ki Adhunatam Pravritiya - 1978.
- 31) Ehsanul Haq Education and political culture in India
The elements of schooling system and cal socialization, New Delhi , Sterling
- 32) Eisenstadt, S.W.ed: Political sociology: A reader. 2 vols,
Jaipur Rawat, 1989.
- 33) Fredrik J .Karl Constitutional Government and democracy
- 34) Goel ,M.L Political participation in a developing nation: India ,Bombay Asia, 1975.
- 35) Gena C.B. Comperative Politics ,Vikas 1978)
- 36) Ghure , G.S. Cast and class in India.
- 37) Goswami, Binod Behari: Mizo unrest: A study of
of culture, 1976.
Thesis : Gauhati University.

- 38) Guota K.S. A study in the process of Political socialization. Bombay,Himalaya-1989.
- 39) Guota N.K. Political development and political leadership in village communities
Indian journal of social Research Aug.84
- 40) Hansan and Dugglas Indias democracy vikas 1974.
- 41) Iswardutta Congress Encyclopedia.
- 42) Jena B.B.ed. Social conflict and Indian politics,
Meerut,Meenakshi , 1989, viii ,
- 43) Jones W.H.Morris Language and Region with in Indian Union
Philip messon company -1967. India &
cylon :Unity and diversity
- 44) Jones Morris & Gupta: Indias political report on an Ecologica
B.Das. investigation - Asian Survey no. 6
June -1969.
- 45) Jones Morris . Government and Politics of India ,
Hachinson and company- London-1967.
- 46) Jones Morris The Indian congress Party- A.Dilena
dimension - Modern Asian studies 1 & 2
- 47) Jones Morris Indian goverment and Politics .
- 48) Jena B.B.ed Social conflict and Indian Politics,
Merrut, Meenakashhi , 1989.

- 49) Jain R.B. Contemporary issue Indians Administratio
Vikas , New Delhi 1976.
- 50) Kamal K.L. Democratics in India, Vikas , New Delhi -
- 51) Karunakaran K.P Religions Political awaking in India ,
Merntt - 1965.
- 52) Khan Dr.Rassinddian-Democracy in India -
The Regional dimention seminer 169, 1974
- 53) Kothari Rajani Politics in India.
- 54) Kothari Rajani The congress system in India.
- 55) Kothari Rajani Party system
- 56) Kothari Rajani Cost in Indian Politics.
- 57) Kothari Rajani National Unity in danger case for smaller
states -Times of INDIA 1968.
- 58) Kothari Rajani Tredition and Modernity Avisited governme
and opoosition No.(3) 1968.
- 59) Kothari Rajani Introduction context of electoral change
in India , Indian council of developing
socities -1969.
- 60) Krishna Gopal One party dominance -Developments party
system and election studies developing
socities- 167.

- 61) K ashya~~p~~^Subash Dalbadal and Rajyon ki rajniti Merrut
1971.
- 62) Kashyap Subash & POLITICAL Science Encyclopidia
Gupta V.P.
- 63) Khan Dr. Rassinddian - The regional dimension ,Seminar No.1
1974
- 64) Miliband Ralph Class power and state power, London Ve
1984 .
- 65) Nandi Ashish The culture of Indian Politics a stack
taking (Centre for Study of developin
society .
- 66) Oomen, T.K. Social structure and politics: Studies
independent India, Delhi, Hindustan, 1
- 67) Panchanadikar and Democratic studycture and socializatio
Panchanadikar,J. rural India: Analysis of participation
Bombay Popular, 1980.
- 68) Palmar & Norman India's forth general election (Asian
survey volume VII ,May -1967.
- 69) Pai L.W. Political culture and political develo
July 1975. Rajya Shashtra Samiksha .
- 70) Rao K.N. Regional and cast factors in India's
development,publish - J.C.Daruwala

- 71) Bai Ramashray Selection of Congress condidate ,
Economic and political weekly Feb,11,
1967.
- 72) Said P.M. Bhartiya Rajnitik Pranali .
- 73) Sethi J.D. India in crises -1975 .
- 74) Siwach J.R. Dynamics of Indian Government and
- 75) Sharma Neena Political socialization on and its
on attitudinal change towards social
political system : a case study of
women of Delhi , New Delhi Inter India
- 76) Shivaih,M Politics in an Indian village : A theo
empirical exploration in political
1980.
- 77) Singh Kamal Kumar Political socialisation : A case
Bihar legislative assembly, Delhi
1987 .
- 78) Saxena Brajesh C,- Princely heritage : The social basis
administrative Emerging sociology.
- 79) Swarn Naidu,D- The linkales of policy and society
modern democracies. Journal of
studies 13(2) September 1980-
- 80) Sharma Damodhar Indian Political Culture different
JAIPUR 1979

- 81) SRI Aurobindo The foundation of Indian Culture
and Renaissance in India Pandichery
- 82) Subramanyam B. Representative Bureocracy and Assesment
The Amercian political science review
No.4 1010 to 19. -1967.
- 83) Sharma Mahadev prasad Public Administrative theory and
practice Kitab Mahal ,Allahabad 1971
- 84) Standly a Kochenek The congress party of India ,the
dynamics of one party democracy.
- 85) Tripathi A. The extremist challenge vikas 1971.
- 86) Veer & Ulan Patterns of government - New York
Random house 1962.
- 87) Verma S.R. &
Narayan Iqbal Voting behavious in a chaning societ
- 88) Verba Sydney Political culture and political dev
ment 1965, Prinston
- 89) Weinner Minor State Politics in India 1967.
- 90) Weinner Minor Party building in a nationa Indian
National Congress (Chicago) 1967
- 91) Weinner Minor Party politics in India
of a multyparty system

- 92) Weiner Vinor India's two political cultures
- 93) Williams Emond Culture and society 1958.
- 94) Weber Max Politics as vocation
Essay in sociology Kegan Paul
Ltd. London 1952.
- 95) Bricher Michea Succession in India 1967 -The
routinization of Political Change - Asian
survey Nuber 7 July 1967.
- 96) Naidu Ratna Commercial edge of Rural societics -
India and MALASIYA.
- 97) Nayyar Kuldip India ,the critical year 1977
- 98) Pam Dutt Rajani Aaj' Ka Bharat
- 99) Narayan Iqabal Bharitiya Sarkar avam ki Rajniti .
- 100) Mohanti Manoranjan Revoludionary violence in India.
New Delhi,1977